

[2012] 7 एस.सी.आर. 644

मोनेट इस्पात एवं ऊर्जा लिमिटेड

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3285/2009)

26 जुलाई, 2012

[न्यायमूर्ति आर.लोढ़ा .एम., और न्यायमूर्ति एचगोखले .एल.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 294, प्रथम अनुसूची - राज्य सरकार का खनिजों और खदानों में स्वामित्व उसके क्षेत्र में - निर्णय: पूर्व राज्य बिहार जो कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट भाग-ए राज्य है और इससे पूर्व बिहार प्रांत, अनुच्छेद 294 के अनुसार, सभी संपत्तियाँ और संसाधन जो कि उनके अधीन थे, बिहार राज्य में स्थानांतरित हो गए - बिहार अधिनियम, 1950 के अनुसार, सभी अन्य भूमि, अर्थात् संपत्तियाँ और किसी भी प्रकार की अवधि जिसमें खनिज और खदानें शामिल हैं, बिहार राज्य में स्थानांतरित हो गईं - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, सभी भूमि, विशेष रूप से, उस समय के बिहार राज्य की जो स्थानांतरित क्षेत्रों में स्थित थी, नए निर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दी गई जो कि विषय क्षेत्र का स्वामी है - खनिज और खदानें उसके क्षेत्र में पूरी तरह से उसके स्वामित्व में हैं - बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - न्यायशास्त्र-'स्वामित्व'।

सातवीं अनुसूची - सूची I, प्रविष्टि 54, सूची II, प्रविष्टि 23 को प्रविष्टि 18 के साथ पढ़ें - खनिज - लौह अयस्क - सार्वजनिक क्षेत्र के दोहन के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित करने का राज्य सरकार का अधिकार - निर्णय: राज्य सरकार का अधिकार इस तथ्य से आता है कि यह अपने क्षेत्र में खदानों और खनिजों का स्वामी है - 1960 नियमों का नियम 59 स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के आदेश द्वारा आरक्षण की कल्पना करता है - 1957 अधिनियम की धारा 2 के बाद की व्यवस्थाएँ राज्य के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती हैं जबकि खदानों का नियमन और खनिजों का विकास संघ के नियंत्रण में लिया गया है - इसलिए, राज्य सरकार द्वारा 21.12.1962, 28.02.1969 और 27.10.2006 की अधिसूचनाओं के तहत किया गया आरक्षण 1957 अधिनियम के खिलाफ या असंगत नहीं है - ये अधिसूचनाएँ केंद्रीय सरकार की विधायी शक्ति पर प्रभाव नहीं डालती हैं - खनिज और खदानों (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 - धाराएँ 2 से 17-ए - खनिज अनुदान नियम 1960 - नियम 58, 59 और 63 ए।

अनुच्छेद 19(1)(ग), 39 और 299 - किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार - सरकारी अनुबंध - झारखंड राज्य सरकार ने संघ सरकार को कुछ कंपनियों को खनन पट्टा देने की सिफारिश की - बाद में यह स्वीकार करते हुए कि विषय क्षेत्र पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के दोहन के लिए आरक्षित था, उसने प्रस्ताव वापस ले लिया और एक और अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि विषय क्षेत्र में लौह अयस्क जमा निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाएगा - निर्णय: किसी व्यक्ति के पास कोई मौलिक अधिकार या यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसे खनन पट्टा या अन्वेषण लाइसेंस दिया जाना चाहिए या उसे किसी भी सरकारी भूमि पर पुनः खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए सिवाय इसके कि वह 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के तहत हो - यह सच है कि राज्य सरकार और अपीलकर्ताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता जापन (एमओयू) में कुछ प्रतिबद्धताएँ की गई थीं लेकिन सबसे पहले, ऐसा एमओयू अनुच्छेद 299(1) के तहत अनुबंध नहीं है और दूसरे, राज्य की संपत्ति के खनन पट्टे के अनुदान में राज्य सरकार को कोई भी खनन पट्टा देने या न देने का विवेकाधिकार होता है - स्पष्ट रूप से, राज्य सरकार को कानून की आवश्यकताओं के अनुसार अपना विवेकाधिकार लागू करना आवश्यक है - इस तथ्य को देखते हुए कि यह क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के दोहन के लिए आरक्षित है, यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया गया विवेकाधिकार किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त है।

खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957:

धारा 17-ए, 1960 नियमों के नियम 58 और 59 के साथ पढ़ी गई - खनन पट्टे के अनुदान के लिए केंद्रीय सरकार की स्वीकृति - निर्णय: नियम 58 में 1980 में संशोधन किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए आरक्षित कर सकती है - संशोधन केवल यह स्पष्ट करने के लिए किए गए थे कि जो पहले निहित था, उसे स्पष्ट किया गया है और ये राज्य सरकार की शक्तियों को शून्य नहीं कर सकते हैं जो कि अन्यथा अधिनियम के तहत उसके पास थीं - धारा 17-ए के लागू होने पर, नियम 58 को हटा दिया गया है - धारा 17-ए(2) के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी खनन पट्टे के तहत नहीं है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में खनन कार्य किए जा सकें - धारा 17-ए भविष्य की प्रकृति की है - धारा 17-ए के सम्मिलित होने से पहले किए गए आरक्षण लागू रहेंगे - इसके अलावा, धारा 17-ए द्वारा विचारित स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की शक्ति का प्रयोग करने से पहले या बाद में प्राप्त की जा सकती है - यह स्पष्ट या निहित हो सकता है - विधियों की व्याख्या - भविष्य की कार्रवाई।

विधियों की व्याख्या:

किसी वैधानिक प्रावधान का भविष्य की कार्रवाई - निर्णय: भविष्यवाद का अनुमान तब तक लागू होता है जब तक कि इसे स्पष्ट प्रावधान द्वारा विपरीत दिखाया न जाए या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रकट न किया जाए - सिद्धांत - 'नव संविधान भविष्य को रूप देना चाहिए, न कि पूर्ववर्ती को'

प्रशासनिक कानून:

**प्रतिज्ञा रोकने और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या - निर्णय:** प्रतिज्ञा रोकने का सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब वादा एक गलत धारणा में किया गया हो - राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम और नियमों के अनुसार खनिज अनुदान देने पर सहमति व्यक्त की थी - वास्तव में, जब एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब राज्य सरकार को विषय खनन क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए आरक्षित होने का पता भी नहीं था - इस तथ्य को देखते हुए कि विषय खनन क्षेत्र को 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए आरक्षित किया गया था, एमओयू में यह प्रावधान कि राज्य सरकार कंपनी की आवश्यकता के अनुसार लौह अयस्क और अन्य खनिजों के लिए क्षेत्र का चयन करने में सहायता करेगी और खनिज अनुदान देने का वादा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सबसे पहले, एमओयू में प्रावधान बिना शर्त नहीं है - दूसरी बात, यदि राज्य सरकार से कहा जाता है कि वह एमओयू के तहत जो करने का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका अर्थ होगा कि राज्य सरकार से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो अधिसूचनाओं का उल्लंघन करता है जो अभी भी लागू हैं - इस प्रकार, प्रतिज्ञा रोकने और वैध अपेक्षा के सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होते हैं - झारखंड राज्य द्वारा जारी 13.9.2005 की वापसी पत्र और भारत संघ द्वारा जारी 6.3.2006 की अस्वीकृति पत्र में कोई त्रुटि नहीं है।

**'डॉक्ट्रिन ऑफ डेस्यूट्यूड - व्याख्या की गई - निर्णय:** जहां तक 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं का संबंध है, डेस्यूट्यूड का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि: सबसे पहले, ऐसी अधिसूचनाओं का 30-35 वर्षों तक कार्यान्वयन न होना 'इतना लंबा समय नहीं है जो डेस्यूट्यूड के सिद्धांत की आवश्यकता को पूरा कर सके - दूसरी बात, वास्तव में, आरक्षित क्षेत्र के एक या दो पक्षों को बहुत छोटे हिस्से के लिए खनन पट्टे का बिखरा हुआ अनुदान छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो विपरीत उपयोग या विपरीत प्रथा को स्थापित करे कि दो अधिसूचनाओं में किए गए आरक्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है - इसके अलावा, चूंकि झारखंड राज्य ने 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं को संशोधित, रद्द या संशोधित नहीं किया है, इसलिए इसे समाप्त नहीं कहा जा सकता।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - धाराएँ 84, 85 और 86।

अपीलकर्ताओं, जो लोहे और स्टील आदि के उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए थे, ने झारखंड राज्य सरकार के साथ समझौतों में प्रवेश करने की बात कही, जिसके तहत राज्य सरकार ने उन्हें लौह अयस्क और अन्य खनिजों के लिए क्षेत्र का चयन करने में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की। अगस्त 2004 में, राज्य सरकार ने विषय क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन पट्टे के लिए भारत सरकार को अपनी सिफारिश के साथ दस कंपनियों, जिनमें छह अपीलकर्ता भी शामिल थे, के आवेदन भेजे। हालांकि, 17 नवंबर 2004 को जिला खनन अधिकारी ने झारखंड सरकार के खनिज और भूविज्ञान विभाग के सचिव को सूचित किया कि विषय क्षेत्र बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं दिनांक 21.12.1962 और 28.2.1969 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दोहन के लिए आरक्षित था। इसके परिणामस्वरूप, झारखंड सरकार ने 13.9.2005 को एक पत्र द्वारा नौ प्रस्तावों को वापस लेने का प्रयास किया, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं के प्रस्ताव भी शामिल थे। 6 मार्च 2006 को केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। इसके बाद, 27 अक्टूबर 2006 को एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने यह भी घोषित किया कि विषय क्षेत्र में लौह अयस्क जमा (जहां अपीलकर्ताओं के लिए खनन पट्टे का प्रस्ताव था और जो हमेशा से बिहार राज्य द्वारा जारी 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा आरक्षित था) निजी पक्षों के लिए अन्वेषण लाइसेंस, खनन लाइसेंस या अन्यथा नहीं खोला जाएगा। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में 13.9.2005 और 6.3.2006 की पत्रों के साथ-साथ 21.12.1962, 28.2.1969 और 27.10.2006 की अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर कीं और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें प्रस्तावित खनन पट्टे प्रदान किए जाएं। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कंपनियों द्वारा दायर किए गए इस अपील में अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था: क्या बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाएँ दिनांक 21.12.1962 और 28.2.1969 तथा झारखंड राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 वैध और कानूनी थीं। अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने निर्णय दिया: (न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा)

1.1 भारत के संविधान, 1950 में, खनिज संसाधनों का प्रबंधन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों के पास छोड़ दिया गया है, जो कि सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 54 और सूची II में प्रविष्टि 23 के अनुसार है। संविधान की योजना के तहत, राज्य विधानसभाओं को 'खनिजों और खदानों के विकास' के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानसभाओं पर केवल एक ही प्रतिबंध लगाया गया है, जो कहता है 'संघ के नियंत्रण के तहत नियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन'। यदि संसद ने अपने कानून द्वारा यह घोषित किया है कि खदानों का नियमन और खनिजों का विकास सार्वजनिक हित में

संघ के नियंत्रण में होना चाहिए, जैसा कि उसने खनिज और खदान (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 2 में घोषणा करके किया, तो उस कानून की सीमा तक जिसमें यह घोषणा शामिल है, राज्य विधानसभाओं की शक्ति को बाहर रखा गया है। 1957 अधिनियम की धारा 2 में संसद द्वारा की गई घोषणा कहती है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ को खदानों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, जैसा कि अधिनियम में स्वयं प्रदान किया गया है। आवश्यक घोषणा का प्रभाव यह है कि खदानों का नियमन और खनिजों का विकास प्रविष्टि 23, सूची II से उस सीमा तक हटा दिया गया है। चूंकि धारा 2 में की गई घोषणा राज्य विधानमंडल की शक्ति पर असर डालती है, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। धारा 2 में 'यहां बाद में प्रदान की गई सीमा तक' की प्रमुख अभिव्यक्ति की उपस्थिति से संघ ने 1957 अधिनियम में निर्धारित सीमा तक नियंत्रण ग्रहण कर लिया है। 1957 अधिनियम नियंत्रण की सीमा निर्धारित करता है और इसे स्पष्ट करता है। इसलिए, धारा 2 में की गई घोषणा पूरी तरह से व्यापक नहीं है। खदानों के नियमन और खनिजों के विकास से संबंधित कानूनी व्यवस्था इस प्रकार 1957 अधिनियम और खनिज अनुदान नियम, 1960 द्वारा मार्गदर्शित होती है। हालांकि, संसद द्वारा की गई घोषणा प्रभावी होने के लिए नियम बनाने या बनाए गए नियमों को लागू करना निर्णायक नहीं है। [पैराग्राफ 101-102, 108 और 109]

हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 1961 एससीआर 537 = एआईआर 1961 एससी 459; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम मिस एम.ए. टुल्लोक और कंपनी 1964 एससीआर 461 = एआईआर 1964 एससी 1284; बैजनाथ कडियो बनाम बिहार राज्य और अन्य 1970 (2) एससीआर 100 = 1969 (3) एससीसी 838; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य 1990 (3) एससीआर 744 = 1990 (4) एससीसी 557; डी.के. त्रिवेदी और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 1986 एससीआर 479 = 1986 सप्लीमेंटल एससीसी 20; एचआरएस मूर्ति बनाम चित्तूर के कलेक्टर 1964 एससीआर 666 = एआईआर (1965) एससी 177, एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ और अन्य 1979 (3) एससीआर 254 = 1979 (3) एससीसी 431, धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ 1996 (6) सप्लीमेंटल एससीआर 566 = 1996 (6) एससीसी 702; भूपत्राई मगनलाल जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2001 (10) एससीसी 476; एम.पी. राम मोहन राजा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य 2007 (5) एससीआर 576 = 2007 (9) एससीसी 78; सैंड्र मॅगनीज और आयरन ऑर्से लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 2010 (11) एससीआर 240 = 2010 (13) एससी सी1 - संदर्भित।

1.2. लौह अयस्क एक खनिज है जिसे 1957 अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके लिए बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के कोई खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति के पास यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार या अन्य कोई अधिकार नहीं है कि उसे खनन पट्टा या अन्वेषण लाइसेंस दिया जाना चाहिए या किसी भी सरकारी भूमि पर पुनः खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, सिवाय 1957 अधिनियम और खनिज अनुदान नियम 1960 के अंतर्गत। [पैराग्राफ 104] [767-एच; 768-एसी]

*तमिलनाडु राज्य बनाम मिस. हिंद स्टोन और अन्य* 1981 (2) एससीआर 742 = 1981 (2) एससीसी 205 - पर निर्भर

2.1. खनिज राष्ट्रीय संपत्ति का गठन करते हैं और ये बुनियादी ढांचे, पूंजीगत सामान और मूल उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। अर्थव्यवस्था और उद्योग के उचित विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता; बल्कि राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से, एक दुर्लभ खनिज के मामले में, राज्य या इसकी एजेंसी द्वारा दोहन की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा दोहन पर रोक लगाना संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन का सबसे प्रभावी तरीका है। [पैराग्राफ 103-104] [767-डी-एफ; 768-डी-ई]

राज्य सरकार का खदानों और खनिजों में स्वामित्व और आरक्षण की शक्ति:

2.2. यह विवाद में नहीं है कि सभी अधिकार और हित, जिनमें विषय क्षेत्र में खदानों और खनिजों के अधिकार शामिल हैं, पूर्व बिहार राज्य में सभी बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह से निहित थे। संविधान की शुरुआत के समय, पूर्व बिहार राज्य संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट भाग-ए राज्य था और इससे पहले बिहार प्रांत था। अनुच्छेद 294 के अनुसार, सभी संपत्तियाँ और संसाधन जो कि बिहार प्रांत के सरकार के उद्देश्य के लिए उनके अधीन थे, बिहार राज्य में स्थानांतरित हो गए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत, अन्य सभी भूमि, अर्थात् संपत्तियाँ और किसी भी प्रकार की अवधि जिसमें खदानें और खनिज शामिल हैं, बिहार राज्य में स्थानांतरित हो गईं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, सभी भूमि, विशेष रूप से उस समय के बिहार राज्य की जो स्थानांतरित क्षेत्रों में स्थित थी, नए निर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। यह स्वीकार किया गया है कि *राज्य सरकार (पूर्व बिहार और अब झारखंड) विषय क्षेत्र की मालिक है। उसके क्षेत्र में खदानें और खनिज पूरी तरह से उसके स्वामित्व में हैं। वास्तव में यही*

स्थिति है जिसके कारण अपीलकर्ताओं ने राज्य सरकार से खनन पट्टे के लिए आवेदन किया। [पैराग्राफ 105] [768-एफ-एच; 769- ए-सी]

2.3. चूंकि राज्य सरकार का लौह अयस्क पर सर्वोच्च अधिकार, जो कि खदानों का मालिक होने के नाते है, 1957 अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विषय क्षेत्रों को आरक्षित करने की शक्ति थी। [पैराग्राफ 107] [770-8-सी]

2.4. यह नहीं कहा जा सकता कि 1957 अधिनियम द्वारा 'खनिजों के विकास' से संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व अधिकार स्थिर हो गए हैं। सबसे पहले, संसद द्वारा धारा 2 में की गई घोषणा और उसके बाद की व्यवस्थाएँ धारा 2 के तहत राज्य के खदानों और खनिजों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती हैं, हालांकि खदानों का नियमन और खनिजों का विकास संघ के नियंत्रण में लिया गया है। धारा 4 भूमि से संबंधित गतिविधियों से संबंधित है और राज्य के स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करने का विस्तार नहीं करती है। धारा 4 हस्तांतरण के अधिकार को नियंत्रित करती है लेकिन एक राज्य में खनिजों के स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है और राज्य सरकार को अपने खनिजों का दोहन करने से रोकती नहीं है। धारा 4(1) का कोई उपयोग नहीं हो सकता जहां राज्य सरकार उस क्षेत्र में खुद खनन कार्य करना चाहती है जो उसके स्वामित्व में है। इसके अलावा, धारा 5 या अन्य धाराएँ जैसे कि धाराएँ 6, 9, 10, 11 और 13(2)(ए) भी उसके क्षेत्र में खदानों और खनिजों पर राज्य के स्वामित्व अधिकार को समाप्त नहीं करती हैं। संघ के नियंत्रण में खदानों और खनिजों के विकास हेतु विधायी शक्ति निश्चित रूप से सार्वजनिक हित में उचित विधायी द्वारा खदानों और खनिजों को अधिग्रहित करने की शक्ति का संकेत देती है, लेकिन 1957 अधिनियम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो यह सुझाव देता हो - यहां तक कि दूर-दूर तक - कि राज्यों में निहित खदानें और खनिज अधिग्रहित किए गए हैं। बल्कि, 1957 अधिनियम की योजना और व्यवस्थाएँ स्वयं दिखाती हैं कि संसद ने स्वयं उन भूमि को राज्यों की सरकार को निहित करने हेतु राज्य विधान बनाने की कल्पना की थी जिसमें खनिज जमा होते हैं और उसने प्रविष्टि 18, सूची II के तहत राज्य विधानसभाओं की शक्तियों पर आक्रमण करने का इरादा नहीं रखा था। 1957 अधिनियम की धारा 2 में की गई घोषणा पूरी तरह से व्यापक नहीं है। यह खदानों और खनिजों का अधिग्रहण करने की कल्पना नहीं करती है। हालांकि 'नियमन' शब्द को संदर्भ में व्यापक व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन संघ द्वारा निर्धारित नियंत्रण की सीमा को सख्ती से समझा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रविष्टि 54 के तहत एक घोषणा होने पर राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्ति केवल उस सीमा तक क्षीण होती है

जब तक संघ उस घोषणा के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है जैसा कि विधायी अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है जो घोषणा करता है। [पैराग्राफ 107,108,109 और 110] [770-सी-ई-एच; 771-ए-डी-ई-एफ; 772-एफ-जी]

*उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य* 1991 (2) एससीआर 105 = 1991 (1) सप्लीमेंटल एससीसी 430; *हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम चानन मल एवं अन्य* 1976 (3) एससीआर 688 = 1977 (1) एससीसी 340; *ईश्वर खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* 1980 (3) एससीआर 331 = 1980 (4) एससीसी 136; *वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा एवं अन्य* 1982 (2) एससीआर 1 = 1982 (1) एससीसी 125 - पर निर्भर

2.5. दूसरी बात, 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के लागू होने के बाद, केंद्रीय सरकार ने हमेशा समझा है कि राज्य सरकारें, जो अपने क्षेत्र में खदानों और खनिजों की मालिक हैं, किसी विशेष क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए आरक्षित करने का स्वाभाविक अधिकार रखती हैं। [पैराग्राफ 111] [773-बी ]

*अमृतलाल नाथुभाई शाह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* 1977 (1) एससीआर 372 = 1976 (4) एससीसी 108; और *भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य* 1990 (2) सप्लीमेंटल एससीआर 27 = 1992 (1) सप्लीमेंटल एससीसी 91 - पर निर्भर

2.6. इस न्यायालय का अमृतलाल नाथुभाई शाह में दिया गया निर्णय एक तरफ खनिज को अपनी संपत्ति के रूप में दोहन करने के लिए आरक्षण की शक्ति (राज्य सरकार की) और दूसरी तरफ 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के तहत खदानों और खनिज विकास के नियमन के बीच का अंतर स्थापित करता है। राज्य सरकार की किसी विशेष खनन क्षेत्र को अपने उपयोग के लिए आरक्षित करने की शक्ति स्वामित्व की उपज है; और यह इससे अलग नहीं की जा सकती जब तक कि इसे किसी उचित कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया हो। 1957 अधिनियम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। राज्य द्वारा उसके स्वामित्व वाली भूमि को उसके विशेष उपयोग के लिए और उसके प्रभुत्व और नियंत्रण के तहत अलग करना संप्रभुता और स्वामित्व की एक घटना है। यह नहीं कहा जा सकता कि *अमृतलाल नाथुभाई शाह* एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं है क्योंकि इसे पेर इन्कुरियम माना गया है क्योंकि इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार नहीं किया गया और लागू नहीं किया गया। इस न्यायालय के निर्णयों में *हिगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक और कंपनी, बैजनाथ कडियो और*

अमृतलाल नाथुभाई शाह में कोई असंगति या विरोधाभास नहीं है। अमृतलाल नाथुभाई शाह की पीठ ने इस न्यायालय द्वारा हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक और कंपनी तथा बैजनाथ कडियो में उजागर की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखा, हालांकि उसने इन निर्णयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। अमृतलाल नाथुभाई शाह में प्रस्तुत कानूनी स्थिति यह है कि भले ही खदानों के नियमन और खनिजों के विकास के संबंध में विधायी क्षेत्र संसद द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 2 में किए गए घोषणा से कवर किया गया हो, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में निहित खनिजों पर अपना अधिकार खो दिया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति खदानों का दोहन करने का अधिकार नहीं रखता सिवाय इसके कि वह 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का आदेश देने की शक्ति इस तथ्य से आती है कि वह अपने क्षेत्र में खदानों और खनिजों का मालिक है। ऐसी शक्ति नियम 59 के तहत भी देखी जा सकती है। [पैराग्राफ 113-114] [774-ई-एच; 775-ई-ई]

2.7. इस प्रकार, 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किया गया आरक्षण बिल्कुल भी 1957 अधिनियम के खिलाफ या असंगत नहीं है। विवादित अधिसूचनाएँ केंद्रीय सरकार की विधायी शक्ति पर प्रभाव नहीं डालती हैं। पूर्व बिहार राज्य सरकार को आरक्षण करने की शक्ति थी, जिसे उसने 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किया। ऐसी आरक्षण बनाने में राज्य में कोई कमी नहीं थी। [पैराग्राफ 102] [767-8-सी]

2.8. यह भी नहीं कहा जा सकता कि 1957 अधिनियम की धाराएँ 17 और 18 के संदर्भ में, 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ उन वैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं हैं जो 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में शामिल हैं। धारा 17 अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार करने के विषय में पूरी तरह से व्यापक नहीं है और इसका सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। यह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अपने खदानों और खनिजों के आरक्षण के अधिकार से संबंधित नहीं है। इसका आवेदन सामान्य नहीं है बल्कि यह उस विशेष स्थिति तक सीमित है जहां केंद्रीय सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में अन्वेषण या खनन कार्य करने का प्रस्ताव करती है जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है। जहां तक धारा 18 का संबंध है, यह मूल रूप से केंद्रीय सरकार को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त नियम बनाने की शक्ति देती है, अर्थात्, उसमें व्यक्त किए गए खनिजों का संरक्षण और व्यवस्थित विकास। यदि राज्य सरकार सार्वजनिक हित में उन खनिजों के संबंध में आरक्षण करती है जो उसके पास सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन हेतु निहित हैं, तो ऐसा आरक्षण केंद्रीय सरकार

पर धारा 18 के तहत डाले गए दायित्व को कमजोर करने के रूप में नहीं देखा जा सकता। [पैराग्राफ 115-116] [775-एफ-एच; 776-ए-डी]

2.9. नियम 59 ने राज्य सरकार के अधिकार को किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में खनन हेतु किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षित करने की मान्यता दी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन भी शामिल है। [पैराग्राफ 118] [777-ई]

*अमृतलाल नाथुभाई शाह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1977 (1) एससीआर 372 =1976 (4) एससीसी 108 - पर निर्भर*

*जनक लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 1989 (3) एससीआर 830 =1989 (4) एससीसी 121 - उद्धृत*

2.10. नियम 58 को 1980 में संशोधित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को सरकारी उपयोग हेतु आरक्षित कर सकती है, एक निगम जो केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या कंपनियों अधिनियम की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी हो। नियम 58 को अब हटा दिया गया है क्योंकि आरक्षण का प्रावधान अब स्पष्ट रूप से धारा 17 ए जोड़कर बनाया गया है जो कि 1957 अधिनियम में शामिल किया गया था। धारा 17 ए(2) के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से किसी भी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं हो ताकि वह एक सरकारी कंपनी या उसके द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली निगम द्वारा अन्वेषण या खनन कार्य कर सके। धारा 17 ए(2) के अनुसार, उस धारा के लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आरक्षण केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार, जो प्रावधान मूल रूप से 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में शामिल किए गए थे, उनके संदर्भ में राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में खनन हेतु किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार स्पष्ट रूप से पहले नियम 58 में संशोधन करके किया गया था और बाद में धारा 17 ए जोड़ने द्वारा जो कि संशोधन प्रभावी हुआ था जो कि 1987 से लागू हुआ। [पैराग्राफ 119 और 120] [777-जी-एच; 778-ए डी]

2.11. इस न्यायालय की संविधान पीठों के निर्णयों से, जैसे कि *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक और बैजनाथ कादियो* के मामलों में, यह स्पष्ट है कि यदि संसद द्वारा कोई घोषणा की गई है, तो उस घोषणा के दायरे तक, खानों और खनिज विकास का नियमन राज्य

विधान की परिधि से बाहर होगा, जैसा कि केंद्रीय सूची के प्रविष्टि 54 के तहत प्रदान किया गया है। इस मामले में, न्यायालय किसी भी प्रावधानों के संघर्ष से संबंधित नहीं है जो एम एम डीआर अधिनियम के तहत हैं, न ही किसी राज्य विधान या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी कार्यकारी आदेश से। अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि राज्य सरकार 1962 और 1969 में सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने वाले अधिसूचनाएं जारी करने में सक्षम नहीं थी, इस मामले में अमृतलाल नथुभाई शाह के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार की शक्ति उसके खनिजों के स्वामित्व से उत्पन्न होती है, और उसके पास उनके साथ निपटने का स्वाभाविक अधिकार है। [पैराग्राफ 50, 53 और 55] [869-ब; 871-डी-एफ; 872-सी]

*अमृतलाल नथुभाई शाह बनाम भारत संघ 1977 (1) एससीआर 372 = 1976 (4) एसईसी 108 - पर निर्भर*

*हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य 1961 एससीआर 537 = एआईआर 1961 एससी 459; उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी 1964 एससीआर 461 एआईआर 1964 एससी 1284; बैजनाथ कादियो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1970 (2) एससीआर 100 = 1969 (3) एससीसी 838 - संदर्भित।*

2.12. *अमृतलाल का निर्णय हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी और बैजनाथ कादियो के प्रस्तावों के विपरीत कुछ नहीं कहता है, बल्कि यह एक बाध्यकारी उदाहरण है।* अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान समूह की अपीलों में चुनौती दी गई अधिसूचनाएं एम एम डीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से सुरक्षित थीं, और अमृतलाल में समझाया गया। [पैराग्राफ 59] [875-सी]

3.1. यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों अधिसूचनाएं निराधारता के कारण प्रभावित हैं। कानून की आवश्यकता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण अवधि की उपेक्षा होनी चाहिए, और यह दिखाना आवश्यक है कि एक विपरीत प्रथा एक महत्वपूर्ण समय से चल रही है। अपीलकर्ताओं ने इस संबंध में कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहे हैं। झारखंड राज्य के अधिकारियों ने जैसे ही अधिसूचनाओं को उनके ध्यान में लाया, उसी क्षण कार्रवाई की, और उन्होंने इसके अनुसार कार्य किया। यह निश्चित रूप से निराधारता नहीं हो सकती। [पैराग्राफ 60] [875-डी-एफ]

3.2. वचनबद्धता की रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक वादा होना चाहिए, और उसी आधार पर संबंधित पक्ष को अपने नुकसान में कार्य करना चाहिए। इस मामले में, यह केवल एक प्रस्ताव था, और यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसे केंद्रीय सरकार द्वारा

अनुमोदित किया जाना था, इससे पहले इसे वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता था। इसके अलावा, न्यायिक सिद्धांत का उपयोग किसी वैधानिक प्रावधान या अधिसूचना के खिलाफ नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता जो मांग कर रहे हैं वह किसी प्रकार का विशिष्ट प्रदर्शन है जबकि पक्षों के बीच कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं है। एक एमओयू अनुबंध नहीं है, और किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 299 के अर्थ में नहीं आता। सी.ए. संख्या 3286 वर्ष 2009 में अपीलकर्ता को छोड़कर अन्य अपीलकर्ताओं ने आगे कोई कदम नहीं उठाया प्रतीत होता है। किसी भी स्थिति में, किसी वादे की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता संबंधित वैधानिक शक्तियों के तहत जारी अधिसूचनाओं के खिलाफ वचनबद्धता की रोकथाम का दावा नहीं कर सकते। [पैराग्राफ 61-62] [875-एफ-एच; 876-ए-बी]

3.3. वैध अपेक्षा का सिद्धांत तब लागू नहीं किया जा सकता जब सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय कानून के किसी प्रावधान पर आधारित हो, और यह सार्वजनिक हित के अनुरूप हो। जैसा कि इस न्यायालय ने सांडूर मेंगनीज में दोहराया है, "यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई मामला विधि द्वारा शासित होता है, तो न्यायिक सिद्धांत को बाहर रखा जाता है।" [पैराग्राफ 62] [876-सी-डी]

*सांडूर मेंगनीज और आयरन ऑर्से लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य* 2010 (11) एससीआर 240 = 2010 (13) एससीसी 1 - पर निर्भर

4.1. खनिज और खनिज एक राष्ट्र की संपत्ति का हिस्सा हैं। वे समुदाय के भौतिक संसाधनों का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार, राज्य को विशेष रूप से यह निर्देशित करना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई की सेवा करे। अनुच्छेद 39(सी) में कहा गया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक प्रणाली का संचालन धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामान्य हानि का कारण न बने। एम एम डीआर अधिनियम के प्रावधानों में और इसके धारा 2 के तहत घोषणा में सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से लिखा गया है। खानों का स्वामित्व झारखंड राज्य में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत की गई घोषणा के अनुसार है, जिसे नवम अनुसूची में रखा गया है। [पैराग्राफ 66] [878-जी-एच; 879-ए-बी]

*तमिलनाडु राज्य बनाम हिंदू स्टोन* [1981] 2 एससीआर 742 = एआईआर 1981 एससी 711; और *वामन राव बनाम भारत संघ* 1981 (2) एससीआर 1 = 1981 (2) सेक 362 - पर निर्भर

4.2. झारखंड राज्य द्वारा जारी किए गए 13.9.2005 के वापस लेने के पत्र में कोई त्रुटि नहीं है, और भारत संघ द्वारा जारी किए गए 6.3.2006 के अस्वीकृति पत्र में भी कोई त्रुटि नहीं है, जैसा कि वहां बताए गए कारणों में है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों को पट्टे देने से इनकार करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने में पूरी तरह से उचित कार्य किया, जो कि 1962, 1969 और 2006 की अधिसूचनाओं के आधार पर था। राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है वह उस अधिनियम की नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, जिस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। [पैराग्राफ 67] [879-एफ-जी]

एयर इंडिया बनाम भारत संघ 1995 (2) सप्ली. एससीआर 175 = 1995 (4) एससीसी 734; मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1979 (2) एससीआर 641 = 1979 (2) एससीसी 409; पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य 2004 (2) सप्ली. एससीआर 135 = 2004 (6) एससीसी 465; महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण शंकर पुराणिक 1983 (1) एससीआर 655 = 1982 (3) एससीसी 519; पुणे नगर निगम एवं अन्य बनाम भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड एवं अन्य 1995 (2) एससीआर 716 = 1995 (3) एससीसी 434; कैंटोनमेंट बोर्ड मऊ बनाम मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1997 (3) एससीआर 813 = 1997 (9) एससीसी 450; अमृत बनस्पति लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1992 (2) एससीआर 13 = 1992 (2) एससीसी 411; एमपी माथुर और अन्य बनाम ओटीसी और अन्य 2006 (9) सप्ली. एससीआर 519 = 2006 (13) एससीसी 706; धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ 1996 (6) सप्ली. एससीआर 566 = 1996 (6) एससीसी 702; एमपी राम मोहन राजा बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 (5) एससीआर 576 = 2007 (9) एसएफसी 78; केरला राज्य बनाम बी. सिक्स हॉलीडे रिसॉर्ट्स {पी} लिमिटेड 2010 (3) एससीआर 1 = 2010 (5) एससीसी 186 – उद्धृत

मामला कानून संदर्भ:

न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा द्वारा

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| 1961 एससीआर 537     | पैराग्राफ 21     | का संदर्भ |
| 1964 एससीआर 461     | पैराग्राफ 21     | का संदर्भ |
| 1970 (2) एससीआर     | 100 पैराग्राफ 21 | का संदर्भ |
| 1977 (1) एससीआर 372 | पैराग्राफ 21     | पर निर्भर |

|                            |              |            |
|----------------------------|--------------|------------|
| 1989 (1) सप्ली. एससीआर 692 | पैराग्राफ 21 | का संदर्भ  |
| 1991 (2) एससीआर 105        | पैराग्राफ 21 | का संदर्भ  |
| 2010 (3) एससीआर 16         | पैराग्राफ 21 | में उद्धृत |
| 2008 (56) 1 बीएलजेआर 660   | पैराग्राफ 21 | में उद्धृत |
| 1990 (3) एससीआर 744        | पैराग्राफ 23 | का संदर्भ  |
| 1989 (3) एससीआर 830        | पैराग्राफ 26 | का संदर्भ  |
| 2010 (11) एससीआर 240       | पैराग्राफ 28 | का संदर्भ  |
| 1986 एससीआर 479            | पैराग्राफ 30 | का संदर्भ  |
| 1981 (2) एससीआर 742        | पैराग्राफ 30 | पर निर्भर  |
| 1990 (2) सप्ली. एससीआर 27  | पैराग्राफ 30 | पर निर्भर  |
| 1973 (1) एससीआर 896        | पैराग्राफ 31 | का संदर्भ  |
| 1952 एससीआर 889            | पैराग्राफ 33 | में उद्धृत |
| 2001 (10) सेक 476          | पैराग्राफ 33 | का संदर्भ  |
| 1961 एससीआर 204            | पैराग्राफ 35 | उद्धृत     |
| 1985 (3) सप्ली. एससीआर 909 | पैराग्राफ 35 | उद्धृत     |
| 1995 (2) एससीआर 716        | पैराग्राफ 35 | का संदर्भ  |
| 2003 (1) एससीआर 593        | पैराग्राफ 35 | उद्धृत     |
| 1976 (3) एससीआर 688        | पैराग्राफ 36 | पर निर्भर  |
| 1980 (3) एससीआर 331        | पैराग्राफ 36 | पर निर्भर  |
| 1979 (2) एससीआर 641        | पैराग्राफ 37 | का संदर्भ  |
| 1992 (2) एससीआर 13         | पैराग्राफ 37 | का संदर्भ  |

|                                |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 2004 (2) सप्ली. एससीआर 135     | पैराग्राफ 37     | का संदर्भ  |
| 2006 (9) सप्ली. एससीआर 519     | पैराग्राफ 37     | का संदर्भ  |
| 1964 एससीआर 666                | पैराग्राफ 94     | का संदर्भ  |
| 1979 (3) एससीआर 254            | पैराग्राफ 94     | का संदर्भ  |
| 1985 सप्ली. एससीआर 145         | पैराग्राफ 94     | में उद्धृत |
| 1982 (2) एससीआर 1              | पैराग्राफ 94     | पर निर्भर  |
| 1996 (6) सप्ली. एससीआर 566     | पैराग्राफ 96 बी  | का संदर्भ  |
| 2007 (5) एससीआर 576            | पैराग्राफ 98     | का संदर्भ  |
| 1951 एससीआर 228                | पैराग्राफ 123    | का संदर्भ  |
| (1905) एसी 369                 | पैराग्राफ 123    | का संदर्भ  |
| (1894) 1 क्यूबी 725, पृष्ठ 737 | पैराग्राफ 123    | का संदर्भ  |
| (1956) 1 ऑल ईआर 256            | पैराग्राफ 131    | का संदर्भ  |
| (1854) 5 एचएलसी 185            | पैराग्राफ 131    | का संदर्भ  |
| (1877) 2 एसी 439               | पैराग्राफ 131 डी | का संदर्भ  |
| (1889) 40 च डी 268             | पैराग्राफ 131    | का संदर्भ  |
| (1968) 2 ऑल ईआर 987            | पैराग्राफ 132    | का संदर्भ  |
| (1975) 3 ऑल ईआर 269            | पैराग्राफ 132 ई  | का संदर्भ  |
| (1975) 3 ऑल ईआर 865            | पैराग्राफ 132    | का संदर्भ  |
| 57 एएलआर 980                   | पैराग्राफ 135    | का संदर्भ  |
| (1958) 31 कैल. 2डी 409         | पैराग्राफ 135    | का संदर्भ  |
| (1968) 2 एससीआर 366            | पैराग्राफ 136    | का संदर्भ  |

|                                               |               |           |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| (1952) एससीआर 43                              | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1970 (2) एससीआर 854                           | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| (1974) 1 एससीआर 515                           | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1975 (2) एससीआर 359                           | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1974 (1) एससीआर 671                           | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1976 सप्ली. एससीआर 535                        | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1978 (1) एससीआर 375                           | पैराग्राफ 136 | का संदर्भ |
| 1977 (3) एससीआर 249                           | पैराग्राफ 137 | का संदर्भ |
| 1985 (3) सप्ली. एससीआर 123                    | पैराग्राफ 138 | का संदर्भ |
| 1988 (1) एससीआर 383                           | पैराग्राफ 139 | पर निर्भर |
| 1994 (4) सप्ली. एससीआर 448                    | पैराग्राफ 141 | का संदर्भ |
| 2003 सप्ली. एससीआर 476                        | पैराग्राफ 142 | का संदर्भ |
| 2004 (6) सप्ली. एससीआर 264                    | पैराग्राफ 144 | का संदर्भ |
| 1993 (3) एससीआर 128                           | पैराग्राफ 148 | का संदर्भ |
| 1996 (2) सप्ली. एससीआर 662                    | पैराग्राफ 148 | का संदर्भ |
| 1997 (1) सप्ली. एससीआर 671                    | पैराग्राफ 150 | का संदर्भ |
| 2003 (2) एससीआर 933                           | पैराग्राफ 151 | का संदर्भ |
| 1983 (1) एससीआर 655                           | पैराग्राफ 163 | का संदर्भ |
| (1931) 2 केबी 215 (सीए)                       | पैराग्राफ 163 | का संदर्भ |
| 1931 एसएलटी (स्कॉट्स लॉ टाइम्स रिपोर्ट्स) 456 | पैराग्राफ 163 | का संदर्भ |
| (1970) 2 ऑल ईआर 193                           | पैराग्राफ 163 | का संदर्भ |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| 1997 (3) एससीआर 813  | पैराग्राफ 166 | का संदर्भ  |
| एआईआर 1936 पीसी 253  | पैराग्राफ 172 | का संदर्भ  |
| 2008 (14) एससीआर 859 | पैराग्राफ 172 | में उद्धृत |
| 2001 (2) एससीआर 207  | पैराग्राफ 173 | में उद्धृत |
| 1978 (2) एससीआर 272  | पैराग्राफ 174 | का संदर्भ  |

न्यायमूर्ति गोकले के अनुसार:

|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 1961 एससीआर 537            | पैराग्राफ 14 | का संदर्भ           |
| 1961 एससीआर 537            | पैराग्राफ 14 | का संदर्भ           |
| 1964 एससीआर 461            | पैराग्राफ 14 | का संदर्भ           |
| 1970 (2) एससीआर 100        | पैराग्राफ 14 | का संदर्भ           |
| 1977 (1) एससीआर 372        | पैराग्राफ 14 | पर निर्भर           |
| 1989 (3) एससीआर 830        | पैराग्राफ 14 | में अनुपयुक्त घोषित |
| 1973 (1) एससीआर 896        | पैराग्राफ 16 | में भिन्नता         |
| 1990 (2) सप्ली. एससीआर 27  | पैराग्राफ 16 | में अनुपयुक्त घोषित |
| [1986] एससीआर 479          | पैराग्राफ 16 | में भिन्नता         |
| 1995 (2) सप्ली. एससीआर 175 | पैराग्राफ 17 | में उद्धृत          |
| 1990 (3) एससीआर 744        | पैराग्राफ 18 | में अनुपयुक्त घोषित |
| 1979 (2) एससीआर 641        | पैराग्राफ 18 | में उद्धृत          |
| 2004 (2) सप्ली. एससीआर 135 | पैराग्राफ 18 | उद्धृत              |
| 1952 एससीआर 1056           | पैराग्राफ 19 | में उद्धृत          |
| 1981 (2) एससीआर 1          | पैराग्राफ 19 | पर निर्भर           |

|                            |              |           |
|----------------------------|--------------|-----------|
| 1966 एससीआर 709            | पैराग्राफ 22 | पर निर्भर |
| 1983 (1) एससीआर 655        | पैराग्राफ 23 | उद्धृत    |
| 1995 (2) एससीआर 716        | पैराग्राफ 23 | उद्धृत    |
| 1997 (3) एससीआर 813        | पैराग्राफ 23 | उद्धृत    |
| 1992 (2) एससीआर 13         | पैराग्राफ 24 | उद्धृत    |
| 2006 (9) सप्ली. एससीआर 519 | पैराग्राफ 24 | उद्धृत    |
| 2010 (11) एससीआर 240       | पैराग्राफ 24 | पर निर्भर |
| 1981 (2) एससीआर 742        | पैराग्राफ 25 | पर निर्भर |
| 1996 (6) सप्ली. एससीआर 566 | पैराग्राफ 25 | उद्धृत    |
| 2007 (5) एससीआर 576        | पैराग्राफ 25 | उद्धृत    |
| 2010 (3) एससीआर 1          | पैराग्राफ 25 | उद्धृत    |
| 1980 (3) एससीआर 331        | पैराग्राफ 32 | संदर्भित  |
| 1991 (2) एससीआर 105        | पैराग्राफ 32 | संदर्भित  |

[1985] 2 एससीआर 175

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3285 वर्ष 2009 आदि।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायादेश एवं आदेश दिनांक 04.04.2007 से, ब्रिट याचिका (सिविल ) संख्या 4151/2006

साथ में

सीए. संख्याएँ 3286, 3287, 3288, 3289 और 3290/2009

सी. पेल् (सी) संख्या 14/2009 में सी.ए. संख्या 3287/2009 में।

डॉ अभिषेक एम. सिंहवी, ओर. राजीव धवन, ओहरव मेहता, अजीत कृष्ण सिन्हा, पी.एस. नरसिम्हा, टी.एस. दोबिया, अशोक भान, जे.के. ओस, कृष्णन वेणुगोपाल, संजीव सेन, गौरव गोयल, सुनील मित्तल, पुलकित शर्मा, ई.जी. अग्रवाल, ओमर अहमद, प्रशांत मेहता, सुनीता बंकोटी (सुरेश ए. श्रॉफ और कंपनी के लिए), जया भारुखा, गुरु प्रताप (देवाशीष भारुखा के लिए), संजीव के. कपूर, जफर इनायत, गौरव जूनेजा, योगेश वी. कोटेमाथ, रोहिणी मिश्रा, राहुल चंद्र (खालतान और कंपनी के लिए), के.बी. रोहतगी, महेश कासना, अपर्णा रोहतगी जैन, बी. विजयताक्ष्मी मेनन, रोहित चौधरी, प्रीति खिवानी, श्री राम कृष्णन, गर्वेश काबरा, गौरव प्रताप (देवाशीष भारुखा के लिए), रतन कुमार चौधरी, ब्रह्मजीत मिश्रा, एन.एन. सिंह, एस. चंद्रशेखर, अश्वार्या सिन्हा, सुनील कुमार जैन, अनिश मित्तल, सचिन शर्मा, श्रीधर पोताराजु, गैचांग गणमेई, श्रीराम परक्कट, डी. सिरी राव, अन्नपूर्णा, संदीप गोवर, सिद्धार्थ (लुथरा और लुथरा के लिए), मधुरिमा टालिया, साधना संधू, सुनीता शर्मा, गर्गी खन्ना, एस.एस. रावत (डी.एस. महारा के लिए), अविजीत भुजबल, पी.पी. नायक (परमानंद गौर के लिए), एस.के. दिवाकर, छाया कुमारी उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एवं आदेश **न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा** द्वारा दिया गया।

## **प्रस्तावना**

1. इस छह अपीलों के समूह ने न्यायालय का काफी समय लिया। इन मामलों की सुनवाई 2 नवंबर 2011 से 29 नवंबर 2011 के बीच दस दिनों में की गई। हालांकि, तथ्यों में कुछ मामलों में भिन्नता है, लेकिन चूंकि मौलिक मुद्दे सामान्य प्रतीत होते हैं और ये सभी मामले झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की विभाजन पीठ द्वारा 4 अप्रैल 2007 को पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमने इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की है, जिन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

## **प्रार्थनाएँ**

2. उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं में प्रार्थनाएँ भी भिन्न हैं। हालांकि, मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा उनकी याचिकाओं में मांगी गई राहतें निम्नलिखित थीं: (i) झारखंड सरकार के खनिज और भूविज्ञान विभाग के उस निर्णय को रद्द करना, जो 13 सितंबर 2005 के पत्र में निहित है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में किए गए खनन पट्टे के लिए अनुशंसा को वापस लेने का प्रयास किया था, जो कि मऊजा घाटकुरी, पश्चिम सिंहभूम जिला, झारखंड के लौह अयस्कधारी क्षेत्रों में था; (ii) भारत सरकार के खनिज मंत्रालय का आदेश, जिसके अंतर्गत मंत्रालय ने झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक अपीलकर्ता के पक्ष में की गई अनुशंसा को वापस कर दिया; (iii) बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ दिनांक 21 दिसंबर 1962 और 28 फरवरी 1969 तथा झारखंड सरकार

द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2006 को शून्य और अमान्य घोषित करना; और (iv) उत्तरदाताओं को निर्देश देना कि वे खनिज अनुबंध नियम, 1960 (संक्षेप में '1960 नियम') के नियम 59(2) के तहत प्रत्येक अपीलकर्ता को घाटकुरी में लौह अयस्कधारी क्षेत्रों में खनन पट्टे के लिए आगे बढ़ें।

### **बिहार भूमि सुधार अधिनियम**

3. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (संक्षेप में '1950 बिहार अधिनियम') बिहार विधानमंडल द्वारा उन भूमि पर मालिकों और पट्टेदारों के हितों को राज्य को हस्तांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिनमें बंधक और पट्टेदारों के हित शामिल हैं, जिसमें खनिजों और उनसे संबंधित अन्य मामलों का भी समावेश है। यह 25 सितंबर 1950 को लागू हुआ। 1950 बिहार अधिनियम का अध्याय II राज्य में संपत्ति या पट्टे का अधिकार और इसके परिणामों से संबंधित है। राज्य सरकार को धारा 3 के तहत यह घोषणा करने का अधिकार दिया गया है कि किसी मालिक या पट्टेदार की संपत्तियाँ या पट्टे, जो समय-समय पर अधिसूचना/स से निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, राज्य में हस्तांतरित हो जाएँगी। धारा 4 राज्य में संपत्ति या पट्टे के हस्तांतरण के परिणामों का प्रावधान करती है। धारा 4 कुछ अवसरों पर संशोधनों से गुजरी है। जितना यह प्रासंगिक है, 1950 बिहार अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"4. राज्य में संपत्ति या पट्टे के हस्तांतरण के परिणाम। - किसी अन्य कानून में निहित किसी भी प्रावधान या किसी अनुबंध के बावजूद और किसी भी गैर-अनुपालन या असामान्य अनुपालन के बावजूद ..... उपधारा (1) धारा 3 या उपधारा (1) या उपधारा (2) धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे और हमेशा उत्पन्न माने जाएंगे, अर्थात्;

(ए ) ऐसी संपत्ति या पट्टा जिसमें मालिक या पट्टेदार का कोई भवन या भवन का भाग शामिल है ..... तथा उसकी सभी उप-सोइल सहित खनिजों और खानों में कोई अधिकार चाहे वह खोजा गया हो या न हो, चाहे उसे कार्यान्वित किया गया हो या नहीं, ऐसे अधिकारों सहित जो कि खानों और खनिजों के पट्टेदार के हैं, ऐसी संपत्ति या पट्टा (रैयतों या अंडर-रैयतों के हितों को छोड़कर) राज्य में पूर्ण रूप से हस्तांतरित हो जाएंगे सभी बंधनों से मुक्त होकर और ऐसा मालिक या पट्टेदार ऐसी संपत्ति में कोई हित नहीं रखेगा सिवाय उन हितों के जो इस अधिनियम की धाराओं द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षित किए गए हैं।"

4. अब इन अपीलों से संबंधित संक्षिप्त तथ्य देखे जा सकते हैं।

## तथ्यात्मक विशेषताएँ

### सिविल अपील संख्या 3285/2009, मोनेट इस्पात और ऊर्जा लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।

5. अपीलकर्ता कंपनी, जिसे मोनेट के नाम से संदर्भित किया गया है, कंपनियों के अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। मोनेट खनन, स्टील उत्पादन, फेरो-एलॉय और पावर के व्यवसाय में संलग्न है। मोनेट ने झारखंड के हजारीबाग जिले में 1400 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ एक एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया। 5 फरवरी 2003 को मोनेट और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एकीकृत स्टील प्लांट के लिए मुख्य कच्चा माल लौह अयस्क है। 29 जनवरी 2004 को, मोनेट ने झारखंड राज्य सरकार से घटकुरी मौजा में प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए 3566.54 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क की खनन पट्टा के लिए आवेदन किया।

5.1. मोनेट का कहना है कि आवेदन पर विचार करने और खनिजों और खनन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे '1957 अधिनियम' कहा जाता है) और 1960 नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, राज्य सरकार ने अगस्त 2004 में मोनेट के आवेदन की सिफारिश भारत सरकार से की। यह सिफारिश घटकुरी में 705 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क की खनन पट्टा देने के लिए की गई थी। यह सिफारिश तब की गई जब राज्य सरकार संतुष्ट थी कि उक्त खनन ब्लॉक शोषण के लिए उपयुक्त था और मोनेट की आवश्यकताओं को पूरा करता था। यह सिफारिश प्राथमिकता के आधार पर भी की गई क्योंकि मोनेट ने राज्य की औद्योगिक नीति के आवश्यक लक्ष्यों को पूरा किया था।

5.2. भारत सरकार के खान मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने पर, 6 सितंबर 2004 को कुछ स्पष्टीकरण मांगे। कहा जाता है कि राज्य सरकार ने इस संचार का उत्तर दिया और 17 नवंबर 2004 को अपनी स्थिति स्पष्ट की। राज्य सरकार ने मोनेट के पक्ष में सिफारिश दोहराई।

5.3. 17 नवंबर 2004 को, जिला खनन अधिकारी, चाईबासा ने झारखंड सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग के सचिव को सूचित किया कि घटकुरी और आस-पास के क्षेत्रों के कुछ हिस्से सार्वजनिक क्षेत्र की शोषण हेतु आरक्षित थे।

5.4. केंद्रीय सरकार ने 15 जून 2005 को सूचित किया कि खान मंत्रालय तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

5.5. 29 जून 2005 को, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से लंबित आवेदनों की प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया।

5.6. 13 सितंबर 2005 को, राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से नौ आवेदकों में से आठ की खनन पट्टा प्रस्तावों को वापस करने का अनुरोध किया।

5.7. 14 सितंबर 2005 को, राज्य और केंद्रीय सरकारों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को सूचित किया कि उसने मोनेट सहित नौ लंबित खनन पट्टा प्रस्तावों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

5.8. मोनेट ने कहा है कि उसे आवंटित करने के लिए अनुशंसित कंपार्टमेंट संख्या 5 किसी भी आरक्षण से प्रभावित नहीं थी।

5.9. भारत सरकार ने 6 मार्च 2006 को उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जो राज्य सरकार ने मोनेट सहित आवेदकों के पक्ष में खनन प्रस्तावों को वापस लेने के लिए किया था।

#### **सिविल अपील संख्या 3286 वर्ष 2009, आधुनिक अलॉयज और पावर लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**

6. अपीलकर्ता कंपनी, एम/एस आधुनिक अलॉयज और पावर लिमिटेड, जिसे आधुनिक के नाम से संदर्भित किया गया है, कंपनियों के अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। यह लौह और स्टील का व्यवसाय करती है। आधुनिक ने झारखंड राज्य के कंद्रा में 2.2 एमटीपीए एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने का इरादा रखा। इस एकीकृत स्टील प्लांट का पहला चरण जून 2005 में पूरा और कमीशन किया गया था। चरण-II की पूर्णता का कार्य चल रहा है। 1 सितंबर 2003 को, आधुनिक ने झारखंड में कंद्रा में अपने प्रस्तावित एकीकृत स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क की कैप्टिव खपत हेतु घटकुरी मौजा में 8809.37 एकड़ (3566.54 हेक्टेयर) क्षेत्र में खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया।

6.1. 16 सितंबर 2003 को, उप आयुक्त, चाईबासा ने आधुनिक के आवेदन को कुछ अन्य आवेदनों के साथ खनिज निदेशक, झारखंड को अग्रेषित किया।

6.2. चूंकि आवेदन ओवरलैप हो रहे थे, खनिज निदेशक ने 26 दिसंबर 2003 को आधुनिक और अन्य आवेदकों को बैठक के लिए बुलाया। खनिज निदेशक ने आवेदकों, जिसमें आधुनिक भी शामिल था, की सुनवाई की।

6.3. 26 फरवरी 2004 को, राज्य सरकार और आधुनिक के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें सिरेकीला-खरसवां जिले के गांव कंद्रा में एकीकृत स्टील प्लांट से संबंधित परियोजना का विवरण; वार्षिक क्षमता, परियोजना लागत और कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई।

6.4. 4 अगस्त 2004 को, राज्य सरकार ने कैप्टिव खपत हेतु लौह अयस्क के लिए 426.875 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा देने के लिए आधुनिक के मामले की सिफारिश केंद्रीय सरकार से की। अपने पत्र में, जिसमें उसने केंद्रीय सरकार से अनुमोदन मांगा था, राज्य सरकार ने आधुनिक को खनन पट्टा देने के विभिन्न कारण दिए।

6.5. आधुनिक का दावा है कि इसके 790 करोड़ रुपये के एकीकृत स्टील प्लांट के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यह संयंत्र लौह अयस्क की कमी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

#### **सिविल अपील संख्या 3287 वर्ष 2009, अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**

7. अपीलकर्ता कंपनी, एम/एस अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे अभिजीत कहा जाता है, पहले अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। अभिजीत पिछले कई वर्षों से लौह और स्टील के व्यवसाय में है। 21 नवंबर 2003 को, अभिजीत ने अपने प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट और फेरो-एलॉय प्लांट के लिए घटकुरी मौजा में लौह अयस्क और मैंगनीज हेतु 1633.03 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया।

7.1. 5 अगस्त 2004 को, राज्य सरकार ने अभिजीत को कैप्टिव खपत हेतु लौह अयस्क का खनन पट्टा देने का निर्णय लिया जो घटकुरी मौजा में किसी अन्य आवेदक के क्षेत्र से ओवरलैप नहीं करता था।

7.2. अभिजीत ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से 26 फरवरी 2004 को किए गए एमओयू की ठोस और निश्चित प्रतिबद्धता के आधार पर उसने आवश्यक कदम उठाए हैं जिसमें गांव कुड़, रेवाली और दामोदीह में भूमि अधिग्रहण के कदम शामिल हैं।

#### **सिविल अपील संख्या 3288 वर्ष 2009, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**

8. अपीलकर्ता इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे इस्पात कहा जाता है, कंपनियों के अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। इस्पात का कहना है कि यह निजी क्षेत्र में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है और इसके पास विशाल संसाधन और तकनीकी अनुभव है। इस्पात ने झारखंड राज्य में एक

एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने का इरादा रखा और इसके अनुसार उसने लौह अयस्क हेतु राजाबेड़ा गांव में 725.32 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया।

8.1. राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2004 को लौह अयस्क की कैप्टिव खपत हेतु किसी अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्र से ओवरलैप न करते हुए 470.06 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा देने का निर्णय लिया।

**सिविल अपील संख्या 3289/2009, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**

9. झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, जिसे झारखंड इस्पात कहा जाता है, रामगढ़ जिले में स्थित एक पंजीकृत कंपनी है। झारखंड इस्पात रामगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील प्लांट चलाती है।

9.1. झारखंड इस्पात ने घटकुरी मौजा में लौह अयस्क खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को आवेदन दिया।

9.2. 4 अगस्त 2004 को, राज्य सरकार ने झारखंड इस्पात के पक्ष में खनन पट्टा देने हेतु निर्णय एवं प्रस्ताव तैयार किया और इसे भारत सरकार के खान मंत्रालय को अग्रेषित किया।

**सिविल अपील संख्या 3290 वर्ष 2009, प्रकाश इस्पात लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**

10. अपीलकर्ता प्रकाश इस्पात लिमिटेड, जिसे प्रकाश के नाम से संदर्भित किया गया है, कंपनियों के अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। प्रकाश स्टील का व्यवसाय करती है और इसका वार्षिक कारोबार 2200 करोड़ रुपये होने का दावा करती है। प्रकाश ने 20 जनवरी 2004 को झारखंड में घटकुरी मौजा में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क की खनन पट्टा के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया, जिसका उपयोग उसके प्रस्तावित स्टील प्लांट अमादिया गांव, पश्चिम सिंहभूम जिले में कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा।

11. 26 मार्च 2004 को, राज्य सरकार ने प्रकाश के साथ मिनी ब्लास्ट फर्नेस आदि स्थापित करने के लिए 71.40 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 4 अगस्त 2004 को, राज्य सरकार ने प्रकाश को कैप्टिव खपत हेतु लौह अयस्क के लिए 294.06 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा देने का निर्णय लिया और केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन की सिफारिश की।

12. यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच विभिन्न बैठकों से संबंधित तथ्य; दोनों के बीच आदान-प्रदान की गई संचार, जिसमें राज्य सरकार का 13 सितंबर 2005 का संचार; जिला खनन अधिकारी, चाईबासा का 17 नवंबर 2004 का संचार झारखंड राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग को और प्रस्ताव की अस्वीकृति को अपीलकर्ताओं - आधुनिक,

अभिजीत, इस्पात, झारखंड इस्पात और प्रकाश के तथ्य का उल्लेख करते समय दोहराया नहीं गया है क्योंकि ये तथ्य पहले ही मोनेट मामले में नोट किए जा चुके हैं।

## मुख्य मुद्दा

13. विचार करने के लिए सबसे पहला बिंदु यह है कि क्या बिहार राज्य द्वारा जारी किए गए 21 दिसंबर 1962 (जिसे 1962 अधिसूचना कहा जाएगा) और 28 फरवरी 1969 (जिसे 1969 अधिसूचना कहा जाएगा) अधिसूचनाएँ तथा झारखंड राज्य द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2006 (जिसे 2006 अधिसूचना कहा जाएगा) कानूनी और वैध हैं। यह एक थोड़ा जटिल बिंदु है, क्योंकि इसमें 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से रास्ता निकालना शामिल है। मैं उन्हें उन बिंदुओं तक प्रस्तुत करूंगा जो प्रासंगिक हैं।

14. श्री रंजीत कुमार, मोनेट के लिए वरिष्ठ वकील, ने शुरू में यह तर्क उठाया कि 1962 और 1969 अधिसूचनाएँ कभी भी आधिकारिक गजट में प्रकाशित नहीं हुईं लेकिन झारखंड राज्य के वरिष्ठ वकील द्वारा इन अधिसूचनाओं की गजट प्रतियों को प्रस्तुत करने पर, इन अधिसूचनाओं की गैर-प्रकाशन के संबंध में तर्क आगे नहीं बढ़ाया गया।

## 1962 अधिसूचना

15. पूर्व बिहार राज्य द्वारा जारी की गई 1962 अधिसूचना इस प्रकार है:

### अधिसूचना

21 दिसंबर, 1962

संख्या ए/एमएम-40510/62-6209/एम - यह सार्वजनिक सूचना के लिए सूचित किया जाता है कि इस राज्य में निम्नलिखित लौह अयस्कधारी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण हेतु आरक्षित किया गया है:"

जिले का नाम -

सिंहभूम

आरक्षित क्षेत्रों का विवरण।

1. संसंगदा मुख्य ब्लॉक -

### सीमा

दक्षिण - दक्षिणी सीमा उत्तरी सीमा के समान है। यह बिहार-उड़ीसा सीमा से शुरू होती है, जो मेघनहातु नाला की दक्षिणी सहायक नदी के घाट के सामने है और घाट के साथ पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर चलती है जब तक कि यह पहाड़ी के तल तक नहीं पहुँचती।

पूर्व - बिहार और उड़ीसा राज्यों के बीच की सीमा।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व- बिहार-उड़ीसा सीमा से 2680 तक एक बिंदु 2-3/4 मील उत्तर-पूर्व की ओर, जो ससंगदा मुख्य ब्लॉक की दक्षिणी सीमा से मिलती है।

उत्तर: उत्तरी सीमा ससंगदा मुख्य ब्लॉक की दक्षिणी सीमा के समान है और 2935 के ठीक उत्तर में एक मील से अधिक घाट का अनुसरण करती है।

#### 5.डिरिशुम्बुरु ब्लॉक -

##### सीमा

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम- किरीबुरु कोलाइबुरु गांव (22 11'30": 85 14') के लगभग 5 फर्लांग पूर्व-उत्तर-पूर्व में चुरु लकीर नाला से शुरू होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में एक मील तक जाती है।

दक्षिण-पूर्व- ऊपर दिए गए अंत से उत्तर-पूर्व की ओर 2-1/2 मील तक, बहाड़ा गांव (22 11'30": 85 17'30") के उत्तर-पश्चिम में एक बिंदु तक पहुँचने के लिए।

उत्तर-पूर्व- ऊपर दिए गए अंत से उत्तर-पश्चिम की ओर घाट तक पहुँचने के लिए 20 13': 85 18" पर।

उत्तर-पश्चिम- ऊपर दिए गए स्थान से दक्षिण-पश्चिम की ओर डिरिशुम्बुरु पहाड़ी और आस-पास की हाकतलताबुरु के तल के साथ चलते हुए चुरु लकीर नाले के प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचने के लिए, जो कोलाइबुरु गांव के पूर्व-उत्तर-पूर्व में है।

#### 6.बानालता ब्लॉक -

##### सीमा

- दक्षिण-पूर्व: बानालता पहाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर 2.20 फीट की कर्व रेखा से गुजरते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व दिशा में चलती है - 2187 से 2-1/2 फर्लांग पूर्व की ओर उत्तर-पूर्व दिशा में 1/2 मील तक पहुँचती है, पेचहलू गांव (22 16': 85 20') के उत्तर-पश्चिम में और यहाँ से उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में 3 फर्लांग पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में 2567 पैसिरा बुरु तक जाती है।
- उत्तर: ऊपर दिए गए स्थान से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में पहाड़ी को पार करते हुए पांच फर्लांग तक पहुँचती है ताकि पहाड़ी की उत्तर-पश्चिम ढलान पर पहुँच सके।
- पश्चिम: ऊपर दिए गए स्थान से सामान्य रूप से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा में पहाड़ी की ढलान के साथ चलते हुए, तीन फर्लांग उत्तर-पश्चिम दिशा में 2187 पर दक्षिण-पश्चिम सीमा तक पहुँचती है।

बिहार के गवर्नर द्वारा आदेशित

ह/० (बी.एन. सिन्हा)

सरकार के सचिव

### 1969 अधिसूचना

16.फिर, 28 फरवरी 1969 को निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गई:

"बिहार सरकार

खनिज एवं भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

पटना, 28 फरवरी 1969

फाल्गुन, 1890 - एस

संख्या बी/एम 6-1019/68-1564/एम

यह सार्वजनिक सूचना के लिए सूचित किया जाता है कि सिंहभूम जिले के घटकुरी आरक्षित वन ब्लॉक संख्या 10 में स्थित 416 एकड़ (168.349 हेक्टेयर) लौह अयस्कधारी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण के लिए आरक्षित किया गया है। इस संबंध में पूर्ण विवरण के लिए जिला खनन अधिकारी, चाईबासा से संपर्क किया जाना चाहिए।

बिहार के राज्यपाल द्वारा आदेशित

ह/० (सी.पी. सिंह)

उप सचिव, सरकार" 2006 अधिसूचना

17. झारखंड राज्य ने 27 अक्टूबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की, जो इस प्रकार है:

खनिज एवं भूविज्ञान विभाग, रांची

### **अधिसूचना**

27 अक्टूबर 2006

संख्या 3277 - यह सामान्य जनता के लिए सूचित किया जाता है कि राज्य में खनिज संसाधनों का अनुकूल उपयोग और शोषण तथा उस पर मूल्य संवर्धन के लिए खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि घटकुरी में लौह अयस्क के भंडार को निजी पक्षों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टा या अन्यथा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भंडार सभी महत्वपूर्ण समय पर बिहार राज्य की गजट अधिसूचना संख्या ए/एम एम-40510/62-6209/एम दिनांक 21 दिसंबर 1962 और संख्या बी/एम -6-1019/68-1564/एम दिनांक 28 फरवरी 1969 के तहत आरक्षित रखा गया था। उक्त क्षेत्र में आरक्षित खनिज अब सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम या राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम परियोजना द्वारा शोषण के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य को अधिकतम लाभ प्रदान करेगा और राज्य में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न करेगा।

उपरोक्त अधिसूचना जनहित में और राज्य के व्यापक हित में जारी की जा रही है।

आरक्षित क्षेत्र की परिभाषित समन्वय बिंदुओं को संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है।

बिहार के गवर्नर द्वारा आदेशित

एस.के. सतापथी

सरकार के सचिव

घटकुरी में आरक्षित क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है:-

जिला: सिंहभूम

मुख्य ब्लॉक: घटकुरी

घटकुरी के आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं, जो 21 दिसंबर 1962 और 28 फरवरी 1969 को बिहार गजट में प्रकाशित की गई हैं, नीचे दी गई हैं:

Xxx

xxx

xxx

ह/० विजॉय कुमार

प्रभारी निर्देशक (भूविज्ञान निदेशालय)

## विवाद

18.अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1962, 1969 और 2006 अधिसूचनाओं को चुनौती देते समय विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। श्री रंजीत कुमार, मोनेट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, मोनेट से संबंधित तथ्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मैं न्यायालय के निर्णय के बाद के भाग में श्री रंजीत कुमार द्वारा उजागर किए गए तथ्यों का उल्लेख करूंगा। 1962, 1969 और 2006 अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देते हुए, उन्होंने 1957 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि आरक्षण एक नियामक व्यवस्था का हिस्सा था। उनके अनुसार, 'खनन का नियमन' का अर्थ है वह नियामक व्यवस्था जिसे केंद्रीय सरकार ने अपने अधीन ले लिया है और इसमें 'आरक्षण' शामिल होगा। वे यह भी कहेंगे कि खनन से संबंधित मामलों में स्वामित्व का अधिकार अंतर्निहित अधिकार के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

19.श्री सी.ए. सुंदरम, इस्पात के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि 2006 की अधिसूचना कानून में खराब थी क्योंकि (1) 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ वैध नहीं थीं और इसलिए 2006 की अधिसूचना को मान्यता देने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता; (2) 2006 की अधिसूचना ने सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों या संयुक्त उद्यमों द्वारा शोषण के लिए क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रयास किया, जबकि 1957 अधिनियम की धारा 17ए केवल राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों और गैर-संयुक्त उद्यमों के लिए क्षेत्र आरक्षित करने की अनुमति देती है; धारा 17ए निजी भागीदारी की

कल्पना नहीं करती है; और (3) 1957 अधिनियम की धारा 17ए के तहत, राज्य द्वारा किसी भी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए आरक्षित करने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी और ऐसी कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी।

20. श्री सी.ए. सुंदरम यह भी कहेंगे कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ अमान्य थीं क्योंकि 1957 अधिनियम की धारा 18 खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास का अधिकार केंद्रीय सरकार को देती है; भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के संबंध में कानून बनाने पर राज्य सरकार पर वैधानिक प्रतिबंध था। 1962 और 1969 में लागू नियम 59 ने ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया जहाँ आरक्षण केवल अस्थायी उद्देश्य या आपातकालीन स्थिति के लिए किया जा सकता था और यह राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए क्षेत्र आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का अधिकार पहली बार 1980 में 1960 नियमों के नियम 58 में संशोधन द्वारा पेश किया गया था और इसलिए इससे पहले राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने का कोई अधिकार नहीं था। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने कहा कि यदि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ उस समय कानून के उचित प्राधिकरण के साथ वैध रूप से जारी मानी जाएं, तो तथ्य यह है कि नियम 58 को बिना किसी बचत खंड के 1988 में हटाया गया था, जिसका अर्थ यह था कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ अब वैध नहीं थीं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क किया कि वर्तमान आरक्षण का अधिकार जो 1957 अधिनियम की धारा 17ए में निहित है, पूर्ववर्ती नियमों 58/59 के अनुरूप है क्योंकि धारा 17ए स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित करने हेतु कोई अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

21. इस न्यायालय के निर्णयों में *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य* क ; *उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम मिस एम.ए. टुल्लोक एवं कंपनी* ख; *बैजनाथ कडियो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* ग; *अमृतलाल नाथुभाई शाह एवं अन्य बनाम भारत संघ सरकार एवं अन्य* घ ; *इंडिया सीमेंट लिमिटेड एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य* ङ ; *उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य* च; तथा *माया मैथ्यू बनाम केरला राज्य एवं अन्य* छ शामिल हैं। श्री सी.ए. सुंदरम ने अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले को भिन्नता देने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी मामले में अमृतलाल नाथुभाई शाह एक अच्छा कानून नहीं था।

क. एआईआर 1961 एससी 459 ख. एआईआर 1964 एससी 1284 ग. 1969 (3) धारा 838 घ. 1976 (4) धारा 108 ङ. 1990 (1) धारा 12.

च. 1991 अनुपूरक (1) धारा 430 छ. 2010 (4) धारा 498

22. श्री एल. नागेश्वर राव और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आधुनिक के लिए उपस्थित हुए और तर्क किया कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ कानून का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय सरकार की 1957 अधिनियम के तहत वैधानिक पूर्व स्वीकृति के बिना जारी की गई थीं। 2006 की अधिसूचना केवल 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं में निहित बातों का पुनरावृत्ति थी। 2006 की अधिसूचना कानून में खराब है और 1957 अधिनियम की धारा 17ए के तहत अवैध है। यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने कभी भी 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं को अपनाया नहीं और इसलिए, ये अधिसूचनाएँ समाप्त हो गईं, भले ही इन्हें कानून के उचित प्राधिकरण के साथ पारित किया गया हो। इस संबंध में, प्रतीक सरकार, *एम.बी. सुरेश और जितेंद्र लक्ष्मण थोरवे बनाम झारखंड राज्य* छ में निर्णय पर भरोसा किया गया।

23. श्री जी.सी. भारुका, अभिजीत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 1963 तक, राज्य सरकार के पास किसी भी खनिजधारक भूमि को किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों शामिल हैं, को संभावित लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए आरक्षित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि 1957 अधिनियम की धारा 2 के तहत घोषणा पर, राज्य विधानमंडल को खनिजों और खानों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था और परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के पास खनिजों और खानों के संबंध में कोई कार्यकारी अधिकार नहीं रह गया था, हालांकि यह भूमि और खनिजों का मालिक बना रहा। इस संबंध में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया *एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी ख ; बैजनाथ कडियो ग और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* झ में। श्री भारुका ने इस न्यायालय के अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले का भी भेदभाव किया और प्रस्तुत किया कि हालांकि राज्य सरकार को आरक्षण के लिए अधिकार देने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन उस मामले में न्यायालय ने नियम 59 से ऐसा अधिकार निकाला था। नियम 59, जैसा कि 1960 में मूल रूप से तैयार किया गया था, केवल "खनिजों के लिए संभावित या खनन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य" के लिए आरक्षण की अनुमति देता था। 1963 की अधिसूचना के अनुसार, "खनिजों के लिए संभावित या खनन के अलावा" शब्दों को हटा दिया गया, और इसलिए, 21 दिसंबर 1962 को जब बिहार राज्य द्वारा विवादित भूमि को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा शोषण के लिए आरक्षित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई, तो उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले ने 1963 में नियम 59 में संशोधन के बाद की स्थिति पर विचार किया और पूर्व संशोधन पर नहीं।

24. वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि "जनता क्षेत्र द्वारा शोषण के लिए खनिजधारक क्षेत्रों का आरक्षण" 1957 अधिनियम की धारा 2 के तहत संसद द्वारा किए गए घोषणा के अंतर्गत आता है, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1, प्रविष्टि 54 के संदर्भ में है। "आरक्षण" से संबंधित विषय "खनन पट्टा देने के नियमन" के क्षेत्र में आता है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति को खनन पट्टा देने या न देने का अधिकार शामिल होता है। "आरक्षण" "खनन पट्टा देने के नियमन" के दायरे में आएगा, जिसके लिए केंद्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय सरकार, संसद के प्रतिनिधि के रूप में, "खनन पट्टा देने के नियमन" के संबंध में नियम बना सकती है। *बैजनाथ कडियो* ग और *भारत कोकिंग कोल* झ पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि चाहे नियम बनाए जाएं या नहीं, यह विषय संसदीय कानून द्वारा कवर किया गया है और इस हद तक राज्य विधानमंडल का अधिकार समाप्त हो गया है। नियम 58 के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि 1980 में 1960 नियमों में लाए गए संशोधन द्वारा, राज्य सरकारों को सरकार या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनियों के लिए क्षेत्रों को शोषण हेतु आरक्षित करने की क्षमता प्राप्त हुई। केंद्रीय सरकार उपरोक्त नियम को 1957 अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने नियम बनाने के अधिकार के अंतर्गत बना सकती थी केवल इसलिए कि आरक्षण का विषय 1957 अधिनियम की धारा 2 के तहत किए गए घोषणा में शामिल था और "यहां बाद में प्रदान की गई सीमा तक" के दायरे में था।

25. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई 27 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना की वैधता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि 2006 की अधिसूचना "संयुक्त उद्यम" के लिए क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रयास करती है लेकिन यह 1957 अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमति नहीं है। धारा 17ए (2) अनिवार्य करती है कि क्षेत्र को "केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से" आरक्षित किया जाना चाहिए और 2006 की अधिसूचना को कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, 2006 की अधिसूचना अपने शब्दों से केवल एक सूचनात्मक अधिसूचना है जिसका कोई कानूनी महत्व या परिणाम नहीं है।

26. डॉ. राजीव धवन, झारखंड इस्पात के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1962 की अधिसूचना पूरी तरह से अवैध और अमान्य थी क्योंकि यह 1960 नियमों के नियम 59 के खिलाफ थी, जो उस समय खनिजों के लिए संभावित या खनन करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षण की अनुमति देती थी। इस संबंध में, उन्होंने *जनक लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* जे मामले का हवाला दिया।

27. वरिष्ठ अधिवक्ता ने 10 फरवरी 1987 से प्रभावी 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 17ए (3) जो 1987 में लाई गई थी, राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान करती थी। 13 अप्रैल 1988 से, 1960 नियमों के नियम 59(2) के तहत, केंद्रीय सरकार किसी विशेष मामले में उप-नियम (1) के प्रावधानों को शिथिल कर सकती थी। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, 1969 की अधिसूचना के तहत आरक्षण तकनीकी रूप से उचित था क्योंकि नियम 59 को 1963 में 'कोई खनन प्रतिबंध नहीं' हटाकर संशोधित किया गया था लेकिन 1980 और विशेष रूप से 1988 के बाद आरक्षण केवल एक नए वैधानिक शासन के तहत ही किया जा सकता था।

28. डॉ. राजीव धवन ने अपने तर्क को संघवाद के सिद्धांत पर आधारित किया और प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य के पास 1957 अधिनियम के तहत क्षेत्र को आरक्षित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि 1957 अधिनियम पूरी तरह से खनिजों और खानों के विषय पर कब्जा करता है और यह राज्य की विधायी और समकक्ष कार्यकारी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया: *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी क, बैजनाथ कडियाल ग, असम राज्य और अन्य बनाम ओम प्रकाश मेहता और अन्य के, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य एल, और संदूर मेंगनीज एंड आयरन ओर्से लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य एम।*

29. डॉ. राजीव धवन ने कहा कि केवल इसलिए कि राज्य भूमि का मालिक है जिसमें खनियाँ शामिल हैं, यह उसे 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के तहत खनन या आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा कि *अमृतलाल नथुभाई शाह घ* का मामला केवल अपनी विशिष्ट तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। *अमृतलाल नथुभाई शाह घ* में निर्णय इस विशेष निष्कर्ष पर आधारित था कि राज्य की कार्रवाई नियम 59 के अनुरूप थी; यह भूमि पर राज्य की शक्ति और संघ द्वारा खानों और खनिजों के क्षेत्र पर नियंत्रण के बीच संघर्ष की प्रस्तावना का परीक्षण नहीं करता। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि *अमृतलाल नथुभाई शाह घ* का निर्णय इस न्यायालय के पूर्व संविधान पीठ के निर्णयों पर ध्यान नहीं देता। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस न्यायालय का निर्णय केसोराम का कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह निर्णय राज्य की कर लगाने की शक्ति से संबंधित है।

के. ई. 1973 सी1 एल सेक 584.

एल. 2004 (10) सेक 201.

एम. 2010 (13) सेक 1

30. श्री ध्रुव मेहता, प्रकाश के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 16 नवंबर, 1980 से पहले राज्य सरकारों के पास किसी भी क्षेत्र को सरकार या केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या सरकारी कंपनी द्वारा शोषण के लिए आरक्षित करने की शक्ति नहीं थी। यह केवल 16 नवंबर, 1980 को नियम 58 में संशोधन के द्वारा था कि पहली बार राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को सरकार या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित निगम के लिए शोषण के लिए आरक्षित करने की शक्ति दी गई। उसके अनुसार, वर्तमान संदर्भ में विचार करने के लिए प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या 1980 से पहले राज्य के पास 'खनन पर प्रतिबंध लगाने' या 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए खनन आरक्षित करने' की शक्ति थी। इस संबंध में, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया: *बैजनाथ कडियाल ग, डी.के. त्रिवेदी और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य एन, तमिलनाडु राज्य बनाम मिस. हिंद स्टोन और अन्य ओ, और भारतीय धातु और फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य पी*। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त के मददेनजर, 1962 अधिसूचना जो बिहार राज्य में लौह अयस्क क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण के लिए आरक्षित करती है, स्पष्ट रूप से राज्य की शक्ति से परे थी। उन्होंने कहा कि राज्य के पास खनन के लिए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी, जैसा कि संसद द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 2 के तहत घोषित किया गया था, और किसी भी मामले में 1960 नियमों का नियम 59, जैसा कि मूल रूप से था, विशेष रूप से 9 जून, 1963 से पहले खनिजों की अन्वेषण या खनन के संबंध में आरक्षण को बाहर करता था।

31. 2006 अधिसूचना के संबंध में, श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिसूचना पहले, एक नई आरक्षण प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि यह पहले से 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किए गए आरक्षण का संदर्भ देती है। दूसरी बात, यदि यह मान लिया जाए कि 2006 अधिसूचना 1957 अधिनियम की धारा 17 ए(2) के तहत आरक्षण के लिए एक नई आदेश है, तो भी उक्त अधिसूचना विभिन्न दोषों से ग्रस्त है, अर्थात् (क) केंद्रीय सरकार द्वारा कोई स्वीकृति नहीं है और (ख) यह एक अधीनस्थ कानून बनाने की प्रक्रिया होने के नाते इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता ने *हुकम चंद आदि बनाम भारत संघ और अन्य* क्यू पर निर्भरता जताई।

एन. 1986 (सप्ल.) एससीसी 20.

ओ. 1981 (2) धारा 20एस.

पी. 1992 सप्ल (1) धारा 91.

क्यू. 1972 (2) धारा 601.

## केंद्र सरकार की स्थिति

32. श्री अशोक भान, भारत संघ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने संघ सूची के प्रविष्टि 54, राज्य सूची के प्रविष्टि 23, संविधान के अनुच्छेद 246, 1957 अधिनियम के विभिन्न धाराओं और 1960 नियमों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि केंद्रीय सरकार ने 1957 अधिनियम को लागू करके 'खनिज - नियमन और विकास' से संबंधित विधायी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और केंद्रीय सरकार ही एकमात्र नियामक है। श्री अशोक भान ने प्रस्तुत किया कि कानून की योजना के तहत, राज्य सरकार को 1957 अधिनियम से उत्पन्न शक्तियों के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं दी गई थी। खानों के नियमन और खनिजों के विकास के मामलों में, श्री अशोक भान के अनुसार, सार्वजनिक हित सर्वोपरि है।

## राज्य सरकार की ओर से उत्तर

33. श्री अजीत कुमार सिन्हा, झारखंड राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तर में, अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को भूमि और उसमें निहित खनिजों के मालिक के रूप में किसी भी क्षेत्र को शोषण के लिए आरक्षित करने की अंतर्निहित शक्ति है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिहार विधानमंडल ने 1950 का बिहार अधिनियम पारित किया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 25 सितंबर, 1950 को लागू हुआ। इसके धारा 4(क) ने सभी पूर्व-निर्धारित संपत्तियों या अधिकारों को जिसमें खानों और खनिजों के अधिकार शामिल हैं, राज्य में पूरी तरह से निहित किया। 1950 का बिहार अधिनियम इस न्यायालय के निर्णय में संविधानिक रूप से वैध माना गया है: *बिहार राज्य बनाम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह, दरभंगा और अन्य* आर । किसी भी स्थिति में, श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1950 का बिहार अधिनियम संविधान की नवम अनुसूची में रखा गया है और इसलिए यह चुनौती से परे है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत राज्य सरकार की संप्रभु कार्यकारी शक्ति किसी भी व्यापार या व्यवसाय को संचालित करने और किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति को अधिग्रहित करने, धारण करने और निपटाने में शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में अपने खनिजों के शोषण के लिए भूमि आरक्षित करने की शक्ति भी शामिल है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भारी निर्भरता जताई: *अमृतलाल नथुभाई शाह घ, भारतीय धातु और फेरो अलॉयज लिमिटेड* पी और *भूपानाई मगनलाल जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* एस ।

आर. 1952 एससीआर 889.

एस. 2001 सी10) सेक 476

34. श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1962, 1969 और 2006 की अधिसूचनाओं के जारी करने के लिए शक्ति का स्रोत स्पष्ट रूप से संबंधित वैधानिक प्रावधानों में पाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ, जो तब के बिहार राज्य द्वारा जारी की गई थीं, 1960 के नियमों के नियम 59 से संबंधित थीं जैसा कि तब था, और उसके बाद 9 जुलाई, 1963 को उस नियम में संशोधन किया गया, जबकि 2006 की अधिसूचना 1957 अधिनियम की धारा 17 ए(2) से संबंधित है जिसे 13 अप्रैल, 1988 से प्रभावी रूप से नियम 59(1)(इ) के साथ पढ़ा गया।

35. श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी राज्य द्वारा किसी भी कब्जे वाले क्षेत्र पर कोई संघर्ष या अतिक्रमण नहीं था। राज्य को न तो वंचित किया गया है और न ही 1957 अधिनियम या 1960 नियमों द्वारा इसे प्रतिबंधित या निषिद्ध किया गया है। इसके बजाय, 1960 नियमों के नियम 59 के तहत आरक्षण की अनियंत्रित शक्ति केवल राज्य के पास थी जो 1962 से 1987 तक थी और उसके बाद धारा 17 ए(2) के तहत। उनके अनुसार, 1987 के बाद राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार दोनों के पास आरक्षण की समवर्ती शक्ति है जैसा कि 1957 अधिनियम की धारा 17 ए और 1960 नियमों के नियम 59(1)(इ) में प्रदान किया गया है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया: *लॉर्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स बनाम इसके श्रमिक टी, जीवन बीमा निगम भारत बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य यू, पुणे नगर निगम और अन्य बनाम भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड और अन्य वी*, तथा *राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम पी.पी. सिंह और अन्य डब्ल्यू*।

36. श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1957 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया, विशेष रूप से धाराएँ 2, 4(3), 4ए, 10(1), 13(2)(इ), 16(1)(बी), 17(1), 17ए (1)(ए), 18ए (6), 21(5), 28 और 30 को यह दिखाने के लिए कि संसद ने स्वयं राज्य विधानसभाओं के लिए खनिज जमा वाले भूमि को राज्य सरकार को सौंपने के लिए विधायी प्रावधानों की कल्पना की थी और संसद ने सूची II के प्रविष्टि 18 के तहत राज्य विधानसभाओं की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखा। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया: *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चंदन माल और अन्य एक्स, ईश्वरि खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाई*, और *केसोरामा*।

टी. एआईआर 1961 एससी 860.

यू. 1986 (1) धारा 264.

वी. 1995 (3) धारा 434.

डब्ल्यू. 2003 (4) धारा 239

एक्स 1977 (1) धारा 340., वाई. आरएनएओ (4) सेकंड 136

उन्होंने प्रविष्टि 54 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'जिस सीमा तक ऐसे नियमन और विकास का नियंत्रण संघ के अधीन है, जिसे संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित किया गया है' और 1957 अधिनियम की धारा 2 में 'जिस सीमा तक आगे प्रदान किया गया है' की अभिव्यक्ति पर भारी निर्भरता जताई और प्रस्तुत किया कि इसका तात्पर्य यह है कि केवल तभी जब 1957 अधिनियम और/या इसके तहत बनाए गए नियमों में संसद द्वारा घोषित कानून में कोई प्रतिबंध या निषेध हो, और यदि राज्य उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है जो कवर/कब्जा किया गया है, तो उस सीमा तक राज्य की कार्यवाही या कार्य अवैध (अल्ट्रा वायर्स) होगी। इस प्रकार, श्री अजीत कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि राज्य विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्ति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की क्षमता अप्रभावित रहती है यदि वह क्षेत्र न तो कब्जा किया गया हो, न ही प्रकट किया गया हो और न ही निषिद्ध हो। इस संदर्भ में, उन्होंने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया, जैसे: *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक एंड को., बैजनाथ कडियाल, इंडिया सीमेंट लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल, उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड और केसोराम*

37. विद्वेष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि केंद्रीय सरकार ने आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों की जांच के बाद 1962 और 1969 के अधिसूचनाओं के तहत बिहार राज्य द्वारा किए गए आरक्षण के आधार पर प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन अधिसूचनाओं को केंद्रीय सरकार से पश्चात अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस संबंध में, विद्वेष वरिष्ठ अधिवक्ता ने *मिस मोटिलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य जेड , अमृत बनस्पति लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य पंजाब और अन्य एए , राज्य पंजाब बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य बीबी , एम.पी. माथुर और अन्य बनाम ओटीसी और अन्य सीसी तथा संद्र मंगनीज और आयरन ओर्स लिमिटेड एम* का उल्लेख किया।

38. श्री अजीत कुमार सिन्हा, विद्वेष वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएं जो उस समय के बिहार राज्य द्वारा जारी की गई थीं, राज्य सरकार द्वारा 2006 की अधिसूचना के माध्यम से पुनः पुष्टि की गई हैं। उन्होंने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 का उल्लेख किया जो प्रदान करता है कि उचित सरकार दो वर्षों की समाप्ति से पहले कानून को अनुकूलित और/या संशोधित कर सकती है और ऐसा प्रत्येक कानून अनुकूलन और संशोधनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा बदला, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 को धारा 84 और 86 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि मौजूदा कानून तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे बदला, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता।

जेड. 1979 (2) धारा 409.

एए. 1992 (2) धारा 411.

बीबी. 2004 (6) धारा 465.

सीसी. 2006 (13) धारा 106

## हस्तक्षेपकर्ताओं का दृष्टिकोण

39. श्री विकास सिंह, श्री कृष्णन वेणुगोपाल और श्री पी.एस. नरसिम्हा, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता, हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए। झारखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को अपनाते हुए, श्री विकास सिंह ने कहा कि खनिजों का आरक्षण राज्य का अंतर्निहित अधिकार है। श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने इस न्यायालय के निर्णय *अमृतलाल नाथुभाई शाह* पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय बाध्यकारी था और अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया 'लापरवाही वाला' नहीं था। उन्होंने कहा कि 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में कई प्रावधान यह स्वीकार करते हैं कि सभी खनिज राज्य में निहित हैं और आरक्षण का अधिकार 1960 नियमों के नियम 59 द्वारा कल्पित है।

40. इस अपील समूह की पूरी सुनवाई के बाद और अपीलों को निर्णय के लिए सुरक्षित रखे जाने पर, एक विशेष अनुमति याचिका, जियो-खनिज और मार्केटिंग (पी) लिमिटेड बनाम राज्य उड़ीसा एवं अन्य, जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई थी, अंतिम निपटान के लिए आई, जिसमें एक मुद्दा था कि उड़ीसा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए खनन क्षेत्र का आरक्षण शामिल था। हमने यह उचित समझा कि उस मामले में उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता भी सुने जाएं ताकि हम उनके दृष्टिकोण का लाभ उठा सकें। इसके अनुसार, हमने सामान्य कानूनी पहलू पर मिस. हरिश साल्वे, के.के. वेणुगोपाल और आर.के. द्विवेदी, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना।

41. मैं इस निर्णय को सूची 1 की प्रविष्टि 54, सूची II की प्रविष्टि 23 और 1957 अधिनियम तथा 1960 नियमों में शामिल प्रासंगिक प्रावधानों के पाठ से बोझिल नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ प्रावधानों का पुनरुत्पादन इस बिंदु पर विचार करने के लिए आवश्यक है ताकि इसे उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके।

### प्रासंगिक प्रविष्टियाँ

42. सूची 1 की प्रविष्टि 54 इस प्रकार है:

"54. खनिजों और खानों के विकास का नियमन उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा नियमन और विकास संघ के नियंत्रण में संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में आवश्यक घोषित किया गया हो।"

43. सूची II की प्रविष्टि 23 इस प्रकार है:

"23. संघ के नियंत्रण में नियमन और विकास के संबंध में सूची 1 के प्रावधानों के अधीन खनिजों और खानों का नियमन।"

### खनिज और खनन (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948

44. खनिज और खनन (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में '1948 अधिनियम') को खानों और तेल क्षेत्रों के नियमन तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रविष्टि 36 के तहत खनिजों के विकास के लिए लागू किया गया था। इसे 8 सितंबर 1948 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति

मिली और यह उसी दिन से प्रभावी हुआ। 1948 अधिनियम के तहत, केंद्रीय सरकार ने खनिज अनुदान नियम बनाए।

45. 1948 अधिनियम को 1957 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। 1957 अधिनियम का परिचय इस प्रकार है:

"संविधान की सप्तम अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 54 खानों और खनिजों के विकास का नियमन प्रदान करती है उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा नियमन और विकास संघ के नियंत्रण में संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में आवश्यक घोषित किया गया हो। इस प्रावधान के कारण एक अलग विधायी आवश्यकता बन गई। खानों के नियमन और खनिजों के विकास के लिए, खनिज और खनन (नियमन और विकास) विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया।"

### **खनिज और खनन (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और संशोधन**

46. 1957 अधिनियम 1 जून 1958 को प्रभावी हुआ। इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

47. 1957 अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

"धारा 2. संघ नियंत्रण की आवश्यकताओं की घोषणा - यह घोषित किया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ को खानों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में लेना चाहिए जिस सीमा तक आगे प्रदान किया गया है।"

48. धारा 3(क), (ग), (घ), (छ), (च), (छ) और (ज) में 'खनिज', 'खनन पट्टा', 'खनन संचालन', 'सूक्ष्म खनिज', 'निर्धारित', 'खोज लाइसेंस' और 'खोज संचालन' को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

"3(क) "खनिज" सभी खनिजों को शामिल करता है सिवाय खनिज तेलों के;

(ग) "खनन पट्टा" का अर्थ है एक पट्टा जो खनन संचालन करने के उद्देश्य से दिया जाता है, और इसमें ऐसे उद्देश्य के लिए दिया गया उप-पट्टा भी शामिल है;

(घ) "खनन संचालन" का अर्थ है किसी भी खनिज को जीतने हेतु किए गए किसी भी संचालन;

(छ) "सूक्ष्म खनिज" का अर्थ है निर्माण पत्थर, बजरी, सामान्य मिट्टी, सामान्य रेत जो निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं होती हैं, तथा कोई अन्य खनिज जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म खनिज घोषित कर सकती है;

(च) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(छ) "खोज लाइसेंस" का अर्थ है खोज संचालन करने हेतु दिया गया लाइसेंस;

(ज) "खोज संचालन" का अर्थ है कोई संचालन करना जिसका उद्देश्य खनिज जमा की खोज करना, स्थान निर्धारित करना या प्रमाणित करना है;"

49. 1957 अधिनियम की मूल धारा 4 इस प्रकार थी:

"धारा 4. (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खोज या खनन संचालन नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वह इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए खोज लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार हो:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस उप-धारा में कुछ भी उस क्षेत्र में किए गए किसी भी खोज या खनन संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो इस अधिनियम की शुरुआत से पहले दिए गए खोज लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार हो और जो उस समय प्रभावी हो।

(2) कोई खोज लाइसेंस या खनन पट्टा इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार दिए बिना नहीं दिया जाएगा।"

50.1986, 1987 और 1999 में, 1957 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के बाद, धारा 4 इस प्रकार है:

**"धारा 4.- खोज या खनन संचालन लाइसेंस या पट्टे के तहत होगा.**-(1) डीडी [ कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अन्वेषण, खोज या खनन संचालन नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वह इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार हो]

यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस उप-धारा में कुछ भी उस क्षेत्र में किए गए किसी भी खोज या खनन संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो इस अधिनियम की शुरुआत से पहले दिए गए खोज लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार हो और जो उस समय प्रभावी हो:

इइ [यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस उप-धारा का कुछ भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, एफएफ [परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय], किसी राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय (जिसे चाहे जिस नाम से जाना जाए), और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, जो कंपनियों अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है, द्वारा किए गए किसी भी खोज संचालन पर लागू नहीं होगा:]

डीडी 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 5 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (18-12-1999 से)।

इइ 1986 के अधिनियम सं. 37 की धारा 2 द्वारा (10-2-87 से) अंतःस्थापित।

एफएफ 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 5 द्वारा "परमाणु खनिज प्रभाग" के स्थान पर प्रतिस्थापित (18-12-1999 से)

जीजी [यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस उप-धारा में कुछ भी उस खनन पट्टे पर लागू नहीं होगा (चाहे उसे खनन पट्टा, खनन अनुदान या किसी अन्य नाम से जाना जाए) जो इस अधिनियम की शुरुआत से ठीक पहले गोवा, दमन और दीव के संघ शासित प्रदेश में प्रभावी था।]

एचएच [(1ए ) कोई व्यक्ति किसी भी खनिज को इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार परिवहन या भंडारण नहीं करेगा या परिवहन या भंडारण करने का कारण नहीं बनेगा।]

(2)आईआई [कोई अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा] इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार दिए बिना नहीं दिया जाएगा।

जेजे [(3) कोई राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बाद और धारा 18 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, केके [किसी भी खनिज के संबंध में अन्वेषण, खोज या खनन संचालन कर सकती है जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है] किसी भी क्षेत्र में जो उस राज्य के भीतर है और जो पहले से किसी अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है।"]

51.1957 अधिनियम की धारा 5, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, यह प्रदान करती थी कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई खोज लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं देगी जब तक कि उसमें निर्धारित शर्तें संतुष्ट न हों। यह राज्य सरकार द्वारा खोज लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी।

जीजी. 1987 के अधिनियम 16 की धारा 14 द्वारा (1-10-1963 से प्रभावी) अंतःस्थापित।

एचएच. 1999 के अधिनियम 38 की धारा 5 द्वारा (18-12-1999 से प्रभावी) अंतःस्थापित।

आईआई. 1999 के अधिनियम 38 की धारा 5 द्वारा "खनन पट्टे की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नहीं" के स्थान पर प्रतिस्थापित (18-12-1999 से प्रभावी)।

जेजे. 1986 के अधिनियम 37 की धारा 2 द्वारा (10-12-1987 से प्रभावी) अंतःस्थापित

केके. 1999 के अधिनियम 38 की धारा 5 द्वारा (8-12-1999 से प्रभावी) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

52. 1957 अधिनियम की मूल धारा 5 में 1986, 1994 और 1999 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के बाद, धारा 5 अब यह प्रदान करती है कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं देगी जब तक कि वह आवश्यक शर्तों को पूरा न करे। यह प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि पहले अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में, कोई अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दिया जाएगा।

53. 1957 अधिनियम की धारा 6 उस अधिकतम क्षेत्र का प्रावधान करती है जिसके लिए खोज लाइसेंस या खनन पट्टा दिया जा सकता है। धारा 7 उन अवधि के लिए प्रावधान करती है जिनके लिए खोज लाइसेंस दिया जा सकता है या नवीनीकरण किया जा सकता है, और धारा 8 उन अवधि के लिए प्रावधान करती है जिनके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है या नवीनीकरण किया जा सकता है।

54. 1957 अधिनियम की धारा 10 यह प्रदान करती है कि किसी भी भूमि के लिए जिसमें खनिज सरकार के पास निहित हैं, अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकार को किया जाएगा। इसके अंतर्गत, यह संबंधित राज्य सरकार को इस अधिनियम या 1960 नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुमति, लाइसेंस या पट्टा देने या अस्वीकार करने का अधिकार देती है।

55. 1957 अधिनियम की मूल धारा 11 इस प्रकार थी:

"धारा 11. (1) जहाँ किसी भूमि के संबंध में एक खोज लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसी को उस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में खनन पट्टा प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार होगा:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि लाइसेंसी ने खोज लाइसेंस की शर्तों और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और वह खनन पट्टा दिए जाने के लिए अन्यथा एक योग्य व्यक्ति है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों ने उसी भूमि के संबंध में खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है, वह आवेदक जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, उसे लाइसेंस या पट्टा प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार होगा:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई ऐसे आवेदन उसी दिन प्राप्त होते हैं, तो राज्य सरकार उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के बाद, उन आवेदकों में से किसी एक को जो वह उचित समझे, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा दे सकती है।

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित मामले निम्नलिखित हैं:

(क) आवेदक द्वारा किए गए अन्वेषण संचालन या खनन संचालन में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव;

(ख) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(ग) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित तकनीकी कर्मचारियों की प्रकृति और गुणवत्ता;

(घ) अन्य ऐसे मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) उप-धारा (2) में शामिल किसी भी बात के बावजूद लेकिन उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार किसी विशेष कारणों से जो रिकॉर्ड किए जाएंगे और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एक आवेदक को जो बाद में आवेदन प्राप्त हुआ हो, प्राथमिकता दे सकती है उस आवेदक की तुलना में जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ था।"

56. उपरोक्त प्रावधान को अधिनियम 38 द्वारा 18 दिसंबर 1999 से प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन के बाद, धारा 11 अब इस प्रकार है:

"धारा 11. कुछ व्यक्तियों का प्राथमिक अधिकार.-(1) जहाँ किसी भूमि के संबंध में एक अन्वेषण अनुमति या खोज लाइसेंस दिया गया है, परमिट धारक या लाइसेंसी को उस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में खोज लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार होगा:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि परमिट धारक या लाइसेंसी ने,-

- (क) उस भूमि में खनिज संसाधनों की स्थापना करने हेतु अन्वेषण संचालन या खोज संचालन किया है;
- (ख) अन्वेषण अनुमति या खोज लाइसेंस की शर्तों और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है;
- (ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं हुआ है; और
- (घ) उसने अन्वेषण अनुमति या खोज लाइसेंस की समाप्ति के तीन महीने के भीतर खोजना लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है, जैसा भी मामला हो, या उस सरकार द्वारा विस्तारित किए गए किसी अन्य अवधि के भीतर।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ राज्य सरकार ने अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए आधिकारिक गजट में क्षेत्र की अधिसूचना नहीं दी है, और दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी भूमि के संबंध में अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है, तो वह आवेदक जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, उसे अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक अधिकार होगा, उस आवेदक की तुलना में जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ हो:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई क्षेत्र अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध है, और राज्य सरकार ने ऐसे अनुमति, लाइसेंस या पट्टे के लिए आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा आवेदन आमंत्रित किए हैं, तो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और उन आवेदनों को जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पहले प्राप्त हुए थे और निपटाए नहीं गए थे, उन्हें इस उप-धारा के तहत प्राथमिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से उसी दिन प्राप्त माना जाएगा:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई ऐसे आवेदन उसी दिन प्राप्त होते हैं, तो राज्य सरकार उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के बाद, अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, उन आवेदकों में से किसी एक को दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित मामले निम्नलिखित हैं:

(क) आवेदक द्वारा किए गए अन्वेषण संचालन, खोज संचालन या खनन संचालन में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव;

(ख) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(ग) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित तकनीकी कर्मचारियों की प्रकृति और गुणवत्ता;

(घ) वह निवेश जो आवेदक खानों और खनिजों पर आधारित उद्योग में करने का प्रस्ताव करता है;

(ङ) अन्य ऐसे मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए क्षेत्र की अधिसूचना देती है, सभी आवेदन जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त होते हैं, जो तीस दिनों से कम नहीं होगी, को एक साथ विचार किया जाएगा जैसे कि सभी ऐसे आवेदन उसी दिन प्राप्त हुए हों और राज्य सरकार उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के बाद, अन्वेषण अनुमति, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, उन आवेदकों में से किसी एक को दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(5) उप-धारा (2) में शामिल किसी भी बात के बावजूद लेकिन उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार किसी विशेष कारणों से जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक आवेदक को जो बाद में आवेदन प्राप्त हुआ हो उसे प्राथमिकता दे सकती है उस आवेदक की तुलना में जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ था:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी इससे पहले कि इस उप-धारा के तहत कोई आदेश पारित किया जाए।

57.1957 अधिनियम की धारा 13 केंद्रीय सरकार को खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 13(2)(ङ) के तहत केंद्रीय सरकार को प्रदत्त शक्ति द्वारा 1960 नियम बनाए गए हैं जो खनिजों के संबंध में खनन पट्टों को देने का नियमन करते हैं और इससे संबंधित उद्देश्यों के लिए।

58. धारा 14 यह बताती है कि धारा 5 से 13 (दोनों सहित) की प्रावधानें सूक्ष्म खनिजों के संबंध में पत्थर खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों पर लागू नहीं होंगी। धारा 15 राज्य सरकारों को सूक्ष्म खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है।

59. धारा 16 उन खनन पट्टों को संशोधित करने का प्रावधान करती है जो 25 अक्टूबर 1949 से पहले दिए गए थे। धारा 16 की मूल उप-धारा (1) ने यह निर्धारित किया था कि 25 अक्टूबर 1949 से पहले दिए गए सभी खनन पट्टे 1957 अधिनियम और धारा 13 और 18 के तहत बनाए गए नियमों की प्रावधानों के अनुसार लाए जाएंगे। फिर यह कहा गया कि यदि केंद्रीय सरकार का मानना था कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी व्यक्ति को एक या अधिक ऐसे खनन पट्टे रखने की अनुमति दे सकती है जो किसी एक राज्य में धारा 6 की उप-धारा (बी) में निर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक हो या धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक हो। धारा 16 की उप-धारा (1) को 1972 और 1994 में संशोधित किया गया है।

60. धारा 17 के अनुसार, केंद्रीय सरकार को कुछ मामलों में अन्वेषण या खनन संचालन प्रारम्भ करने के लिए विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। धारा 17(1) में 1972 में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद, धारा 17(1) इस प्रकार है:

"धारा 17.- केंद्रीय सरकार की विशेष शक्तियाँ कुछ भूमि में अन्वेषण या खनन संचालन प्रारम्भ करने के लिए.- (1) इस धारा के प्रावधान उन भूमि पर लागू होंगे जिनमें खनिज राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं।"

61. 1957 अधिनियम में धारा 17ए को अधिनियम 37 द्वारा 1987 में जोड़ा गया। इसके बाद, धारा 17 ए में उप-धारा (1ए) को अधिनियम 25 द्वारा 1994 में जोड़ा गया। धारा 17 ए, 1994 में संशोधन के बाद, इस प्रकार है:

**"धारा 17ए. संरक्षण के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का आरक्षण.-** (1) केंद्रीय सरकार, किसी खनिज को संरक्षित करने के उद्देश्य से और राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद, किसी ऐसे क्षेत्र का आरक्षण कर सकती है जो पहले से किसी खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है और, यदि वह ऐसा करने का प्रस्ताव रखती है, तो उसे आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके संबंध में वह क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(1ए) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, किसी ऐसे क्षेत्र का आरक्षण कर सकती है जो पहले से किसी खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, ताकि किसी सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से अन्वेषण या खनन संचालन प्रारम्भ किया जा सके जो उसके द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित हो, और यदि वह ऐसा करने का प्रस्ताव रखती है, तो उसे आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके संबंध में वह क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से, किसी ऐसे क्षेत्र का आरक्षण कर सकती है जो पहले से किसी खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, ताकि किसी सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से अन्वेषण या खनन संचालन प्रारम्भ किया जा सके जो उसके द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित हो और यदि वह ऐसा करने का प्रस्ताव रखती है, तो उसे आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके संबंध में वह क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(3) जहाँ उप-धारा (1ए) या उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे क्षेत्र में अन्वेषण या खनन संचालन प्रारम्भ करती है जिसमें खनिज एक निजी व्यक्ति के पास निहित हैं, तो उसे समय-समय पर उसी दर पर अन्वेषण शुल्क, रॉयल्टी, सतह किराया या मृत किराया चुकाना होगा जिस दर पर यह इस अधिनियम के तहत भुगतान योग्य होता यदि ऐसा अन्वेषण या खनन संचालन एक निजी व्यक्ति द्वारा खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत किया गया होता।"

62. धारा 18 यह बताती है कि केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए और पर्यावरण की रक्षा करे ताकि कोई भी प्रदूषण जो अन्वेषण या खनन संचालन द्वारा उत्पन्न हो सकता है उसे रोका जा सके या नियंत्रित किया जा सके और ऐसे उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। धारा 18 की उप-धारा (2) केंद्रीय सरकार को नियम बनाने और धारा (ए) से (क्यू) तक निर्दिष्ट मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है।

63. धारा 18ए को 1957 अधिनियम में जोड़ा गया ताकि केंद्रीय सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को किसी भूमि में या उसके नीचे किसी भी खनिज की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक जांच करने की अनुमति दे सके जिसके संबंध में कोई खोज लाइसेंस या खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। धारा 18ए की उप-धारा (1) के बाद आने वाला प्रावधान यह बताता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए खोज लाइसेंस या खनन पट्टों के मामलों में, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि राज्य सरकार से परामर्श किया गया हो। जिस हद तक धारा 18ए प्रासंगिक है, इसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"धारा 18ए . भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि को जांच करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति.-(1) जहाँ केंद्रीय सरकार का यह मानना है कि भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए किसी भी खनिज के संबंध में, जो किसी भूमि में या उसके नीचे उपलब्ध है, सटीक जानकारी एकत्र करना आवश्यक है, जिसके संबंध में कोई खोज लाइसेंस या खनन पट्टा राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, केंद्रीय सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या इस संबंध में जिस अन्य प्राधिकरण या एजेंसी को वह निर्दिष्ट कर सकती है, को ऐसी विस्तृत जांच करने के लिए अधिकृत कर सकती है ताकि आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए खोज लाइसेंस या खनन पट्टों के मामलों में, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि राज्य सरकार से परामर्श किया गया हो।

XXX XXX XXX XXX XXX

(6) इस धारा के तहत की गई जांच की लागत केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति जिसमें खनिज निहित हैं या किसी खोज लाइसेंस या खनन पट्टे का धारक केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि उसे उप-धारा (5) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए, तो वह राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति या खोज लाइसेंस या खनन पट्टे का धारक, जैसा भी मामला हो, जांच की लागत का ऐसा उचित हिस्सा वहन करेगा जैसा केंद्रीय सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसी जांच की लागत के उस हिस्से का भुगतान करने पर, केंद्रीय सरकार से उप-धारा (5) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट की एक सत्यापित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

64. धारा 19 यह प्रदान करती है कि कोई भी खोज लाइसेंस या खनन पट्टा जो 1957 अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिया गया, नवीनीकरण किया गया या अधिग्रहित किया गया हो, वह अमान्य और अप्रभावी होगा। धारा 19 में 1994 और 1999 में संशोधन किए गए लेकिन ये संशोधन इन मामलों के उद्देश्यों के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं हैं।

65. धारा 29 के अनुसार, 1948 अधिनियम के तहत बनाए गए नियम जो 1957 अधिनियम में प्रदान किए गए मामलों के अनुसार संगत हैं, उन्हें तब तक जारी रखने के लिए बनाया गया था जब तक कि उन्हें 1957 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। इस प्रकार, 1948 अधिनियम के तहत बनाए गए नियम तब तक लागू रहे जब तक कि 1960 नियम नहीं बनाए गए।

### **खनिज अनुदान नियम, 1960 और संशोधन**

66. 1960 नियम केंद्रीय सरकार द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए। ये नियम 11 नवंबर 1960 को प्रकाशित किए गए। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, जब तक ये नियम प्रभावी नहीं हुए, तब तक 1948 अधिनियम के तहत बनाए गए नियम लागू रहे।

67. नियम 8 के अनुसार, अध्याय 11, III और IV के प्रावधानों को अन्वेषण अनुमतियों और खोज लाइसेंसों तथा खनन पट्टों के देने और नवीनीकरण पर लागू किया गया है जिनके संबंध में खनिज राज्य सरकार में निहित हैं।

68. नियम 9 यह प्रदान करता है कि किसी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, खोज लाइसेंस और उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन राज्य सरकार को क्रमशः फॉर्म बी और फॉर्म डी में

किया जाएगा। राज्य सरकार को नियम 9 के उप-नियम (2) की धारा (डी) के प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार है।

69. अध्याय-IV उन भूमि पर खनन पट्टे देने से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं। नियम 22 का उप-नियम (1) यह प्रदान करता है कि उस भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन राज्य सरकार को फॉर्म 1 में किया जाएगा। नियम 22 का उप-नियम (4) यह प्रदान करता है कि खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार को सटीक क्षेत्र देने का निर्णय लेना होगा और उस निर्णय को आवेदक को सूचित करना होगा। आवेदक को राज्य सरकार से सटीक क्षेत्रों की सूचना प्राप्त होने पर छह महीने की अवधि या उस अवधि में जो राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है, केंद्रीय सरकार को उसके अनुमोदन हेतु एक खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक को उस क्षेत्र पर खनन पट्टा देने हेतु राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या केंद्रीय सरकार द्वारा उचित रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी। नियम 22 का उप-धारा (4ए) एक गैर-विपरीत धारा है और राज्य सरकार को गैर-धात्विक या औद्योगिक खनिजों के संबंध में ओपन-कास्ट खानों (भूमिगत खानों को छोड़कर) की खनन योजना को अनुमोदित करने का अधिकार देती है जो उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में धाराओं (i) से (xxix) में निर्धारित हैं। ऐसी खनन योजना की अनुमोदना का अधिकार राज्य सरकार को उन अधिकारियों द्वारा प्रयोग करना होगा जिनके पास योग्यताएँ, अनुभव और पद तथा वेतनमान निर्धारित हैं। नियम 22 के उप-धारा (48) के तहत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो खनन योजना की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ हो, उस आवेदन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर।

70. नियम 22डी को 17 जनवरी, 2000 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो खनन पट्टे के लिए न्यूनतम आकार का प्रावधान करता है।

71. नियम 26, जिसे 18 जुलाई, 1963 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, को 1979, 1988, 1991 और 2002 में संशोधित किया गया। नियम 26 अब इस प्रकार है:

"26. खनन पट्टे के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकार। - (1) राज्य सरकार, सुनवाई का अवसर देने के बाद और लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए, और आवेदक को सूचित करते हुए, पूरे या भाग के लिए खनन पट्टा देने या नवीनीकरण करने से इनकार कर सकती है।

(2) नियम 22 या नियम 24ए के तहत किए गए खनन पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन को केवल इस आधार पर राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि फॉर्म 1 या फॉर्म J, जैसा भी हो, सभी महत्वपूर्ण विवरणों में पूरा नहीं है, या उप-धारा 22 के उप-धारा (i) के उप-धाराओं (डी), (इ), (एफ), (जी) और (एच) में संदर्भित दस्तावेजों के साथ नहीं है।

(3) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी महत्वपूर्ण विवरणों में पूरा नहीं है या आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं है, राज्य सरकार नोटिस द्वारा आवेदक से कमी को पूरा करने या आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की मांग करेगी, बिना देरी किए और किसी भी मामले में उस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

72. नियम 31 उस समय अवधि का प्रावधान करता है जिसके भीतर पट्टा निष्पादित किया जाना है। यह अवधि की शुरुआत की तारीख का भी प्रावधान करता है।

73. नियम 58, जैसा कि यह मूल रूप से था, इस प्रकार था:

"58. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्रों की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी। (1) कोई भी क्षेत्र जो पहले से ही एक अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत हो रहा हो, या जिसके संबंध में लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश उप-धारा (1) नियम 15 या उप-धारा (1) नियम 31 के तहत रद्द किया गया हो, वह अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि -

(ए) उप-धारा (2) नियम 21 या उप-धारा (2) नियम 40 में संदर्भित रजिस्टर में स्याही से प्रभावी प्रविष्टि की गई हो; और

(बी) जिस तारीख से क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा वह आधिकारिक गजट में कम से कम तीस दिन पहले सूचित किया गया हो।

(2) केंद्रीय सरकार लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए किसी विशेष मामले में उप-धारा (1) की व्यवस्थाओं को शिथिल कर सकती है।"

नियम 58 को 16 नवंबर, 1980 को संशोधित किया गया और संशोधित नियम 58 इस प्रकार था:

"58. सार्वजनिक क्षेत्र आदि में शोषण के लिए क्षेत्र का आरक्षण। - राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को सरकार द्वारा शोषण के लिए आरक्षित कर सकती है, एक निगम जो केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या कंपनियों अधिनियम, 1956 (1 of 1956) की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी हो।"

बाद में, नियम 58 को समाप्त कर दिया गया।

74. नियम 59, जैसा कि 1960 के नियमों में मूल रूप से तैयार किया गया था, इस प्रकार था:

"59. कुछ क्षेत्रों की उपलब्धता के लिए अनुदान की सूचना दी जाएगी। - किसी भी भूमि के मामले में जो अन्यथा अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए उपलब्ध है, लेकिन जिसके संबंध में राज्य सरकार ने किसी उद्देश्य के लिए (अन्वेषण या खनिजों के लिए खनन के अलावा) लाइसेंस या पट्टा देने से इनकार किया है, राज्य सरकार, जैसे ही वह

भूमि फिर से अन्वेषण या खनन पट्टे के लिए उपलब्ध हो जाती है, नियम 58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंस या पट्टा देगी।"

मूल नियम 59 को 9 जुलाई, 1963 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया। उक्त संशोधन के बाद, नियम इस प्रकार था:

"59. कुछ क्षेत्रों की उपलब्धता के लिए अनुदान की सूचना दी जाएगी। - किसी भी भूमि के मामले में जो अन्यथा अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए उपलब्ध है, लेकिन जिसके संबंध में राज्य सरकार ने किसी उद्देश्य के लिए लाइसेंस या पट्टा देने से इनकार किया है, राज्य सरकार, जैसे ही वह भूमि फिर से अन्वेषण या खनन पट्टे के लिए उपलब्ध हो जाती है, लाइसेंस या पट्टा देगी, नियम 58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए।"

नियम 59 को 1980 में फिर से संशोधित किया गया। संशोधन के बाद, उक्त नियम इस प्रकार था:

"59. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी - (1) कोई भी क्षेत्र

-

(ए) जो पहले से ही एक अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत हो; या

(बी) जिसके संबंध में अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे देने का आदेश दिया गया था, लेकिन आवेदक लाइसेंस देने या पट्टा निष्पादित करने से पहले मर गया; या

(सी) जिसके संबंध में लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश उप-धारा (1) नियम 15 या उप-धारा (1) नियम 31 के तहत रद्द कर दिया गया; या

(डी) जिसके संबंध में धारा 17 की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के तहत अधिसूचना जारी की गई; या

(इ) जिसे सरकार द्वारा नियम 58 के तहत आरक्षित किया गया है, वह अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि -

(i) इस प्रभाव से एक प्रविष्टि रजिस्टर में की गई हो जो उप-धारा (2) नियम 21 या उप-धारा (2) नियम 40 में संदर्भित है; और

(ii) क्षेत्र की उपलब्धता को आधिकारिक गजट में सूचित किया जाए और एक तारीख निर्दिष्ट की जाए (जो कि आधिकारिक गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले तीस दिन नहीं हो) जिस तारीख से यह क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा:

यह प्रावधान किया गया है कि इस नियम का कुछ भी मूल पट्टेदार या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण करने पर लागू नहीं होगा, भले ही पट्टा पहले ही

समाप्त हो चुका हो: आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां नियम 58 के तहत आरक्षित क्षेत्र को एक सरकारी कंपनी को दिया जाने का प्रस्ताव है, वहां धारा (ii) के तहत कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) केंद्रीय सरकार लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों के आधार पर किसी विशेष मामले में उप-धारा (1) की व्यवस्थाओं को शिथिल कर सकती है।"

नियम 59 को 13 अप्रैल, 1988 को और संशोधित किया गया। संशोधित नियम 59 इस प्रकार है:

"59. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी: - (1) कोई भी क्षेत्र

-

(ए) जो पहले से ही एक अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत हो; या

(बी) जिसके संबंध में अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे देने का आदेश दिया गया था, लेकिन आवेदक लाइसेंस देने या पट्टा निष्पादित करने से पहले मर गया; या

(सी) जिसके संबंध में लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश रद्द कर दिया गया है, उप-धारा (1) नियम 15 या उप-धारा (1) नियम 31 के तहत; या

(डी) जिसके संबंध में धारा 17 की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के तहत अधिसूचना जारी की गई; या

(इ) जिसे राज्य सरकार द्वारा नियम 58 के तहत आरक्षित किया गया है, या अधिनियम की धारा 17-ए के तहत अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि -

(i) इस प्रभाव से एक प्रविष्टि रजिस्टर में की गई हो जो उप-धारा (2) नियम 21 या उप-धारा (2) नियम 40 में संदर्भित है; और

(ii) क्षेत्र की उपलब्धता को आधिकारिक गजट में सूचित किया जाए और एक तारीख निर्दिष्ट की जाए (जो कि आधिकारिक गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले तीस दिन नहीं हो) जिस तारीख से यह क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा:

यह प्रावधान किया गया है कि इस नियम का कुछ भी मूल पट्टेदार या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण करने पर लागू नहीं होगा, भले ही पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका हो: आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां नियम 58 या अधिनियम की धारा 17-ए के तहत आरक्षित क्षेत्र को एक सरकारी कंपनी को दिया जाने का प्रस्ताव है, वहां धारा (ii) के तहत कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(2) केंद्रीय सरकार लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों के आधार पर किसी विशेष मामले में उप-धारा (1) की व्यवस्थाओं को शिथिल कर सकती है।

75. नियम 60, 1960 के नियमों का, दो बार संशोधन किया गया है, पहले 16 जनवरी, 1980 की अधिसूचना द्वारा और उसके बाद 17 जनवरी, 2000 की अधिसूचना द्वारा। संशोधन के बाद, नियम 60 इस प्रकार है:

"60. पूर्ववर्ती आवेदन - अन्वेषण परमिट, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन जो उन क्षेत्रों के संबंध में हैं जिनकी उपलब्धता के लिए अनुदान नियम 59 के तहत सूचित की जानी चाहिए, यदि -

(ए) उस नियम के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है; या

(बी) जहां कोई ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहां अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो इसे पूर्ववर्ती माना जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

76. नियम 63, 1960 के नियमों में यह प्रावधान करता है कि जहां 1957 अधिनियम या 1960 के नियमों के तहत केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, वहां ऐसी स्वीकृति के लिए आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय सरकार को किया जाएगा।

77. उपरोक्त प्रावधान हमें खनिज विकास और खानों के नियमन से संबंधित वैधानिक ढांचे और कानूनी व्यवस्था का पूरा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करते हैं।

## निर्णय

### हिंंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड

78. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने हिंंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड मामले में ओडिशा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम, 1952 की वैधता के प्रश्न पर विचार किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलील यह थी कि भले ही इसके तहत लगाया गया उपकर 'शुल्क' हो जो सूची II की प्रविष्टियों 23 और/या 66 से संबंधित हो, फिर भी यह सूची I की प्रविष्टि 54 के खिलाफ होगा, जैसा कि 1948 अधिनियम की धारा 2 में घोषित किया गया था: 'यह घोषित किया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार खानों और तेल क्षेत्रों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में ले।'।

79. बहुमत का दृष्टिकोण उपरोक्त दलील पर इस प्रकार विचार करता है:

"23. अगला प्रश्न यह उठता है कि यदि उपकर शुल्क है और इस प्रकार सूची II में प्रविष्टियों 23 और 66 से संबंधित हो सकता है, तो इसकी वैधता अभी भी चुनौती दी जा सकती है क्योंकि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता प्रविष्टि 23 के तहत संघ के नियंत्रण में नियमन और विकास के संबंध में सूची I की व्यवस्थाओं के अधीन है; और यह हमें सूची I की प्रविष्टि 54 तक ले जाता है। यह प्रविष्टि इस प्रकार पढ़ती है: 'खानों और खनिज विकास का नियमन उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा नियमन और विकास संघ के नियंत्रण में सार्वजनिक हित में आवश्यक

घोषित किया गया हो।' इन दोनों प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ने का प्रभाव स्पष्ट है। राज्य विधानमंडल का अधिकार प्रविष्टि 23 के अंतिम भाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। यदि संसद ने अपने कानून द्वारा घोषित किया है कि खानों का नियमन और विकास सार्वजनिक हित में संघ के नियंत्रण में होना चाहिए, तो उस घोषणा की सीमा तक राज्य विधानमंडल का अधिकार समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि एक केंद्रीय अधिनियम पारित किया गया है जिसमें संसद द्वारा आवश्यक रूप से प्रविष्टि 54 के अनुसार एक घोषणा शामिल है, और यदि वह घोषणा विवादित अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को कवर करती है तो विवादित अधिनियम अवैध होगा, न कि किसी विरोधाभास के कारण बल्कि इसलिए कि राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने का अधिकार नहीं था। प्रविष्टि 23 के अंतिम भाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर एक प्रतिबंध हैं। यह स्थिति विवादास्पद नहीं है।

24 ..... यदि यह माना जाता है कि यह अधिनियम प्रविष्टि 23 में संदर्भित घोषणा को शामिल करता है तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि वह घोषणा खनिजों का संरक्षण और विकास कवर करती है, और वह क्षेत्र विवादित अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। प्रविष्टि 23 जो प्रावधान करती है वह यह है कि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता संघ के नियंत्रण में नियमन और विकास के संबंध में सूची 1 की व्यवस्थाओं के अधीन होती है, और सूची 1 में प्रविष्टि 54 संसद द्वारा कानून द्वारा एक घोषणा की आवश्यकता रखती है कि खानों का नियमन और विकास सार्वजनिक हित में संघ के नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए, यदि एक केंद्रीय अधिनियम खनिजों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से पारित किया गया हो, और यदि इसमें आवश्यक घोषणा शामिल हो, तो राज्य विधानमंडल को उस विषय पर कानून पारित करने का अधिकार नहीं होगा जो उस घोषणा द्वारा कवर किया गया हो। ताकि घोषणा प्रभावी हो सके, यह आवश्यक नहीं है कि नियम बनाए जाएं या लागू किए जाएं; इसके लिए केवल संसद द्वारा यह घोषणा करना आवश्यक है कि खानों का नियमन और विकास संघ के नियंत्रण में लेना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। ऐसे मामले में परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या विधायी घोषणा क्षेत्र को कवर करती है या नहीं। इस परीक्षण से आंकने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि विवादित अधिनियम द्वारा कवर किया गया क्षेत्र केंद्रीय अधिनियम LIII oएफ 1948 द्वारा कवर किया गया है।

25. अब यह विचार करना बाकी रह जाता है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 2 कानून में संसद द्वारा आवश्यक रूप से एक घोषणा बनती है जैसा कि अनुच्छेद 54 द्वारा अपेक्षित होता है। जब उक्त अधिनियम 1948 में पारित हुआ था तब केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की विधायी शक्तियां संविधान अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टियों द्वारा नियंत्रित थीं। सूची 1 में प्रविष्टि 36 वर्तमान सूची 1 की प्रविष्टि 54 से मेल खाती है। यह इस प्रकार पढ़ती है: 'खानों और तेल क्षेत्रों का नियमन तथा खनिज विकास उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा नियमन एवं विकास डोमिनियन नियंत्रण में सार्वजनिक हित में आवश्यक घोषित

किया गया हो।' यह देखा जाएगा कि प्रविष्टि 36 द्वारा अपेक्षित घोषणा डोमिनियन कानून द्वारा एक घोषणा होती है। फिर धारा 2 पर लौटते हुए स्पष्ट होता है कि उक्त धारा में शामिल घोषणा निष्क्रिय स्वर में रखी गई है; लेकिन संदर्भ में कोई कठिनाई नहीं होगी यह मानने में कि उक्त घोषणा अनिवार्य रूप से डोमिनियन कानून द्वारा बनाई गई थी। यह एक ऐसा बयान है जो डोमिनियन विधानमंडल द्वारा पारित धारा में शामिल होता है और इसलिए यह स्पष्ट होता है कि यह डोमिनियन कानून द्वारा एक बयान होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है: क्या डोमिनियन कानून द्वारा बनाई गई इस घोषणा को संवैधानिक रूप से संसद द्वारा बनाई गई घोषणा माना जा सकता है जैसा कि सूची 1 की प्रविष्टि 54 द्वारा अपेक्षित होता है?"

बहुमत ने पाया कि संसद द्वारा आवश्यकता अनुसार बनाई गई घोषणा जो सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत थी वह अनुपस्थित थी क्योंकि 1948 अधिनियम की धारा 2 के तहत डोमिनियन विधानमंडल द्वारा बनाई गई घोषणा को 1957 अधिनियम की धारा 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई घोषणा के बराबर नहीं माना गया था।

### एम.ए.तुल्लोक और कंपनी

80. एम.ए. तुल्लोक और कंपनी में, इस उच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ओडिशा खनन क्षेत्र विकास कोष अधिनियम, 1952 (ओडिशा अधिनियम) के तहत कुछ शुल्कों की वैधता के साथ संबंधित थी। संविधान पीठ ने यह प्रश्न विचार किया, 'क्या 1957 अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया नियंत्रण और विनियमन का दायरा 1952 अधिनियम के अधीन क्षेत्र या विषय को अपने अंतर्गत लेता है?' उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि ओडिशा अधिनियम द्वारा लगाया गया शुल्क 1957 अधिनियम के दृष्टिगत अप्रभावी हो गया था। ओडिशा राज्य ने उस निर्णय के खिलाफ अपील की थी। न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 5 और पैरा 6 में निम्नलिखित रूप से नोट किया:

"5. आगे बढ़ने से पहले, संबंधित विषय पर विधायी शक्ति को संक्षेप में निर्दिष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि निर्णय का आधार संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों के सटीक शब्दों और राज्य तथा केंद्रीय विधाननों के दायरे, उद्देश्य और प्रभाव पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 246(1) पढ़ता है:

'किसी भी बात के बावजूद जो उपबंध (2) और (3) में है, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है (जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा जाता है)।'

और हम वर्तमान मामले में राज्य क्षेत्र में राज्य शक्ति से संबंधित हैं। उस संदर्भ में प्रासंगिक उपबंध अनुच्छेद का उपबंध (3) है जो इस प्रकार चलता है:

'उपबंध (1) और (2) के अधीन, किसी भी राज्य की विधायिका ... उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए सूची ॥ में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार रखती है (जिसे इस संविधान में 'राज्य सूची' कहा जाता है)।'

अब सातवीं अनुसूची पर आते हुए, राज्य सूची की प्रविष्टि 23 राज्य विधायिका को 'खदानों और खनिज विकास के विनियमन' पर कानून बनाने का अधिकार देती है, संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के लिए सूची 1 की प्रविष्टियों के प्रावधानों के अधीन। यह देखा जाएगा कि 'सूची 1' की प्रावधानों के अधीन राज्य का कानून बनाने का अधिकार 'खदानों और खनिज विकास' विषय पर पूर्ण है। सूची 1 में प्रासंगिक प्रावधान पहले ही नोट किया गया है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 54 है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण का यह ढांचा नया नहीं है बल्कि यह केवल भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत विद्यमान स्थिति का निरंतरता है जिसमें संघ सूची की प्रविष्टि 54 की रेखाओं पर एक प्रावधान शामिल था जो तब संघीय सूची की आइटम संख्या 36 थी और राज्य सूची में प्रविष्टि 23 जो प्रांतीय विधायी सूची में समान संख्या रखती थी। कोई विवाद नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम संसद द्वारा प्रविष्टि 54 में निहित विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है या केंद्रीय अधिनियम में वह घोषणा शामिल है जो प्रविष्टि 54 द्वारा आवश्यक होती है क्योंकि यह धारा 2 द्वारा लागू करता है:

'यह घोषित किया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ खदानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले।'

यह समझने के लिए बहुत अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है कि जिस हद तक संघ सरकार ने 'अपने नियंत्रण' में 'खनिजों का विनियमन और विकास' लिया, उतनी ही सीमा राज्य विधायिका की शक्ति से हटा दी गई।"

6. हालांकि, यह स्पष्ट होगा कि राज्यों को केवल 'उस हद तक विधायी क्षमता खोनी होगी जिस हद तक संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास को संसद द्वारा सार्वजनिक हित में आवश्यक घोषित किया गया हो।' इसलिए महत्वपूर्ण जांच इस "हद" को निर्धारित करने की दिशा में होनी चाहिए क्योंकि इसके पार राज्य की विधायी शक्ति अपरिवर्तित रहती है। चूंकि इस मामले में राज्य द्वारा पारित कानून समय की दृष्टि से पहले वाला था, इसलिए पहले राज्य अधिनियम का परीक्षण करना और उसके उद्देश्य, चौड़ाई और दायरे तथा इसके संचालन क्षेत्र को निर्धारित करना तार्किक होगा और फिर विचार करना होगा कि केंद्रीय अधिनियम इसमें कितनी "हद" तक कटौती करता है या इसका उल्लंघन करता है।

पैरा 9 में विचाराधीन प्रश्न था कि क्या '1957 अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया नियंत्रण और विनियमन का दायरा' ओडिशा अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या विषय को अपने अंतर्गत लेता था। इस न्यायालय ने पैरा 11 में देखा कि मामला पहले ही निर्णय हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा समाप्त हो चुका था। हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड का पालन करते हुए, रिपोर्ट के पैरा 12 में यह देखा गया कि धारा 18 की उपधारा (1) और (2) 1957 अधिनियम की दायरे और विस्तार में व्यापक थीं और केंद्रीय सरकार को 1948 अधिनियम की संबंधित प्रावधानों से अधिक शक्तियाँ प्रदान करती थीं।

**बैजनाथ कादियो**

81. *बैजनाथ कादियो* मामले में, बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1964 (बिहार अधिनियम 4 of 1965) द्वारा जोड़ा गया धारा 10(2) का उपबंध (2) और बिहार लघु खनिज अनुदान नियम, 1964 के तहत 10 दिसंबर, 1964 को गवर्नर के नोटिफिकेशन द्वारा जोड़ा गया नियम 20(2) विवाद में था। न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम, 1935, 1948 अधिनियम और 1957 अधिनियम का उल्लेख करते हुए सूची I की प्रविष्टि 54 और सूची II की प्रविष्टि 23 के संदर्भ में *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड* और *एम.ए. तुल्लोक और कंपनी* के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

"13. संघ सूची की प्रविष्टि 54 खदानों और खनिज विकास के विनियमन दोनों के बारे में बात करती है और प्रविष्टि 23 प्रविष्टि 54 के अधीन है। संसद के लिए यह घोषित करना संभव है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास होना चाहिए। इस प्रकार की घोषणा कितनी दूर तक जा सकती है, यह संसद के लिए निर्धारित करना है और यह सार्वजनिक हित के साथ सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। एक बार जब यह घोषणा की जाती है और दायरा निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारित सीमा तक विधायी विषय संसद द्वारा कानून बनाने का विशेष विषय बन जाता है। ऐसी घोषणा के बाद राज्य द्वारा कोई भी विधायी कार्य जो उस क्षेत्र में आता है जिसे घोषणा में दर्शाया गया है, अनिवार्य रूप से असंवैधानिक होगा क्योंकि वह क्षेत्र राज्य विधायिका की विधायी क्षमता से हटा दिया गया है। यह प्रस्तावना भी स्व-सिद्ध है कि इसे गलत साबित करने का कोई प्रयास सही नहीं था। इस न्यायालय के दो निर्णय भी हैं जो *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य ओडिशा* और *राज्य ओडिशा बनाम एम.ए. तुल्लोक और कंपनी* में चर्चा की गई हैं। इसलिए एकमात्र विवाद यह हो सकता है कि संसद द्वारा की गई घोषणा राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाने के लिए कितनी गुंजाइश छोड़ती है। यदि विवादित विधायी कार्य उस गुंजाइश के दायरे में आता है तो यह वैध होगा; यदि इसके बाहर आता है, तो इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

14. यह घोषणा अधिनियम 67 of 1957 की धारा 2 में निहित है और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में खदानों का विनियमन और खनिजों का विकास लेने की बात करती है, जैसा कि अधिनियम में स्वयं प्रदान किया गया है। इसलिए हमें यह निर्धारित करने के लिए अधिनियम 67/ 1957 से बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या राज्य विधायिका की क्षमता में क्या बचा है, बल्कि हमें उस अधिनियम की शर्तों से इसे निकालना होगा। इस संबंध में हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने दो मामलों में क्या निर्णय लिया। *हिंगिर-रामपुर* मामले में एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या 1948 का अधिनियम खनिजों के संरक्षण और विकास के क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करता है ताकि राज्य विधायी कार्य के लिए कोई गुंजाइश न रहे। यह निर्णय लिया गया कि घोषणा प्रभावी थी भले ही 1948 के अधिनियम के तहत विचारित नियम नहीं बनाए गए हों। हालांकि, आगे विचार करते हुए कि क्या डोमिनियन कानून द्वारा की गई घोषणा को प्रविष्टि 54 के उद्देश्य से संसद द्वारा की गई घोषणा माना जा सकता है, इसे अस्वीकार किया गया था और इस प्रकार एक कमी थी जिसे कानूनों के अनुकूलन आदेश, 1950 नहीं हटा सका। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाने की गुंजाइश थी।

15. *एम.ए. तुल्लोक* मामले में फर्म ने 1948 के अधिनियम के तहत दिए गए खनन पट्टे पर काम किया। ओडिशा की राज्य विधायिका ने फिर ओडिशा खनन क्षेत्र विकास कोष अधिनियम, 1952 पारित किया और राज्य में खनन क्षेत्रों के विकास के लिए एक शुल्क लगाया। जब प्रावधान लागू हुए तो जुलाई 1957 से मार्च 1958 तक बकाया शुल्क का भुगतान करने की मांग की गई और इस मांग को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब अधिनियम 67/1957 लागू हुआ तो ओडिशा अधिनियम को अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। अपील पर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि अधिनियम 67 of 1957 में प्रविष्टि 54 के तहत संसद द्वारा आवश्यक घोषणा शामिल थी और वह अधिनियम खदानों और खनिज विकास के संबंध में 1948 के अधिनियम के समान क्षेत्र को कवर करता था, इसलिए *हिंगिर-रामपुर* मामले का निर्णय लागू होता था और चूंकि अधिनियम 67 / 1957 की धाराएँ 18(1) और (2) बहुत व्यापक थीं, उन्होंने राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाने को अस्वीकार कर दिया। जहां एक उच्चतर विधायिका ने पूरे क्षेत्र को कवर करने का इरादा व्यक्त किया हो, वहां अन्य विधायिका द्वारा पारित किए गए कानून चाहे वे पहले या बाद में पारित किए गए हों, उन्हें अवरुद्ध माना जाना चाहिए। यह निर्धारित किया गया कि असंगति को दो विवादास्पद अधिनियमों की प्रावधानों की विस्तृत तुलना करके नहीं बल्कि केवल दो विधाननों की उपस्थिति से सिद्ध किया जा सकता है। चूंकि धारा 18(1) पूरे क्षेत्र को कवर करती थी, इसलिए इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि जब तक उस धारा के तहत नियम बनाए नहीं जाते, तब तक स्थान उपलब्ध था।

### **अमृतलाल नाथुभाई शाह**

82. *अमृतलाल नाथुभाई शाह* घ मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ एक ऐसे मुद्दे से संबंधित थी जो हमारे सामने प्रस्तुत विवाद के समान था। यह मामला गुजरात राज्य में आरक्षित क्षेत्रों में बॉक्साइट के लिए खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित था। 31 दिसंबर, 1963 को, गुजरात सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें सूचित किया गया कि कच्छ जिले के सभी तालुकों और जामनगर जिले के कल्याणपुर तालुका में भूमि को सार्वजनिक क्षेत्र में बॉक्साइट के दोहन के लिए आरक्षित किया गया है। 26 फरवरी, 1964 को जामनगर और जूनागढ़ जिलों के सभी क्षेत्रों के संबंध में एक अन्य अधिसूचना में, बॉक्साइट का दोहन सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किया गया था। वहां के अपीलकर्ताओं ने आरक्षित क्षेत्रों में बॉक्साइट के लिए खनन पट्टों के अनुदान के लिए गुजरात सरकार से आवेदन किया। हालांकि अन्य कोई आवेदन नहीं थे, राज्य सरकार ने अपीलकर्ताओं के आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि क्षेत्रों को पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित किया जा चुका है। अपीलकर्ता, जो राज्य सरकार के आदेश से असंतुष्ट थे, केंद्रीय सरकार के पास पुनरीक्षण अधिकार का उपयोग करते हुए गए। केंद्रीय सरकार ने पुनरीक्षण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया। अपीलकर्ताओं ने फिर उच्च न्यायालय का रुख किया लेकिन वे वहां भी असफल रहे और उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और इसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से मामला इस न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सूची I की प्रविष्टि 54, 1957 अधिनियम की धारा 2 में संसद द्वारा किए गए उद्घोषणा और सूची II की प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति पर विचार किया, और यह देखा कि

सूची 1 की प्रविष्टि 54 में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने विशेष रूप से 1957 अधिनियम की धारा 2 में यह घोषित किया कि संघ का खनन और खनिजों का विकास नियंत्रित करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल की प्रविष्टि 23 की शक्ति छीन ली गई और खनन और खनिजों का विकास 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा कहते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"3 ..... प्रश्नगत खनिज (बॉक्साइट) हालांकि गुजरात राज्य की सीमा में थे और जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं के पुनरीक्षण आवेदनों पर पारित आदेशों में कहा गया था, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में "खनिजों का मालिक" है और खनिज "उसमें निहित" हैं। अधिनियम या नियमों में इस मूल तथ्य को कम करने वाली कोई बात नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय सरकार ने अपने पुनरीक्षण आदेशों में आगे कहा कि राज्य सरकार को "सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए किसी विशेष क्षेत्र को आरक्षित करने का अंतर्निहित अधिकार" है। इसलिए यह स्पष्ट है कि, किसी कानून या अनुबंध आदि की अनुपस्थिति में, बॉक्साइट, एक खनिज के रूप में, और इसके खदानें गुजरात राज्य में निहित हैं और किसी व्यक्ति को इसे अधिनियम और नियमों की धाराओं के अनुसार दोहन करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 10 और नियमों के अध्याय II, III और IV उन भूमि पर अन्वेषण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित हैं जिनमें खनिज राज्य सरकार में निहित हैं। यही कारण है कि अपीलकर्ताओं ने राज्य सरकार से अपने आवेदन किए।"

83. *अमृतलाल नाथुभाई शाह* घ मामले में, इस न्यायालय ने 1957 अधिनियम की धारा 4 का उल्लेख किया और कहा कि 1957 अधिनियम या 1960 नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो यह आवश्यक बनाता हो कि यदि राज्य सरकार स्वयं किसी खनिज का दोहन करना चाहती है तो नियमों के अध्याय II, III और IV द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू होंगे क्योंकि वह उसकी अपनी संपत्ति है। न्यायालय ने कहा:

"4 ..... इसलिए कोई कारण नहीं है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वह किसी भी उद्देश्य के लिए "आरक्षित" भूमि नहीं रख सकती और ऐसी आरक्षित भूमि फिर किसी व्यक्ति को अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं होगी।"

84. फिर न्यायालय ने 1957 अधिनियम की धारा 10 पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय दिया:

"5 ..... यह धारा इसलिए राज्य सरकार की शक्ति को इंगित करती है कि वह ऐसे मामलों में एक या दूसरे तरीके से निर्णय ले सके और यह तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि उस शक्ति में लाइसेंस या पट्टा देने से इनकार करने की शक्ति शामिल थी क्योंकि प्रश्नगत भूमि उस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित होने के कारण ऐसी अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं थी।"

85. धारा 17 के संदर्भ में, विशेष रूप से इसके उप-धारा (2) और (4) में, न्यायालय ने कहा कि उक्त प्रावधान किसी अन्य को अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार करने की पूरी शक्ति को

कवर नहीं करते हैं और राज्य सरकार के लिए किसी क्षेत्र को अपने लिए आरक्षित करने की शक्ति को नहीं छीनते हैं। इसे आगे कहा गया:

"6 ..... जैसा कि कहा गया है, आरक्षण का आदेश देने की शक्ति इस तथ्य से निकलती है कि राज्य अपने क्षेत्र में खदानों और खनिजों का मालिक है, जो उसमें निहित हैं। लेकिन इसके अलावा, हमें यह भी मिलता है कि नियम 59, जो अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए हैं, स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के आदेश द्वारा ऐसे आरक्षण की कल्पना करता है। ..... "

86. *अमृतलाल नाथुभाई शाह* घ मामले में, न्यायालय ने 1960 नियमों के नियम 58, 59 और 60 पर भी विचार किया और यह देखा कि किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस या पट्टा के लिए आवेदन करना तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि वह ऐसे अनुदान के लिए उपलब्ध न हो जाए। मामले के तथ्यों पर यह कहा गया कि विचाराधीन क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचनाओं में बताए गए उद्देश्य के लिए आरक्षित किए गए थे और चूंकि वे भूमि अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं हुईं, इसलिए राज्य सरकार ने अपीलकर्ताओं के आवेदन को नियम 60 के तहत समय से पहले अस्वीकृत करने में अपने अधिकार का सही प्रयोग किया और केंद्रीय सरकार ने भी राज्य सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति आदेशों के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदनों को अस्वीकृत करने में उचित ठहराया।

87. *चानन मल* एक्स मामले में, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ हरियाणा खनिज (अधिकारों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'हरियाणा अधिनियम') की संवैधानिक वैधता से संबंधित थी। हरियाणा अधिनियम को चुनौती देने में एक तर्क यह था कि यह अधिनियम राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे था क्योंकि जिस क्षेत्र में हरियाणा अधिनियम लागू होता है वह अनिवार्य रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) के तहत 1957 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा व्याप्त था। पीठ ने 1957 अधिनियम में निहित प्रावधानों और इस न्यायालय के पिछले निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार किया। न्यायालय ने फिर 1957 अधिनियम की धारा 16(1)(b) और धारा 17 का उल्लेख किया और निम्नलिखित निर्णय दिया:

"38. हम विशेष रूप से धारा 16 और 17 के प्रावधानों से प्रभावित हैं जैसे वे अब हैं। धारा 16(1)(बी) पर एक नजर डालने से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम 67 of 1957 स्वयं उन भूमि का हस्तांतरण करने की कल्पना करता है, जो किसी संपत्ति या अधिकार धारक के स्वामित्व में थीं, या तो 25 अक्टूबर, 1949 के बाद, एक राज्य अधिनियम के तहत जो भूमि में संपत्तियों या अधिकारों का अधिग्रहण या कृषि सुधारों के लिए प्रदान करता है। यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि ऐसे भूमि में दिए गए खनन पट्टे को अधिनियम 56 of 1972 द्वारा पेश किए गए संशोधित कानून के अनुरूप लाना होगा। हमें लगता है कि इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसद ने स्वयं राज्य विधानमंडल को खनिज जमा वाले भूमि का राज्य सरकार में हस्तांतरण करने के लिए कानून बनाने की कल्पना की थी। इसे केवल इस धारणा पर समझाया जा सकता है कि संसद ने सूची II की प्रविष्टि 18 के तहत राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर हस्तक्षेप करने का

इरादा नहीं रखा। फिर, केंद्रीय अधिनियम 67 of 1957 की धारा 17 दिखाती है कि राज्यों में भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा बाधित करने का कोई इरादा नहीं था।"

### ईश्वरि खेतान शुगर मिल्स

88. ईश्वरि खेतान शुगर मिल्स वाई मामले में, हालांकि प्रश्न उत्तर प्रदेश शुगर अंडरटेकिंग्स (अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 की संवैधानिक वैधता से संबंधित था जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू किया गया था और सूची I और सूची II में विभिन्न प्रविष्टियाँ शामिल थीं लेकिन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'घ R अधिनियम') की धारा 2 में किए गए उद्घोषणा के संदर्भ में, बहुसंख्यक निर्णय ने इस न्यायालय के पिछले निर्णयों पर निर्भर करते हुए कहा कि जिस हद तक संघ ने घ R अधिनियम की धारा 2 में किए गए उद्घोषणा के कारण नियंत्रण प्राप्त किया, उस हद तक सूची II की प्रविष्टि 24 के तहत राज्य विधानमंडल का अधिकार किसी घोषित उद्योग के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार खो जाएगा ताकि घ R अधिनियम द्वारा व्याप्त नियंत्रण क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा सके। यह कहा गया कि 1957 अधिनियम केवल यह आवश्यक बनाता है कि ऐसे भूमि में दिए गए खनन अधिकार को उसमें निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

### मिस. हिंद स्टोन

89. मिस. हिंद स्टोन ओ मामले में, विचाराधीन प्रश्न तमिलनाडु लघु खनिज अनुदान नियम, 1959 के नियम 8-सी की वैधता के बारे में था, जो काले ग्रेनाइट के लिए खदानों के पट्टे सरकार की निगम या स्वयं सरकार को प्रदान करता था और यह कि 7 दिसंबर, 1977 से काले ग्रेनाइट की खनन के लिए किसी भी निजी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह मामला पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन से उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने सूची II की प्रविष्टि 23 और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 और इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार किया। न्यायालय ने खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों तथा 1957 अधिनियम की योजना के संबंध में निम्नलिखित सामान्य टिप्पणियाँ कीं:

"6. नदियाँ, वन, खनिज और अन्य संसाधन एक राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति का गठन करते हैं। इन संसाधनों को किसी एक पीढ़ी द्वारा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह सभी अगली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण सर्वोत्तम संभव तरीके से करे। यह मानवता के हित में है। यह राष्ट्र के हित में है। इसे संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है। संसद ने यह घोषित किया है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ खदानों का विनियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में ले। इसने खनन और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 को लागू किया है। हमने पहले ही इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया है। धारा 18, जैसा कि हमने देखा है, भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का विशेष कर्तव्य केंद्रीय सरकार पर डालती है। धारा 17 केंद्रीय सरकार को किसी भी क्षेत्र में अन्वेषण या खनन संचालन करने का अधिकार देती है, जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं हैं। धारा 4-ए राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर, लघु खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के मामले में,

मौजूदा खनन पट्टों को समय से पहले समाप्त करने और सरकारी कंपनी या निगम के पक्ष में नए पट्टे देने का अधिकार देती है, यदि ऐसा करना खदानों के विनियमन और खनिज विकास के हित में आवश्यक हो। लघु खनिजों के मामले में, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद समान रूप से यह अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक हित जो संसद को 1957 अधिनियम की धारा 2 में किए गए उद्घोषणा को बनाने के लिए प्रेरित करता है, स्वाभाविक रूप से खदानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च विचार होना चाहिए। संसद की नीति अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। यह खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण तथा विवेकशील दोहन है, ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। नियम बनाने वाली अधीनस्थ प्राधिकरण को नियम बनाने में मार्गदर्शन करने वाले स्पष्ट संकेत हैं। अधिनियम की अन्य धाराओं द्वारा दी गई रोशनी में, विशेष रूप से धाराएँ 4-ए, 17 और 18, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 15 के तहत नियम बनाने वाली प्राधिकरण ने काले ग्रेनाइट की खदानों के पट्टे निजी पक्षों को देने पर प्रतिबंध लगाकर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है और यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकार स्वयं काले ग्रेनाइट की खदानें कर सकती है या किसी निगम को काले ग्रेनाइट की खदानें देने का पट्टा दे सकती है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व में हो। इस तरह का नियम जो अधीनस्थ विधायी निकाय द्वारा बनाया गया हो उसे केवल इसलिए लाभकारी समझना कि राज्य सरकार उसी अधीनस्थ विधायी निकाय है, उस निकाय की कार्यप्रणाली पर बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण लेना होगा ..... "

90. न्यायालय ने फिर तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर प्रतिवाद हलफनामे में किए गए बयान की रोशनी में नियम 8-सी पर विचार किया और यह कहा गया कि नियम 8-सी राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का ईमानदारी से प्रयोग करते हुए बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुच्छेद 10 में न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"10. हमारे सामने रखी गई एक तर्क यह थी कि खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 15 ने खनन पट्टों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया था न कि उन्हें प्रतिबंधित करने का जैसा कि नियम 8-सी करना चाहता था, और इसलिए नियम 8-सी धारा 15 से परे था। इस विषय पर प्रसिद्ध मामले जैसे कि *नगर निगम टोरंटो बनाम विर्गो* [1896 एसी 88] और *अटॉर्नी जनरल फॉर ऑंटारियो बनाम अटॉर्नी जनरल फॉर डोमिनियन्स* [1896 एसी 348] से लेकर *उत्तर प्रदेश बनाम हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* [1979 (3) एससीसी 229] तक हमारे ध्यान में लाए गए थे। हमें नहीं लगता कि "विनियमन" का अर्थ इतना कठोर होना चाहिए कि कभी भी "प्रतिबंध" को शामिल न करे। बहुत कुछ उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इस शब्द का प्रयोग अधिनियम में किया गया है और उस विनियमन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति मैथ्यू ने *जी.के. कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य* [1975 (1) एससीसी 375] में कहा: "शब्द 'विनियमन' का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ उस चीज़ की प्रकृति के अनुसार भिन्न होता है जिस पर इसे लागू किया जाता है।" आधुनिक अधिनियम जो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित हैं, "विनियमन" को

आवश्यक रूप से इतना व्यापक अर्थ देना चाहिए कि कुछ स्थितियों में इसे निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र तक प्रतिस्पर्धा को बाहर करना चाहिए। विशेष रूप से कल्याणकारी राज्य में ऐसा होना चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने *कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स* [1950 एसी 235] में इस बात पर प्रकाश डाला और हम इससे सहमत हैं - कि यह समस्या कि क्या कोई अधिनियम विनियामक था या कुछ अधिक था या कोई प्रतिबंध सीधा था या केवल दूरस्थ या केवल सहायक था, इसमें कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचार शामिल थे और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार करना ताकि एकाधिकार बनाया जा सके, चाहे वह राज्य हो या कॉमनवेल्थ एजेंसी, उचित ठहराया जा सके। प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों और समय तथा परिस्थितियों की सेटिंग में मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कुछ चरणों में राज्य एकाधिकार बनाने हेतु प्रतिबंध लगाना ही विनियमन का एकमात्र व्यावहारिक और उचित तरीका हो। जिस अधिनियम पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह खनिजों का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण तथा विवेकशील दोहन करने हेतु लक्षित है जैसा कि हमने पहले ही कई बार कहा है। निश्चित रूप से, जब कोई दुर्लभ खनिज हो तो राज्य या उसके एजेंसी द्वारा दोहन करने की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा दोहन पर प्रतिबंध लगाना संरक्षण एवं विवेकपूर्ण दोहन का सबसे प्रभावी तरीका होता है। यदि आप भविष्य के लिए संरक्षण करना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में प्रतिबंधित करना होगा। हमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलों में पट्टों पर प्रतिबंध लगाना अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रस्तावित विनियमन का हिस्सा है।"

### डी.के. त्रिवेदी एंड संस

91. डी.के. त्रिवेदी एंड संस में, इस न्यायालय का ध्यान 1957 अधिनियम की धारा 15(1) की संवैधानिक वैधता पर था; राज्य सरकारों की उस धारा के तहत नियम बनाने की शक्ति ताकि वे मृत किराया और रॉयल्टी चार्ज कर सकें जो उन्होंने छोटे खनिजों के पट्टों के संबंध में दिया है और ऐसे पट्टे के दौरान मृत किराया और रॉयल्टी की दरों को बढ़ा सकें। गुजरात छोटे खनिज नियम, 1966 के नियम 21-बी की वैधता और गुजरात सरकार द्वारा धारा 15 के तहत जारी कुछ अधिसूचनाओं को भी देखा गया, जो रॉयल्टी और मृत किराया की दरों को बढ़ाने के लिए उन नियमों में संशोधन करती हैं। न्यायालय ने अधिनियम के विधायी इतिहास का पता लगाया; बैजनाथ केडिया का उल्लेख किया और रिपोर्ट पृष्ठ (46-47) के अनुच्छेद 27 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"27. 1957 का अधिनियम संघ सूची में प्रविष्टि 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया है। उक्त प्रविष्टि 54 और राज्य सूची में प्रविष्टि 23 को इस न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा बैजनाथ केडिया बनाम बिहार राज्य में व्याख्यायित किया गया। उस मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि संघ सूची में प्रविष्टि 54 खानों के नियमन और खनिज विकास दोनों की बात करता है और राज्य सूची में प्रविष्टि 23 प्रविष्टि 54 के अधीन है। प्रविष्टि 54 के तहत, संसद को यह घोषित करने का अधिकार है कि इन मामलों में नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास होना चाहिए। इस प्रकार की घोषणा कितनी दूर तक जा सकती है, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाना

चाहिए और यह जनता के हित के साथ संगत होना चाहिए, लेकिन एक बार जब ऐसी घोषणा की जाती है और उस नियमन और विकास की सीमा निर्धारित होती है, तो उस सीमा तक विधायी विषय संसद द्वारा विशेष रूप से विधायी विषय बन जाता है। ऐसी घोषणा के बाद राज्य द्वारा कोई भी विधायी कार्य जो उस क्षेत्र को छूता है, अनिवार्य रूप से असंवैधानिक होगा क्योंकि वह क्षेत्र राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता से निकाला गया है। उस मामले में न्यायालय ने आगे यह भी बताया कि संघ सूची में प्रविष्टि 54 और राज्य सूची में प्रविष्टि 23 में "संघ के नियंत्रण में" शब्द का अर्थ "संघ सरकार का नियंत्रण" नहीं है क्योंकि संघ तीन अंगों, अर्थात् संसद, संघ सरकार और संघ न्यायपालिका से मिलकर बना है, और संघ का नियंत्रण जो इन दोनों प्रविष्टियों के तहत प्रयोग किया जाना है, वह संसद द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण है, अर्थात् संघ का विधायी अंग। न्यायालय ने आगे कहा कि संघ ने छोटे खनिजों के संबंध में सभी शक्तियों को अपने पास ले लिया है और राज्य सरकारों को पट्टों के नियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है और इस प्रकार धारा 2 में की गई घोषणा और धारा 15 के अधिनियमित होने से छोटे खनिजों से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र संसद की अधिकारिता में आ गया और राज्य विधानसभाओं को इसके संबंध में कोई अधिनियम बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति देकर संघ का नियंत्रण नकारा नहीं गया, बल्कि इसके विपरीत, यह स्थापित किया गया कि संघ नियंत्रण का प्रयोग कर रहा था। उस मामले में उठाए गए एक तर्क में यह कहा गया था कि धारा 15 असंवैधानिक है क्योंकि इसमें नियम बनाने वाली प्राधिकरण को दी गई विधायी शक्ति अत्यधिक थी। हालांकि, इस तर्क को न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया क्योंकि उस मामले में अपीलें अन्य बिंदुओं पर स्वीकार की गई थीं।"

जब 'नियमन' शब्द के अर्थ, विशेष रूप से 'नियमन करने की क्रिया, या नियमन की स्थिति' और संघ सूची में प्रविष्टि 54 पर विचार किया गया, तो इस न्यायालय ने रिपोर्ट के अनुच्छेद 31 में निम्नलिखित कहा:

"31. संघ सूची में प्रविष्टि 54 में 'नियमन' शब्द का उपयोग किया गया है। 'नियमन' को शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, 3री संस्करण में 'नियमन करने की क्रिया, या नियमन की स्थिति' के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रविष्टि 54 भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संघीय विधायी सूची की प्रविष्टि 36 की भाषा को पुनः प्रस्तुत करता है, जिसमें 'और तेल क्षेत्र' शब्दों को छोड़ दिया गया है। जब संविधान को लागू किया गया, तो संविधान के निर्माताओं को पता था कि प्रारंभिक दिनों से खनिजों और खानों का नियमन स्थानीय सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जा रहा था। उन्हें यह भी पता था कि संघीय विधायी सूची में संबंधित प्रविष्टि 36 के तहत 1948 का अधिनियम लागू किया गया था और वह वैधानिक पुस्तक पर था और कि 1948 का अधिनियम केंद्रीय सरकार को खनन पट्टों के अनुदान और खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए व्यापक नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता था। उन्हें यह भी ज्ञात था कि ऐसी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने खनिज अनुदान नियम, 1949 बनाए थे, और कि उक्त नियमों के नियम 4 द्वारा छोटे खनिजों का निष्कर्षण प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा नियोजित किया गया था। इस प्रकार, संविधान के

निर्माताओं को न केवल खानों और खनिजों के विषय की विधायी इतिहास की जानकारी थी बल्कि उन्हें यह भी पता था कि डोमिनियन विधानमंडल ने 1948 के अधिनियम को लागू करते समय संघीय विधायी सूची में प्रविष्टि 36 की व्याख्या कैसे की थी। जब 1957 का अधिनियम लागू हुआ, तो संसद को पता था कि विभिन्न राज्य सरकारों ने खनिज अनुदान नियम, 1949 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार छोटे खनिजों के संबंध में पट्टों के अनुदान को नियंत्रित करने और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए नियम बनाए थे और इस कारण से इसने स्पष्ट रूप से 1957 के अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में यह प्रावधान किया कि उस अधिनियम की शुरुआत से पहले प्रभावी नियम तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि धारा 15 की उपधारा (1) के तहत बनाए गए नियमों द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। इसलिए, छोटे खनिजों के संबंध में खनन पट्टों का अनुदान नियंत्रित करना और अन्य संबंधित मामलों का नियमन ऐसा कुछ नहीं था जो पहली बार 1957 के अधिनियम द्वारा किया गया हो, बल्कि यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत विधायी प्रथा का पालन करता था। वास्तव में, छोटे खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में संसद ने जो किया, जैसा कि पहले बताया गया है, वह यह था कि उसने 1957 के अधिनियम में कुछ प्रावधानों को स्थानांतरित कर दिया जो तब तक केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति के तहत निपटाए गए थे ताकि अधीनस्थ विधान की सीमा को प्रतिबंधित किया जा सके ....."

फिर रिपोर्ट के अनुच्छेद 33 में (पृष्ठ 50-51), न्यायालय ने 1957 अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के संदर्भ में आगे कहा:

"33 ..... धारा 13 की उपधारा (2) के उद्घाटन वाक्य, अर्थात् 'विशेष रूप से, और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता को प्रभावित किए बिना', यह स्पष्ट करता है कि उस उपधारा में निर्धारित विषय पहले से ही उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्ति में शामिल हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। केंद्रीय सरकार उपधारा (2) के तहत नियम बना सकती है, इसलिए उन विशेष मामलों में भी केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है जिनके संबंध में राज्य सरकारें धारा 15 की उपधारा (1) के तहत 'छोटे खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों के अनुदान को नियंत्रित करने और इससे जुड़े उद्देश्यों' के लिए नियम बना सकती हैं। जब धारा 14 निर्देश देती है कि 'धारा 4 से 13 (समावेशी) के प्रावधान छोटे खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों पर लागू नहीं होंगे', तो इसका तात्पर्य यह है कि उन धाराओं में निहित मामले, जहां तक वे छोटे खनिजों से संबंधित हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके नियंत्रित किए जाएंगे। धाराएँ 4 से 12 'खोज और खनन संचालन करने पर सामान्य प्रतिबंध' के शीर्षक के तहत एक समूह बनाती हैं। इन धाराओं का छोटे खनिजों पर अनुप्रयोग का बहिष्कार यह दर्शाता है कि ये प्रतिबंध छोटे खनिजों पर लागू नहीं होंगे, बल्कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे धारा 15(1) के तहत बनाए गए नियमों द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे प्रतिबंध निर्धारित करें। छोटे खनिजों को अन्य

खनिजों से अलग तरीके से मानने का कारण स्पष्ट है। जैसा कि धारा 3 के उपधारा (e) में दिए गए छोटे खनिजों की परिभाषा से देखा गया है, ये ऐसे खनिज हैं जो मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों और स्थानीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि अन्य खनिज वे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास और देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि छोटे खनिजों से संबंधित मामलों को संसद ने राज्य सरकारों को सौंपा है जबकि अन्य खनिजों से संबंधित मामलों को केंद्रीय सरकार के पास रखा गया है। धाराएँ 13, 14 और 15 उन धाराओं के समूह में आती हैं जिसका शीर्षक 'खोज लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियम' है। इन तीन धाराओं को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह प्रदान करते हुए कि धारा 13 छोटे खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों पर लागू नहीं होगी, इसका तात्पर्य यह था कि केंद्रीय सरकार से छोटे खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति को हटा लिया गया और धारा 15(1) द्वारा वह शक्ति राज्य सरकारों को सौंपी गई। हालांकि, धारा 13 और धारा 15 के तहत शक्ति का दायरा समान है, केवल अंतर यह है कि एक मामले में केंद्रीय सरकार अन्य खनिजों के संबंध में शक्ति का प्रयोग करती है जबकि दूसरे मामले में राज्य सरकारें छोटे खनिजों के संबंध में ऐसा करती हैं। धारा 13 की उपधारा (2), जो धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है, राज्य सरकारों को धारा 15(1) के तहत नियम बनाने में पालन करने हेतु पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करती है, और उसी तरह, राज्य सरकारें अपने नियम बनाने के दौरान धाराएँ 4 से 12 में निर्धारित प्रतिबंधों और अन्य मामलों का ध्यान रखती हैं।"

## जनक लाल

92. जनक लाल में, इस न्यायालय को 1960 के नियमों के नियम 59 के अर्थ और दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। न्यायालय ने नियम 59 पर विचार किया, जैसा कि 1963 में संशोधन से पहले था, और संशोधन के बाद का प्रावधान। रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 में (पृष्ठ 123) न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"6. पहले 'किसी उद्देश्य के लिए आरक्षित' शब्दों के बाद 'खनिजों के लिए खोज या खनन के अलावा' शब्द थे, जिन्हें 1963 में एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। श्री ढोलकिया, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता, जो विवादित निर्णय का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुए, ने तर्क किया कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप यह अभिव्यक्ति अब खनिजों के लिए खोज या खनन के मामलों तक सीमित होनी चाहिए और सभी अन्य मामलों जहां पहले आरक्षण कृषि, औद्योगिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए था, को नियम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। हम सुझाए गए व्याख्या को स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं हैं। पहले एकमात्र श्रेणी जो नियम 59 की लागूता से बाहर थी, वह थी खोज या खनन पट्टे और संशोधन का प्रभाव यह है कि इस अपवाद को हटाकर, खोज और खनन पट्टे को भी अन्य मामलों के समान स्थिति में रखा गया है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि क्यों नियम में खोज और खनन पट्टों को शामिल करने से पहले जिन अन्य मामलों पर यह लागू होता था, वे बाहर हो जाएं। संशोधन का परिणाम नियम

का विस्तार करना है न कि इसके संचालन के क्षेत्र को कम करना। 'किसी उद्देश्य' शब्द का व्यापक अर्थ है और इसके अर्थ को सीमित करने का कोई कारण नहीं है।" न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1963 में संशोधन का उद्देश्य नियम का विस्तार करना था न कि इसके संचालन के क्षेत्र को कम करना।

### भारत कोकिंग कोल

93. भारत कोकिंग कोल के मामले में, न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल के पास खानों और खनिज विकास के नियमन के लिए कानून बनाने की क्षमता है, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के तहत है, लेकिन यह शक्ति संसद द्वारा कानून द्वारा की गई घोषणा के अधीन है, जैसा कि संघ सूची की प्रविष्टि 54 में परिकल्पित किया गया है। यह कहा गया कि खानों और खनिजों के विषय पर राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता संसद की विधायी शक्ति के अधीन है। धारा 18(1) पर विचार करते हुए, इसके संशोधन से पहले और संशोधन के बाद, न्यायालय ने रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 में (पृष्ठ 572) निम्नलिखित कहा:

"16 ..... संशोधित और अप्रवर्तित धाराएँ दोनों यह निर्धारित करती हैं कि केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह 'भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास' के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए और इस उद्देश्य के लिए वह ऐसे नियम बना सकती हैं जो उसे उचित लगें। धारा 18(1) के तहत 'खनिजों के संरक्षण' का अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार को किसी भी नियम को बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है जो खनिजों को हानि से बचाने और उसके संरक्षण के लिए आवश्यक हो। 'संरक्षण' का अभिव्यक्ति का अर्थ है 'हानि या चोट से रखने या बचाने की क्रिया'। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, इस अभिव्यक्ति का अर्थ खनिजों का संरक्षण है; 'खनिजों के संरक्षण' की व्यापकता उस नियम को समाहित करती है जो कोयले की खदानों के अपशिष्ट द्वारा कोयले की हानि को रोकने के उद्देश्य से उचित रूप से संबंधित हो, ऐसा नियम स्लरी के निर्वहन या पानी की सामग्री सोखने के बाद कोयले के कणों का संग्रह भी नियंत्रित कर सकता है। खनिजों के संरक्षण के लिए नियम बनाने की सामान्य शक्ति के अलावा, ....."

न्यायालय ने रिपोर्ट के अनुच्छेद 19 में (पृष्ठ 575-576) आगे कहा:

"..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूची II की प्रविष्टि 23 के तहत, राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सूची I की प्रविष्टि 54 के अधीन है, जो खानों और खनिजों के नियमन और विकास से संबंधित है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, राज्य विधानमंडल को सूची I की प्रविष्टि 54 और अधिनियम की धारा 2 के तहत किए गए संसदीय घोषणा के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है। चूंकि राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति सूची II की प्रविष्टि 23 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संसदीय घोषणा द्वारा ले ली गई है, इसलिए राज्य सरकार को खानों और खनिज विकास के नियमन से संबंधित मामलों में कोई कार्यकारी शक्ति नहीं रह गई। इसके अलावा, अनुच्छेद 162 का उपबंध स्वयं राज्य के कार्यकारी शक्ति के प्रयोग पर सीमा निर्धारित करता है। यह निर्धारित करता है

कि किसी भी मामले में जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल और संसद कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, राज्य का कार्यकारी शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा संघ या उसके प्राधिकरण पर स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति की सीमाओं के अधीन होगा ....."

### ओडिशा सीमेंट लिमिटेड

94. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ओडिशा सीमेंट लिमिटेड के मामले में बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा खनन भूमि से प्राप्त रॉयल्टी के आधार पर एक उपकर के लेवी की वैधता पर विचार किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इसी तरह की लेवी को इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में निरस्त कर दिया था। दूसरी ओर, राज्यों का तर्क था कि यह मुद्दा इंडिया सीमेंट लिमिटेड से भिन्न था क्योंकि इन राज्यों द्वारा लगाए गए उपकरों की प्रकृति और चरित्र तमिलनाडु के उपकर से भिन्न था। पीठ ने संघ सूची की प्रविष्टियाँ 52 और 54 और राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 18, 23, 45, 49, 50 और 66 पर विचार किया और इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भी विचार किया, जैसे कि *एचआरएस मूर्ति बनाम कलेक्टर चित्तूर एलएल, हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी, ईश्वरि खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड, बैजनाथ केडिया, एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ और अन्य एमएम , मिस. हिंद स्टोन, आई.टी.सी. और अन्य बनाम राज्य कर्नाटका और अन्य एनएन तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा और अन्य ओओ*। मैं रिपोर्ट के अनुच्छेद 49, 50, 51 और 53 (पृष्ठ 480-486) का उल्लेख करूंगा जो निम्नलिखित हैं:

"49. ऊपर उल्लेखित निर्णयों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हमारे सामने प्रश्न का उत्तर एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 के दायरे की उचित समझ और इसके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में विवादित राज्य विधान के द्वारा किए गए अतिक्रमण का आकलन करने पर निर्भर करता है। ऊपर उल्लेखित प्रत्येक मामले का निर्णय दोनों विधियों के संबंधित क्षेत्रों के ऐसे ही मूल्यांकन पर आधारित था। जैसा कि ईश्वरि खेतान में बताया गया है, संसद के कानून की केवल घोषणा कि यह उद्योग या खानों और खनिजों के नियमन और विकास के लिए संघ के नियंत्रण में होना आवश्यक है, प्रविष्टि 52 या प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानसभाओं को सूची II या सूची III में कई प्रविष्टियों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के संबंध में उनकी विधायी शक्तियों से वंचित नहीं करती है। विशेष रूप से, प्रविष्टि 54 के तहत एक घोषणा के मामले में, यह विधायी शक्ति केवल उस सीमा तक कम होती है जब संघ उस घोषणा के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है, जैसा कि उस विधायी अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है जो घोषणा करता है।

एलएल एआईआर (1965) एससी 177.

एमएम. (1979) 3 सेक 431.

एनएन. 1985 (सप) एससीसी 476.

ओओ. 1982 (1) सेक 125.

कमी की मात्रा उस अधिनियम के क्षेत्र पर निर्भर करती है जो उस घोषणा के अनुपालन में तैयार किया गया है। जब हिंगिर-रामपुर और टुल्लोक में कानूनों को निषेध की परिधि में पाया गया, तो चन्नन मल, ईश्वरि खेतान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स में कानून सामान्य प्रकृति के थे और राज्य सूची में विशिष्ट प्रविष्टियों से जुड़े थे और केंद्रीय अधिनियम के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते थे सिवाय इसके कि आकस्मिक प्रभाव द्वारा। चन्नन मल में विचारित केंद्रीय अधिनियम ने ऐसे राज्य विधान की अनुमति दी प्रतीत होती है।"

"50. उन दोनों विधियों के संबंधित क्षेत्रों पर लौटते हुए, हम जिस केंद्रीय अधिनियम (एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957) की बात कर रहे हैं, वह खानों और खनिज विकास के मामले में संघ नियंत्रण के क्षेत्र को सीमांकित करता है। जबकि यह खनिजों की खोज और शोषण के लिए लाइसेंस और पट्टों के अनुदान से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में सामान्य रूप से संबंधित है, इसमें कुछ प्रावधान शामिल हैं जो हमारे सामने मुद्दे के लिए सीधे प्रासंगिक हैं। धारा 9, जो रॉयल्टी के विषय पर है और न केवल मात्रा बल्कि इसके बढ़ाने पर भी सीमाएँ निर्दिष्ट करती है, पहले ही देखी जा चुकी है। धारा 9ए मृत किराए के संबंध में एक समान प्रावधान बनाती है।

51. यदि कोई उपरोक्त प्रावधानों को देखता है और ध्यान में रखता है कि संसद के अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का आकलन करते समय, किसी को (जैसा कि हिंगिर-रामपुर और टुल्लोक में निर्धारित किया गया है) केवल केंद्रीय अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के वास्तविक प्रावधानों द्वारा नहीं बल्कि उन मामलों और पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्हें वैध रूप से उक्त अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है, तो निष्कर्ष अनिवार्य प्रतीत होता है, विशेष रूप से हिंगिर-रामपुर और टुल्लोक के संदर्भ में, कि राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में अतिक्रमण कर चुका है। केंद्रीय अधिनियम के क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण की प्रकृति अन्य मामलों में भिन्न थी। वर्तमान विधायी प्रावधान, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 23 या प्रविष्टि 50 के तहत विधायी शक्ति से संबंधित हैं, जो प्रविष्टि 54 के तहत संसदीय घोषणा द्वारा प्रभावित हुई हैं, भूमि अधिग्रहण या नगरपालिका प्रशासन के कानूनों के बराबर नहीं हो सकते जो उल्लेखित मामलों में विचार किए गए थे और जो सूची II या सूची III में विभिन्न विशिष्ट प्रविष्टियों से जुड़े थे।

53. ये टिप्पणियाँ एक ओर यह स्थापित करती हैं कि खनिज विकास और खनिज क्षेत्र विकास के बीच जो अंतर बनाया गया है वह वास्तविक नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार का विकास आपस में जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर, जिस प्रकार की फीस हम चर्चा कर रहे हैं वह केंद्रीय अधिनियम की धाराओं के दायरे में पूरी तरह से आती है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 का उद्देश्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय अधिनियम की धारा 13 की पूर्ववर्ती धाराएँ संघ को सड़कों और पर्यावरण से संबंधित मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देती हैं। धारा 18(1) केंद्रीय सरकार को भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का अधिकार देती है। ये, वस्तुतः, केवल खानों में ऐसी सुविधाओं का अर्थ नहीं रखती

बल्कि खानों तक पहुँचने वाले क्षेत्रों और चारों ओर भी शामिल करती हैं। खनिज क्षेत्रों का विकास इनमें निहित है। धारा 25 स्पष्ट रूप से अधिनियम और नियमों के तहत किराया, रॉयल्टी, कर और शुल्क लगाने की अनुमति देती है। इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है। समग्र रूप से पढ़े जाने पर, प्रविष्टि 54 और एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 द्वारा परिकल्पित संघ नियंत्रण का उद्देश्य खानों और खनिज क्षेत्रों का उचित विकास करना और साथ ही रॉयल्टी के मामले में अनुसूची 1 में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में देश भर में एकरूपता लाना है, और परिणामस्वरूप कीमतें ..... "

### भारत धातु और फेरो मिश्र धातु लिमिटेड

95. भारत धातु और फेरो मिश्र धातु लिमिटेड के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को यह मुख्य प्रश्न विचार करने का अवसर मिला कि क्या याचिकाकर्ता वहां क्रोम खनन के लिए पट्टे प्राप्त करने के हकदार थे। मुख्य प्रश्न और अन्य सहायक प्रश्नों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने सूची 1 की प्रविष्टि 54, सूची II की प्रविष्टि 23, 1957 अधिनियम, विशेष रूप से, इसकी धाराएँ 2, 4, 10, 11, 17ए और 19 तथा 1960 के नियमों जिनमें नियम 58, 59 और 60 शामिल हैं, पर विचार किया। राज्य सरकार की आरक्षण नीति पर विचार करते हुए जिसमें क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्रों में शोषण के लिए आरक्षित किया गया था, न्यायालय ने अनुच्छेद 39 और 40 (पृष्ठ 133) में निम्नलिखित कहा:

"39. ओआरआईएनडी और अन्य निजी पक्षों को कोई पट्टा प्राप्त करने में मुख्य बाधा एस.जी, ओएमसी और आईडीसीओएल द्वारा उत्पन्न की गई थी। उन्होंने दावा किया कि किसी भी निजी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी संबंधित जिलों में पूरा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित है जैसा कि पहले उल्लेखित अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त, 1977 द्वारा है। इसलिए सभी निजी पक्षों ने एस.जी, ओएमसी और आईडीसीओएल द्वारा किए गए आरक्षण के मामले को लड़ने के लिए हाथ मिलाए हैं। हमने पहले ही संकेत दिया है कि एस.जी ने राव रिपोर्ट को स्वीकार करने की अपनी तत्परता व्यक्त की थी और इस हद तक आरक्षण का दावा छोड़ने का निर्णय लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ओएमसी और आईडीसीओएल ने यहां एक चेतावनी दी है और दावा किया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में एस.जी के रुख से स्वतंत्र रूप से यह दावा कर सकते हैं कि पट्टे केवल उन्हें दिए जाने चाहिए और राव रिपोर्ट जो आईएमएफए, एफएसीओआर और एआईकेएटीएच को पट्टे देने की सिफारिश करती है, हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए।"

40. अधिनियम और नियमों की प्रासंगिक धाराएँ पहले ही हमारे द्वारा निकाली गई हैं। पहले, नियम 58 ने राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए किसी क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को सक्षम नहीं किया था। ऐसी आरक्षण की शक्ति का अस्तित्व और वैधता *ए.कोटिया नायडू बनाम राज्य ए.पी.* (एआईआर 1959 एपी 485) और *अमृतलाल नाथुभाई शाह बनाम भारत सरकार* (एआईआर 1973 गुज. 117) में कायम रखी गई थी, जिसमें से बाद वाला इस न्यायालय द्वारा *अमृतलाल नाथुभाई शाह बनाम भारत सरकार* ([1977] 1 एससीआर 372) में

स्वीकृत किया गया। (जैसा कि पहले बताया गया है, नियम 58 को 1980 में संशोधित किया गया था ताकि राज्य सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान की जा सके।) यह भी विवाद में नहीं है कि आरक्षण का एक अधिसूचना 3 अगस्त, 1977 को जारी किया गया था। इसलिए, राज्य सरकार, ओएमसी और आईडीसीओएल यह कहने में सही हैं कि, स्पष्ट रूप से, प्रश्न में क्षेत्र किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं सिवाय राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की निगम के [नियम 59(1), उपबंध] जब तक कि कानून के अनुसार पुनः अधिसूचना नहीं की जाती [नियम 59(1)(ई)] या केंद्रीय सरकार नियम 59(1) के प्रावधानों को शिथिल करने का निर्णय नहीं लेती [नियम 59(2)]। इनमें से कोई भी स्थिति तब से नहीं हुई है सिवाय इसके जो इस निर्णय में आगे बताया गया है। इसलिए, एस.जी., ओएमसी और आईडीसीओएल द्वारा उठाए गए आरक्षण के निवेदन का कोई उत्तर नहीं है।

फिर अनुच्छेद 45 (पृष्ठ 136-138) में, जब हम 1987 में संशोधन द्वारा 1957 अधिनियम में डाले गए धारा 17ए (1) पर विचार कर रहे थे, न्यायालय ने कहा:

"45. हमारा निष्कर्ष कि हमारे सामने प्रश्न में क्षेत्र सभी सार्वजनिक क्षेत्र के शोषण के लिए उचित रूप से आरक्षित थे, इसका मतलब यह नहीं है कि निजी पक्षों को इन क्षेत्रों के संबंध में कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि, जैसा कि पहले बताया गया है, केंद्रीय सरकार आरक्षण को रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए शिथिल करने के लिए स्वतंत्र है। न ही इसका मतलब यह है, जैसा कि ओएमसी और आईडीसीओएल द्वारा कहा गया है, कि उन्हें उनके द्वारा मांगे गए पट्टे मिलेंगे। यह दो कारणों से है। पहले स्थान पर, आरक्षण सामान्य प्रकृति का है और ओएमसी और आईडीसीओएल पर सीधे अधिकार नहीं देता। यह आरक्षण दो प्रकार का है। धारा 17ए (1) के तहत, जिसे 1986 में डाला गया था, केंद्रीय सरकार एस.जी. से परामर्श करने के बाद किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है- जो एक निजी पट्टा या खनन पट्टा द्वारा कवर नहीं किया गया हो- किसी खनिज को संरक्षित करने के उद्देश्य से। स्पष्ट रूप से, ऐसे आरक्षण का विचार यह है कि इस क्षेत्र में खनिजों का शोषण बिल्कुल नहीं किया जाएगा, न ही निजी पक्षों द्वारा और न ही सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा। यह आवश्यक नहीं है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र जो आरक्षित किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र में शोषित किया जा सकता है क्योंकि हम यहां ऐसे आरक्षण के दायरे से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि 1986 के बाद एस.जी. के साथ परामर्श किए बिना धारा 17ए (1) के तहत कोई अधिसूचना नहीं दी गई थी। आरक्षण का दूसरा प्रकार नियम 58 में प्रदान किया गया था जिसे पहले ही इस निर्णय में निकाला गया है। यह आरक्षण एस.जी. द्वारा किया जा सकता था (केंद्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता के बिना) और इसका उद्देश्य व्यापक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करना था। अधिसूचना स्वयं उस सरकारी निगम या कंपनी को निर्दिष्ट कर सकती थी जो क्षेत्रों का शोषण करेगी या केवल सामान्य हो सकती थी, नियम की अपनी रेखाओं पर। नियम 59(1) के तहत, एक बार जब नियम 58 के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो उस तरह से आरक्षित क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक उप-नियम (इ) की

दो आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं: अर्थात् एक रजिस्टर में प्रविष्टि और एक गजट अधिसूचना कि क्षेत्र देने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मार्च 5, 1974 की अधिसूचना इन आवश्यकताओं का पालन करती थी लेकिन शायद इस प्रश्न पर जाना अनावश्यक होगा क्योंकि क्षेत्रों का आरक्षण फिर से 1977 में अधिसूचित किया गया था। ये अधिसूचनाएँ सामान्य हैं। वे केवल कहती हैं कि क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित किया गया है। क्या ऐसे क्षेत्रों को ओएमसी या आईडीसीओएल या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की निगम या सरकारी कंपनी को पट्टे पर दिया जाना चाहिए या इसे स्वयं सरकार द्वारा शोषित किया जाना चाहिए यह सरकार के लिए निर्धारित करना है कानून और नियमों से बाहर। इनमें से किसी भी चीज़ में ओएमसी या आईडीसीओएल को इस बात पर जोर देने का अधिकार नहीं दिया गया है कि पट्टे केवल उन्हें दिए जाने चाहिए और किसी और को नहीं सार्वजनिक क्षेत्र में। इसलिए यदि हम पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में 1977 में आरक्षण का दावा स्वीकार करते हैं, और यदि हम राव की खोजों से सहमत नहीं होते हैं कि न तो ओएमसी और न ही आईडीसीओएल किसी अनुदान के योग्य हैं, तो हम केवल एस.जी. को छोड़ सकते हैं ताकि वह विचार करे कि क्या उस तरह से आरक्षित भूमि का कोई हिस्सा इन दोनों निगमों को दिया जाना चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में एस.जी. या सी.जी. द्वारा नियंत्रित संगठनों से प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन नहीं हैं लेकिन यदि होते भी तो यह एस.जी. पर निर्भर करेगा कि वह कितनी दूर भूमि या उनमें से किसी भी हिस्से का शोषण प्रत्येक ऐसे निगम या सी.जी. या एस.जी. द्वारा करे। दोनों निगम स्पष्ट रूप से एस.जी. की संस्थाएँ हैं और एस.जी. का निर्णय उन पर बाध्यकारी होता है। हमारा मानना है कि यदि एस.जी. ने आरक्षित क्षेत्र के संबंध में किसी संस्थान को पट्टा देने का निर्णय नहीं लिया तो उस संस्थान को यह आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे एक खनन पट्टा दिया जाना चाहिए। एस.जी. को किसी भी समय राज्य या नियम में निर्दिष्ट किसी भी एक संस्थान का विकल्प चुनने का अधिकार है। यह सच है कि यदि अंततः एस.जी. ने उन भूमि पर उनमें से एक या अन्य को पट्टा देने का निर्णय लिया तो जिस संस्थान का आवेदन अस्वीकृत हुआ वह दूसरे द्वारा पट्टे के चयन से असंतुष्ट हो सकता है। विशेष रूप से जहाँ सी.जी. की एक संस्था और एस. जी. की एक संस्था या सी. जी. की संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो प्रश्न उठ सकता है कि असफल संस्था कितनी दूर तक एस.जी. द्वारा किए गए चयन को चुनौती दे सकती है। लेकिन हमें यहाँ इन विवादों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न जो हमें यहाँ चिंतित करता है वह यह है कि क्या ओएमसी या आईडीसीओएल किसी निजी पक्षों को दिए जाने वाले अनुदान पर आपत्ति कर सकते हैं इस आधार पर कि सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में एक आरक्षण किया गया था। हमें लगता है कि उत्तर नकारात्मक होना चाहिए कानून संबंधी प्रावधानों के दृष्टिकोण से। क्योंकि एस.जी. हमेशा आरक्षण को निराधारित कर सकता था और इसे निजी पक्षों को अनुदान देने के लिए उपलब्ध बना सकता था। या वास्तव में एक अधिसूचित क्षेत्र की निराधारणता किए बिना विशेष मामले में नियम 59(1) की सीमाओं को शिथिल करने हेतु सी.जी. को मनाने का प्रयास कर सकता था। इसलिए एस.जी. द्वारा जारी

अधिसूचना वाले क्षेत्रों के संबंध में निजी पट्टे देना खुला होता था और इसे सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी संस्था द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

1987 के केन्द्रीय अधिनियम 37 द्वारा 1957 के अधिनियम में संशोधन के बाद की कानूनी स्थिति को निम्नलिखित तरीके से समझाया गया (पैरा 46; पृष्ठ 138-139):

"46. इस बिंदु को छोड़ने से पहले, हम केवल 1986 के बाद की स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं। केन्द्रीय अधिनियम 37, 1986 ने उपधारा (2) डाली, जो राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने का अधिकार देती है। यह प्रावधान नियम 58 से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न है-

(i) आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है;

(ii) आरक्षण केवल उन क्षेत्रों का हो सकता है जो वास्तव में पीएल या एमएल के तहत नहीं रखे गए हैं;

(iii) आरक्षण केवल एक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र की निगम (जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित हो) द्वारा शोषण के लिए हो सकता है, न कि सरकार द्वारा।

स्पष्ट है कि धारा 17ए (2) और नियम 58 एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि धारा 17ए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के साथ आरक्षण करने का अधिकार देती है जबकि नियम 58 में ऐसी कोई रोक नहीं थी। उनके शब्दों में भी थोड़ी भिन्नता थी। शायद इसी कारण से नियम 58 को 1988 के संशोधन (जी.एस.आर. 449ई / 1988) द्वारा हटा दिया गया था, जो 13 अप्रैल, 1988 से प्रभावी हुआ। हालांकि, नियम 59 केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षण में छूट की कल्पना करता है।

1987 के संशोधन (जी.एस.आर. 86-ई / 87) के तहत नियम 59(1)(ई) में "राज्य सरकार द्वारा आरक्षित" शब्दों को "सरकार द्वारा आरक्षित" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया। बाद में, नियम 59(1) को धारा "या अधिनियम की धारा 17- ए के तहत" शब्दों को "नियम 58 के तहत" शब्दों के बाद जोड़कर संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप:

(i) मार्च 13, 1988 के बाद, निश्चित रूप से, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी आरक्षण की अधिसूचना नहीं दे सकती है, क्योंकि नियम 58 हटा दिया गया है। अनुमानतः, यह स्थिति इस तिथि से पहले भी समान थी और जैसे ही अधिनियम 37/1986 लागू हुआ।

(ii) हालांकि, राज्य सरकार के लिए यह खुला है कि वह नियम 58 या धारा 17ए के तहत किए गए किसी आरक्षण को निराधारित कर सकती है। अनुमानतः, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित क्षेत्र की निराधारणता केवल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही की जा सकती है क्योंकि यह असंगत होगा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो

लेकिन निराधारणता को नहीं। फिर भी, यह स्पष्ट है कि आरक्षित क्षेत्रों में छूट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा दी जा सकती है।

(iii) केवल केंद्रीय सरकार ही खनिजों को सामान्य रूप से संरक्षित करने के उद्देश्य से आरक्षण कर सकती है लेकिन यह एस.जी. की सहमति से किया जाना चाहिए।

### **धर्मबीर सिंह**

*धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य* पीपी मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 1957 अधिनियम की धारा 10(3) और 11(2) पर विचार करते हुए कहा कि राज्य की संपत्ति के खनन पट्टे के अनुदान में, राज्य सरकार को किसी भी आवेदक को संभावित लाइसेंस या लाइसेंस देने या न देने का विवेकाधिकार है। किसी भी आवेदक को राज्य के भीतर किसी स्थान पर खनन संचालन के लिए खनन पट्टे के अनुदान का कोई अधिकार नहीं है, और न ही कोई स्थापित अधिकार है। लेकिन, राज्य सरकार को कानून की आवश्यकताओं के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है।

### **भूपात्राई मगनलाल जोशी**

*भूपात्राई मगनलाल जोशी* मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ उच्च न्यायालय के निर्णय की सहीता पर विचार कर रही थी कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र में खनिज संसाधनों के शोषण के लिए भूमि का आरक्षण 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के तहत अनुमेष था। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया, जिससे मामला इस न्यायालय तक पहुँचा। इस न्यायालय ने एक बहुत संक्षिप्त आदेश में उच्च न्यायालय की तर्क और निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की।

### **एम.पी. राम मोहन राजा**

*एम.पी. राम मोहन राजा बनाम राज्य तमिलनाडु एवं अन्य* क्यूक्यू मामले में, इस न्यायालय ने एम/एस हिंद स्टोन के निर्णय पर भरोसा किया और दोहराया कि खनन और खनिज पट्टे के अनुदान के संबंध में किसी व्यक्ति का इसमें कोई स्थापित अधिकार नहीं है।

### **संदूर मैंगनीज और आयरन ऑर्स लिमिटेड**

संदूर मैंगनीज और आयरन ऑर्स लिमिटेड के हालिया निर्णय में, जिन विविध मुद्दों पर विचार किया गया, उन्हें रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 में नोट किया गया है। न्यायालय ने 1957 अधिनियम, 1960 नियमों और इस न्यायालय के निर्णयों जैसे *हिंजरारामपुर कोल कंपनी*, *एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी*, *बैजनाथ कडियोक*, *भारत कोकिंग कोल*; और कुछ अन्य निर्णयों में निहित वैधानिक प्रावधानों पर विचार किया, और यह देखा कि 1957 अधिनियम की धारा 2 के संदर्भ में राज्य विधानमंडल को खनिजों के विकास के संबंध में किसी भी कानून बनाने की वैधानिक शक्ति से वंचित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुच्छेद 61, 62 और 63 (पृष्ठ 30-31) में न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

पीपी 1996 (6) धारा 102.

क्यूक्यू. 2001 (9) धारा 78

"61. हमने जो कहा है, उसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 11(5) मुख्य प्रावधान धारा 11(2) में पूर्व आवेदकों के पक्ष में प्राथमिकता के लिए एक अपवाद फिर से बनाती है। यह राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, धारा 11(2) के मुख्य प्रावधान में समय की प्राथमिकता की अनदेखी करने और विशेष कारणों के लिए लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले एक बाद के आवेदक के पक्ष में अनुदान देने की अनुमति देती है। यह यह भी संकेत देती है कि इसका उन मामलों पर कोई आवेदन नहीं हो सकता जहां अधिसूचना जारी की गई हो क्योंकि, ऐसे मामलों में, धारा 11(2) के पहले उपबंध और धारा 11(4) स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि सभी आवेदनों पर एक ही तारीख को प्राप्त होने के रूप में विचार किया जाएगा। हमारे व्याख्या के अनुसार, मुख्यमंत्री की कार्यवाही और 06.12.2004 की सिफारिश एम.एम.डी.आर. अधिनियम की योजना के खिलाफ हैं क्योंकि वे धारा 11(5) पर आधारित थीं जो कि 15.03.2003 की अधिसूचना के अनुसार किए गए आवेदनों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती।

62. हमने पहले ही नियम 59 और 60 निकाले हैं और उन नियमों का विश्लेषण उपरोक्त धारा 11 की व्याख्या की पुष्टि करता है और इस निष्कर्ष को भी कि यह धारा 11(4) है जो नियम 59(1) के तहत जारी अधिसूचना पर लागू होगी। नियम 59(1) प्रदान करता है कि इसमें सूचीबद्ध क्षेत्रों की श्रेणियाँ, जिसमें अन्य बातों के अलावा, वे क्षेत्र शामिल हैं जो पहले खनन पट्टे के तहत रखे गए थे या जिनका राज्य सरकार द्वारा शोषण के लिए आरक्षण किया गया था या अधिनियम की धारा 17ए के तहत आरक्षित किया गया था, अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जब तक (i) रजिस्टर में एक प्रविष्टि नहीं की जाती है और (ii) इसकी उपलब्धता का अनुदान आधिकारिक गजट में अधिसूचित नहीं किया जाता है जिसमें अधिसूचना की तारीख से पहले 30 दिनों से अधिक का समय नहीं होता। नियम 59 का उप-नियम (2) केंद्रीय सरकार को नियम 59(1) में निर्धारित शर्तों को शिथिल करने का अधिकार देता है यदि किसी क्षेत्र की उपलब्धता को नियम 59 के तहत अधिसूचित किया जाना आवश्यक है और यदि कोई आवेदन जारी नहीं किया गया है या जहां अधिसूचना जारी की गई है, वहां नियम 59(1)(i) और (ii) के अनुसार अधिसूचना में निर्दिष्ट 30-दिनों का ब्लैक-आउट अवधि समाप्त नहीं हुआ है, तो इसे पूर्ववर्ती माना जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

63. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, धारा 11(4) नियम 59 और 60 के साथ संगत है जब यह केवल उन आवेदनों पर विचार करने का प्रावधान करती है जो एक अधिसूचना के अनुसार किए गए हैं। दूसरी ओर, अधिसूचना से पूर्व किए गए आवेदनों पर विचार करना, जैसा कि धारा 11(2) के पहले उपबंध द्वारा आवश्यक है, स्पष्ट रूप से नियम 59 और 60 के साथ असंगत है। ऐसे परिस्थितियों

में, धारा 11 को नियम 59 और 60 के साथ सामंजस्यपूर्ण पढ़ाई करने से यह अनिवार्य होता है कि अधिसूचनाएँ धारा 11(4) के तहत जारी की जाएँगी उन क्षेत्रों की श्रेणियों के मामले में जो नियम 59(1) द्वारा कवर किए गए हैं। इन परिस्थितियों में, हम जिंदल और कल्याणी के वरिष्ठ वकील द्वारा उन प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

अमृतलाल नाथुभाई शाह के अनुच्छेद 7 को रिपोर्ट के अनुच्छेद 65 में विचार किया गया और फिर अनुच्छेद 66 (पृष्ठ 32) में पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"66. इसके बाद भी, इस न्यायालय ने लगातार यह स्थिति अपनाई है कि अधिसूचना से पूर्व किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता। हमारे विचार में, नियम 59(1) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन पट्टे के क्षेत्र राज्य सरकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनकी पसंद के अनुसार सामान्य जनता को बिना सूचना दिए न दिए जाएं, अन्यथा इसका उल्लंघन होगा। वास्तव में, एकल न्यायाधीश ने धारा 11 की व्याख्या को सही रूप से नियम 59 और 60 के साथ पढ़ा। उक्त निष्कर्ष को इस न्यायालय के निर्णय राज्य तमिलनाडु बनाम हिंदस्टोन (1981) 2 एससीसी बी 205 पृष्ठ 218 में भी समर्थन मिला है, जहां यह कहा गया है कि एम.एम.डी.आर. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में एक वैधानिक नियम, जबकि मूल अधिनियम के अधीन होता है, फिर भी इसे अधिनियम का हिस्सा माना जाना चाहिए और यह प्रभावी होता है। यही स्थिति राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबू राम उपाध्याय (1961) 2 एससीआर 679 पृष्ठ 701 और गुजरात प्रदेश पंचायत परिषद बनाम राज्य गुजरात (2007) 1 सेक 718 में भी दोहराई गई है।"

राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ सूची II के प्रविष्टि 23 के तहत, न्यायालय ने संदूर मैंगनीज और आयरन ऑर्स लिमिटेड मामले में अनुच्छेद 80 (पृष्ठ 36) में निम्नलिखित कहा:

"80. यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार पूरी तरह से संसद का प्रतिनिधि और एक वैधानिक कार्यकारी है, इसलिए यह धारा 11(3) के तहत खनन पट्टों के अनुदान में एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधानों के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2 स्पष्ट रूप से कहती है कि खानों और खनिज विकास का नियमन संघ सरकार के दायरे में आता है न कि राज्य सरकार के। वास्तव में, उत्तरदाताओं ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम या एम.सी. नियमों में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं बताया जो पिछले प्रतिबद्धताओं के आधार पर खनन पट्टे का अनुदान देने की अनुमति देता हो। जैसा कि सही ढंग से बताया

गया है, राज्य सरकार को एम.एम.डी.आर. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को यह प्रतिबद्धता करने का अधिकार नहीं है कि वह भविष्य में किसी परियोजना में निवेश करने पर उसे खनन पट्टा देगी। मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता की है, तो उसके लिए असंगत स्थिति लेना और विशेष क्षेत्र की अधिसूचना करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, एक बार क्षेत्र की अधिसूचना करने के बाद, राज्य सरकार निश्चित रूप से किसी अन्य आवेदक को बाहर करके कथित प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर सकती, भले ही वे धारा 11(3) में निर्धारित मेरिट मानदंडों पर अधिक योग्य हों।"

### **क्या 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ अधिकार से परे (अल्ट्रा वायर्स) हैं?**

100. अब, उपरोक्त के प्रकाश में, मुझे यह विचार करना है कि क्या 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ, जो पूर्व बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थीं, सार्वजनिक जानकारी के लिए सूचित करते हुए कि विषय क्षेत्र में लौह अयस्क का शोषण सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित है, अल्ट्रा वायर्स हैं और 1957 अधिनियम और 1960 नियमों से बाहर हैं।

### **खनिजों और खानों के संबंध में कानून बनाने के लिए संवैधानिक दर्शन**

101. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची में सूची I (संघीय सूची) में प्रविष्टि 36 और सूची II (प्रांतीय सूची) में प्रविष्टि 23 हमारे संविधान में सूची I (संघ सूची) में प्रविष्टि 54 और सूची II (राज्य सूची) में प्रविष्टि 23 के अनुरूप हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त प्रविष्टियों के संबंध में भारत सरकार विधेयक पर बहस के दौरान, हाउस ऑफ कॉमन्स में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 'खननों का नियमन' और 'खनिजों का विकास' को केवल उस हद तक शामिल करने का तर्क था जब इसे संघीय कानून द्वारा सार्वजनिक हित में उचित माना गया, ताकि प्रांतों को खानों और खनिजों से संबंधित कानून से पूरी तरह से बाहर न रखा जाए और यदि केंद्र में निष्क्रियता हो, तो प्रांत अपने स्वयं के कानून बना सके। इस प्रकार, खानों और खनिजों के संबंध में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों दोनों को दी गईं। यही दर्शन हमारे संविधान में भी परिलक्षित होता है। खनिज संसाधनों का प्रबंधन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों के पास प्रविष्टि 54 (सूची I) और प्रविष्टि 23 (सूची II) के संदर्भ में छोड़ा गया है। हमारे संविधान की योजना के अनुसार, राज्य विधानसभाओं को 'खनन और खनिज विकास' के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानसभाओं पर केवल एक बंधन लगाया गया है, जो कहता है 'संघ के नियंत्रण के तहत नियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन'। दूसरे शब्दों में, राज्य विधानमंडल अपनी अधिकारिता खो देता है जब तक कि संघ सरकार ने नियंत्रण ले लिया हो, खानों का नियमन और खनिजों का विकास जैसा कि विधायी घोषणा द्वारा प्रकट होता है और बस इतना

ही। यदि संसद ने अपने कानून द्वारा घोषित किया है कि खानों का नियमन और खनिजों का विकास सार्वजनिक हित में संघ के नियंत्रण में होना चाहिए, जैसा कि उसने 1957 अधिनियम की धारा 2 में घोषणा करके किया, तो ऐसी विधायी घोषणा की सीमा तक राज्य विधानमंडल की शक्ति को बाहर रखा गया है। आवश्यक घोषणा का प्रभाव यह है कि वह खानों का नियमन और खनिजों का विकास प्रविष्टि 23, सूची II से उस हद तक निकाल लेती है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस हद तक केंद्रीय सरकार ने 'अपने नियंत्रण' में 'खनियों का नियमन और खनिजों का विकास' लिया है, राज्यों ने अपनी विधायी क्षमता खो दी है। धारा 2 में 'यहां बाद में प्रदान की गई सीमा तक' शब्दों की उपस्थिति से संघ ने 1957 अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक नियंत्रण ग्रहण कर लिया है। 1957 अधिनियम नियंत्रण की सीमा निर्धारित करता है और इसे निर्दिष्ट करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही धारा 2 में की गई घोषणा राज्य विधायी शक्ति पर प्रभाव डालती है, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। ऐसी घोषणा के बाद राज्य द्वारा कोई भी कानून जो उस क्षेत्र का अतिक्रमण करता है जो घोषणा में शामिल किया गया है, वह संवैधानिक रूप से नहीं टिक सकता। यह पता लगाने के लिए कि 1957 अधिनियम की धारा 2 में किए गए घोषणा के बाद राज्य विधानमंडल की क्या क्षमता बची है, किसी को 1957 अधिनियम की धाराओं को बाहर नहीं देखना पड़ेगा बल्कि जैसा कि बैजनाथ कडियोक मामले में कहा गया था, 'उसे उस अधिनियम की शर्तों से काम करना होगा'। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद द्वारा की गई घोषणा प्रभावी होनी चाहिए, नियम बनाने या बनाए गए नियमों को लागू करना निर्णायक नहीं है।

102. 1957 अधिनियम की धारा 2 में संसद द्वारा की गई घोषणा में कहा गया है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ खानों के नियमन और खनिजों के विकास को अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक अपने नियंत्रण में ले। खानों के नियमन और खनिजों के विकास से संबंधित कानूनी व्यवस्था इस प्रकार 1957 अधिनियम और 1960 नियमों द्वारा मार्गदर्शित है। क्या 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किया गया आरक्षण किसी भी प्रकार से 1957 अधिनियम के खिलाफ या असंगत है? मेरे विचार में, बिल्कुल नहीं। क्या विवादित अधिसूचनाएँ केंद्रीय सरकार की विधायी शक्ति पर प्रभाव डालती हैं? मेरा उत्तर नकारात्मक है। क्या पूर्व बिहार राज्य सरकार के पास 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किया गया आरक्षण करने की शक्ति नहीं थी? मुझे लगता है कि राज्य के पास ऐसा आरक्षण करने की शक्ति की कोई कमी नहीं थी। मैं इसके लिए कारण बताता हूँ।

### **खनिजों का प्रबंधन: सामान्य टिप्पणियाँ**

103. सबसे पहले, कुछ सामान्य टिप्पणियाँ। खनिज - नदियों और जंगलों की तरह - एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। खनिज हमारे राष्ट्रीय धन का निर्माण करते हैं और बुनियादी ढाँचे, पूंजीगत वस्तुओं

और बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल होते हैं। खनिजों का संरक्षण, संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग न केवल आज की आवश्यकता है बल्कि मानवता और आने वाली पीढ़ियों के हित में भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिजों का प्रबंधन इस तरह होना चाहिए कि यह देश के आर्थिक विकास में मदद करे और भविष्य की पीढ़ियों को राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों को सर्वोत्तम संभव तरीके से संरक्षित और विकसित करने का अवसर दे। अर्थव्यवस्था और उद्योग के उचित विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण मनमाने तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती; बल्कि राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसे कुछ वर्षों के भीतर समाप्त न किया जा सके।

### **खनन में कोई मौलिक अधिकार नहीं**

104. अपीलकर्ताओं ने झारखंड सरकार (पूर्व बिहार) की भूमि पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है, और यह लौह अयस्क के लिए है जो 1957 अधिनियम की पहली अनुसूची में एक खनिज है, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता। यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति सरकार की किसी भी भूमि या किसी भी खदान में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, सिवाय 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के तहत। किसी व्यक्ति को यह दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है कि उसे खनन पट्टा या अन्वेषण लाइसेंस दिया जाना चाहिए या किसी भी सरकारी भूमि पर अन्वेषण संचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायाधीश द्वारा *मेसर्स हिंद स्टोन* मामले में दी गई निम्नलिखित टिप्पणी उद्धृत करना उपयुक्त होगा, 'सार्वजनिक हित जिसने संसद को धारा 2 में शामिल घोषणा करने के लिए प्रेरित किया ..... सभी मामलों में खानों के नियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सर्वोपरि विचार होना चाहिए'। उन्होंने आगे कहा, 'जिस अधिनियम से हम संबंधित हैं, वह खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण तथा विवेकी शोषण करने का उद्देश्य रखता है। निश्चित रूप से, एक दुर्लभ खनिज के मामले में, राज्य या इसके एजेंसी द्वारा शोषण की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा शोषण को प्रतिबंधित करना संरक्षण और विवेकपूर्ण शोषण का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप भविष्य के लिए संरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में प्रतिबंधित करना होगा।'

### **राज्य सरकार का अपने क्षेत्र में खनिज और खनिजों में स्वामित्व और आरक्षण की शक्ति**

105. यह विवादित नहीं है कि सभी अधिकार और हित, जिसमें विषय क्षेत्र में खनिजों के अधिकार भी शामिल हैं, पहले के बिहार राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से निहित थे। संविधान की शुरुआत में, पहले का बिहार राज्य संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक भाग-ए राज्य था और इससे पहले यह बिहार प्रांत था। अनुच्छेद 294 के अनुसार, सभी संपत्तियाँ और संपत्तियाँ जो महाराज के

पास बिहार प्रांत के सरकारी उद्देश्यों के लिए निहित थीं, वे बिहार राज्य में निहित हो गईं। 1950 के बिहार अधिनियम के तहत, अन्य सभी भूमि, अर्थात्, संपत्तियाँ और किसी भी प्रकार की अवधि, जिसमें वहां के खनिज भी शामिल हैं, बिहार राज्य में निहित हो गईं। इस प्रकार, पहले के बिहार राज्य में स्थित सभी भूमि और खनिज उस पर निहित हो गए। इसके बाद 15 नवंबर 2000 से झारखंड राज्य को बिहार राज्य से काटा गया। इसके अनुसार, सभी भूमि, विशेष रूप से, उस समय के बिहार राज्य की जो सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम) जिलों के स्थानांतरित क्षेत्रों में स्थित थीं, नए बने झारखंड राज्य को चली गईं। स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार (पहले का बिहार और अब झारखंड) विषय क्षेत्र की स्वामी है। उसके क्षेत्र में खनिज पूरी तरह से उसमें निहित हैं।

106. वास्तव में, यही स्थिति थी जिसके कारण अपीलकर्ताओं ने राज्य सरकार को खनन पट्टे के लिए आवेदन किया। अब प्रश्न यह है कि केंद्रीय सरकार द्वारा खानों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में लेने के बाद, क्या 1957 अधिनियम या 1960 नियमों में ऐसे किसी विशेष क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति पर कोई रोक लगती है।

107. 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में खनिजों और खानों के विषय पर कानून को पहले भाग में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 4 एक केंद्रीय प्रावधान है जिसके चारों ओर 1957 अधिनियम में खानों का नियमन और खनिजों का विकास करने का कानूनी ढांचा घूमता है। जिस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क के शोषण के लिए आरक्षित करने वाले विवादास्पद अधिसूचनाओं की प्रकृति को 1957 अधिनियम और 1960 नियमों की प्रावधानों की रोशनी में आंका जाना चाहिए। संसद द्वारा धारा 2 में किए गए घोषणा का उद्देश्य और प्रभाव तथा धारा 2 के बाद आने वाले प्रावधान, जो ऊपर व्यापक रूप से संदर्भित किए गए हैं, यह सुझाव नहीं देते कि पहले का बिहार राज्य सरकार को अपने क्षेत्र के भीतर लौह अयस्क से संबंधित विषय खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने का अधिकार या क्षमता नहीं थी जो इसके पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निहित था। इसलिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि चूंकि राज्य सरकार का लौह अयस्क पर सर्वोच्च अधिकार था और वह खानों का मालिक था, इसलिए उसके पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए विषय क्षेत्रों को आरक्षित करने की शक्ति थी। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि 1957 अधिनियम द्वारा 'खनिजों के विकास' से संबंधित राज्य की स्वामित्व अधिकार ठंडे पड़ गए थे। 'विकास' में खनिज संसाधनों का शोषण शामिल है और शोषण की अनुमति देना या अनुमति नहीं देना सब कुछ 1957 अधिनियम द्वारा कवर किया गया है।

108. 108. मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात, संसद द्वारा धारा 2 में की गई घोषणा और 1957 अधिनियम में धारा 2 के बाद आने वाले प्रावधानों ने राज्य के क्षेत्र में खानों और खनिजों के स्वामित्व को छुआ नहीं है, हालांकि खानों का नियमन और खनिजों का विकास संघ के नियंत्रण में ले लिया गया है। धारा 4 भूमि से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करती है और इस प्रकार की भूमि में राज्य के स्वामित्व के अधिकार को समाप्त नहीं करती है। धारा 4 हस्तांतरण के अधिकार को नियंत्रित करती है लेकिन राज्य में खनिजों के स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है और राज्य सरकार को अपने खनिजों का शोषण करने से रोकती नहीं है। धारा 4(1) का कोई आवेदन नहीं हो सकता जहां राज्य सरकार उस क्षेत्र में खनन संचालन करना चाहती है जो उसके स्वामित्व में है। धारा 5 पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि वही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। धारा 5 या इसके अलावा धारा 6, 9, 10, 11 और 13(2)(ए) भी राज्य के खानों और खनिजों के स्वामित्व अधिकारों को उसके क्षेत्र में समाप्त नहीं करते हैं। संघ के नियंत्रण में खानों का नियमन और खनिजों का विकास करने के लिए कानून बनाने की शक्ति निश्चित रूप से उचित कानून द्वारा सार्वजनिक हित में खानों और खनिजों का अधिग्रहण करने की शक्ति को निहित कर सकती है, लेकिन 1957 अधिनियम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। 1957 अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि जो खनिज राज्यों में निहित थे, उन्हें अधिग्रहित कर लिया गया है। बल्कि, 1957 अधिनियम की योजना और प्रावधान स्वयं यह दिखाते हैं कि संसद ने स्वयं राज्य सरकार को खनिज जमा वाले भूमि का निहित करने के लिए राज्य कानून बनाने की कल्पना की थी और संसद ने राज्य विधानसभाओं की शक्तियों पर कटौती करने का इरादा नहीं रखा था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1957 अधिनियम की धारा 2 में संसद द्वारा की गई घोषणा कहती है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ खानों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में ले। इस प्रकार, धारा 2 में की गई घोषणा पूरी तरह से सर्वसमावेशी नहीं है।

109. खानों का नियमन और खनिजों का विकास केंद्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, जिस हद तक यह 1957 अधिनियम में प्रकट होता है, जो खानों और खनिजों के अधिग्रहण की कल्पना नहीं करता। धारा 2 में 'यहां बाद में प्रदान किए गए अनुसार' प्रमुख अभिव्यक्ति की उपस्थिति से संघ ने धारा 2 के बाद आने वाले प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा तक नियंत्रण ग्रहण किया है। मेरी राय में, हालांकि 'नियमन' शब्द को संदर्भ में व्यापक व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन संघ द्वारा निर्दिष्ट नियंत्रण की सीमा को सख्ती से समझा जाना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय जैसे कि एम ए तुल्लोक & कंपनी बनाम बैजनाथ कडियो, भारत कोकिंग कोल और कुछ अन्य निर्णय जहां इस न्यायालय ने 1957 अधिनियम की धारा 2 में संसद द्वारा किए गए घोषणा और उस अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में कहा कि संपूर्ण विधायी क्षेत्र कवर किया गया था, वे विशिष्ट राज्य विधानसभाओं पर विचार करते समय थे। विषय राज्य कानून के संदर्भ में, संपूर्ण विधायी क्षेत्र केंद्रीय कानून द्वारा कब्जा किया गया पाया

गया। यही स्थिति हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी के मामले में भी थी जहां 'खनिजों' से संबंधित संपूर्ण विधायी क्षेत्र 1948 अधिनियम की धारा 2 में किए गए घोषणा द्वारा कवर किया गया था।

110. मैं अपने विचार का समर्थन एक तीन-न्यायाधीश बेंच के निर्णय से करता हूं जिसमें ओडिशा सीमेंट लिमिटेड का मामला शामिल है जिसमें जोर देकर कहा गया था कि प्रवेश 54 के तहत एक घोषणा के मामले में, राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्ति केवल उसी हद तक कम होती है जिस हद तक संघ उस घोषणा के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है जैसा कि उस घोषणा को बनाने वाले विधायी अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। तीन-न्यायाधीश बेंच ने सावधानीपूर्वक विचार करते हुए कहा, 'क्षति की मात्रा उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसे उस घोषणा के अनुसार तैयार किए गए अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया हो। जबकि *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी* और *एमए तुल्लोक & कंपनी* का कानून निषेध के दायरे में पाया गया था, वहीं *चानन मॉल*, *ईश्वरि खेतान शुगर मिल्स* और *वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड* सामान्य प्रकृति के थे और राज्य सूची में विशिष्ट प्रविष्टियों से जुड़े थे और केंद्रीय अधिनियम के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करते थे सिवाय इसके कि अप्रत्यक्ष प्रभाव से।

111. दूसरी बात, 1957 अधिनियम और इसके तहत बनाए गए 1960 नियमों के लागू होने के बाद, केंद्रीय सरकार ने हमेशा यह समझा है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में खानों और खनिजों की मालिक होने के नाते किसी विशेष क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित करने का स्वाभाविक अधिकार रखती हैं। यह स्थिति केंद्रीय सरकार के आदेश से प्रकट होती है जो *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामले में चुनौती दी गई थी। अपने आदेश में केंद्रीय सरकार ने कहा, '.... राज्य सरकार के पास किसी विशेष क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित करने का स्वाभाविक अधिकार था। खनिज उन पर निहित होते हैं और वे खनिजों के मालिक हैं ..... और केंद्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार के साथ सहमत है ..... '

112. केंद्रीय सरकार द्वारा रखी गई उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय ने *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामले में मंजूरी दी है। मैंने पहले ही *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामले के तथ्यों और उसमें शामिल मुद्दे - जो हमारे सामने प्रस्तुत विवाद के समान हैं - का उल्लेख किया है। अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले में, न्यायालय ने 1957 अधिनियम की धारा 4 का संदर्भ दिया और यह कहा कि 1957 अधिनियम या 1960 नियमों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यदि राज्य सरकार चाहती है तो वह किसी भूमि को अपने लिए 'आरक्षित' नहीं कर सकती, और ऐसा आरक्षित भूमि फिर किसी व्यक्ति को अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। न्यायालय ने फिर यह भी बताया, 'आरक्षण का आदेश देने की शक्ति इस तथ्य से निकलती है कि राज्य अपने क्षेत्र में खानों और खनिजों का मालिक है'। यह भी कहा गया कि इसके अलावा, 1960 नियमों की धारा 59 स्पष्ट

रूप से राज्य सरकार के आदेश द्वारा आरक्षण की कल्पना करती है। उपरोक्त कानूनी स्थिति को इस न्यायालय ने भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड मामले में दोहराया है।

113. हालांकि, अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि अमृतलाल नाथुभाई शाह एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं है क्योंकि इसे पर इनकुरियम माना गया है क्योंकि इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार नहीं किया गया और उन्हें लागू नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि अमृतलाल नाथुभाई शाह का निर्णय केवल अपने तथ्यों तक सीमित था और उस निर्णय ने नियम 59 में संशोधन से पहले आरक्षण पर विचार नहीं किया। उस मामले में अधिसूचना 31 दिसंबर, 1963 की थी जिसके तहत विशेष क्षेत्रों में बॉक्साइट के शोषण के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। उस समय 1960 नियमों की धारा 59 को संशोधित किया गया था और इसके अलावा, वह राज्य द्वारा स्वयं खनिज का शोषण करने का मामला था और राज्य के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के शोषण को केवल 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के अनुसार ही किया जा सकता था।

114. मुझे डर है कि अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा उजागर किए गए विशेषताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और मुझे *अमृतलाल नाथुभाई शाह* का पालन न करने के लिए प्रेरित नहीं करतीं। इस न्यायालय का निर्णय अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले में खनिजों को अपने संपत्ति के रूप में शोषण करने के लिए आरक्षण की शक्ति और 1957 अधिनियम तथा 1960 नियमों के तहत खानों का नियमन स्थापित करता है। राज्य सरकार की एक विशेष खनन क्षेत्र को अपने उपयोग के लिए आरक्षित करने की शक्ति स्वामित्व का परिणाम है; और इसे स्पष्ट रूप से किसी उचित कानून द्वारा अस्वीकृत किए बिना इससे अलग नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरे विचार में, एक राज्य द्वारा अपनी स्वामित्व वाली भूमि को उसके विशेष उपयोग के लिए आरक्षित करना उसकी संप्रभुता और स्वामित्व का एक घटक है। *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एमए तुल्लोक & कंपनी, बैजनाथ कडियो* और *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों में कोई असंगति या विरोधाभास नहीं है। अमृतलाल नाथुभाई शाह बेंच उस कानूनी स्थिति से अवगत थी जिसे इस न्यायालय ने *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एमए तुल्लोक & कंपनी* और *बैजनाथ कडियो* मामलों में उजागर किया था, हालांकि उसने इन निर्णयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। यह उस अवलोकन से स्पष्ट है जो पैराग्राफ 3 में किया गया है जिसमें कहा गया है कि संसद ने अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए जो सूची I की प्रविष्टि 54 से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार रखती थी, उसने विशेष रूप से 1957 अधिनियम की धारा 2 में घोषित किया कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक था कि संघ खानों का नियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में ले। बेंच ने देखा कि सूची II की प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानसभा की शक्ति इस प्रकार छीन ली गई थी और इसलिए खानों का नियमन और खनिज

विकास को 1957 अधिनियम और 1960 नियमों के अनुसार होना चाहिए था। *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामले में उजागर कानूनी स्थिति यह है कि भले ही खानों का नियमन और खनिज विकास संबंधी विधायी क्षेत्र संसद द्वारा किए गए घोषणा से कवर किया गया हो, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालने का औचित्य नहीं बनता कि राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में जो खनिज हैं उनके प्रति अपना अधिकार खो दिया है; इसलिए कोई भी व्यक्ति केवल 1957 अधिनियम और 1960 नियमों की प्रावधानों के अनुसार ही खानों का शोषण कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का आदेश देने की शक्ति इस तथ्य से निकलती है कि वह अपने क्षेत्र में खानों और खनिजों की मालिक है। ऐसी शक्ति भी 1960 नियमों की धारा 59 से प्राप्त होती है।

115. एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं हैं। धारा 17 और 18 और 1960 नियमों की धारा 58 और 59 का संदर्भ दिया गया और यह तर्क किया गया कि ये प्रावधान इस स्थिति का संकेत देते हैं कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण के लिए किया गया आरक्षण कानून में असमर्थनीय और अस्थायी था।

#### **धारा 17 - सर्वसमावेशी प्रावधान नहीं**

116. मेरा मानना है कि धारा 17 खनिज लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार के विषय में सर्वसमावेशी नहीं है। धारा 17 का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। यह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अपने खानों और खनिजों के आरक्षण के अधिकार से संबंधित नहीं है। इसका अनुप्रयोग सामान्य नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट स्थिति तक सीमित है जहां केंद्रीय सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में अन्वेषण या खनन संचालन करने का प्रस्ताव करती है जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है। धारा 17 के संबंध में उपरोक्त दृष्टिकोण को *अमृतलाल नाथुभाई शाह* मामले से समर्थन प्राप्त होता है। जहां तक धारा 18 का संबंध है, यह मूल रूप से केंद्रीय सरकार को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, अर्थात्, खनिजों का संरक्षण और प्रणालीबद्ध विकास जो उसमें व्यक्त किए गए हैं। यदि राज्य सरकार सार्वजनिक हित में उन खनिजों के संबंध में आरक्षण करती है जो उसके पास हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा आरक्षण केंद्रीय सरकार पर धारा 18 के तहत डाले गए दायित्व को कैसे प्रभावित कर सकता है।

#### **नियम 59 और जनक लाल**

117. यह सच है कि मूल रूप से नियम 58 ने राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण के लिए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन नियम 59 ने किसी

भी उद्देश्य के लिए आरक्षण करने के लिए राज्य सरकार की अधिकारिता को मान्यता दी। हालांकि, डॉ. राजीव धवन ने तर्क किया कि उस समय नियम 59 ने खनिजों के अन्वेषण या खनन के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षण की अनुमति दी। उन्होंने जनक लाल मामले के निर्णय पर भरोसा किया। जनक लाल मामले में, विवादित क्षेत्र को निस्तार उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था। जब एक तीसरे पक्ष द्वारा खनन पट्टे के लिए आवेदन किया गया था, तो इसे इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि यह पहले से आरक्षित था। इस न्यायालय के समक्ष यह भी एक स्वीकार्य स्थिति थी कि नियम 58 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जब उत्तरदाता संख्या 4 के पक्ष में अनुमति दी गई थी और उत्तरदाता संख्या 4 के आवेदन पर विचार करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति को कोई अवसर नहीं दिया गया था। उपरोक्त स्वीकार्य स्थिति की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने विचार किया कि क्या नियम 59 लागू होता है या नहीं। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार किया कि नियम 59 में 'किसी उद्देश्य के लिए आरक्षित' अभिव्यक्ति उस मामले को कवर नहीं करती जहां क्षेत्र निस्तार उद्देश्यों या खनन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की दृष्टि को स्वीकार नहीं किया। जब न्यायालय ने मूल रूप से मौजूद नियम 59 की व्याख्या की और 'अन्वेषण या खनन के अलावा' शब्दों को हटाने वाले संशोधन पर विचार किया, तो न्यायालय ने कहा कि संशोधन का परिणाम नियम को विस्तारित करना था, न कि इसके कार्यक्षेत्र को सीमित करना। यह कहा गया कि 'किसी उद्देश्य' शब्द व्यापक अर्थ का था और इसके अर्थ को सीमित करने का कोई कारण नहीं था।

118. मेरा मानना है कि *जनक लाल* मामले ने अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं किया। 'अन्वेषण या खनन के अलावा' अभिव्यक्ति जो मूल नियम 59 का हिस्सा थी, मेरे विचार में, बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी और इसने राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण हेतु आरक्षित करने की अधिकारिता को बाधित नहीं किया जो उसके स्वामित्व पर आधारित थी। इसी कारण यह महत्वहीन और अप्रासंगिक अभिव्यक्ति बाद में 1963 में नियम 59 से हटा दी गई। इस प्रकार, नियम 59 ने राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए खनन हेतु किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार बनाए रखा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण भी शामिल था। अमृतलाल नाथुभाई शाह मामले में, इस स्थिति की स्पष्ट पुष्टि की गई जब कहा गया, "लेकिन इसके अलावा, हम पाते हैं कि नियम 59 जो अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए हैं, स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा ऐसे आरक्षण की कल्पना करते हैं।"

### **नियम 58 और धारा 17 ए का निराकरण**

119. नियम 58 में 1980 में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया कि राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी क्षेत्र को सरकार, केंद्रीय,

राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनियों के लिए शोषण के लिए आरक्षित कर सकती है। नियम 58 को 1960 नियमों से हटा दिया गया है क्योंकि अब आरक्षण का प्रावधान 1957 अधिनियम में धारा 17 ए के समावेश द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है। धारा 17 ए(2) के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के साथ किसी भी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, ताकि वह सरकारी कंपनी या उसके द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगम के माध्यम से अन्वेषण या खनन संचालन कर सके। धारा 17 ए(2) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा उस धारा के लागू होने के बाद किया गया कोई भी आरक्षण केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता।

120. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में मूल रूप से निहित प्रावधानों से जो राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में खनन के लिए किसी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार दिया गया था, उसे पहले 1980 में नियम 58 में संशोधन द्वारा और बाद में 1987 से प्रभावी संशोधन द्वारा 1957 अधिनियम में धारा 17 ए के समावेश द्वारा स्पष्ट किया गया है।

121. यह भी तर्क दिया गया कि यदि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ उस समय उचित कानूनी प्राधिकार के साथ वैध रूप से जारी की गई थीं, तो यह तथ्य कि नियम 58 को बिना किसी बचत क्लॉज के 1988 में हटा दिया गया, का अर्थ है कि ये अधिसूचनाएँ अब वैध नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क किया कि 1957 अधिनियम की धारा 17 ए में निहित वर्तमान आरक्षण की शक्ति पूर्ववर्ती नियमों 58/59 के अनुरूप है क्योंकि धारा 17 ए स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता करती है इससे पहले कि कोई राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में खनन क्षेत्र के आरक्षण के लिए कोई अधिसूचना जारी करे।

122. 1988 में नियम 58 का हटाना और सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र के आरक्षण पर धारा 17 ए का समावेश इस न्यायालय द्वारा भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड मामले में सीधे विचाराधीन आया। न्यायालय ने पहले ही भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक भाग उद्धृत किया है। न्यायालय ने 1957 अधिनियम और 1960 नियमों में प्रासंगिक संशोधनों का संदर्भ दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 17 ए के समावेश से पहले किए गए आरक्षण प्रभावी बने रहते हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 1977 में किए गए आरक्षण जो नियम 58 के हटने और नियम 59 में संशोधन तथा धारा 17 ए के समावेश से पहले थे, उन्हें अप्रभावित माना गया।

123. धारा 17 ए पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त प्रावधान भविष्यकारी है। धारा 17 ए या संशोधन अधिनियम की शर्तों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि धारा 17 ए के समावेश से संसद ने पूर्ववर्ती स्थिति को बदलने का इरादा रखा था। संसद ने ऐसा लगता नहीं कि धारा 17 ए लाकर किसी खनन क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण हेतु पहले किए गए राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को निरस्त करना चाहा। संसद निश्चित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में विधायी अधिकार रखती है ताकि वह भविष्यकारी और पूर्ववर्ती दोनों तरह से कानून बना सके। जैसे कि पहले ही, इस न्यायालय ने *केसवान माधव मेनन बनाम राज्य ऑफ बॉम्बे* आरआर मामले में कहा था कि हर कानून प्राथमिक रूप से भविष्यकारी होता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती प्रभाव देने का इरादा न हो। जब तक कानून में ऐसे शब्द नहीं होते जो विधानमंडल की मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने का इरादा दिखाते हों, इसे केवल भविष्यकारी माना जाता है। न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह की "प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रीटेशन" (सातवां संस्करण, 1999) में *कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी बनाम एल.आर.विंग्स* एसएस. में लॉर्ड ब्लेन्सबर्ग के कथन और *पु/बोरो पैरिश स्कूल बोर्ड चुनाव, बोरके बनाम न्यूफ्टल* टीटी. में लोपेस, एल.जे. की टिप्पणियों को इस प्रकार नोट किया गया है:

लॉर्ड ब्लेन्सबर्ग के शब्दों में, "वे प्रावधान जो उस अधिकार को छूते हैं जो अधिनियम के पारित होने के समय अस्तित्व में हैं, उन्हें स्पष्ट अधिनियम या आवश्यक उद्देश्य की अनुपस्थिति में पूर्ववर्ती रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।" "यह कहा गया है कि", लोपेस, एल.जे. ने अवलोकन किया, "हर अधिनियम जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित अधिकारों को समाप्त करता है या उन्हें कमजोर करता है, या एक नया दायित्व उत्पन्न करता है या एक नया कर्तव्य लगाता है, या पहले की गई लेन-देन के संबंध में एक नई अक्षमता जोड़ता है, उसे यह मान लेना चाहिए कि इसका पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं होगा।"

124. जहां न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठता है कि कोई अधिनियम भविष्यकारी है या पूर्ववर्ती, न्यायालय को कानूनी सिद्धांत "नव संविधान भविष्य में रूप निर्धारित करना चाहिए, न कि अतीत में" का ध्यान रखना चाहिए। भविष्यकारी होने का अनुमान तब तक लागू रहता है जब तक कि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान द्वारा इसके विपरीत सिद्ध नहीं किया जाता या आवश्यक रूप से इसे समझा नहीं जाता।

आरआर एआईआर 1951 एससी 128.

एसएस. (1905) एसी 369.

टीटी. (1894) 1 क्यूबी 725, पृ. 737

125. कुछ पहलुओं में शामिल हैं, (i) 1993 में केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई खनिज नीति ने देश भर में खनिजों के कैप्टिव उपभोग की अनुमति दी; (ii) 1994 में केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से 13 खनिजों, जिसमें लौह अयस्क शामिल है, को डीरिजर्व करने के लिए कहा और उन्हें इसके अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया; (iii) 1994 में बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को पुष्टि कि तब बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कोई खनन क्षेत्र आरक्षित नहीं था; (iv) 2001 में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को पुष्टि कि राज्य में कोई आरक्षित क्षेत्र नहीं है; और (v) 2004 में, अपीलकर्ताओं के पक्ष में केंद्रीय सरकार को पूर्व अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश और 2005 में अनुस्मारक, मेरे विचार में, 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। बिहार सरकार और झारखंड सरकार के उपरोक्त कार्य, 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं की अनजानगी में किए गए, इन अधिसूचनाओं को अमान्य करने के लिए एक पर्याप्त आधार के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। यदि एक राज्य सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए खनिज-धारक क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार है - और मैंने पहले ही कहा है कि तब बिहार सरकार के पास ऐसा अधिकार था - तो 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किए गए आरक्षण का कार्य अवैध या अमान्य नहीं होता है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं की जानकारी की कमी इन अधिसूचनाओं की वैधता और कानूनी स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है, जब यह पाया गया है कि ये अधिसूचनाएँ पहले के बिहार राज्य द्वारा वैध शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई थीं।

### **2006 अधिसूचना की वैधता**

126. 27 अक्टूबर, 2006 को, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि घाटकुरी में लौह अयस्क जमा को अन्वेषण लाइसेंस, खनन लाइसेंस या अन्यथा निजी पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया कि जमा हमेशा से बिहार राज्य द्वारा जारी 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा आरक्षित रखे गए थे। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया कि घाटकुरी क्षेत्र में आरक्षित खनिजों का अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजना द्वारा शोषण करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इससे राज्य को अधिकतम लाभ होगा और राज्य में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न होगा। 2006 की अधिसूचना कहती है कि इसे सार्वजनिक हित और राज्य के व्यापक हित में खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग

और शोषण करने तथा इसके आधार पर मूल्य वर्धित उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किया गया है। यह तर्क किया गया कि 2006 की अधिसूचना उन ही कारणों से खराब है जिनसे 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ कानून में खराब हैं और अमान्य हैं। यह तर्क अस्वीकृत किया गया है। क्योंकि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ मुझसे किसी भी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं पाई गई हैं। 2006 की अधिसूचना ने 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किए गए आरक्षण का तथ्य उल्लेख किया है। यह राज्य सरकार की नीति पर आधारित है कि ऐसा आरक्षण राज्य को अधिकतम लाभ प्रदान करेगा और राज्य में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न करेगा। इस प्रकार, सार्वजनिक हित सर्वोपरि है। राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार था जो 1957 अधिनियम की धारा 17 ए(2) और 1960 नियमों की धारा 59(1)(e) के साथ पढ़ा गया।

127. हालांकि, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क किया गया कि 2006 की अधिसूचना ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या संयुक्त उद्यम परियोजना द्वारा शोषण के लिए क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रयास किया है जबकि 1957 अधिनियम की धारा 17 ए(2) राज्य सरकार को उसके स्वामित्व वाली या नियंत्रित सरकारी कंपनी या निगम के लिए क्षेत्र आरक्षित करने की अनुमति देती है, न कि संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए। प्रस्तुतिकरण यह था कि 2006 की अधिसूचना एक प्रयास है जो अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त उद्यम परियोजना के माध्यम से निजी कंपनियों को लाने का प्रयास कर रही है, जबकि धारा 17 ए स्पष्ट रूप से निजी भागीदारी का अनुमान नहीं लगाती है।

128. 2006 की अधिसूचना द्वारा उक्त क्षेत्र में आरक्षित खनिजों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजना द्वारा शोषण के लिए किया जाने का निर्णय लिया गया है। 2006 की अधिसूचना में राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है, लेकिन मेरे विचार में, उक्त अभिव्यक्ति को एक ऐसे उपकरण के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित सरकारी कंपनी या निगम की विशेषताएँ और स्वरूप हो, और न कि ऐसी किसी अन्य संस्था के लिए।

129. धारा 17 ए के तहत आरक्षण के प्रकार और उनके दायरे पर इस न्यायालय ने भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड मामले में विचार किया है, रिपोर्ट के पैरा 45 और 46 (पृष्ठ 136-139) में। मैं उस दृष्टिकोण से सहमत हूँ। हालांकि, यह तर्क किया गया कि धारा 17 ए(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र के आरक्षण से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। यह तर्क धारा 17 ए(2) की गलत व्याख्या पर आधारित है। इस प्रावधान में 'पूर्व

स्वीकृति' का अभिव्यक्ति नहीं है, जो धारा 11 में उपयोग किया गया है। दूसरी ओर, धारा 17 ए(2) में 'केंद्रीय सरकार की स्वीकृति' शब्दों का उपयोग किया गया है। ये शब्द धारा 17 ए(2) में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बराबर नहीं हैं। मेरे अनुसार, धारा 17 ए में विचारित स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की शक्ति का प्रयोग करने से पहले या उसके बाद प्राप्त की जा सकती है। धारा 17 ए(2) में केंद्रीय सरकार द्वारा विचारित स्वीकृति स्पष्ट या निहित हो सकती है। वर्तमान मामले में जहां केंद्रीय सरकार ने अपीलकर्ताओं के खनन पट्टे के लिए आवेदन को अस्वीकार करते समय 2006 की अधिसूचना पर भरोसा किया है, इसका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय सरकार ने 2006 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को मंजूरी दी है, अन्यथा वह इस पर कार्रवाई नहीं करती। किसी भी मामले में, केंद्रीय सरकार ने 2006 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को अस्वीकृत नहीं किया है।

130. अपीलकर्ताओं की ओर से दो और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, एक 2006 की अधिसूचना के संबंध में और दूसरा 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के संबंध में। जहां तक 2006 की अधिसूचना का संबंध है, यह तर्क किया गया कि यह कानूनी रूप से वैध नहीं है क्योंकि इसे पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ लागू किया गया है। 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने कभी इन अधिसूचनाओं को अपनाया नहीं और इसलिए ये अधिसूचनाएँ समाप्त हो गईं। इनमें से कोई भी दो तर्कों का कोई महत्व नहीं है। अपीलकर्ताओं की ओर से जो कहा गया है उसके अनुसार, 2006 की अधिसूचना को पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया गया है। मैंने पहले ही कहा है कि 2006 की अधिसूचना भविष्यकारी है। 2006 की अधिसूचना में केवल 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं का संदर्भ देने से इसे पूर्ववर्ती नहीं बनाया जा सकता।

131. यह तर्क कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ समाप्त हो गईं क्योंकि राज्य सरकार ने कभी उन्हें अपनाया नहीं, भी बिना किसी महत्व और सामग्री के है। नया झारखंड राज्य पहले के बिहार राज्य से काटा गया था और यह बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के माध्यम से अस्तित्व में आया। उस अधिनियम की धारा 85 में प्रावधान है कि उचित सरकार दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले कानून को अनुकूलित और/या संशोधित कर सकती है और ऐसा प्रत्येक कानून अनुकूलन और संशोधन के प्रभाव में रहेगा जब तक कि इसे किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 को धारा 84 और 86 के साथ पढ़ने पर यह स्थिति उभरती है कि मौजूदा कानून का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक कि इसे परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। चूंकि नए झारखंड राज्य ने पहले के बिहार राज्य द्वारा जारी 1962 और 1969 की

अधिसूचनाओं को परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ समाप्त हो गईं। इसके अलावा, 2006 की अधिसूचना में 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं और उनके प्रभाव का उल्लेख किया गया है, जो यह भी दिखाता है कि ये अधिसूचनाएँ जारी रहीं। अभिव्यक्ति, "जमा हमेशा से आरक्षित रखा गया था जैसा कि बिहार राज्य द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या एनएमएम-40510/62-6209/एम दिनांक 21 दिसंबर, 1962 और संख्या बी/एम-6-1019/68-1564/एम दिनांक 28 फरवरी, 1969 में उल्लेखित है" इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ जारी रहीं और समाप्त नहीं हुईं।

### वचनात्मक रोकथाम के नियम

132. वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत अब दृढ़ता से स्थापित हो चुका है और भारत में इसे अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। इसकी प्रकृति, दायरा और विस्तार बार-बार इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए हैं। इस न्यायालय का वचनात्मक रोकथाम पर एक प्रमुख मामला "मोतीलाल/पद्मपत शुगर मिल्स" का मामला है। उस मामले में, न्यायालय ने वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं और पक्षों पर विस्तार से विचार किया। यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलकर्ता मुख्य रूप से चीनी के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ था और इसके पास एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट और एक स्टील फाउंड्री भी थी। 10 अक्टूबर, 1968 को एक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई कि उत्तर प्रदेश राज्य ने नए औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्षों की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें "विकास के चरण में मजबूत स्थिति में आने" में मदद मिल सके। मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स ने उपरोक्त समाचार के आधार पर उद्योग निदेशक को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा घोषित बिक्री कर की छुट्टी के मद्देनजर, वह वानस्पति के उत्पादन के लिए एक हाइड्रोजेनरेशन प्लांट स्थापित करने का इरादा रखता है और यह पुष्टि मांगी कि प्रस्तावित औद्योगिक इकाई को उत्पादन शुरू करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए बिक्री कर की छुट्टी मिलेगी। उद्योग निदेशक ने उत्तर दिया कि वानस्पति के तैयार उत्पाद पर उत्पादन शुरू करने के लिए बिजली कनेक्शन मिलने की तारीख से तीन वर्षों तक कोई बिक्री कर नहीं होगा। मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स ने फिर कारखाने की स्थापना के लिए कदम उठाना शुरू किया। इसने संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए समझौता किया और वानस्पति फैक्ट्री की स्थापना में कई कदम उठाए और काफी प्रगति हुई। बाद में, राज्य सरकार ने बिक्री कर की छूट पर पुनर्विचार किया और अंततः सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि राज्य में नए वानस्पति इकाइयाँ जो 30 सितंबर, 1970 तक व्यावसायिक उत्पादन में जाएँगी, उन्हें केवल बिक्री कर में आंशिक छूट दी जाएगी। मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स ने सरकार के साथ इस मामले को उठाया और इस बीच इसका उत्पादन 2 जुलाई, 1970 को शुरू हुआ, जिसकी

जानकारी राज्य के अधिकारियों को भी दी गई। उद्योग निदेशक द्वारा पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद पूरी बिक्री कर की छुट्टी से इनकार किए जाने पर, उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। *मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स* की ओर से प्रस्तुत मुख्य तर्क यह था कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासन पर कि उसे उत्पादन शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों तक बिक्री कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, उसने वानस्पति के उत्पादन के लिए हाइड्रोजेनरेशन प्लांट स्थापित किया। यह आश्वासन राज्य सरकार द्वारा दिया गया था जानबूझकर या जानकर कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा और वास्तव में इसके आधार पर कार्य करके उसने अपनी स्थिति बदल दी थी, इसलिए राज्य सरकार वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत पर उस आश्वासन का सम्मान करने और उसे तीन वर्षों तक बिक्री कर से छूट देने के लिए बाध्य थी। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, जब मामला इस न्यायालय में पहुँचा, तो न्यायालय ने वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत की प्रकृति, दायरा और विस्तार पर विचार किया। रिपोर्ट के पैरा 8 में, न्यायालय ने *सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज़ हाउस लिमिटेड* यूू मामले में न्यायाधीश डेनिंग के दृष्टिकोण पर विचार किया, जहाँ डेनिंग, जे. ने *जोर्डन बनाम मनी* वीवी पर विचार किया था। इस न्यायालय ने पैरा 8 में *ह्यूजेस बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी डब्लूडब्लू* , *बर्मिंघम एंड डिस्ट्रिक्ट लैंड कंपनी बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेल कंपनी* एक्सएक्स जैसे मामलों का भी उल्लेख किया जो न्यायाधीश डेनिंग ने *हाई ट्रीज़ यूू* मामले में विचार किए थे। न्यायालय ने *डर्बन फेंसी गुड्स लिमिटेड बनाम माइकल जैक्सन (फेंसी गुड्स) लिमिटेड* वाईवाई , *एवेंडन बनाम गिल्डफोर्ड सिटी एसोसिएशन फुटबॉल क्लब लिमिटेड* जेडजेड और *क्रैब बनाम अरुण डिस्ट्रिक्ट काउंसिल* एएए मामलों में निर्णयों पर भी विचार किया और कानूनी स्थिति को निम्नलिखित रूप से संक्षेपित किया:

8."इस प्रकार, वचनात्मक रोकथाम का सही सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक सीधा और स्पष्ट वादा किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में कानूनी संबंध को प्रभावित करना है, यह जानते या मंशा करते हुए कि इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसे वादा किया गया है, और वास्तव में इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो यह वादा उसे करने वाले पक्ष पर बाध्यकारी होगा और वह इस पर वापस नहीं जा सकेगा, यदि ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा, यह देखते हुए कि पक्षों के बीच जो लेन-देन हुआ है। और यह इस बात से स्वतंत्र होगा कि पक्षों के बीच कोई पूर्ववर्ती संबंध है या नहीं।"

यूू (1956) 1 सभी ईआर 256, वीवी (1854) 5 एचएलसी 185, डब्लूडब्लू (1877) 2 एसी 439

एक्सएक्स . (1889) 40 सी डी 268, वाईवाई (1968) 2 सभी ईआर 987, जेडजेड (1975) 3 सभी ईआर 269

एएए . (1975) 3 सभी ईआर 865

फिर पैरा 9 में, न्यायालय ने कहा कि यह एक सिद्धांत है जिसे न्याय की रक्षा के लिए विकसित किया गया है। न्यायालय ने यह इंगित किया कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा एक वादा किया जाता है यह जानते हुए कि इसे उस व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसे यह वादा किया गया है और वास्तव में इसे इस प्रकार कार्यान्वित किया गया है, तो वादा करने वाले पक्ष को इस पर वापस जाने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण है।

133. पैरा 13 में, इंग्लैंड में वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत के विकास का उल्लेख करते हुए कहा गया, "यहां तक कि इंग्लैंड में, जहां न्यायाधीशों को आशंका होती है कि यदि वचनात्मक रोकथाम पर आधारित कोई कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, तो यह विचार के सिद्धांत को काफी कमजोर कर देगा, अगर पूरी तरह से नहीं तो, वचनात्मक रोकथाम को आक्रमण के हथियार के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने में वे भयभीत रहे हैं, यह दिलचस्प है कि वचनात्मक रोकथाम केवल एक शुद्ध रक्षात्मक भूमिका तक सीमित नहीं रहा है।"

134. मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स मामले में, न्यायालय ने इस विषय पर अमेरिकी कानून का भी उल्लेख किया। पैरा 14 में यह कहते हुए कि "वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत अमेरिकी न्यायाधीशों के हाथों में अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य प्रदर्शित करता है और यह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से विकसित और विस्तारित हो रहा है", न्यायालय ने अमेरिकी कानून संस्थान के "रिएस्टेटमेंट ऑफ दि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट" के अनुच्छेद 90 और अमेरिकी न्यायशास्त्र के वॉल्यूम 19 के पृष्ठ 657 पर दिए गए कथन का उल्लेख किया।

135. इसके बाद न्यायालय ने "अलेगहेनी कॉलेज बनाम नेशनल चाउटॉक काउंटी बैंक" बीबीबी और "ड्रेनेन बनाम स्टार पेविंग कंपनी" सीसीसी में न्यायमूर्ति कार्डोजो के दृष्टिकोण पर विचार किया और निम्नलिखित नोट किया:

"14. ऐसे कई मामले हैं जहाँ वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू किया गया है जहाँ न्याय, नैतिकता और सामान्य निष्पक्षता के हित स्पष्ट रूप से ऐसा करने का निर्देश देते हैं। जब हम सरकार के खिलाफ समानता रोकथाम के सिद्धांत की लागूता पर चर्चा करेंगे, तो हम इन मामलों का उल्लेख करेंगे। वर्तमान में यह कहना पर्याप्त है कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत अमेरिका में अंग्रेजी और राष्ट्रमंडल के अधिकार क्षेत्रों की तुलना में बहुत आगे बढ़ाया गया है और कुछ राज्यों में, इसे विचार के महत्व को कम करने के लिए उपयोग किया गया है, यदि नष्ट नहीं किया गया है, जैसा कि एक वैध अनुबंध का आवश्यक तत्व। स्पेंसर बोवर और टर्नर की "रोकथाम बाय रिप्रेजेंटेशन" (2d) पृष्ठ 358 देखें।

बीबीबी. 57 एएलआर 980.

सीसीसी. (1958) 31 कैल 2डी 409

136. इसके बाद अदालत ने विचार किया कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सरकार के खिलाफ किस हद तक लागू होता है। अंग्रेजी अदालतों और अमेरिकी अदालतों के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस अदालत के निर्णयों पर ध्यान दिया गया: *भारत संघ बनाम इंदो-अफगान एजेंसियाँ* डीडीडी., *मुंबई के कलेक्टर बनाम मुंबई नगर निगम* इइइ., *सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद* एफएफएफ., *एम. रमणाथन पिल्लई बनाम केरल राज्य* जीजीजी., *सहायक संरक्षक बनाम ब्रिज किशोर अग्रवाल* एचएचएच., *केरल राज्य बनाम ग्वालियर रयोन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड* आईआईआई., *यूपी में उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद बनाम राम कुमारी* जेजेजे., *बिहार पूर्वी गंगोटिक मछुआरों सहकारी समाज लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह* केकेके और *राधाकृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य* एलएलएल. ।

137. ऊपर नोट किए गए विस्तृत विचार में, मोटिलाल पदमपत शुगर मिल्स मामले में इस अदालत ने यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत राज्य के खिलाफ लागू किया जा सकता है, यहां तक कि इसकी सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता में भी जहां धोखाधड़ी या स्पष्ट अन्याय को रोकना आवश्यक हो। निम्नलिखित स्थिति निकाली गई:

"वचनात्मक रोकथाम का उपयोग सरकार या यहां तक कि किसी निजी पार्टी को कानून द्वारा निषिद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता।

वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वचनदाता यह दिखाए कि उसने वादे पर भरोसा करते हुए कोई हानि उठाई। हानि वह पूर्वाग्रह नहीं है जो वचनदाता ने वादे पर कार्य करके उठाई है बल्कि वह पूर्वाग्रह है जो वचनदाता को होगा, यदि वचनदाता को वादे से पीछे हटने की अनुमति दी जाती।

सरकार द्वारा निभाई जा रही किसी भी कार्य की प्रकृति जो भी हो, सरकार वचनात्मक रोकथाम के नियम के अधीन है और यदि इस नियम की आवश्यक सामग्री पूरी होती है तो सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।"

डीडीडी. (1968) 2 एससीआर 366

इइइ. (1952) एससीआर 43

एफएफएफ. (1970) 1 एसईसी 582

जीजीजी. (1974) 1 एससीआर 515

एचएचएच. (1975) 1 एसईसी 21

आईआईआई. (1973) 2 एसईसी 713

जेजेजे. (1976) 3 एसईसी 540

केकेके. (1977) 4 एसईसी 145

एलएलएल. (1977) 3 एसईसी 457

138. *भारत संघ और अन्य बनाम गाँडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड* एमएमएम (पैराग्राफ 9, रिपोर्ट के पृष्ठ 383) में, इस अदालत ने निम्नलिखित कहा:

"9. अब वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत भारत के प्रशासनिक कानून में अच्छी तरह से स्थापित है। यह अन्याय से बचने के लिए न्याय द्वारा विकसित एक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और, हालांकि इसे सामान्यतः वचनात्मक रोकथाम कहा जाता है, यह अनुबंध के क्षेत्र में नहीं है और न ही रोकथाम के क्षेत्र में। इस सिद्धांत का आधार न्याय का हस्तक्षेप है जिसने हमेशा, अपनी प्रकृति के प्रति सच्चा रहते हुए, कठोर कानून की कठोरता को कम करने के लिए कदम रखा है। यह सिद्धांत, हालांकि प्राचीन है, न्यायमूर्ति डेनिंग के निर्णय द्वारा अंधकार से बाहर लाया गया था जैसा कि वह थे, अपने प्रसिद्ध निर्णय में केंद्रीय लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज़ हाउस लिमिटेड में। वचनात्मक रोकथाम का सच्चा सिद्धांत यह है कि जब एक पक्ष ने अपने शब्दों या व्यवहार द्वारा दूसरे पक्ष को एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा या प्रतिनिधित्व किया है जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में कानूनी संबंध उत्पन्न करना है, यह जानते हुए या intending कि इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसे वादा या प्रतिनिधित्व किया गया है और वास्तव में इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो वादा या प्रतिनिधित्व उस पक्ष पर बाध्यकारी होगा जो इसे बना रहा है और उसे इससे पीछे हटने का अधिकार नहीं होगा, यदि उसे ऐसा करने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण होगा, उन लेन-देन को ध्यान में रखते हुए जो पक्षों के बीच हुए हैं। इंग्लैंड में अक्सर कहा गया है कि वचनात्मक रोकथाम स्वयं किसी कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता: यह केवल एक ढाल हो सकता है और न कि एक तलवार: लेकिन भारत में कानून इंग्लैंड में अपनाई गई संकीर्ण स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुका है और इस अदालत के मोटिलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय के परिणामस्वरूप अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत केवल रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। इस अदालत का मोटिलाल शुगर मिल्स मामले में निर्णय वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत पर एक व्यापक चर्चा प्रस्तुत करता है और हम उस निर्णय में outlined विभिन्न मापदंडों के साथ पूरी तरह सहमत हैं।"

139. वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत इस अदालत के समक्ष *दिल्ली कपड़ा और सामान्य मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ एनएनएन* में भी विचाराधीन आया। रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 (पृष्ठ 95) में अदालत ने निम्नलिखित कहा:

"18. यहाँ रेलवे दर ट्रिब्यूनल स्पष्ट रूप से पटरी से उतर गया प्रतीत होता है। ट्रिब्यूनल द्वारा वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सही ढंग से समझा नहीं गया है। यह सच है कि प्रारंभिक अवधि में, आमतौर पर कहा जाता था कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वादे को स्वीकार करने वाले ने 'हानि' या 'पूर्वाग्रह' सहन किया हो। अक्सर कहा जाता था कि रोकथाम को लागू करने वाले पक्ष को अपने हानि की ओर प्रेरित होना चाहिए। लेकिन अब इसे कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। अब केवल यही आवश्यक है कि रोकथाम को लागू करने वाला पक्ष उस आश्वासन पर कार्य कर चुका हो जो उसे दिया गया था। उसे उस प्रतिनिधित्व पर भरोसा करना चाहिए जो उसे दिया गया था। इसका अर्थ है कि पक्ष ने आश्वासन या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करके अपनी स्थिति को बदल दिया या संशोधित कर दिया है। पार्टी द्वारा स्थिति का परिवर्तन इस सिद्धांत की केवल अनिवार्य आवश्यकता है। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि रोकथाम को लागू करने वाले पक्ष को कोई नुकसान, हानि या पूर्वाग्रह हुआ हो। हालांकि, अदालत विपरीत पक्ष को उस प्रतिनिधित्व पर बने रहने के लिए मजबूर करेगी जिस पर कार्य किया गया था या कार्य करने से रोका गया था। पूरा सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि यह भरोसे पर आधारित है और कुछ नहीं।"

140. अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड में वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत की सीमा और लागूता पर विचार किया और इस अदालत के पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि *इंदो-अफगान एजेंसियाँ*, *मोटिलाल पदमपत शुगर मिल्स*, *गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड* और *दिल्ली कपड़ा और सामान्य मिल्स लिमिटेड*, यह कानूनी स्थिति निकाली कि यदि सरकार की ओर से किसी अधिकारी द्वारा कोई प्रतिनिधित्व किया गया है, तो जब तक उस प्रतिनिधित्व को अधिकार की सीमा से बाहर स्थापित नहीं किया जाता, तब तक इसे सरकार पर बाध्यकारी माना जाना चाहिए। हालांकि, यदि ऐसा प्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है, तो ऐसा प्रतिनिधित्व लागू नहीं होगा। फिर अदालत ने कहा (पैराग्राफ 10, पृष्ठ 424):

"10. लेकिन वचनात्मक रोकथाम , जो न्याय के सिद्धांत का एक विस्तार है, जिसका मूल उद्देश्य निष्पक्षता पर आधारित न्याय को बढ़ावा देना और वादे को स्वीकार करने वाले को वचनदाता द्वारा किए गए वादे से उत्पन्न अन्याय से राहत देना है, यदि वादा जो कार्रवाई का कारण बनता है या अनुबंध को बाध्यकारी बनाने वाला स्पष्ट या निहित समझौता वैधानिक रूप से निषिद्ध है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, तो इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता..."

141. *कासिका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* ओओओ में, अदालत मुख्य रूप से मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत के उपयोग पर विचार कर रही थी। अदालत ने इस अदालत के इंदो-अफगान एजेंसियों के निर्णय और इसके बाद के निर्णयों पर विचार किया। अदालत ने (पैराग्राफ 11-12, पृष्ठ 283-284) में निम्नलिखित कहा:

"11. वचनात्मक रोकथाम या समानता रोकथाम का सिद्धांत देश के प्रशासनिक कानून में अच्छी तरह से स्थापित है। इसे सरलता से कहें तो, यह सिद्धांत न्याय को बचाने के लिए न्याय द्वारा विकसित एक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जब कोई पक्ष अपने शब्दों या व्यवहार द्वारा दूसरे पक्ष को एक स्पष्ट वादा या प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में कानूनी संबंध उत्पन्न करना होता है, यह जानते हुए और intending कि यह प्रतिनिधित्व, आश्वासन या वादा उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसे यह दिया गया है और वास्तव में इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो वादा, आश्वासन या प्रतिनिधित्व उस पक्ष पर बाध्यकारी होना चाहिए जो इसे बना रहा है और उस पक्ष को इससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा, उन लेन-देन को ध्यान में रखते हुए जो पक्षों के बीच हुए हैं या होने वाले हैं।

12. इस अदालत द्वारा यह तय किया गया है कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सरकार के खिलाफ भी लागू होता है, विशेष रूप से जहां धोखाधड़ी या स्पष्ट अन्याय को रोकना आवश्यक हो। हालांकि, इस सिद्धांत का उपयोग सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को "किसी ऐसे प्रतिनिधित्व या वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता जो कानून के खिलाफ हो या जो सरकार के अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण की शक्ति से बाहर हो।" न्यायिक राय में यह स्पष्टता है कि वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के

लिए याचिका में स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है और बिना किसी सहायक सामग्री के केवल सामान्य अभिव्यक्तियाँ कि यह सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि याचिका देने वाला पक्ष सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदल चुका है, इसे लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारे विचार में, वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत अमूर्त रूप में लागू नहीं किया जा सकता और अदालतों को सभी पहलुओं पर विचार करना होगा जिसमें प्राप्त परिणाम और व्यापक सार्वजनिक भलाई शामिल हैं, क्योंकि जब इस सिद्धांत की लागूता पर विचार करते हैं, तो अदालतों को न्याय करना होता है और न्याय के मूलभूत सिद्धांत हमेशा अदालत के मन में रहने चाहिए जब इस सिद्धांत की लागूता पर विचार किया जाता है। यदि यह दिखाया जा सके कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व पर बाध्य ठहराना अन्यायपूर्ण होगा, तो यह सिद्धांत पीछे हट जाएगा।"

फिर रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 में विचाराधीन तथ्यों को अलग करते हुए, जो *भारत-अफगान एजेंसियों* और *मतिलाल पदमपत शुगर मिल्स* के तथ्यों के अनुरूप नहीं पाए गए, न्यायालय ने (पैरा 20-21, पृष्ठ 287-288) इस प्रकार कहा:

"20. हमारे समक्ष प्रस्तुत अपीलों के तथ्य *इंदो-अफगान एजेंसियों* या *एम.पी. शुगर मिल्स* के तथ्यों के समान नहीं हैं। पहले मामले में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट वादों पर कार्य किया था जो उसे दिए गए थे और उसने विशेष आश्वासन पर सामान का निर्यात किया था और इसी तथ्य की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जो वस्त्र आयुक्त ने योजना का उल्लेख किया था, वह उसके आश्वासन से बाध्य था और उसे उसके तहत किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य होना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामलों के समूह में न तो अधिसूचना कार्यकारी चरित्र की है और न ही यह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई योजना का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक सार्वजनिक हित में जारी की गई अधिसूचना थी और फिर से सार्वजनिक हित में वापस ले ली गई। जहां तक दूसरे मामले (एम.पी. शुगर मिल्स मामले) का संबंध है, तथ्य पूरी तरह से भिन्न थे। राज्य और याचिकाकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान में यह याचिकाकर्ताओं को बताया गया था कि उद्योग को प्रारंभिक वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए बिक्री कर से छूट दी जाएगी, लेकिन जब राज्य ने बिक्री कर लगाने का प्रयास किया तो इस अदालत ने यह निर्णय लिया कि इसे ऐसा करने से रोका गया था क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं को लिखित पत्रों के माध्यम से किए गए स्पष्ट

प्रतिनिधित्व के कारण ऐसा करने से रोका गया था, जिन्होंने उसी पर भरोसा किया और उद्योग स्थापित किया।

21. अधिनियम के तहत शुल्क, अतिरिक्त शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों से प्राप्त होती है। छूट देने की शक्ति में इसे संशोधित या वापस लेने की शक्ति शामिल है। अधिनियम के तहत सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की जिम्मेदारी तब उत्पन्न होती है जब कर योग्य घटना होती है। तब वे सामान की प्रविष्टि की तारीख पर प्रचलित शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं। अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी की गई एक छूट अधिसूचना का प्रभाव सीमा शुल्क संग्रह को निलंबित करना होता है। यह उन वस्तुओं को सीमा शुल्क आदि के लिए लेवी से छूट नहीं देती। यह केवल सीमा शुल्क आदि की लेवी और संग्रह को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करती है और उन शर्तों के अधीन होती है जो सरकार द्वारा "सार्वजनिक हित" में अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं। इस प्रकार की छूट स्वाभाविक रूप से रद्द या संशोधित होने या अन्य शर्तों के अधीन होने योग्य होती है। "सार्वजनिक हित" में एक छूट अधिसूचना का निरसन या रद्दीकरण कानून के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति का प्रयोग है जैसा कि अधिनियम की धारा 25 की भाषा से स्पष्ट है। सामान्य धारणा अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने वाली प्राधिकरण को समान रूप से रद्द या संशोधित करने का संदेह रहित अधिकार होता है। अधिनियम की धारा 25 के तहत सरकार को दी गई छूट की शक्ति के स्वभाव से यह स्पष्ट होता है कि *इसका उद्देश्य सरकार को देश में उद्योगों और औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रित, नियंत्रित और बढ़ावा देने में सक्षम बनाना है।* हमारे विचार में, 1979 की अधिसूचना संख्या 66 का उद्देश्य या जारी नहीं किया गया था ताकि अपीलकर्ताओं को पीवीसी रेजिन का आयात करने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्पष्ट रूप से, उक्त अधिसूचना आयात के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी नहीं थी। अधिसूचना अपनी स्पष्ट भाषा में केंद्रीय सरकार द्वारा "यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है" पर आधारित थी। इसलिए, सख्ती से बोलते हुए, यह अधिसूचना किसी भी 'प्रतिनिधित्व' का विस्तार नहीं करती, इससे भी कम 'वादे' का किसी पक्ष को लाभ प्राप्त करने के लिए जिससे वह राज्य के खिलाफ वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू कर सके। यह दोहराना उचित होगा कि वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक है कि जो वादा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है उसे दूसरे पक्ष के लिए एक स्पष्ट वादा दिखाना होगा जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना होता है और इसे उस पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसे यह दिया गया था। अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी की गई एक अधिसूचना को सरकार द्वारा किसी ऐसे स्पष्ट वादे का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा

सकता जो सरकार और उस पक्ष के बीच कोई कानूनी संबंध बनाने का इरादा रखता हो जो उक्त अधिसूचना से लाभ प्राप्त कर रहा हो। इसलिए, यह तर्क करना व्यर्थ है कि यदि सार्वजनिक हित ऐसा मांग करता है और केंद्रीय सरकार संतुष्ट थी कि छूट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, तो वह अभी भी छूट वापस नहीं ले सकती।"

अदालत ने आगे अवलोकन किया (पैराग्राफ 24 और 25, पृष्ठ 289-290) निम्नलिखित के रूप में:

"24. यह कोई जोर देने की बात नहीं है कि अधिनियम की धारा 25(1) के तहत छूट देने की शक्ति सरकार को विधायिका द्वारा इस उद्देश्य से दी गई है कि वह देश में उद्योगों और औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रित, नियंत्रित और बढ़ावा दे सके। जहां सरकार अपने सामने उपलब्ध सामग्री के आधार पर, ईमानदारी से, संतुष्ट है कि 'सार्वजनिक हित' को छूट देने या पहले से दी गई छूट को वापस लेने, संशोधित करने या रद्द करने से लाभ होगा, उसे ऐसा करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हम अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता के साथ सहमत नहीं हैं कि अधिसूचना संख्या 66 का 1979 में 31-3-1981 से पहले वापस नहीं लिया जा सकता। पहले, क्योंकि छूट अधिसूचना जो अधिनियम की धारा 25(1) के तहत जारी की गई थी, इसमें निहित था कि इसे किसी भी समय रद्द या संशोधित किया जा सकता है यदि सार्वजनिक हित ऐसा मांग करता है और दूसरी बात यह है कि यदि सरकार उस तारीख से पहले परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में संतुष्ट है तो 'सार्वजनिक हित' की मजबूरियों को 31-3-1981 तक स्थगित नहीं किया जा सकता। चूंकि, सरकार इस मामले में संतुष्ट थी कि वही सार्वजनिक हित जिसने सीमा शुल्क के भुगतान से पूरी छूट की मांग की थी अब यह मांग कर रहा था कि छूट को वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए इसे जिस तरीके से कार्य किया गया उसमें स्वतंत्रता थी। यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि अधिसूचना संख्या 66 का 1979 में प्रारंभिक रूप से केवल 31-3-1979 तक वैध था लेकिन उस तारीख को 'सार्वजनिक हित' में बढ़ा दिया गया था, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि इसे सार्वजनिक हित में क्यों कम नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के पक्ष में समर्पण करना चाहिए।"

25. हमारे विचार में, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह सही ढंग से कहा कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 25(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई विवादित अधिसूचना पर लागू नहीं होता है, जैसा कि रिकॉर्ड पर स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर है।"

142. राज्य ओडिशा और अन्य बनाम मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में, इस अदालत ने कहा कि रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पक्षों के बीच लिखित अनुबंध होना चाहिए। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि यह प्रारंभिक दृष्टि में भी संतुष्ट नहीं थी कि यह राज्य सरकार द्वारा की गई एक गलती का मामला था जिसके बारे में वह अवगत नहीं थी। यह देखते हुए कि राज्य अपनी ही चूक का लाभ नहीं उठा सकता, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था और उस पक्ष ने राज्य सरकार के गंभीर वादे पर कार्य किया, कच्चे माल को निश्चित मूल्य पर खरीदा और अपने उत्पादों को भी उसी मूल्य पर बेचा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए राज्य सरकार को उस पक्ष के हितों के खिलाफ कच्चे माल की आपूर्ति की शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

143. नेस्ले इंडिया लिमिटेड में, वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत की लागूता फिर से इस अदालत के समक्ष विचाराधीन आई। अदालत ने *इंदो-अफगान एजेंसियों, मोटिलाल पदमपत शुगर मिल्स, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड* पीपीपी, *अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड* और *कासिका ट्रेडिंग* के पूर्व निर्णयों पर विचार किया। अदालत ने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का अनुसरण किया जो उस मामले के तथ्यों के करीब पाया गया। अदालत ने पंजाब राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सर्वोपरि सार्वजनिक हित इसे अन्यायपूर्ण बना देगा कि रोकथाम को राज्य सरकार के खिलाफ लागू किया जाए।

144. *बन्नारी अम्मन शुगर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य* क्यूक्यूक्यू में, वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत का विकास नोट किया गया (पैराग्राफ 5-7, पृष्ठ 631-633) और इसे निम्नलिखित रूप में कहा गया:

"5. रोकथाम एक न्याय का नियम है जिसने हाल के वर्षों में नए आयाम प्राप्त किए हैं। इस देश में और इंग्लैंड में अदालतों द्वारा एक नई श्रेणी के रोकथाम को मान्यता दी गई है। 'वचनात्मक रोकथाम' का सिद्धांत हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण हो गया है, हालांकि इसे कुछ पूर्व मामलों में धुंधला सा देखा गया था। इस विषय पर प्रमुख मामला है केंद्रीय *लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज़ हाउस लिमिटेड*, (1947) 1 केबी. 130। *हाई ट्रीज़* मामले में स्थापित नियम को फिर से किंग्स बेंच में *कॉम्ब बनाम कॉम्ब* [(1951) 2 केबी 215] में विचार के लिए लाया गया। वहां अदालत ने निर्णय दिया कि *हाई ट्रीज़* मामले में वर्णित किया गया सिद्धांत यह है कि, जहां एक

पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण द्वारा दूसरे पक्ष को एक वादा या आश्वासन दिया है जिसका उद्देश्य उनके बीच कानूनी संबंधों को प्रभावित करना और इसके अनुसार कार्य करना है, तो जब दूसरा पक्ष उसके शब्द पर विश्वास करके उस पर कार्य करता है, तो वादा या आश्वासन देने वाला पक्ष बाद में पूर्व कानूनी संबंध पर वापस नहीं जा सकता जैसे कि उसके द्वारा कोई ऐसा वादा या आश्वासन नहीं दिया गया हो, बल्कि उसे उन कानूनी संबंधों को स्वीकार करना चाहिए जो उसने स्वयं प्रस्तुत किए हैं, भले ही यह किसी विचार के दृष्टिकोण से कानून द्वारा समर्थित न हो, बल्कि केवल उसके शब्द द्वारा। लेकिन वह सिद्धांत कोई ऐसा कारण नहीं बनाता जो पहले मौजूद नहीं था; इसलिए, जहां कोई वादा किया जाता है जो किसी विचार द्वारा समर्थित नहीं होता है, वहां वादा उस वादे के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता। *हाई ट्रीज़* मामले में वर्णित किया गया सिद्धांत भी *टूल मेटल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम टंगस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड* [(1955) 2 ऑल इआर 657] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। उस सिद्धांत को इस अदालत ने *भारत संघ बनाम एंग्लो अफगान एजेंसियों* (एआइआर 1968 एससी 718) और *टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड* [(1972) 1 एससीसी 857] में अपनाया। 'वचनात्मक रोकथाम' का सिद्धांत न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि अन्याय से बचा जा सके। 'वचनात्मक रोकथाम' को ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"यह तब उत्पन्न होता है जब एक वादा होता है जिसे वचनदाता को यह अपेक्षा होती है कि यह वादे के आधार पर निश्चित और महत्वपूर्ण कार्रवाई या संयम उत्पन्न करेगा और जो ऐसी कार्रवाई या संयम उत्पन्न करता है, और यदि अन्याय को केवल वादे के प्रवर्तन द्वारा ही टाला जा सकता है तो ऐसा वादा बाध्यकारी होता है।"

इस अदालत के संदर्भ में, इसने एंग्लो अफगान एजेंसियों के मामले में सिद्धांत को लागू किया जिसमें यह कहा गया कि भले ही मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") जो रोकथाम के नियम को लागू करता है, फिर भी उस पक्ष के लिए यह खुला रहेगा जिसने सरकार द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर कार्य किया हो, यह दावा करने के लिए कि सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य होना चाहिए, भले ही वह वादा संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा आवश्यक रूप में एक औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज न किया गया हो। [देखें *सैचुरी स्पनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद*, ((1970) 1 एससीसी 582), *राधाकृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य*, [(1977) 3 एससीसी 457], *मोटिलाल*

पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(1979) 2 एससीसी 409], भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड [(1985) 4 एससीसी 369] और अशोक कुमार महेश्वरी (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1998) 2 एससीसी 502]।

6. इस पृष्ठभूमि में, आइए हम अतीत में थोड़ी दूर चलते हैं ताकि "वचनात्मक रोकथाम" के सिद्धांत के विकास को समझ सकें। डिकसन, जज, एक ऑस्ट्रेलियाई न्यायविद, ने *ग्रैंट बनाम ग्रेट बोल्डर गोल्ड माइंस प्रा लि.* [(1939) 59 सीएलआर 641 (ऑस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय)] में निम्नलिखित कहा:

"यह अक्सर सरलता से कहा जाता है कि रोकथाम का दावा करने वाले पक्ष को अपने नुकसान के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रकार का बयान मूलतः सही है और इससे कोई गलतफहमी नहीं होती, यह सिद्धांत के मूल उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताता। उस उद्देश्य का मतलब है कि रोकथाम का दावा करने वाले पक्ष को होने वाले नुकसान से बचाना या उसे रोकना है, जिससे विपरीत पक्ष को उस धारणा पर बने रहने के लिए मजबूर किया जा सके जिस पर पहले पक्ष ने कार्य किया या कार्य करने से रोका। इसका मतलब यह है कि वास्तविक नुकसान या हानि जिसे कानून सुरक्षा प्रदान करना चाहता है वह उस स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होगा यदि उन धारणाओं को छोड़ दिया जाए जो इसे लाती हैं।"

उपरोक्त सिद्धांत को लॉर्ड डेनिंग ने हाई ट्रीज़ मामले में दोहराया। यह सिद्धांत न्याय द्वारा अन्याय से बचने के लिए विकसित किया गया है। यह अनुबंध के क्षेत्र में नहीं है और न ही रोकथाम के क्षेत्र में। इसका उद्देश्य न्याय को बिना उसके रूप के हस्तक्षेप करना है ताकि कठोर कानून की कठोरता को कम किया जा सके, जैसा कि *एंग्लो अफगान एजेंसियों* के मामले और *शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम सरकार ए.पी.* [(2002) 2 एससीसी 188] में देखा गया।

7. किसी व्यक्ति को जो छूट दी जाती है, उसके पास कर-धारण का कोई अधिकार नहीं होता। यदि कोई छूट दी गई है तो इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और इसे वापस लेने से पहले किसी समय-सीमा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। वचनात्मक रोकथाम का नियम केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सरकार द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर उद्योग की स्थापना की गई हो ताकि छूट का लाभ उठाया जा सके। *कासिका ट्रेडिंग बनाम भारत संघ* [(1995) 1 एससीसी 274] में यह कहा गया था कि वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत न्याय से बचने के लिए न्याय द्वारा विकसित एक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।

145. *एम.पी. माथुर* मामले में, अदालत इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता वचनात्मक रोकथाम के आधार पर अपने पक्ष में संपत्तियों का हस्तांतरण

करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने (पैराग्राफ 14, रिपोर्ट के पृष्ठ 716) में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"..... 'न्याय' शब्द के चार अलग-अलग अर्थ हैं, जो उस संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं जिसमें इसे उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका अर्थ 'संपत्ति में एक न्यायिक हित' होता है। कभी-कभी, इसका अर्थ 'एक साधारण न्याय' होता है, जो किसी संपत्ति के अधिकार से संबंधित एक प्रक्रियात्मक अधिकार होता है, उदाहरण के लिए, एक संविदा को सुधारने का न्यायिक अधिकार। तीसरे, इसका अर्थ 'तैरता हुआ न्याय' हो सकता है, जो एक वसीयत के तहत लाभार्थी के हित का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथे, 'एक निषेधाज्ञा या अन्य न्यायिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार' होता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने ऐसा उपचार मांगा है जो विवेकाधीन है। उन्होंने 1963 अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमा दायर किया है। अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीनता एक न्यायिक विवेकाधीनता होती है। उस विवेकाधीनता का प्रयोग स्थापित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इसलिए, अदालत को उस दायित्व की प्रकृति पर विचार करना होगा जिसके संबंध में प्रदर्शन की मांग की जा रही है, उन परिस्थितियों पर जिनके तहत निर्णय लिया गया था, पक्षों का आचरण और अदालत द्वारा निर्णय देने का प्रभाव। ऐसे मामलों में, अदालत को अनुबंध पर ध्यान देना होगा। अदालत को यह पता लगाना होगा कि क्या अनुबंध में आपसी तत्व मौजूद हैं। यदि आपसी तत्व की अनुपस्थिति होती है तो अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विवेकाधीनता का प्रयोग नहीं करेगी। यहां तक कि यदि आपसी तत्व की कमी विवेकाधीन मानी जाती है और विशेष प्रदर्शन के लिए एक निरंतर बाधा नहीं होती है, तो अदालत को विषय-वस्तु से संबंधित सभी पक्षों के आचरण पर विचार करना होगा और यदि कोई अयोग्य परिस्थितियाँ होती हैं तो अदालत राहत देने से इनकार कर देगी (स्नेल्स इक्विटी, 31वां संस्करण, पृष्ठ 366) ....."

146. मेरे विचार में, निम्नलिखित सिद्धांतों को उस अदालत का मार्गदर्शन करना चाहिए जहां वचनात्मक रोकथाम की लागूता का मुद्दा उठता है:

- (i) जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण द्वारा दूसरे पक्ष को एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा किया है जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में कानूनी संबंध उत्पन्न करना है, यह जानते हुए या intending कि इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसे वादा किया गया है और वास्तव में इसे उस दूसरे पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो वादा उस पक्ष पर बाध्यकारी होगा जो इसे बना रहा है और उसे इससे पीछे हटने का अधिकार नहीं होगा, यदि ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा, उन लेन-देन को

ध्यान में रखते हुए जो पक्षों के बीच हुए हैं, और यह इस बात से स्वतंत्र होगा कि क्या पक्षों के बीच कोई पूर्व-निर्मित संबंध है या नहीं।

- (ii) वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू किया जा सकता है जहां न्याय, नैतिकता और सामान्य निष्पक्षता के हित ऐसा करने का निर्देश देते हैं। यह सिद्धांत राज्य के खिलाफ भी लागू होता है, यहां तक कि इसकी सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता में भी जहां धोखाधड़ी या स्पष्ट अन्याय को रोकना आवश्यक हो। हालांकि, सरकार या यहां तक कि किसी निजी पार्टी को वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत के तहत किसी ऐसे कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो कानून द्वारा निषिद्ध हो। सरकार द्वारा निभाई जा रही भूमिका और कार्य बहुत प्रासंगिक नहीं हैं। सरकार वचनात्मक रोकथाम के नियम के अधीन है और यदि इस सिद्धांत की आवश्यक सामग्री पूरी होती है, तो सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- (iii) वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत केवल रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक कार्रवाई का कारण भी प्रदान कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत स्वयं कार्रवाई का आधार हो सकता है।
- (iv) वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि वादे को स्वीकार करने वाले यह दिखाए कि दूसरे पक्ष द्वारा किए गए वादे पर कार्य करके उसने अपनी स्थिति को बदल दिया। वादे को स्वीकार करने वाले द्वारा स्थिति का परिवर्तन इस सिद्धांत की लागूता के लिए अनिवार्य शर्त है। हालांकि, उसके लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति में परिवर्तन के कारण कोई नुकसान, हानि या पूर्वाग्रह हुआ है।
- (v) किसी भी स्थिति में, वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी ऐसे प्रतिनिधित्व या वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करने में मदद नहीं कर सकता जो कानून के खिलाफ हो या जो सरकार के अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण की शक्ति से बाहर हो। कोई भी वादा लागू नहीं किया जा सकता जो वैधानिक रूप से निषिद्ध हो या जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो।
- (vi) वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक है कि याचिका में एक स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक आधार प्रस्तुत किया जाए। बिना किसी सहायक सामग्री

के सामान्य दावे, कथन या आरोप वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

- (vii) वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत अमूर्त रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जब इसे लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो अदालत को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जिसमें प्राप्त किए जाने वाले परिणाम और व्यापक सार्वजनिक भलाई शामिल हैं। न्याय का मूलभूत सिद्धांत हमेशा अदालत के मन में उपस्थित रहना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व पर बाध्य नहीं कर सकती।

### वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत

147. चूंकि वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांतों के बीच समानताएँ हैं, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं और प्राकृतिक न्याय से उत्पन्न होते हैं, यह उचित है कि वैध अपेक्षाओं के सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ किया जाए ताकि अपीलकर्ताओं के मामले की सराहना की जा सके जो वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

148. *भारत संघ और अन्य बनाम हिंदुस्तान ए डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अन्य* आरआरआर में, इस अदालत को वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत की प्रकृति, दायरा और लागूता पर विचार करने का अवसर मिला। मामला एक सरकारी अनुबंध से संबंधित था। इस अदालत ने पैराग्राफ 35 (पृष्ठ 548-549) में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"35. वैध अपेक्षाएँ विभिन्न रूपों में आ सकती हैं और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और सरकारी गतिविधियों के विशाल और तेज विस्तार के संदर्भ में एक व्यापक सूची देना संभव नहीं है। वे इतनी तेजी से बदलती हैं कि हमारी सूची की शुरुआत मध्य तक पहुँचने से पहले पुरानी हो जाएगी। आमतौर पर ये उन मामलों में उत्पन्न होती हैं जहाँ पदोन्नति सामान्य रूप से अपेक्षित होती है, हालांकि इसे वैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित नहीं किया गया है, अनुबंधों के मामलों में, सरकार द्वारा वितरण की गई भेंटों में और कुछ हद तक समान स्थितियों में। उदाहरण के लिए, लाइसेंस, परमिट या इसी तरह की विवेकाधीन ग्रांट्स इसके साथ एक उचित अपेक्षा लाती हैं, हालांकि नवीनीकरण या न रद्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

होता, लेकिन उस अपेक्षा को संक्षेप में निराश करना अन्यायपूर्ण माना जा सकता है बिना उस अपेक्षित व्यक्ति को सुने। लेकिन फिर भी अदालत को यह देखना होगा कि क्या यह नीति के रूप में या सार्वजनिक हित में किया गया था चाहे वह जी.ओ., नियम या किसी विधायी प्रक्रिया द्वारा हो। यदि ऐसा है, तो वैध अपेक्षा को अस्वीकार करने वाला निर्णय ऐसे आधारों पर हस्तक्षेप के लिए योग्य नहीं होता जब तक कि किसी विशेष मामले में, लिया गया निर्णय या कार्रवाई शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसलिए यह सीमा अत्यंत संकीर्ण है और यदि प्राकृतिक न्याय का पालन शक्ति के प्रयोग को निर्धारित नहीं करता है, तो वैध अपेक्षा का सिद्धांत कोई भूमिका नहीं निभा सकता है और अदालत को उस सार्वजनिक प्राधिकरण की विवेकाधीनता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए जो कानून के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम है और अदालत को एक उद्देश्यपूर्ण मानक लागू करना चाहिए जो निर्णय लेने वाली प्राधिकरण को उस पूर्ण विकल्प की सीमा छोड़ता है जिसे विधायिका ने इरादा किया था। यहां तक कि एक मामले में जहां निर्णय पूरी तरह से निर्णय लेने वाली प्राधिकरण की विवेकाधीनता पर छोड़ा गया है बिना किसी कानूनी सीमाओं के, और यदि निर्णय निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से लिया जाता है, तो अदालत प्रक्रिया की निष्पक्षता के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगी यदि वैध अपेक्षा पर आधारित व्यक्ति का हित प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्राधिकरण जिसे लाइसेंस देने की पूरी विवेकाधीनता है, एक मौजूदा लाइसेंस धारक को नए आवेदक पर प्राथमिकता देता है, तो निर्णय को नए आवेदक द्वारा रखी गई वैध अपेक्षा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए यह देखा जा सकता है कि वैध अपेक्षा अधिकतम न्यायिक समीक्षा का एक आधार हो सकती है लेकिन राहत देने की प्रक्रिया बहुत सीमित होती है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि वैध अपेक्षा को वास्तविक रूप से संरक्षित किए जाने के कारणों की तुलना में इसे संरक्षित न किए जाने के कारणों से अधिक मजबूत कारण हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी कानूनी बाध्यता तब मौजूद होती है जब कानूनी सिद्धांतों के विभिन्न प्रकारों में इसे समर्थन देने वाला मामला उसके खिलाफ मामले से अधिक मजबूत होता है। जैसा कि न्यू साउथ वेल्स मामले में अटॉर्नी जनरल द्वारा अवलोकन किया गया: [(1990) 64 ऑस्ट्रेलियाई एलजेआर 327]: "व्यक्तिगत वैध अपेक्षाओं की निराशा से बचने के आधार पर प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग रद्द करना अदालतों को एक बिना विशेषता वाले समुद्र पर छोड़ देना होगा। इसके अलावा, वैध अपेक्षा (जो कानूनी अधिकार से कम होती है) का विचार इतना अस्पष्ट होता है कि इसका आधार बनाना उचित नहीं होगा जब इसका प्रयोग अन्यथा कानून के अनुसार होता है।" यदि किसी विशेष मामले में वैध अपेक्षा का अस्वीकार करना किसी अधिकार का अस्वीकार करने या मनमाना, भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण या पक्षपाती हो जाता है, तो इसे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 को आकर्षित करने वाले आधारों पर सवाल उठाया जा सकता है लेकिन केवल

वैध अपेक्षा के आधार पर बिना कुछ अधिक होने पर इन सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार स्वतः नहीं दिया जा सकता। यह विचार करने का एक आधार हो सकता है लेकिन अदालत को पर्दा उठाना होगा और देखना होगा कि क्या निर्णय इन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिससे हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। यह बहुत हद तक तथ्यों और ऐसे तथ्यों पर लागू होने वाले मान्यता प्राप्त सामान्य प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों पर निर्भर करता है और वैध अपेक्षा का सिद्धांत जो न्यायिक कार्रवाई की समीक्षा के लिए अदालतों द्वारा निर्मित अवधारणाओं की लंबी सूची में नवीनतम भर्ती है, इसे सामान्य कानूनी सीमाओं तक सीमित रखा जाना चाहिए जो प्रशासनिक शक्ति के भविष्य के प्रयोग को विशेष मामले में बाध्य करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत "प्राकृतिक न्याय की संपत्ति खोलने की कुंजी नहीं है और इसे उन दरवाजों को खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो अदालत को गुणात्मक समीक्षा से बाहर रखते हैं", विशेष रूप से जब उस अवधारणा में अनुमान लगाने और अनिश्चितता का तत्व अंतर्निहित होता है। न्यू साउथ वेल्स मामले में अटॉर्नी जनरल द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अदालतों को अपने आप को रोकना चाहिए और ऐसे दावों को कानूनी सीमाओं तक सीमित करना चाहिए। यह एक अच्छी तरह से मतलब वाली चेतावनी है। अन्यथा, एक संसाधनशील याचिकाकर्ता जो अनुबंधों, लाइसेंस आदि में निहित स्वार्थ रखता हो, सफलतापूर्वक कल्याणकारी गतिविधियों को बाधित कर सकता है ताकि अपने व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ा सके। चेतावनी, विशेष रूप से बदलते परिदृश्य में, और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

जब ऊपर अवलोकन किया गया, तो अदालत ने यह कहा कि अपेक्षा की वैधता केवल तभी अनुमानित की जा सकती है जब यह कानून या प्रथा की स्वीकृति या एक स्थापित प्रक्रिया पर आधारित हो जो नियमित और प्राकृतिक क्रम में अनुसरण की जाती है। हर ऐसी वैध अपेक्षा अपने आप में एक अधिकार में परिणत नहीं होती है और, इसलिए, यह पारंपरिक अर्थ में एक अधिकार के बराबर नहीं होती।

149. इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य एसएसएस में वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर विचार करते हुए पैराग्राफ 3, 4 और 5 (पृष्ठ 272-273) में निम्नलिखित कहा:

"3 ..... वैध अपेक्षा का सिद्धांत तब कोई भूमिका नहीं निभाता जब उचित प्राधिकरण को कार्यकारी नीति या कानून के तहत निर्णय लेने का अधिकार होता है। अदालत प्राधिकरण को

कार्यकारी या विधायी शक्ति के भीतर अपने विकल्पों की पूरी सीमा तय करने के लिए छोड़ देती है। आर्थिक नीति के मामलों में, यह स्थापित कानून है कि अदालत कार्यपालिका और विधायिका को बड़ी छूट देती है। आयात या निर्यात के लिए लाइसेंस देना कार्यकारी या विधायी नीति द्वारा होता है। सरकार विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर सामान के आयात या निर्यात के लिए नीति तैयार करती है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के समग्र बड़े हित में विभिन्न वस्तुओं को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए, यह कार्यपालिका को दिए गए अधिकार का प्रयोग करके या जैसा कि मामला हो, विधायिका को ऐसी नीतियों को विकसित करने की स्वतंत्रता है।

4. एक आवेदक के पास उस तारीख पर लागू नीतियों के अनुसार निर्यात या आयात लाइसेंस प्राप्त करने का कोई निश्चित अधिकार नहीं होता। स्पष्ट कारणों से, लाइसेंस या परमिट देने का निर्णय उस तारीख पर लागू नीति पर निर्भर करता है। संबंधित प्राधिकरण बेहतर स्थिति में हो सकता है कि वह विभिन्न कारकों की समग्र तस्वीर देख सके ताकि वह अनुमति दे सके या सामान के आयात या निर्यात की अनुमति देने से इनकार कर सके। इसलिए निर्णय विभिन्न आर्थिक दृष्टिकोणों से लिया जाएगा जिनमें कार्यपालिका बेहतर जानकारी में होती है, जब तक कि, जैसा कि हमने पहले कहा, इनकार बुरा इरादा न हो या शक्ति का दुरुपयोग न हो, जिसमें मामले में आवेदक को यह साबित करना होगा कि इनकार उपरोक्त कारकों से प्रभावित था।

5. इसलिए यह स्पष्ट होगा कि लाइसेंस का वितरण उस तारीख पर लागू नीति पर निर्भर करता है जिस दिन लाइसेंस दिया जाता है। इसलिए अदालत सरकार को उस नीति से बाध्य नहीं करेगी जो आवेदन की तारीख पर पूर्व नीति के अनुसार मौजूद थी। पूर्व निर्णय सरकार को सभी समय के लिए बाध्य नहीं करेगा। जब सरकार संतुष्ट होती है कि नीति में परिवर्तन सार्वजनिक हित में आवश्यक था, तो उसे नीति को संशोधित करने और नई नीति निर्धारित करने का अधिकार होता है। इसलिए अदालत सरकार को सार्वजनिक हित में वित्तीय नीति विकसित करने और उसी पर कार्य करने की स्वतंत्रता देने का पक्षधर होगी। समान रूप से, सरकार को सार्वजनिक हित में आवंटन या आवंटन के मामलों में प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए यह भी उसे निर्यात या आयात नीति जारी करने, वापस लेने या संशोधित करने का अधिकार है जैसा कि योजना विकसित की गई है। इसलिए हम यह मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं का एमडि या एनओडि पर परमिट जारी करने का कोई निश्चित या अर्जित अधिकार नहीं है, न ही सरकार अपनी पूर्व नीति से बाध्य है। सरकार के लिए नए योजनाओं को विकसित करना खुला रहेगा और याचिकाकर्ताओं को उन दो योजनाओं में से किसी एक के अनुसार अपनी वैध अपेक्षाएँ पूरी

करने का अवसर मिलेगा यदि वे योजना में आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष में सही कहा कि सरकार वादों या वैध अपेक्षाओं से नई नीति विकसित करने से बाधित नहीं होती जो विवादित अधिसूचना में हैं।"

150. *M.P. ऑयल एक्सट्रैक्शन और अन्य बनाम राज्य मध्य प्रदेश और अन्य* टीटीटी के मामले में, इस अदालत ने हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक पूर्व निर्णय पर विचार किया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 44 (पृष्ठ 612) में कहा कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में कार्य करता है और एक उपयुक्त मामले में, यह एक मौलिक और लागू करने योग्य अधिकार का गठन करता है।

151. *J.P. बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य* उउउ में कहा गया कि दोनों सिद्धांत - वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षा - समान मानदंडों की संतोषजनकता की आवश्यकता होती है और ये तर्कसंगतता के सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं।

152. *बन्नारी अम्मन शुगर लिमिटेड* में एक चेतावनी दी गई थी जो ध्यान देने योग्य है। अदालत ने अवलोकन किया कि वैध अपेक्षा प्रत्याशा से भिन्न होती है; केवल अपेक्षा की निराशा पर राहत देना सार्वजनिक कानून द्वारा किए गए किसी सार्वजनिक कार्य को रद्द करने के लिए बहुत अस्पष्ट आधार होगा और यह आवश्यक होगा कि किसी याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मान्यता प्राप्त आधार प्रस्तुत किया जाए।

153. इस अदालत के निर्णयों को बढ़ाना आवश्यक नहीं है। यह अवलोकन करना पर्याप्त है कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हैं:

- (i) वैध अपेक्षा का सिद्धांत एक मौलिक और लागू करने योग्य अधिकार के रूप में लागू किया जा सकता है।
- (ii) वैध अपेक्षा का सिद्धांत तर्कसंगतता और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है।
- (iii) यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न होता है और वैध अपेक्षा और वचनात्मक रोकथाम के बीच समानताएँ हैं। जहां किसी प्राधिकरण का निर्णय सार्वजनिक

हित पर आधारित होता है जैसा कि कार्यकारी नीति या कानून के अनुसार होता है, तो अदालत ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने में संकोच करेगी। यदि सार्वजनिक हित में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्रशासनिक नीति में बदलाव को बाधित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

- (iv) वैध अपेक्षा प्रत्याशा से भिन्न होती है और प्रत्याशा को एक दावा योग्य अपेक्षा नहीं माना जा सकता।
- (v) ऐसी अपेक्षा को उचित, वैध और संरक्षित होना चाहिए।
- (vi) वैध अपेक्षा की सुरक्षा उस अपेक्षा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं रखती जहां कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित अन्यथा की मांग करता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत लाभ को सार्वजनिक हित के पक्ष में समर्पण करना चाहिए और वैध अपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा जो निजी लाभ के लिए सार्वजनिक हित को अवरुद्ध कर सके।

### **क्या वचनबद्धता और वैध अपेक्षा के सिद्धांत लागू हुए**

154. मैं अब यह जांच कर सकता हूँ कि क्या वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षा के सिद्धांत अपीलकर्ताओं को उनके द्वारा मांगी गई राहत प्राप्त करने में मदद करते हैं और क्या राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की कार्रवाई इन सिद्धांतों को लागू करके रद्द की जा सकती है।

155. प्रत्येक अपीलकर्ता ने अपने-अपने तथ्यों के आधार पर वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षा के तर्क उठाए हैं। इन तर्कों के संबंध में प्रत्येक अपील में तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संबंधित अपीलकर्ताओं और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में शर्तें सामान्यतः समान हैं। सुविधा के लिए, अदुनिक मामले में सामान्य विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है। यह एमओयू राज्य सरकार और अदुनिक के बीच 26 फरवरी, 2004 को किया गया था। अदुनिक विविध गतिविधियों में संलग्न है जैसे कि स्पंज आयरन और स्टील का उत्पादन, बिजली उत्पन्न करना आदि। एमओयू की प्रस्तावना में कहा गया है कि झारखंड सरकार अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और राज्य का तेजी से औद्योगिकीकरण चाहती है और नए उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयास कर रही है। एमओयू के पैराग्राफ 2 में कहा गया है, "इस संदर्भ में झारखंड सरकार उपयुक्त प्रमोटरों को नए उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिए तैयार है" (जोर दिया गया)। अदुनिक ने झारखंड राज्य में निर्माण/उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। प्रस्तावित चरण-I में स्पंज आयरन प्लांट और पैलेटाइजेशन प्लांट स्थापित करने का समावेश था, जबकि चरण-II में स्पंज

आयरन प्लांट, पावर प्लांट, कोल वॉशरी, मिनी ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग/एलओ/आईएफ और आयरन ओर माइनिंग शामिल थे और चरण-III में पावर प्लांट की स्थापना शामिल थी। एमओयू का पैराग्राफ 4 कहता है कि अदुनिक को परियोजना का निर्माण, कमीशन और संचालन करने के लिए राज्य सरकार की कई क्षेत्रों में सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकार की सभी संभव सहायता और सहयोग देने की इच्छा उपरोक्त एमओयू में व्यक्त की गई है। एमओयू के पैराग्राफ 4.3 में दर्ज है कि राज्य सरकार अदुनिक के लिए आयरन ओर और अन्य खनिजों के लिए क्षेत्र का चयन करने में सहायता करेगी जो कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार ने मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुसार खनिज छूट देने पर भी सहमति दी।

156. उपरोक्त एमओयू के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अपने उप सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग के माध्यम से 4 अगस्त, 2004 को भारत सरकार को इसकी संयुक्त निदेशक, खान मंत्रालय के माध्यम से अनुशंसा की कि अदुनिक को 1957 अधिनियम की धारा 11 (5) और धारा 5(1) के तहत खनन पट्टे के लिए पूर्व स्वीकृति दी जाए जो 30 वर्षों की अवधि के लिए 426.875 हेक्टेयर क्षेत्र में हो। इस अनुशंसा के कारणों को राज्य सरकार ने उपरोक्त संचार में बताया। उपरोक्त संचार में कहा गया कि अदुनिक ने राज्य में आयरन ओर खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार के साथ 790 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। अदुनिक द्वारा उठाए गए कदमों को भी उजागर किया गया।

157. अदुनिक का मामला यह है कि उसने एमओयू और राज्य की औद्योगिक नीति में निर्धारित कैप्टिव खानों के अनुदान के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए निश्चित प्रतिबद्धता और ठोस वादे के आधार पर तुरंत कार्य किया और उसने चरण-I के तहत संयंत्र और सुविधाएँ स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और उसने चरण-I में संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए लगभग 3500 लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। अदुनिक का कहना है कि उसने चरण-II और चरण-III के लिए उपकरणों और मशीनरी का आदेश दिया है जिसकी लागत 25 करोड़ रुपये है और उसने विस्तार स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ भी की हैं। अदुनिक का दावा है कि उसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 60 करोड़ रुपये उधार भी लिया है और उस राशि को प्रस्तावित परियोजना में निवेश किया है।

158. अदुनिक के अनुसार, झारखंड राज्य में कोई भी एकीकृत स्टील प्लांट कैप्टिव आयरन ओर खानों के बिना और राज्य सरकार द्वारा कैप्टिव खानों के अनुदान का निश्चित वादा किए बिना व्यवहार्य नहीं हो सकता और यदि राज्य सरकार कैप्टिव आयरन ओर खनन उपलब्ध नहीं कराती, तो वह एमओयू पर कार्य करके इतनी बड़ी निवेश नहीं करती। अदुनिक ने यह भी कहा है कि कैप्टिव आयरन ओर खानों

के अनुदान की अनुपस्थिति में, उसे निम्नलिखित कारणों से विशाल और अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ा है: (क) आयरन ओर की आपूर्ति में कमी के कारण, (ख) उसे बाजार से खराब गुणवत्ता का आयरन ओर खरीदना पड़ता है और (ग) कैप्टिव आयरन ओर की वास्तविक लागत की तुलना में असामान्य बाजार कीमतों के कारण अतिरिक्त लागत।

159. राज्य सरकार ने एमओयू में जो व्यक्त किया है, वह अदुनिक द्वारा निर्माण/उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने में सभी संभव सहायता और सहयोग देने की इच्छा है। एमओयू में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार आयरन ओर और अन्य खनिजों के लिए क्षेत्र का चयन करने में सहायता करेगी, जो गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम और नियमों के अनुसार खनिज छूट देने पर सहमति दी। वास्तव में, जब एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में विषय खनन क्षेत्र के आरक्षित होने की जानकारी भी नहीं थी। 17 नवंबर, 2004 को जिला खनन अधिकारी, चाईबासा ने झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग के सचिव को सूचित किया कि मौजा घाटकुरी और आस-पास के क्षेत्रों के कुछ हिस्से 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे जो पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा जारी की गई थीं। जिला खनन अधिकारी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि संबंधित आवेदकों को पट्टे देने के लिए केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। अपने संचार में, उन्होंने कहा कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में विषय क्षेत्र का आरक्षण निदेशक खनिज, झारखंड के ज्ञान में लाया गया था लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई समय पर या पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। यह देखते हुए कि विषय खनन क्षेत्र को 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित किया गया था, मेरे विचार में, एमओयू में यह प्रावधान कि राज्य सरकार कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार आयरन ओर और अन्य खनिजों के लिए क्षेत्र का चयन करने में सहायता करेगी और खनिज छूट देने का वादा लागू नहीं किया जा सकता। पहले, एमओयू में यह प्रावधान बिना शर्त नहीं है। उपरोक्त वादा उपलब्धता और मौजूदा कानून पर निर्भर करता है। दूसरा, यदि राज्य सरकार से कहा जाता है कि वह एमओयू के तहत जो उसने प्रतिनिधित्व किया था उसे करें, तो इसका अर्थ होगा कि राज्य सरकार से उन दोनों अधिसूचनाओं का उल्लंघन करने के लिए कहा जा रहा है जो अभी भी लागू हैं। वर्तमान तथ्यों में वचनात्मक रोकथाम का सिद्धांत लागू नहीं होता, विशेष रूप से जब वादा एक गलत धारणा में किया गया था - मानते हुए कि एमओयू में कुछ धाराएँ वादे का रूप लेती हैं - उस स्थिति से अनजान होते हुए कि विषय भूमि निजी क्षेत्र में आयरन ओर खनन के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो वह 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं को देखते हुए मौजूदा स्थिति में नहीं कर सकती। मेरे विचार में, राज्य सरकार को उसके द्वारा किए गए वादों या आश्वासनों या प्रतिनिधित्वों से बाध्य नहीं

ठहराया जा सकता क्योंकि ऐसे वादों या आश्वासनों या प्रतिनिधित्वों को लागू करने से विषय क्षेत्र के आरक्षण द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्य को विफल किया जा सकता है और इससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकता है। सर्वोपरि सार्वजनिक हित भी मुझे वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों को लागू न करने की प्रेरणा देता है। इसी कारण से कोई भी अपीलकर्ता इन सिद्धांतों पर आधारित किसी भी राहत का हकदार नहीं है; उनका मामला बेहतर नहीं है।

160. वास्तव में, 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के बारे में जानने के बाद, राज्य सरकार ने अपीलकर्ताओं को किए गए प्रस्तावों को वापस ले लिया और 27 अक्टूबर, 2006 की अपनी अधिसूचना द्वारा आरक्षण को स्पष्ट रूप से "सार्वजनिक हित और राज्य के बड़े हित में" दोहराया।

161. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को किए गए अनुशंसाओं को वापस लेने की कार्रवाई को वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के संदर्भ में कानून में गलत नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार की कार्रवाई न तो अन्यायपूर्ण है और न ही मनमानी है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से भी प्रभावित नहीं है। भारत सरकार ने प्रस्तावों की जांच करने के बाद उन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि विषय क्षेत्र आरक्षित था और निजी पक्षों द्वारा शोषण के लिए उपलब्ध नहीं था। इन परिस्थितियों में, यदि एमओयू में धाराओं को लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो यह वादा, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के प्रवर्तन के समान होगा जो कानून, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, जिसे मैं डरता हूँ कि अनुमति नहीं दी जा सकती।

162. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क किया गया कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ लगभग 40 वर्षों तक अनुपयोगी रहीं और यह उचित है कि इन दोनों अधिसूचनाओं का अब कोई प्रभाव नहीं है। इस संबंध में, निष्क्रियता द्वारा अर्ध-रद्दीकरण का सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया गया।

### निष्क्रियता का सिद्धांत

163. निष्क्रियता का सिद्धांत और इसका भारतीय न्यायशास्त्र में अनुप्रयोग इस अदालत द्वारा कई अवसरों पर विचार किया गया है। *महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण शामराव पुराणिक और अन्य* वीवीवी के मामले में, अदालत ने *आर. बनाम लंदन काउंटी काउंसिल डब्लूडब्लूडब्लू* में स्क्रटन, एल.जे. के निर्णय और प्रसिद्ध

वीवीवी (1982) 3 सेकंड 519.

डब्लूडब्लूडब्लू . एलआर (1931) 2 केबी 215 (सीए).

लेखक एलेन के "लॉ इन द मेकिंग" में विचार को नोट किया और कहा कि निष्क्रियता से संबंधित नियम हमेशा सामान्य नापसंद का सामना करता है। यह भी कहा गया कि किसी अधिनियम को केवल स्पष्ट या निहित रद्दीकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है; यह निष्क्रियता में नहीं गिर सकता या पुरातनता या समय की समाप्ति के कारण अप्रभावी नहीं हो सकता।

164. *भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड* के मामले में, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि 17 जून, 1918 की अधिसूचनाएँ आज तक लागू नहीं की गई हैं और इसलिए ये अधिसूचनाएँ मृत पत्र हैं और "क्वासिली" रद्द हो गई हैं। इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निष्क्रियता के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया। अदालत ने निष्क्रियता के सिद्धांत के संबंध में अंग्रेजी कानून और स्कॉट्स कानून का अवलोकन करने के बाद, फ्रांसिस बेनियन की "स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन", क्रेड्स स्टैच्यूट लॉ (7वां संस्करण) और *ब्राउन बनाम एडिनबर्ग* एक्सएक्सएक्स के मजिस्ट्रेट में लॉर्ड मैके की राय को नोट किया।

165. अदालत ने "स्टैच्यूट्स का रद्दीकरण और निष्क्रियता" पर ऑब्रे एल. डायमंड द्वारा भी संदर्भित किया, जिसमें *बर्कॉक बनाम ग्रेटर लंदन काउंसिल* वाईवाईवाई में लॉर्ड डेनिंग, एम.आर. के विचार का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अवलोकन करने के बाद, अदालत ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 34 (पृष्ठ 446-447) में कहा:

"34. हालांकि भारत में निष्क्रियता का सिद्धांत अब तक इस आधार पर नहीं लगाया गया है कि कोई अधिनियम इस प्रक्रिया के कारण रद्द हो गया है, हम अपने अधिनियमों पर इस सिद्धांत को लागू करने में सिद्धांत रूप से कोई आपत्ति नहीं पाते। इसका कारण यह है कि एक नागरिक को यह जानना चाहिए कि क्या, लंबे समय तक अनुपयोगी रहने के बावजूद और इसके बजाय विपरीत प्रथा का उपयोग होने पर, उसे अभी भी "मृत पत्र" के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमारे देश में निष्क्रियता के सिद्धांत को स्वीकार करना न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। हमारी भूमि इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार है; वास्तव में, इसकी स्थापना की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में रहने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने अनुच्छेद 21 में बताए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है, को उस कानून के उल्लंघन के लिए अभियोजित और दंडित होने से सुरक्षित रखा जाना चाहिए जो "मृत पत्र" बन गया है। इसलिए, एक नया मार्ग स्थापित करना और उस पर चलना आवश्यक है।"

एक्सएक्सएक्स . 1931 एसएलटी (स्कॉट्स लॉ लाइम्स रिपोर्ट) 456, 458.

वाईवाईवाई . (1970) 2 ऑल ईआर 193

166. *कैन्टोनमेंट बोर्ड, एमएचओडब्ल्यू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम* जेडजेडजेड के मामले में, इस अदालत को निष्क्रियता के सिद्धांत पर विचार करने का अवसर मिला जब यह विचार किया गया कि मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1947 रद्द हो गया है क्योंकि यह अनुपयोगी रहा है। अदालत ने भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड के पूर्व निर्णय पर विचार किया और कहा कि निष्क्रियता के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि संबंधित अधिनियम लंबे समय तक अनुपयोगी रहा है और इसके विपरीत प्रथा विकसित हुई है। यह भी कहा गया कि इन दोनों तथ्यों में से कोई भी इस मामले में संतुष्ट नहीं हुआ है और इसलिए निष्क्रियता का सिद्धांत लागू नहीं होता।

167. उपरोक्त से, निष्क्रियता के सिद्धांत की आवश्यकताओं को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:

- (i) निष्क्रियता का सिद्धांत अर्ध-रद्दीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है, लेकिन यह सिद्धांत सामान्यतः नापसंद किया जाता है।
- (ii) हालांकि निष्क्रियता का सिद्धांत भारत में कुछ अवसरों पर लागू किया गया है, लेकिन इसके लागू होने के लिए दो कारक, अर्थात् (i) कि अधिनियम या विधान बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहा है और (ii) इसके विपरीत प्रथा एक निश्चित समय के दौरान अनुसरण की गई है, स्पष्ट रूप से संतुष्ट होना चाहिए। दोनों तत्व आवश्यक हैं और इनमें से किसी एक की कमी निष्क्रियता के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, किसी अधिनियम या विधान की केवल अनदेखी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए कि न केवल अधिनियम या विधान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था, बल्कि ऐसे अधिनियम या विधान के विपरीत प्रथा भी एक महत्वपूर्ण लंबे समय तक अनुसरण की गई है।

**क्या 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के संबंध में निष्क्रियता का सिद्धांत लागू होता है**

168. 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं के संबंध में, मैं इस विचार का हूँ कि निष्क्रियता का सिद्धांत कई कारणों से लागू नहीं होता। पहले, ये अधिसूचनाएँ 1962 और 1969 की हैं और ऐसी अधिसूचनाओं का 30-35 वर्षों तक अनुपालन न होना इतना लंबा समय नहीं है जो निष्क्रियता के सिद्धांत की पहली आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, अर्थात्, अधिनियम या विधान बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहा है। इसके अलावा, झारखंड राज्य 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया और यह कहना मुश्किल है कि राज्य सरकार ने 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया। वास्तव में, 2006 में, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा किए गए आरक्षण का उल्लेख किया गया। इस प्रकार, निष्क्रियता के सिद्धांत को

लागू करने के लिए आवश्यक पहला तत्व संतुष्ट नहीं होता। दूसरे, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अपीलकर्ताओं के पक्ष में यह मान लिया जाए कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ 30-35 वर्षों से अधिक समय तक अनुपयोगी रहीं, तो दूसरी आवश्यक तत्व यह है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के विपरीत एक प्रथा एक महत्वपूर्ण लंबे समय तक अनुसरण की गई है और ऐसी विपरीत प्रथा को दृढ़ता से स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह से अनुपस्थित है। वास्तव में, आरक्षित क्षेत्र के एक या दो पक्षों को बहुत छोटे हिस्से के लिए खनन पट्टे का बिखरा हुआ अनुदान छोड़कर, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उपयोग या प्रथा को स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि दो अधिसूचनाओं में किए गए आरक्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

### **मोनेट की ओर से अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ**

169. अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुख्य तर्कों का निपटारा करने के बाद, मैं अब मोनेट की ओर से किए गए कुछ अतिरिक्त तर्कों पर विचार कर सकता हूँ। श्री रंजीत कुमार, मोनेट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के पक्ष में की गई अनुशंसा को वापस लेने के अपने पत्र में रंगटा के पट्टे के साथ ओवरलैपिंग का आधार प्रस्तुत किया, लेकिन उसने 1995 में रंगटा के पट्टे की समाप्ति के तथ्य को जानबूझकर छिपाया और यह भी कि उक्त क्षेत्र को 3 जुलाई, 1996 को आधिकारिक गजट में पुनः अनुदान के लिए अधिसूचित किया गया था। उनका कहना था कि 1960 के नियमों के नियम 24ए के अनुसार पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन एक वर्ष पहले करना आवश्यक है, लेकिन रंगटा ने इस समय सीमा के भीतर नवीनीकरण का कोई आवेदन नहीं किया और इसलिए रंगटा का ओवरलैपिंग क्षेत्र पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

170. श्री रंजीत कुमार ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता मोनेट ने उच्च न्यायालय और इस अदालत के समक्ष दो मानचित्र प्रस्तुत किए (एक 2004 में जिला खनन अधिकारी द्वारा तैयार किया गया) जिसने दिखाया कि अपीलकर्ता को अनुदान देने के लिए अनुशंसित क्षेत्र 1962 या 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा कवर नहीं किया गया था।

171. मोनेट की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि मोनेट का मामला बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के मामले के समान है और राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के प्रति बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के मामले की तुलना में भेदभाव किया है।

172. श्री रंजीत कुमार ने यह भी प्रस्तुत किया कि 1960 के नियमों के नियम 26 के अनुसार सुनवाई के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मोनेट को आदेश नहीं दिया गया और इस प्रकार 1960 के नियमों के नियम 54 के तहत इसका उपाय छीन लिया

गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन मामले की जड़ में जाता है और केवल इसी आधार पर राज्य सरकार का अनुशंसा को वापस लेने का निर्णय और केंद्रीय सरकार का आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार करने का निर्णय कानून में गलत है। इस संबंध में *नजीर अहमद बनाम किंग-एम्परर के प्रिवी काउंसिल एएए* के निर्णय और *नगरजुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बीबीबीबी* के इस अदालत के निर्णय पर भरोसा किया गया।

173. श्री रंजीत कुमार ने यह भी तर्क किया कि एक बार जब उसने केंद्रीय सरकार को अनुशंसा की, तो 1960 के नियमों के नियम 63ए के उपबंध के अनुसार, राज्य सरकार कार्य से बाहर हो गई थी और किसी भी आधार पर पहले की गई अनुशंसा को वापस लेने की कोई शक्ति नहीं रह गई थी। इस संबंध में उन्होंने *जयालक्ष्मी कोएल्हो बनाम ओस्वाल्ड जोसेफ कोएल्हो* सीसीसीसी पर भरोसा किया।

174. इस अदालत के *मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य डीडीडीडी* के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रशासनिक आदेश में मूल रूप से दिए गए कारणों को अदालत में हलफनामों या याचिकाओं में अन्य कारणों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोनेट के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक कारण आरक्षण पर आधारित नहीं था, लेकिन बाद में उसने कारणों को प्रतिस्थापित करके आरक्षण का आधार लाने का प्रयास किया।

175. श्री रंजीत कुमार ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के अपने मामले के अनुसार, प्रारंभ में मोनेट को खनन पट्टे के लिए अनुशंसित भूमि आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थी और इसलिए मोनेट की याचिका को समूह मामलों के साथ सुनवाई और निर्णय नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने इस अदालत द्वारा 18 अगस्त, 2008 को पारित अंतरिम आदेश, उसके बाद केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक और इस अदालत के 15 दिसंबर, 2008 के बाद के अंतरिम आदेश का भी उल्लेख किया।

176. मैंने श्री रंजीत कुमार की प्रस्तुतियों पर ध्यान से विचार किया है। उपरोक्त अधिकांश प्रस्तुतियाँ उच्च न्यायालय के समक्ष मोनेट की ओर से नहीं उठाई गई थीं। प्रस्तुतियाँ आरक्षण, 1962, 1969 और 2006 की अधिसूचनाओं की वैधता और वैधता, अनुशंसा को वापस लेने में राज्य सरकार की अवैध कार्रवाई और केंद्रीय सरकार द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार करने पर केंद्रित थीं।

एएए एआईआर 1936 पीसी 253.

बीबीबीबी. 2008) 16 सेकं 276.

सीसीसीसी. 2001 > 4 सेकं 181.

डीडीडीडी (1978) 1 सेकं 405

177. विवादित निर्णय के पैराग्राफ 17 में, मोनेट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कई तर्क नहीं दिए गए, जिसमें रंगटा के क्षेत्र के साथ ओवरलैपिंग का मुद्दा भी शामिल है। विशेष अनुमति याचिका की तिथियों/संक्षेप में मोनेट ने यह कोई शिकायत नहीं उठाई कि उच्च न्यायालय के समक्ष उसके पक्ष में किए गए तर्क सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए या उच्च न्यायालय ने उसके किसी या कुछ तर्कों पर विचार करने में असफल रहा। इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना उचित नहीं है और मैं श्री रंजीत कुमार के उपरोक्त प्रस्तुतियों पर पहली बार विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

178. मोनेट के लिए यह कहना अब बहुत देर हो चुकी है कि उसका मामला समूह मामलों के साथ नहीं तय किया जा सकता था और किसी भी स्थिति में मामले को उच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, जिसमें (क) क्या अपीलकर्ता के लिए अनुशंसित क्षेत्र केवल 102.25 हेक्टेयर तक रंगटा के साथ ओवरलैपिंग था, जो कुल 705 हेक्टेयर में से था; (ख) क्या रंगटा का पट्टा समाप्त होने के बाद उसका क्षेत्र 1996 में पुनः अधिसूचित किया गया; (ग) जब रंगटा के साथ कथित ओवरलैपिंग केवल 102.25 हेक्टेयर तक था, तो राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के पक्ष में की गई अनुशंसा को वापस लेने का कारण क्या था; और (घ) क्या अपीलकर्ता की अनुशंसा का वापस लेना मनमाना है जब 1962 की अधिसूचना द्वारा आरक्षण अपीलकर्ताओं के पक्ष में अनुशंसित क्षेत्र पर लागू नहीं हुआ। मोनेट की याचिका उच्च न्यायालय में समूह मामलों के साथ तय की गई क्योंकि उसके पक्ष में उठाए गए तर्क अन्य याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उठाए गए तर्कों के समान थे। राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसाएँ एक सामान्य संचार द्वारा वापस लीं और केंद्रीय सरकार ने अनुशंसाएँ लौटाईं और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए खनन पट्टे के आवेदन को सामान्य आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया।

179. राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार को दी गई अनुशंसा को वापस लेने का पूरा अधिकार था, कुछ अच्छे कारणों से। एक बार जब मुझे यह पता चला कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा जारी 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ और झारखंड राज्य द्वारा जारी 2006 की अधिसूचना वैध और कानूनी हैं, तो श्री रंजीत कुमार की उपरोक्त प्रस्तुतियाँ महत्वहीन हो जाती हैं और मोनेट के पक्ष में की गई अनुशंसा को वापस लेने में राज्य सरकार की कार्रवाई को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में खनन क्षेत्र का वैध आरक्षण मोनेट - और अन्य अपीलकर्ताओं - को किसी भी राहत से वंचित करता है।

180. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी को भी खनन पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण का कानूनी या निश्चित अधिकार नहीं है। मोनेट खनन पट्टे के अनुदान का कानूनी या निश्चित अधिकार नहीं रख सकता। यह सच है कि राज्य सरकार और मोनेट के बीच किए गए एमओयू द्वारा राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबद्धताएँ की थीं, लेकिन पहले, ऐसा एमओयू भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के तहत एक अनुबंध नहीं है और दूसरे, राज्य की संपत्ति के खनन पट्टे के अनुदान में, राज्य सरकार को कोई भी खनन पट्टा देने या न देने का विवेकाधीनता होती है। स्पष्ट रूप से, राज्य सरकार को अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, कानून की आवश्यकताओं के अधीन। इस तथ्य को देखते हुए कि

क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के शोषण के लिए आरक्षित है, यह कहना उचित नहीं होगा कि राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया गया विवेक किसी कानूनी दोष से प्रभावित है।

181. मोनेट की ओर से उठाया गया बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के संबंध में भेदभाव का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया और यह बिल्कुल भी स्थापित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में तर्क भी कोई ठोस आधार नहीं रखता। केंद्रीय सरकार के पक्ष में मोनेट के लिए की गई अनुशंसा केवल कुछ पूर्व-शर्तों के साथ एक प्रस्ताव था। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव को वापस लेने के लिए, मेरे विचार में, कोई नोटिस देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था। इसके अलावा, अनुशंसा को वापस लेने से पहले कोई नोटिस न देने के कारण मोनेट को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि उसे खनन पट्टे के अनुदान का कोई कानूनी या निश्चित अधिकार नहीं था। क्षेत्र निजी क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए उपलब्ध नहीं है। इन सभी कारणों से, मुझे नहीं लगता कि मोनेट का मामला अन्य अपीलकर्ताओं से अलग है।

### निष्कर्ष

182. उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

### आदेश

में कार्यवाही से यह पाता हूँ कि अवमानना याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। 28 जनवरी, 2009 की कार्यवाही से पता चलता है कि अदालत ने केवल झारखंड राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता को अवमानना याचिका की प्रति प्रदान करने का आदेश दिया था ताकि वह अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सके। 28 जनवरी, 2009 को पारित आदेश में, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अवमानना याचिका में कोई नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं थी। अब, चूंकि अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी गई है, अवमानना याचिका भी खारिज करने के लिए योग्य है और इसे भी खारिज किया जाता है।

**न्यायमूर्ति एच.एल. गोकले** 1. सभी अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे लौह और स्टील परियोजनाओं के विकास में रुचि रखने वाली कंपनियाँ हैं, और इसलिए उन्होंने झारखंड राज्य में स्थित आयरन-ओर खानों के पट्टे के लिए आवेदन किया। झारखंड सरकार ने अगस्त 2004 के आसपास अपीलकर्ताओं सहित दस ऐसी कंपनियों के आवेदन भारत संघ को पट्टे की कुछ क्षेत्रों में अनुदान के लिए विचार करने के लिए भेजे। चूंकि ये क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित थे, राज्य सरकार ने 13.09.2005 को अपने पत्र द्वारा इनमें से नौ प्रस्तावों को वापस लेने का प्रयास किया, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं के प्रस्ताव शामिल थे। हालांकि, केंद्रीय सरकार ने केवल नौ प्रस्तावों को वापस नहीं किया, बल्कि 6.3.2006 को झारखंड सरकार को संबोधित अपने पत्र द्वारा इन्हें अस्वीकार कर दिया। इसलिए,

सभी अपीलकर्ताओं ने इन दो पत्रों, 13.9.2005 और 6.3.2006 को चुनौती देने के लिए याचिकाएँ दायर कीं और प्रस्तावित क्षेत्रों में उन्हें खनन पट्टे देने का आदेश देने और उचित राहत की मांग की। यहाँ छह अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाएँ क्रमशः निम्नलिखित संख्या रखती हैं: (1) डब्लूपी (सी) संख्या 4151 वर्ष 2006, (2) डब्लूपी (सी) संख्या 1769 वर्ष 2006, (3) डब्लूपी (सी) संख्या 2629 वर्ष 2006, (4) डब्लूपी (सी) संख्या 5527 वर्ष 2006, (5) डब्लूपी (सी) संख्या 7636 वर्ष 2006 और (6) डब्लूपी (सी) संख्या 7363 वर्ष 2006। सभी याचिकाएँ झारखंड उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा एक सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 4.4.2007 से खारिज कर दी गईं। इससे असंतुष्ट होकर, उनमें से छह ने इस अदालत में ये अपीलें दायर की हैं।

2. इन अपीलों में 7.5.2007 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, कि जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते, विवादित खनन क्षेत्र के संबंध में कोई नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। हम यह नोट कर सकते हैं कि एक चरण में इस अदालत द्वारा समान कार्यशील व्यवस्थाओं पर विचार किया गया था, लेकिन वे साकार नहीं हो पाईं। इन अपीलों को 30.4.2009 को स्वीकार किया गया। भारत संघ और झारखंड राज्य इन सभी अपीलों में मुख्य प्रतियोगी हैं, हालांकि कुछ अन्य संस्थाएँ जैसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), टाटा आयरन स्टील कंपनी (टीआईएससीओ) और आर्सेलर मित्तल (इंडिया) लिमिटेड ने इनका विरोध करने के लिए हस्तक्षेप किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.ए. सुंदरम, डॉ. राजीव धवन, रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, डॉ. अभिषेक मनु सिंहवी, एल. नागेश्वर राव, और जी.सी. भारुका ने इन अपीलों के समर्थन में उपस्थिति दर्ज कराई है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सिन्हा और श्री अशोक भान ने क्रमशः झारखंड राज्य और भारत संघ के लिए उपस्थिति दर्ज कराई है। श्री पी.एस. नारसिंहा, एनएमडीसी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विकास सिंह, टीआईएससीओ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कृष्णन वेंगूपाल, आर्सेलर मित्तल (इंडिया) लिमिटेड के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री जे.के. दास, रुड्टा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए अधिवक्ता ने इन अपीलों का विरोध करने के लिए उपस्थिति दर्ज कराई है।

### **इन अपीलों के पीछे के तथ्य:-**

3. इन सभी अपीलों में तथ्यों में लगभग समानता है। हम मेसर्स मॉनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. के पहले सिविल अपील के तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं (संक्षेप में 'मॉनेट' के रूप में)। मॉनेट का कहना है कि वह झारखंड राज्य में एक लोहे और स्टील संयंत्र स्थापित करना चाहता था। इस परियोजना पर 1400 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए वह तैयार था, और इसके लिए वह पश्चिम सिंहभूम जिले के घाटखुरी वन क्षेत्र में स्थित लोहे और मैंगनीज अयस्क खदानों के आवंटन में रुचि रखता था (जिसका मुख्यालय चाईबासा में है)। इस उद्देश्य के लिए 7.7.2002 को रांची में मॉनेट और झारखंड सरकार के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद बैठक की कार्यवृत्ति तैयार की गई जिसमें दोनों पक्षों के बीच चर्चा को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद, 5.2.2003 को झारखंड सरकार और मॉनेट के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जो एक एकीकृत स्टील संयंत्र की स्थापना के लिए था। एमओयू ने मॉनेट की एकीकृत स्टील संयंत्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता को

दोहराया और झारखंड सरकार की भूमि प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी, जिसमें लोहे और मैंगनीज अयस्क खदानें, एक कोयला ब्लॉक और अन्य सुविधाएं शामिल थीं। एमओयू में यह रिकॉर्ड किया गया कि संयंत्र प्रति वर्ष 4 लाख टन स्पंज आयरन, 2 लाख टन माइल्ड स्टील और 2 लाख टन अलॉय स्टील का उत्पादन करेगा। इससे 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। एमओयू में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार मॉनेट के प्रस्ताव को भारत सरकार को सिफारिश करने पर सहमत है, ताकि घाटखुरी वन क्षेत्र में लोहे और मैंगनीज अयस्क जमा और कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा सके। यह धारा इस प्रकार है:

### III. खदानें:

कोयला: ..... .

लोहे और मैंगनीज अयस्क: राज्य सरकार भारत सरकार को सिफारिश करने पर सहमत है कि लोहे और मैंगनीज अयस्क जमा का आवंटन किया जाए, जिसमें परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार होने की संभावना है। स्पंज आयरन बनाने के लिए उपयुक्त लोहे के अयस्क भंडार चाईबासा जिले के घाटखुरी क्षेत्र में पहचाने गए हैं। राज्य सरकार ने यह भी सहमति दी कि भारत सरकार को पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में अतिरिक्त खदानों का आवंटन करने की सिफारिश की जाए ताकि परियोजना की आवश्यकता पूरी हो सके।

हम यह भी नोट कर सकते हैं कि एमओयू के अनुच्छेद VII (डी) में कहा गया है:

यदि परियोजना का कार्यान्वयन नहीं होता है, तो एमओयू में राज्य सरकार का समर्थन/प्रतिबद्धता वापस ली जाएगी।

4. तदनुसार, झारखंड सरकार ने अपने पत्र दिनांक 6.8.2004 द्वारा भारत संघ को मॉनेट के प्रस्ताव की सिफारिश की, जो खनिजों और खदानों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे आगे "एमएमडीआर अधिनियम" कहा गया) की धारा 5 (1) और 11 (5) के तहत थी। पत्र में कहा गया कि लगभग 58 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो घाटखुरी आरक्षित वन क्षेत्र में 3566.54 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टों के लिए अनुरोध कर रहे थे। सभी आवेदकों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जहां तक मॉनेट का संबंध है, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत केंद्रीय सरकार से पट्टे की स्वीकृति के लिए संशोधित क्षेत्र 705 हेक्टेयर की सिफारिश की थी। पत्र में यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत तकनीकी खनिज आधारित उद्योग और वित्तीय क्षमता के आधार पर मॉनेट को प्राथमिकता दी जा रही थी।

5. उस आवेदन को प्राप्त करने पर और यह विचार करते हुए कि खनन पट्टा 30 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाना था, केंद्रीय सरकार ने अपने पत्र दिनांक 6.9.2004 द्वारा राज्य सरकार से प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु अपनी उचितता भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके विचार में खनिज विकास के

हित में पर्याप्त उचितता नहीं भेजी गई थी। राज्य सरकार ने अपने उत्तर दिनांक 17.11.2004 द्वारा मॉनेट को प्राथमिकता देने का कारण स्पष्ट किया और एमएमडीआर अधिनियम की धाराओं 5 (1) और 11 (5) के तहत भारत सरकार से अनुमोदन मांगा। उसने उन 58 आवेदकों के दावों का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जिन्होंने आरक्षित वन क्षेत्र में लोहे के अयस्क के पट्टों के लिए आवेदन किया था जो 3566.54 हेक्टेयर क्षेत्र में थे।

6. ऐसा हुआ कि उस चरण में चाईबासा के जिला खनन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 17.11.2004 द्वारा झारखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि बिहार का अविभाजित राज्य (जब झारखंड इसका हिस्सा था) ने 21.12.1962 को अपने अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के दोहन के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया था, और इसमें सिंहभूम जिले का अनुशंसित क्षेत्र शामिल था। इस अधिसूचना के बाद अविभाजित बिहार राज्य की एक और अधिसूचना 28.2.1969 को जारी की गई, जिसमें यह दोहराया गया कि सिंहभूम जिले के घाटखुरी आरक्षित वन खंड संख्या 10 में 168.349 हेक्टेयर का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के दोहन के लिए आरक्षित था। उक्त अधिसूचना की एक प्रति जिला खनन अधिकारी, चाईबासा को भेजी गई थी।

7. दोनों अधिसूचनाएँ इस प्रकार हैं:

(1)

बिहार सरकार

उद्योग एवं खनन विभाग (खनन)

अधिसूचना:

पटना, 21 दिसंबर, 1962

30वां अग्रहण, 1884-एस

ज्ञापन नंबर ए/एमएम-40510/6209/एम यह सार्वजनिक सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि इस राज्य में निम्नलिखित लोहे के अयस्क-धारक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में खनिजों के दोहन के लिए आरक्षित किया गया है।

| जिले का नाम |        | आरक्षित क्षेत्रों का विवरण                                                                                                                   |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिंहभूम     | 1.     | सासंगदा मुख्य ई-लॉक:- सीमा                                                                                                                   |
|             | दक्षिण | दक्षिणी सीमा उत्तरी सीमा के समान है। यह बिहार, उड़ीसा सीमा से शुरू होकर मेघाहातु नाला की दक्षिणी सहायक नदी जॉर्ज के सामने से शुरू होती है और |

|  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                   | पहाड़ी की तलहटी तक घाटी के साथ-साथ पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में चलती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | पूर्व:                                                            | बिहार और उड़ीसा राज्यों के बीच की सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | उत्तर और दक्षिण-पश्चिम                                            | श्री एम.एल. जैन (एम.एल. 20) की संपत्ति की दक्षिणी सीमा, जो बिहार-उड़ीसा सीमा से शुरू होती है।<br><br>दक्षिण-पश्चिम: 3039 से शुरू होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में 8 मील तक जाती है, जो 2939 के उत्तर-पश्चिम में है। यहाँ से सीमा 2069 के दक्षिणी भाग तक पहुँचती है।                                                                                                |
|  | पश्चिम                                                            | 2069 के दक्षिणी सैडल से, मुख्य पहाड़ी के तल के साथ दक्षिण की ओर जाती है, जो कि किरिबुरु ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम कोने से मिलती है।                                                                                                                                                                                                                              |
|  | ससंगदा<br>उत्तर-पूर्व ब्लॉक<br>दक्षिण<br>पूर्व<br>उत्तर<br>पश्चिम | बिहार, उड़ीसा सीमा<br><br>श्री डब्लू.वी. की संपत्ति।<br><br>एम.एल. नंबर 20 के उत्तरी कोने तक।                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 6.                                                                | भालता ब्लॉक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | सीमा<br>दक्षिण-पश्चिम                                             | एक रेखा जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से पूर्व-दक्षिण की ओर चलती है, प्रत्येक 2200 फीट की ऊँचाई के कॉटूर को पार करती है, जो भानलता पर्वत श्रृंखला के दक्षिण-पश्चिम छोर पर है। दक्षिण-पूर्व: 2181 के पूर्व में 21 फर्लांग से उत्तर-पूर्व की ओर पोचनालु गांव (22016'850 20') तक जाती है, और यहाँ से उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर 2567 (पेंसिरा बुरु) के पूर्व-दक्षिण-पूर्व |

|  |        |                                                                                                                                                                |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | तक 3 फर्लांग तक जाती है।                                                                                                                                       |
|  | उत्तर  | उपर्युक्त स्थान से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में पहाड़ी को पार करते हुए पाँच फर्लांग तक जाते हैं ताकि उत्तर-पश्चिम ढलान वाली पहाड़ी तक पहुँच सकें।              |
|  | पश्चिम | उपर्युक्त स्थान से सामान्यतः दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा में पहाड़ी के किनारे चले हुए 2187 के उत्तर-पश्चिम में तीन फर्लांग पर दक्षिण-पश्चिम सीमा तक पहुँचते हैं। |

बिहार के गवर्नर के आदेशानुसार

हस्ता/-

बी. एन. सिन्हा

सरकार के सचिव

ज्ञापन संख्या 6209/एम

पटना, 21 दिसंबर, 1962

30 अग्रहण

प्रकाशन के लिए अगली बिहार गजट में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को अग्रेषित की गई प्रति।

2. उनसे निवेदन किया जाता है कि इस विभाग को गजट अधिसूचना की दो सौ प्रतियां कृपया उपलब्ध कराएं।

हस्ता/-

बी. एन. सिन्हा

सरकार के सचिव

ज्ञापन संख्या 6209/एम

पटना, 21 दिसंबर, 1962

30 अग्रहण, 1884-एस

जानकारी के लिए छोटानागपुर सी डिवीजन, रांची/सभी जिला अधिकारियों/सभी जिला खनन अधिकारियों को अग्रेषित की गई प्रति।

हस्ता/-

बी. एन. सिन्हा

सरकार के सचिव

(2)

बिहार सरकार

खनन और भूविज्ञान विभाग

सूचना

पटना, 28 फरवरी, 1969

फाल्गुन, 1890-एस

संख्या: बी/एम6-1019/68-1564/एम. यह सार्वजनिक जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के घाटखुरी आरक्षित वन ब्लॉक संख्या 10 में स्थित 416 एकड़ (168.348 हेक्टेयर) लौह अयस्क-धारक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में खनिज के शोषण के लिए आरक्षित हैं। इस संबंध में पूर्ण विवरण के लिए जिला खनन अधिकारी, छाईबासा से संपर्क किया जाना चाहिए।

बिहार के गवर्नर के आदेश द्वारा

(हस्ताक्षर)

सी. पी. सिंह

उप सचिव, सरकार

मेमो संख्या: 1564/एम

पटना, 28 फरवरी, 1969

इस सूचना की सार्वजनिकता के लिए गुलजारबाग, सचिवालय प्रेस के अधीक्षक को बिहार गजट के असाधारण अंक में शीघ्रता से प्रकाशन हेतु भेजी गई प्रति।

2. सूचना की 100 अतिरिक्त प्रतियां भी तुरंत इस विभाग को भेजी जा सकती हैं।

(हस्ताक्षर)

उप सचिव, सरकार

मेमो संख्या: 1564/एम

पटना, 28 फरवरी, 1969

प्रतिलिपि उप आयुक्त, सिंहभूम/खनन निदेशक, 2, कॉलेज रोड, सर्किट हाउस क्षेत्र, जमशेदपुर/जिला खनन अधिकारी, सिंहभूम, छाईबासा/खनन निदेशक, बिहार/भूविज्ञान निदेशक, बिहार/भूविज्ञान सलाहकार, बिहार को जानकारी के लिए भेजी गई।

(हस्ताक्षर)

सी. पी. सिंह

उप सचिव, सरकार

8. इसके बाद, राज्य सरकार के साथ पत्राचार के निरंतरता में, केंद्रीय खान मंत्रालय ने 15.6.2005 के अपने पत्र द्वारा राज्य सरकार के सचिव को लिखा, जिसमें संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की मांग की गई थी ताकि निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त की जा सके:

- (i) राज्य सरकार ने उन आवेदकों को भी अस्वीकृत कर दिया था जो पहले के आवेदक थे लेकिन राज्य में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं थे। राज्य सरकार की यह निर्धारित शर्त राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार नहीं है।
- (ii) संख्या 18, 20, 23, 29, 33, 41, 44 और 58 पर आवेदकों के मुकाबले, राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय सरकार जानना चाहती थी कि राज्य सरकार 'ठोस प्रस्ताव' से क्या तात्पर्य रखती है।
- (iii) अनुशंसित क्षेत्र और प्रस्तावित संयंत्र क्षमता के बीच व्यापक भिन्नता थी।
- (iv) दस प्रस्तावों का कुल क्षेत्रफल 3693.05 हेक्टेयर था जबकि घाटखुरी में उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 3566.54 हेक्टेयर बताया गया। यह भी कहा गया कि श्री बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के प्रस्ताव के मामले में घाटखुरी आरक्षित वन में कुल क्षेत्रफल 4692.46 हेक्टेयर दिखाया गया था।

9. इसी पृष्ठभूमि में झारखंड सरकार ने 13.9.2005 के अपने पत्र द्वारा 10 प्रस्तावों में से नौ को वापस बुलाया (जिसमें बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के पक्ष में प्रस्ताव को छोड़कर)। पत्र में विशेष रूप

से उल्लेख किया गया था कि ये प्रस्ताव सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों और दो अन्य कंपनियों द्वारा पहले से धारण किए गए क्षेत्रों में ओवरलैप करते हैं। यह उच्च न्यायालय में याचिकाओं में चुनौती दिए गए दो पत्रों में से एक था। यह पत्र इस प्रकार है:

"झारखंड सरकार

खनन और भूविज्ञान विभाग

संख्या: खनि (छाया)-78/03 (भाग)-501/M-C रांची

तारीख: 13.09.2005

प्रेषक: अरुण कुमार सिंह

सरकार के सचिव

सेवा में,

श्री अनिल सुब्रह्मण्यम

अधीन सचिव

खनन मंत्रालय

भारत सरकार

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली - 110 001।

विषय: मोजा घाट खुरी में आरक्षित वन भूमि में लौह अयस्क के खनन पट्टे के लिए भेजी गई अनुशंसाओं की वापसी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 5/40/2004/ एमIV दिनांक 30.08.2005 का संदर्भ लें। खनन और खनिज विभाग झारखंड द्वारा लौह अयस्क और मैंगनीज खनिज के खनन के लिए 10 कंपनियों को खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो मोजा घाट खुरी (पश्चिम सिंहभूम

जिला) में आरक्षित वन भूमि पर आधारित था, जो खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) और 11(5) के प्रकाश में है।"

| क्र. सं | कंपनी का नाम                                  |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1       | श्री बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड                 |
| 2       | श्री इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड                |
| 3       | श्री विमल दीप स्टील प्राइवेट लिमिटेड          |
| 4       | श्री अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 5       | श्री उज्जवल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड          |
| 6       | श्री आधुनिक एलॉय और पावर लिमिटेड              |
| 7       | श्री प्रकाश इस्पात लिमिटेड                    |
| 8       | श्री मोनेट इस्पात लिमिटेड                     |
| 9       | श्री स्टिको पावर लिमिटेड                      |
| 10      | श्री झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड           |

विभाग में विश्लेषण के अनुसार, यह स्पष्ट हो गया है कि उपरोक्त 10 प्रस्तावों में से, जो पहले भेजे गए थे, संख्या 1 पर बिहार स्पंज और आयरन लिमिटेड को छोड़कर, शेष नौ प्रस्ताव सार्वजनिक उपक्रम/ श्री जनरल प्रोड्यूस कंपनी मधु बाजार छाईबासा और श्री रुग्गता सन्स लिमिटेड छाईबासा के क्षेत्रों में ओवरलैप करते हैं।

पूर्ण विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पिछले भेजे गए दस प्रस्तावों में से, श्री बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के प्रस्ताव को छोड़कर, शेष नौ प्रस्तावों पर कानून के अनुसार विचार करने के लिए इन्हें भारत सरकार के खान मंत्रालय से वापस बुलाया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में, आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त खनन प्रस्तावों को झारखंड रांची के खनन और खनिज विभाग को वापस करें, ताकि उन पर पुनर्विचार करके राज्य सरकार के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासपूर्वक

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

10.भारत सरकार ने, हालांकि, केवल उन नौ प्रस्तावों को वापस नहीं किया, बल्कि झारखंड सरकार के पत्र में उल्लिखित कारणों पर संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया। इसने 6.3.2006 को झारखंड सरकार को एक पत्र भेजा। यह वही पत्र है जो उच्च न्यायालय में याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। पत्र इस प्रकार है:

"पंजीकृत"

भारत सरकार

खनन मंत्रालय

संख्या 5/55/2004-म.IV

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2006

सेवा में

झारखंड सरकार के सचिव,

खनन और भूविज्ञान विभाग

रांची (झारखंड)

विषय: झारखंड राज्य सरकार द्वारा मोजा बोकना, जिला पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में लौह और मैंगनीज अयस्क के खनन पट्टे के लिए विभिन्न प्रस्तावों को वापस करने का अनुरोध।

महोदय,

मुझे निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषय पर राज्य सरकार द्वारा 13.9.2005 को भेजे गए पत्र संख्या 501/M के संदर्भ में निम्नलिखित नौ प्रस्तावों को संक्षेप में अस्वीकृत कर मूल रूप में वापस किया जाए। ये प्रस्ताव पहले इस मंत्रालय को खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्व स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। इन प्रस्तावों में अनुशंसित क्षेत्र या तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा शोषण के लिए आरक्षित हैं या अन्य आवेदकों जैसे कि एम/एस रुग्नता सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस जनरल प्रोड्यूस कंपनी द्वारा रखे गए हैं:-

| क्रम संख्या | आवेदक कं. का नाम                               | राज्य सरकार सन्दर्भ/संख्या                                                                          | मौजा घाटकुरी जिला पश्चिम सिंहभूम में क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) | अतिव्याप्त क्षेत्र का विवरण              |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | मेसर्स एस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड               | i) ख.नि. (प. सिंहभूम)- 78/03- 115/डी.एस.एम./ एम<br>दिनांक 5.8.2004<br>ii) 1516/एम दिनांक 24.11.2004 | 470.06                                                         | मेसर्स जनरल प्रोड्यूस कंपनी द्वारा धारित |
| 2           | मेसर्स बिमलदीप स्टील प्राइवेट लिमिटेड          | i) ख.नि. (प. सिंहभूम)- 78/03- 131/डी.एस.एम./ एम<br>दिनांक 4.8.2005<br>ii) 519/एम दिनांक 24.11.2004  | 112.072                                                        | पीएसयू हेतु आरक्षित                      |
| 3           | मेसर्स अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | i) ख.नि. (प. सिंहभूम)- 78/03- 117/डी.एस.एम./ एम<br>दिनांक 4.8.2004<br>ii) 519/एम दिनांक 24.11.2004  | 429.00                                                         | पीएसयू हेतु आरक्षित                      |

|   |                                         |                                                                                                                   |         |                                                          |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 4 | મેસર્સ ડજ્જવલ મિનરલ<br>પ્રા. લિમિટેડ    | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-<br>78/03- 114/ડી.એસ.એમ./ એમ<br><br>દિનાંક 4.8.2004<br><br>ii) 1520/એમ દિનાંક<br>24.11.2004 | 103.00  | પીએસયૂ હેતુ<br>આરક્ષિત                                   |
| 5 | મેસર્સ અદુનિક અલોયા<br>અંડ પાવર લિમિટેડ | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-<br>78/03- 111/ડી.એસ.એમ./ એમ<br><br>દિનાંક 4.8.2004<br><br>ii) 1518/એમ દિનાંક<br>24.11.2004 | 426.875 | પીએસયૂ હેતુ<br>આરક્ષિત                                   |
| 6 | મેસર્સ પ્રકાશ<br>એસ્પાત લિમિટેડ         | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-<br>78/03- 110/ડી.એસ.એમ./ એમ<br><br>દિનાંક 4.8.2005<br><br>ii) 1515/એમ દિનાંક<br>24.11.2004 | 294.06  | પીએસયૂ હેતુ<br>આરક્ષિત                                   |
| 7 | મેસર્સ મોનેટ એસ્પાત                     | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-<br>78/03-118/ ડી.એસ.એમ./ એમ<br><br>દિનાંક 6.8.2005<br><br>ii) 1497/એમ દિનાંક<br>17.11.2004 | 705.00  | મેસર્સ રૂંગટા<br>સંસ પ્રાઇવેટ<br>લિમિટેડ દ્વારા<br>ધારિત |
| 8 | મેસર્સ સ્ટેકો પાવર<br>લિમિટેડ           | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-<br>78/03-101/03-134./ એમ<br><br>દિનાંક 16.10.2004<br><br>ii) 1515/એમ દિનાંક<br>22.01.2005  | 400.00  | મેસર્સ રૂંગટા<br>સંસ પ્રાઇવેટ<br>લિમિટેડ દ્વારા<br>ધારિત |
| 9 | મેસર્સ ઝારાખંડ એસ્પાત                   | i) ખ.નિ. (પ. સિંહભૂમ)-                                                                                            | 346.647 | મેસર્સ જનરલ                                              |

|  |                  |                                            |  |                                 |
|--|------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | प्राइवेट लिमिटेड | 78/03-12/ डी.एस.एम./ एम<br>दिनांक 4.8.2004 |  | प्रोड्यूस कंपनी<br>द्वारा धारित |
|--|------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------|

आपका विश्वासपूर्वक

(अनिल सुब्रह्मण्यम)

भारत सरकार के अधीन सचिव

11. इन अपीलों में हम मुख्य रूप से राज्य सरकार के निर्णय की वैधता से संबंधित हैं, जो खनन पट्टों के लिए अपनी सिफारिशों को वापस लेने का प्रयास कर रही है, और केंद्रीय सरकार के उस निर्णय के बाद की स्थिति जो उन सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है। हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि झारखंड सरकार ने बाद में एक और अधिसूचना जारी की थी, दिनांक 27.10.2006, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं में वर्णित क्षेत्र किसी को नहीं दिए जाएंगे, सिवाय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य के संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिकाओं में संशोधन किया और इस बाद की अधिसूचना को भी चुनौती दी। यह अधिसूचना इस प्रकार है:

झारखंड गजट

असाधारण

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

संख्या 581 8 कार्तिक 1928 (स) रांची, सोमवार 30 अक्टूबर, 2006

खनन एवं भूविज्ञान विभाग, रांची

ई अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2006

संख्या 3277 यह सामान्य जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में खनिज संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और दोहन के लिए तथा उन पर मूल्य संवर्धन के साथ खनिज

आधारित उद्योग की स्थापना के लिए, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि घाटखुरी में लोहे के अयस्क के भंडारों को निजी पक्षों के लिए अन्वेषण लाइसेंस, खनन पट्टा या अन्य किसी प्रकार से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भंडार सभी महत्वपूर्ण समय में आरक्षित रखा गया था जैसा कि बिहार राज्य की गजट अधिसूचना संख्या ए/एमएम-40510/62-6209/एम दिनांक 21 दिसंबर, 1962 और संख्या बी/एम-6-1019/68-1564/एम दिनांक 28 फरवरी, 1969 में दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित खनिजों का अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम परियोजना द्वारा दोहन के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य को अधिकतम लाभ प्रदान करेगा और राज्य में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न करेगा।

उपरोक्त अधिसूचना जनहित और राज्य के व्यापक हित में जारी की जा रही है।

आरक्षित क्षेत्र की परिभाषित समन्वय यहाँ संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

गवर्नर के आदेश द्वारा।

एस.के. सतापथी

सरकार के सचिव

### अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ:

12. (i) अन्य अपीलकर्ताओं और मोनेट के तथ्यों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि सिविल अपील संख्या 3286/2009 यानी अद्युनिक अलॉय और पावर लिमिटेड ('अद्युनिक' के संक्षेप में) के संबंध में, यह तर्क करता है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव के अग्रगण्य के आधार पर, उसने कुछ महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। उसने पहले ही 790 करोड़ रुपये की प्रस्तावित निवेश में से लगभग 82 करोड़ रुपये का निवेश किया है, और इसलिए उसके पास वचनबद्धता की रोकथाम के आधार पर एक बेहतर मामला है। अपीलकर्ता द्वारा किए गए निवेश को उचित ठहराने के लिए इसके सिविल अपील के रिकॉर्ड में अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत की गई है।

(ii) चूंकि इन सभी अपीलों के तथ्य लगभग समान हैं, हालाँकि अपीलकर्ताओं की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियाँ उठाई गई हैं, वे भी लगभग समान हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं। हालांकि, संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तथ्यों और कानून के विभिन्न पहलुओं पर अच्छे शोध के साथ जोर दिया है।

13. (i) श्री सी.ए. सुंदरम, जो इस्पात उद्योग लिमिटेड ('इस्पात' के संक्षेप में) के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने सबसे पहले यह प्रस्तुत किया कि जब संविधान भारत की सातवीं अनुसूची की सूची I प्रविष्टि 54 के तहत संघ सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए एमएमडीआर अधिनियम पारित किया गया, तब राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में किसी भी आरक्षण को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था और 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ कानून में गलत थीं। ये अधिसूचनाएँ जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(क) के तहत जारी होने का बचाव किया गया था, एमएमडीआर अधिनियम पारित होने के बाद मान्य नहीं हो सकतीं। इसका कारण यह है कि सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 23 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टियों की शर्तों के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि संख्या 54 कहती है कि खनिजों का नियमन और विकास संघ सरकार की शक्ति में है, जब तक संसद इस संबंध में सार्वजनिक हित में कोई घोषणा करती है, और ऐसी घोषणा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 2 में पाई जाती है। इस स्थिति को देखते हुए, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (अधिनियम संख्या XXX of 1950) (संक्षेप में बिहार अधिनियम) द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा सेवा में नहीं लाया जा सकता।

(ii) श्री सुंदरम ने तर्क किया कि जब ये अधिसूचनाएँ जारी की गईं तब यह क्षेत्र पहले से ही एमएमडीआर अधिनियम द्वारा कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि संसद ने पहले ही इस क्षेत्र पर कानून बनाया था। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17 और 17ए केंद्रीय सरकार को खनन संचालन करने और आरक्षण प्रभावी करने का विशेष अधिकार देती हैं। अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सरकार पर खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास तथा पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य डालती है ताकि किसी भी प्रदूषण को रोका या नियंत्रित किया जा सके जो खोज या खनन संचालन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास नहीं थीं। इसलिए, 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं में किए गए आरक्षण राज्य सरकार की शक्तियों से बाहर माने जाएंगे।

(iii) यह स्थिति तब भी होगी जब इसे खनिज अनुदान नियमावली, 1960 (संक्षेप में एम.सी. नियम 1960) की नियम 59(1)(इ) के साथ पढ़ा जाए, जो राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रों के आरक्षण और पुनः अनुदान के बारे में बात करती है। यहाँ तक कि 27.10.2006 की बाद की अधिसूचना, जो संयुक्त उद्यम का प्रावधान करती है, वह एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17ए के विपरीत है और इसलिए कानून में गलत है।

(iv) श्री सुंदरम ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि राज्य सरकार को खनन क्षेत्रों पर अंतर्निहित शक्ति थी, समान रूप से गलत था।

14. (i) अपीलकर्ता झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ('झारखंड इस्पात' के संक्षेप में) के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने मुख्य रूप से दो प्रस्तुतियाँ दीं। पहले, भारतीय संविधान की संघीय संरचना और एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी खनन केवल एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्रीय अनुमति के साथ किया जा सकता है, हालाँकि खनन राज्य सूची में शामिल है। इस संबंध में, डॉ. धवन ने इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों का उल्लेख किया, जैसे कि *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम राज्य उड़ीसा एवं अन्य* (एआईआर 1961 एससी 459), *राज्य उड़ीसा एवं अन्य बनाम मिस म.ए. टुल्लोक एवं कंपनी* (एआईआर 1964 एससी 1284) और *बैजनाथ कादियो बनाम राज्य बिहार एवं अन्य* (1969 (3) एससीसी 838), और यह प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का बाद का निर्णय अमृतलाल नथुभाई शाह बनाम भारत संघ (1976 (4) एससीसी 108), जिस पर झारखंड राज्य ने भरोसा किया और उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज करने के लिए स्वीकार किया, ने इन तीन निर्णयों पर विचार नहीं किया और उनमें निहित प्रस्तावों का सही अर्थ नहीं समझा।

(ii) दूसरी बात, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार का निर्णय एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17ए(2) के तहत अवैध था। उन्होंने जनक लाल बनाम राज्य महाराष्ट्र (1989 (4) एससीसी 121) के इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 6 का हवाला दिया ताकि अनसंशोधित नियम 59 और नए नियम 59 के बीच भेद को स्पष्ट किया जा सके। उनके अनुसार, 2006 की अधिसूचना भी अवैध थी क्योंकि यह केवल 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं का पुनरुद्धार थी।

(iii) फिर प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने एक कारखाना भी स्थापित किया है और वचनबद्धता की रोकथाम और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत पर भरोसा किया गया। यह भी तर्क किया गया कि दोनों अधिसूचनाएँ लागू नहीं हुईं और 'डेस्यूट्यूड' से ग्रस्त थीं। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के प्रावधानों के संदर्भ में असंगत तरीके से कार्य नहीं कर सकती।

15. श्री रंजीत कुमार, जो मोनेट के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दीं।

(i) राज्य सरकार को 1962 और 1969 में उन नियमों के तहत दो अधिसूचनाएँ जारी करने का अधिकार नहीं था, जैसा कि तब मौजूद थे, विशेष रूप से 1962 की अधिसूचना, क्योंकि संबंधित नियमों की नियम 58 ने राज्य सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया था।

(ii) नियम 58 को बिना किसी बचत धारा के संशोधन अधिनियम संख्या 36 of 1986 द्वारा हटाया गया है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने वाली 1962 और 1969 की दोनों अधिसूचनाएँ 'डेस्यूट्यूड' के कारण प्रभावित हुईं, क्योंकि इन पर कभी कार्य नहीं किया गया।

(iv) नियम 63ए की शर्त को देखते हुए, एक बार सिफारिश किए जाने पर, राज्य सरकार कार्यविहीन हो जाती है, और उसके पास सिफारिश को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होता।

(v) मोनेट का सुनवाई का अधिकार प्रभावित हुआ क्योंकि राज्य सरकार का आवेदन खारिज करने का निर्णय उसके पीछे लिया गया था। इसे खनन पट्टा देने से पहले एम.सी. नियम 1960 के नियम 26 के तहत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, उनके लिए नियम 54 के तहत केंद्रीय सरकार में पुनरीक्षण दाखिल करने का उपाय प्रभावित हुआ।

(vi) अपीलकर्ताओं ने यह तथ्य विवादित किया कि जब उनके आवेदनों को खारिज किया गया था, तब मेसर्स रूंगटा सन्स के पक्ष में कोई जीवित आवंटन था। यह प्रस्तुत किया गया कि मेसर्स रूंगटा सन्स के पक्ष में आवंटन पहले ही समाप्त हो चुका था, और वास्तव में उन्होंने 2006 में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। मोनेट को अनुशंसित क्षेत्र किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य किसी पूर्व आरक्षण के अंतर्गत नहीं था।

(vii) बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के पक्ष में अन्यायपूर्ण भेदभाव था क्योंकि उनका मामला मोनेट के मामले के समान माना जाना चाहिए था।

(viii) राज्य सरकार का निर्णय वचनबद्धता की रोकथाम के सिद्धांत से प्रभावित था, क्योंकि इस बीच मोनेट ने भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार को ₹50 लाख जमा किए थे, और वह आवंटन की उम्मीद में आगे कदम उठा रहा था।

(ix) एमएमडीआर अधिनियम और एम.सी. नियमों की धाराएँ इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए कि नियामक शासन केंद्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया है, और राज्य सरकार को आरक्षण लगाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

16. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता, जो सी.ए. संख्या 3290/2009 में प्रकाश इस्पात लिमिटेड के लिए उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, अधिनियम की धाराएँ 5 से 13 छोटे खनिजों पर लागू नहीं होती हैं, और राज्य सरकार की शक्ति केवल अधिनियम की

धारा 15 के तहत छोटे खनिजों को नियंत्रित करने तक सीमित है। इस संबंध में उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय *डी. के. त्रिवेदी और सन्स बनाम राज्य गुजरात* (1986 पूरक(1) एससीसी 20) का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केवल केंद्रीय सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास तब तक कोई शक्ति नहीं थी जब तक कि 1980 में नियम 59 में संशोधन नहीं किया गया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रमुख खनिजों के संबंध में आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि नियम बनाने की शक्ति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और उन्होंने हुकम चंद बनाम भारत संघ (1972 (2) एससीसी 601) पर भरोसा किया। उन्होंने तर्क किया कि एम.सी. नियम 1960 की नियम 59 के प्रावधान के अनुसार, एक क्षेत्र जिसे आरक्षित किया गया है, उसे निजी क्षेत्र को पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय भारतीय धातु और फेरो एलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1992 पूरक (1) एससीसी 91) का उल्लेख किया।

17. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी और एल. नागेश्वर राव, जो अद्युनिक के लिए उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त संशोधित नियम 59 पर भरोसा करके गलती की है। 1962 की अधिसूचना उस समय जारी की गई थी जब खोज और खनन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस न्यायालय का निर्णय एयर इंडिया बनाम भारत संघ (1995 (4) एससीसी 734) पर निर्भर करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ कानून केवल तभी जीवित रह सकता है जब उसे बचाया जाए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवादित अधिसूचनाएँ केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जारी की गई थीं और इसलिए कानून में गलत थीं।

(i) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.सी. भारुका, जो अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ('अभिजीत' के संक्षेप में) के लिए उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय सरकार ने खनिजों को निजी प्रतिभागियों के लिए खोल दिया है। 1962 में, सरकार के पास किसी भी कार्यकारी शक्ति को प्रदान करने वाले किसी कानून की अनुपस्थिति में अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम राज्य बिहार (1990 (4) एससीसी 557) का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि राज्य केवल किसी कानून या अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी आदेश द्वारा कार्य कर सकता है और अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा कि 1962 की अधिसूचना अनसंशोधित नियम 59 के तहत जारी की गई थी, और उस समय ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके अनुसार, बाद की अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 जो धारा 17ए(2) के तहत जारी की गई थी, भी कानून में गलत थी क्योंकि इसे केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जारी किया गया था।

(ii) फिर श्री भारुका ने प्रस्तुत किया कि अभिजीत का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को 06.08.2004 को भेजा गया था। राज्य सरकार ने इसे 13.09.2005 को वापस ले लिया, और केंद्रीय सरकार ने इसे 06.03.2006 को खारिज कर दिया। इस बीच याचिकाकर्ता ने निवेश के लिए कदम उठाए। उन्होंने वचनबद्धता की रोकथाम के सिद्धांत का महत्व स्पष्ट करने के लिए दो निर्णयों पर भरोसा किया: मिस मोटीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (1979 (2) एससीसी 409) और राज्य पंजाब बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड (2004 (6) एससीसी 465)। उन्होंने अभिजीत द्वारा दायर अवमानना याचिका पर चर्चा करते हुए कहा कि अभिजीत को इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुसार पट्टा दिया जाना चाहिए था।

### **झारखंड राज्य की ओर से उत्तर**

19. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा, जो झारखंड राज्य के लिए उपस्थित हैं, ने राज्य सरकार की शक्ति को उसके क्षेत्र में स्थित खदानों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के संबंध में बताया कि यह राज्य की खदानों के स्वामित्व से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि ये खदानें और खनिज पूरी तरह से राज्य के पास हैं, और यह स्थिति बिहार अधिनियम की धारा 4(क) में निहित संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामों की घोषणा से मजबूत होती है। इस प्रावधान की वैधता को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राज्य बिहार बनाम कामेश्वर सिंह (एआईआर 1952 एससी 252) में पहले ही स्वीकार किया था। किसी भी मामले में, यह अधिनियम नवम अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 1 पर रखा गया है, जिसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था और यह अनुच्छेद 31-बी द्वारा संरक्षित है। जैसा कि इस न्यायालय ने वामन राव बनाम भारत संघ (1981 (2) एससीसी 362) में कहा था, यह अधिनियम स्पष्ट रूप से चुनौती से परे है। राज्य के पास भूमि और उसमें निहित खनिजों के मालिक के रूप में किसी भी क्षेत्र को दोहन के लिए आरक्षित करने की अंतर्निहित शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत राज्य का संप्रभु कार्यकारी अधिकार किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने और संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अपने खनिजों के दोहन के लिए भूमि आरक्षित करने की शक्ति को शामिल करता है।

20. श्री सिन्हा ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास खदानों के मालिक के रूप में निपटने का अधिकार और एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। एमएमडीआर अधिनियम राज्य की भूमि में स्थित खदानों और खनिजों की स्वामित्व को बाधित नहीं करता है। राज्य में स्थित खदानों और खनिजों से संबंधित उचित अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्ति एमएमडीआर अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा नहीं छीनी गई है। वर्तमान मामले में केंद्रीय सरकार ने उच्च

न्यायालय में दाखिल किए गए अपने प्रतिवाद पत्र में अनुच्छेद 5(क) और अनुच्छेद 10 में 1962 एवं 1969 की अधिसूचनाओं की जांच पर आरक्षण को स्वीकृत किया है। यह उस आदेश से अलग था, दिनांक 6.3.2006, जिसने अपीलकर्ताओं के प्रस्तावों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त नौ प्रस्तावों में अनुशंसित क्षेत्र या तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित थे या मेसर्स रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जनरल प्रोड्यूस कंपनी द्वारा धारण किए गए क्षेत्रों पर ओवरलैप करते थे। केंद्रीय सरकार द्वारा इस अपील में दाखिल किए गए प्रतिवाद पत्र में विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राज्य सरकार 'खनिजों की मालिक' है।

21. श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि 1962 और 1969 की अधिसूचनाएँ झारखंड राज्य के निर्माण के बाद भी लागू और संरक्षित थीं, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 के कारण है, जो कहता है कि पुनर्गठन से पूर्व मौजूदा कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उन्हें संशोधित, निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जाता। श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि झारखंड राज्य ने वास्तव में अपनी अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 द्वारा 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं को फिर से दोहराया था।

22. उन्होंने कहा कि विवादित अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्ति एमएमडीआर अधिनियम और उस समय लागू एम.सी. नियमों की नियम 58 और 59 के तहत पूरी तरह से उपलब्ध थी। अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 स्पष्ट रूप से एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17ए (2) से संबंधित थी। संबंधित अधिसूचनाओं में शक्ति का स्रोत उल्लेख न होने मात्र से उन्हें अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता। श्री सिन्हा ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस न्यायालय का निर्णय *डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम राज्य बिहार* (एआईआर 1966 एससी 740) के अनुच्छेद 13 का हवाला दिया।

23. डिस्वेट्यूड के सिद्धांत के संबंध में, श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि इस सिद्धांत के लागू होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात् (i) एक महत्वपूर्ण अवधि की अनदेखी होनी चाहिए, और (ii) एक महत्वपूर्ण समय के लिए विपरीत प्रथा होनी चाहिए। इस मामले में ऐसी कोई अनदेखी या विपरीत प्रथा नहीं दिखाई गई। खनन क्षेत्र को आरक्षित रखा गया है, और आरक्षित क्षेत्र में किसी को भी खनन पट्टा नहीं दिया गया है, जो सूचनाओं के विपरीत है। उन्होंने इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 15 पर भरोसा किया, जो *राज्य महाराष्ट्र बनाम नारायण शंकर पुराणिक* में है, जो 1982 (3) सेक 519 में रिपोर्ट किया गया था, और *नगरपालिका निगम पुणे बनाम भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड* के पैराग्राफ 30 से 36 में, जो 1995 (3) सेक 434 में रिपोर्ट किया गया था, साथ ही *कॅन्टोनमेंट बोर्ड एमएचओडब्लू बनाम एम.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम* के पैराग्राफ 16 पर, जो 1997 (9) एससीसी 450 में रिपोर्ट किया गया था।

24. वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षाओं पर प्रस्तुतियों के संबंध में, श्री सिन्हा ने कहा कि ये सिद्धांत समानता पर आधारित हैं, और जब कोई मामला एक अधिनियम द्वारा शासित होता है, तो समानता को रास्ता देना होगा। इसके अलावा, जो वादे किए गए थे वे सार्वजनिक नीति के खिलाफ थे और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने *अमृत वानस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य* के पैराग्राफ 10 पर भरोसा किया, जो 1992 (2) एससीसी 411 में रिपोर्ट किया गया था, एमपी. माथुर बनाम ओटीसी के पैराग्राफ 12 पर, जो 2006 (13) सेक 706 में रिपोर्ट किया गया था, और *सांडूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य* के पैराग्राफ 83 पर, जो 2010 (13) सेक 1 में रिपोर्ट किया गया था।

25. श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं और राज्य सरकार के बीच का एमओयू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत एक अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता। यह न तो लागू करने योग्य था और न ही बाध्यकारी। इस एमओयू के आधार पर, राज्य सरकार ने एक सिफारिश की थी जो केवल एक प्रस्ताव थी। इसके अलावा, किसी को भी खनन पट्टे की स्वीकृति या नवीनीकरण का कोई कानूनी या स्थायी अधिकार नहीं था। इस संबंध में, उन्होंने *तमिलनाडु राज्य बनाम मिस हिंद स्टोन* के पैराग्राफ 13 पर भरोसा किया, जो 1981 (2) एससीसी 205 में रिपोर्ट किया गया था, *धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ* के पैराग्राफ 4 पर, जो 1996 (6) एससीसी 702 में रिपोर्ट किया गया था, *एमपी. राम मोहन राजा बनाम तमिलनाडु राज्य* के पैराग्राफ 13 पर, जो 2007 (9) एससीसी 78 में रिपोर्ट किया गया था, और *कर्नाटक राज्य बनाम बी. सिक्स हॉलीडे रिसॉर्ट्स (पी) लिमिटेड* के पैराग्राफ 19 से 22 और 28 पर, जो 2010 (5) एससीसी 186 में रिपोर्ट किया गया था।

26. अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, श्री सिन्हा ने यह इंगित किया कि वर्तमान मामले में विवाद पूरी तरह से इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अमृतलाल (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा कवर किया गया है जिसमें तथ्य लगभग समान थे। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके क्षेत्राधिकार में खनिजों का स्वामित्व राज्य सरकार को है, और इसके पास सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ के लिए इसके दोहन को आरक्षित करने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय और *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. तुल्लोक एंड कंपनी* और *बैजनाथ कादियो* मामलों में तीन निर्णयों के बीच कोई संघर्ष नहीं है।

### भारत संघ की ओर से उत्तर

27. श्री अशोक भान, जो भारत संघ की ओर से प्रस्तुत हुए, ने श्री एफ सिन्हा की प्रस्तुतियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में खनिजों का स्वामित्व झारखंड राज्य का है, और इसके पास एमएमडीआर अधिनियम के तहत उचित रूप से निपटने का अधिकार है। इसके पास सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों के विशेष उपयोग के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करने का पूरा अधिकार था, या ओवरलैपिंग से बचने के लिए निर्देश देने का अधिकार था। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की केंद्रीय सरकार ने जांच की। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.09.2005 में निहित कारणों को स्वीकार किया, और इसलिए दस प्रस्तावों में से नौ को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार द्वारा दायर हलफनामे से निम्नलिखित पैराग्राफ पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। अपने प्रतिवाद हलफनामे के पैराग्राफ 5 (क) में, मंत्रालय में खनन के अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि 'राज्य सरकार का अनुरोध केंद्रीय सरकार द्वारा जांचा गया है, और याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुशंसित प्रस्ताव सहित सभी नौ प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए हैं और 06.03.2006 को राज्य सरकार को वापस कर दिए गए हैं।' पैराग्राफ 10 में आगे कहा गया:

"10. जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार, जो प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को खनन और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए थे, वे या तो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दोहन के लिए आरक्षित क्षेत्रों में आते हैं या पहले से अन्य लोगों द्वारा रखे गए क्षेत्रों के साथ ओवरलैप करते हैं और इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार द्वारा जांच किए जाने के बाद, प्रस्ताव को 06.03.2006 को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा खनन पट्टे के तहत क्षेत्र देने की इच्छा रखती है, तो उसे पहले उस क्षेत्र को डी-आरिजर्व करना होगा, इसे खनिज संविदा नियम, 1960 के नियम 59 (1) के तहत अधिसूचित करना होगा और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।"

### **हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ**

28. (i) श्री दास, जो मेसर्स रूंगटा सन्स की ओर से उपस्थित हुए, ने बताया कि रुघंता के पक्ष में एक खनन पट्टा था और वे इसके नवीनीकरण का अधिकार रखते थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं को रुघंता सन्स को आवंटित खनन क्षेत्र के साथ किसी भी तरह से ओवरलैपिंग वाला कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता था।

(ii) वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री नारसिंहा, विकास सिंह और कृष्णन वेंगोपल हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से इन अपीलों का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए। उनकी प्रस्तुतियाँ श्री सिन्हा की तरह ही थीं।

29.इन अपीलों की सुनवाई समाप्त होने के बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न एक अन्य एसएलपी डब्लू. ए. संख्या 6288/2006 (*जियो मिनरल्स एंड मार्केटिंग (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य*) पर विचार करने आए जिसमें एक मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खनन क्षेत्रों के आरक्षण से संबंधित था। उस मामले में संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री हरीश साल्वे, केके वेंगोपल और आरके द्विवेदी को इस मुद्दे पर सुना गया। उनकी प्रस्तुतियाँ वर्तमान अपीलों में उपस्थित संबंधित पक्षों की प्रस्तुतियों के समान थीं।

### **प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार:**

### **झारखंड राज्य की खनिजों और खनन क्षेत्रों से संबंधित अधिकारिता**

30.झारखंड राज्य और भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया कि राज्य के क्षेत्र में खनिजों और खानों का स्वामित्व झारखंड राज्य का है, और इसके पास इन्हें संभालने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (क) से प्राप्त होता है। इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह चुनौती दी कि एमएमडीआर अधिनियम के पारित होने के बाद राज्य सरकार के अधिकार में कमी आई है। इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए, हमें बिहार अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराओं पर ध्यान देना चाहिए। इस अधिनियम की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में घोषित किया गया है:

'एक अधिनियम जो राज्य को भूमि के मालिकों और पट्टेदारों के हितों का हस्तांतरण प्रदान करता है, जिसमें पेड़, जंगल, मछली पालन, जलकर, फेरी, हाट, बाजार, खनिज और खानों में शामिल हित शामिल हैं और बिहार राज्य के लिए एक भूमि आयोग की स्थापना करने के लिए प्रदान करता है जिसके पास राज्य सरकार को ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अपनाई जाने वाली कृषि नीति पर सलाह देने का अधिकार होगा और इससे संबंधित अन्य मामलों के लिए।'

अधिनियम की धारा 3 में राज्यों में संपत्तियों और पट्टों के स्वामित्व की अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। धारा 4 में स्वामित्व के परिणामों का प्रावधान है, अर्थात् वे सभी बंधनों से मुक्त होकर राज्य में पूरी तरह से स्वामित्व में आएंगे। बिहार अधिनियम की धारा 4 (क) इस प्रकार है:

### **4. राज्य में संपत्ति या पट्टे के स्वामित्व के परिणाम-**

[किसी अन्य कानून में निहित किसी भी प्रावधान या किसी अनुबंध के बावजूद और धाराओं 3, 3ए और 38 के प्रावधानों का अनुपालन न होने या अनुपयुक्त अनुपालन के बावजूद (धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3ए की उपधारा (1) को छोड़कर), जब उपधारा (1) के तहत अधिसूचना

प्रकाशित होती है, धारा 3 या धारा 3ए की उपधारा (1) या उपधारा (2), निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे और हमेशा उत्पन्न माने जाएंगे, अर्थात्:]

(क) [xxx] ऐसी संपत्ति या पट्टा जिसमें किसी भवन या भवन के भाग में मालिक या पट्टेदार के हित शामिल हैं जो मुख्य रूप से उस संपत्ति या पट्टे के किराए की वसूली के लिए कार्यालय या कटचरी के रूप में उपयोग किया जाता है, और उसके पेड़, जंगल, मछली पालन, जलकर, हाट, बाजार, मेले और फेरी तथा सभी अन्य सैराती हितों में उसके हित भी शामिल हैं, साथ ही उसकी सभी उपसतह सहित खनिजों और खानों में किसी भी अधिकारों सहित चाहे वे खोजे गए हों या न हों, या चाहे उनका उपयोग किया गया हो या नहीं, ऐसे अधिकारों सहित जो उस संपत्ति या पट्टे में शामिल हैं (रैयतों या अंडर-रैयतों के हितों को छोड़कर) वह संपत्ति की स्वामित्व तिथि से प्रभावी रूप से राज्य में पूरी तरह से बंधनों से मुक्त हो जाएगी और उस मालिक या पट्टेदार का उस संपत्ति में कोई हित नहीं रहेगा अन्यथा इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षित किए गए हितों को छोड़कर।

इसके अलावा, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पहले ही इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा राज्य बिहार बनाम कामेश्वर सिंह मामले में स्थापित की जा चुकी है जो एआईआर 1952 एससी 252 में विस्तृत निर्णय द्वारा रिपोर्ट किया गया था जहां अंततः पैराग्राफ 237 में न्यायालय ने बिहार अधिनियम को वैध घोषित किया था सिवाय धारा 4(ख) और धारा 23(फ) के जो असंवैधानिक और अमान्य घोषित किए गए थे।

31.स्वामित्व अधिकारों का एक जटिल समूह को दर्शाता है जैसा कि प्रसिद्ध लेखक सालमंड ने अपनी न्यायशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक में कहा है (बारहवीं संस्करण के पृष्ठ 246 देखें):

#### 44. स्वामित्व का विचार

स्वामित्व एक व्यक्ति और उस वस्तु के बीच के संबंध को दर्शाता है जो उसके स्वामित्व का विषय है। यह अधिकारों के एक जटिल समूह में निहित है, जिनमें से सभी अधिकार वास्तविक अधिकार हैं, जो सभी के खिलाफ प्रभावी होते हैं और केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इन अधिकारों में से कुछ अनुपस्थित हो सकते हैं, सामान्य स्वामित्व की स्थिति निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकती है।

पहला, मालिक के पास उस चीज़ को रखने का अधिकार होगा जो वह स्वामित्व में रखता है.....

दूसरा, सामान्यतः मालिक के पास उस चीज़ का उपयोग और आनंद लेने का अधिकार होता है: इसे प्रबंधित करने का अधिकार, अर्थात् यह तय करने का अधिकार कि इसे कैसे उपयोग किया जाएगा; और इससे होने वाली आय का अधिकार। जबकि रखने का अधिकार एक सख्त अर्थ में अधिकार है, ये अधिकार वास्तव में स्वतंत्रताएँ हैं: मालिक के पास उस चीज़ का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है, अर्थात् उसे इसका उपयोग न करने की कोई बाध्यता नहीं होती, जबकि अन्य लोग इसका उपयोग न करने या हस्तक्षेप न करने की बाध्यता में होते हैं।

झारखंड राज्य का खानों और खनिजों से संबंधित अधिकार, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षण शामिल है, या खनन पट्टे प्रदान करते समय ओवरलैपिंग से बचने के लिए निर्देश देने का अधिकार स्पष्ट रूप से उन खानों और खनिजों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है।

32.(i) अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार की शक्ति प्रविष्टि 23, सूची II के तहत सातवें अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 54 की प्रावधानों के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि 54 कहती है कि खनिजों और खानों के विकास का नियमन संघ सरकार की शक्ति में है जब तक कि इस संबंध में संसद द्वारा कोई घोषणा की जाती है, और ऐसी घोषणा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 2 में की गई है। ऐसा कहने के बाद, संघ सरकार के इस नियंत्रण की सीमा को समझना आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए हमें अधिनियम की योजना को देखना होगा जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को खनिजों और खानों से निपटने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। यह इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा *इश्वरि खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश* मामले में अपनाई गई दृष्टिकोण था, जो 1980 (4) सेक 136 में रिपोर्ट किया गया था और बाद में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम राज्य उड़ीसा* मामले में 1991 सप्लीमेंट (1) सेक 430 में रिपोर्ट किया गया था।

(ii) इश्वरि खेतान (उपरोक्त) में संविधान पीठ यूपी शुगर अंडरटेकिंग्स (अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 की वैधता पर विचार कर रही थी जिसे यूपी राज्य द्वारा पारित किया गया था। यह तर्क किया गया कि प्रविष्टि 24 सूची II के तहत उद्योगों पर राज्य की विधायी शक्ति उस संदर्भ में संसद द्वारा प्रविष्टि 52 सूची I के तहत किए गए घोषणा तक सीमित कर दी गई है। संबंधित प्रावधानों की जांच करने के बाद, संविधान पीठ ने पैराग्राफ 24 में कहा:

"24. इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्यों की विधायी शक्ति प्रविष्टि 24 सूची II के तहत केवल उसी सीमा तक कम हो जाती है जब संघ द्वारा संसद द्वारा घोषित उद्योग पर नियंत्रण ग्रहण किया जाता है जैसा कि विधायी अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया

हैं और ऐसे अधिनियम द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र कमी की माप है। ऐसी कमी के अधीन, शेष पर राज्य विधानमंडल को घोषित उद्योग पर विधायी शक्ति होगी बिना किसी तरह से कब्जा किए गए क्षेत्र पर आक्रमण किए बिना ....."

(iii) उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ खनन पर उड़ीसा राज्य द्वारा लगाए गए एक उपकर की वैधता पर विचार कर रही थी, और राज्य विधानमंडल की क्षमता को एमएमडीआर अधिनियम और संघ सूची की प्रविष्टि 54 के संदर्भ में चुनौती दी गई थी। इश्वरि खेतान (उपरोक्त) के निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने पैराग्राफ 49 में कहा:

"..... जैसा कि इश्वरि खेतान में बताया गया है, संसद का केवल यह घोषणा करना कि किसी उद्योग या खनिजों और खानों के नियमन एवं विकास को संघ के नियंत्रण में होना आवश्यक है प्रविष्टि 52 या प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानमंडलों को उन क्षेत्रों पर अपनी विधायी शक्तियों से वंचित नहीं करता जो सूची II या सूची III में विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा कवर किए गए हैं। विशेष रूप से, प्रविष्टि 54 के तहत घोषित मामलों में यह विधायी शक्ति केवल उसी सीमा तक कम होती है जब संघ उस घोषणा के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है जैसा कि उस घोषणा को बनाने वाले विधायी अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। कमी की माप उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जो उस घोषणा के अनुसरण में तैयार किए गए अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है ....."

33. इस पृष्ठभूमि पर हम एमएमडीआर अधिनियम की संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 (1) कहती है कि अन्वेषण या खनन संचालन लाइसेंस या पट्टे के प्रावधानों के अनुसार किए जाने चाहिए। धारा 4(3) राज्य सरकार को राज्य क्षेत्र में इन संचालन को प्रारंभ करने से नहीं रोकती है हालांकि, जब यह पहले अनुसूची में खनिजों की बात आती है तो इसे केंद्रीय सरकार से पूर्व परामर्श लेने के बाद किया जाना चाहिए। यह धारा 4 इस प्रकार पढ़ी जाती है:

#### **4. अन्वेषण या खनन संचालन लाइसेंस या पट्टे के तहत होंगे:**

कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई अन्वेषण, खनन या खनन संचालन नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वह इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी किए गए अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या, जैसा मामला हो, खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार हो:

प्रावधान है कि इस उपधारा में कुछ भी किसी क्षेत्र में अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा की शर्तों और नियमों के अनुसार किए गए किसी भी अन्वेषण या खनन संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले जारी किया गया था और जो उस प्रारंभ पर प्रभावी है:

[अतिरिक्त प्रावधान है कि इस उपधारा में कुछ भी भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, [परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय], किसी भी राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय (जिसे भी नाम दिया गया हो), और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, जो कंपनियों अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है, द्वारा किए गए किसी भी अन्वेषण संचालन पर लागू नहीं होगा:

यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा में कुछ भी गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रभावी किसी भी खनन पट्टे (चाहे उसे खनन पट्टा, खनन संविदा या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) पर लागू नहीं होगा।

(1ए) कोई व्यक्ति किसी खनिज को इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार परिवहन या संग्रहित नहीं करेगा या परिवहन या संग्रहित करने का कारण नहीं बनेगा।

(2) [कोई अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा] इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार न ही दिया जाएगा।

[(3) कोई राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से पूर्व परामर्श करने के बाद और धारा 18 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 1 [किसी भी खनिज के संबंध में अन्वेषण, अन्वेषण या खनन संचालन करेगी जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है] उस राज्य के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जो पहले से किसी अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत न हो।

34. अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने का अधिकार उन शर्तों पर विशेष रूप से राज्य सरकार के पास सुरक्षित रखा गया है जो अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित हैं। हालांकि, पहले अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में यह जोड़ा गया है कि केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए, अधिनियम की पहले अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, यह केवल केंद्रीय सरकार की पूर्व परामर्श और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए। यह प्रावधान राज्य सरकार की स्वामित्व और अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित खानों से निपटे। केवल प्रतिबंध पहले अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में है। इस अनुसूची का भाग-सी लोहे की

अयस्क और मैंगनीज अयस्क को प्रविष्टि संख्या 6 और 9 में शामिल करता है। यह धारा 5 इस प्रकार पढ़ी जाती है:

### 5. अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टों के अनुदान पर प्रतिबंध

(1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को [अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा] नहीं देगी जब तक कि वह व्यक्ति-

(ए) भारतीय नागरिक न हो, या कंपनियों अधिनियम, 1956 (1 of 1956) की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कंपनी न हो; और

(बी) ऐसे शर्तों को पूरा न करता हो जो निर्धारित की जा सकती हैं:

प्रावधान है कि पहले अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में, कोई [अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा] केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दिया जाएगा।

व्याख्या.- इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा-

(ए) यदि वह एक फर्म या अन्य व्यक्तियों के संघ का मामला है, तो केवल तभी जब फर्म के सभी सदस्य या संघ के सदस्य भारत के नागरिक हों; और

(बी) यदि वह एक व्यक्ति है, तो केवल तभी जब वह भारत का नागरिक हो।

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि-

(ए) यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टा मांगा गया है, उसका पहले अन्वेषण किया गया है या उसमें खनिज सामग्री की उपस्थिति अन्यथा स्थापित की गई है; और

(बी) उस क्षेत्र में खनिज जमा के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई खनन योजना हो, या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, उस श्रेणी के खानों के संबंध में जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

35. अधिनियम की धारा 10 आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आवेदन राज्य सरकार को किया जाना चाहिए, और यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह अनुमति पत्र, लाइसेंस या पट्टा देने का निर्णय करे। यह धारा इस प्रकार है:

10. अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टों के लिए आवेदन

(1) किसी भी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार के स्वामित्व में हैं, [अन्वेषण अनुमति पत्र, अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा] का आवेदन संबंधित राज्य सरकार को निर्धारित रूप में किया जाएगा और इसे निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होता है, वहां आवेदक को निर्धारित समय और निर्धारित रूप में इसकी प्राप्ति का स्वीकृति पत्र भेजा जाएगा।

(3) इस धारा के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए [अनुमति पत्र, लाइसेंस या पट्टा] देने या न देने का निर्णय ले सकती है।

36. फिर से, यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह पट्टे देने के मामलों में प्राथमिकता दे, हालांकि यह अधिकार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि जिसने पहले अन्वेषण या अन्वेषण कार्य किया है, उसे उस भूमि पर संभावित लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार होगा। उपधारा 2 कहती है कि यदि किसी क्षेत्र को पहले अन्वेषण या खनन के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, तो पहला प्राप्त आवेदन प्राथमिकता से विचारित किया जाएगा। हालांकि, यह आगे कहा गया है कि यदि किसी विशेष तिथि तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो उस तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा। धारा 11 की उपधारा 3 उन कारकों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें लाइसेंस देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(3) उपधारा (2) में संदर्भित मामले निम्नलिखित हैं:-

(ए) आवेदक द्वारा अन्वेषण संचालन, अन्वेषण संचालन या खनन संचालन में विशेष ज्ञान या अनुभव;

(बी) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(सी) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित तकनीकी स्टाफ की प्रकृति और गुणवत्ता;

(डी) खानों और उद्योग में निवेश जो आवेदक करने का प्रस्ताव करता है जो खनिजों पर आधारित हैं;

(इ) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

उपधारा 5 कहती है कि यदि कोई विशेष कारण हैं, तो राज्य उस पक्ष को लाइसेंस दे सकता है जिसका आवेदन समय पर बाद में प्राप्त हुआ हो, लेकिन विशेष कारणों को दर्ज करने के बाद। यह उपधारा फिर से स्पष्ट करती है कि यदि किसी निर्दिष्ट पहले अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज से संबंधित कोई ऐसा बाहर से आवंटन किया जाना है, तो केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। इसलिए, हालांकि केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में आवेदनों को अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है, यह राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण को नहीं छीनता जो उसके क्षेत्र में स्थित खानों और खनिजों पर है।

37. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुंदरम ने तर्क किया कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17 और 17ए केंद्रीय सरकार को खनन संचालन प्रारंभ करने और आरक्षण प्रभावी करने का विशेष अधिकार देती हैं। अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सरकार पर पर्यावरण की रक्षा करने और खनन संचालन से होने वाले प्रदूषण को रोकने का कर्तव्य डालती है। ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास नहीं थीं। इसलिए, 1962 और 1969 की सूचनाओं में आरक्षण राज्य सरकार की शक्तियों से बाहर थे। इस प्रकार, अधिनियम की धाराएँ 17 और 17(ए) राज्य सरकार की अधिकारिता में कमी लाने के लिए प्रस्तुत की गईं। धारा 17 (1) केंद्रीय सरकार को कुछ भूमि पर अन्वेषण और खनन संचालन प्रारंभ करने का अधिकार देती है। हालाँकि, ऐसे संचालन भी केवल राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद किए जाने चाहिए जैसा कि इसकी उपधारा (2) में कहा गया है। इसके अलावा, उपधारा (3) केंद्रीय सरकार से भी अन्वेषण अनुमति पत्र शुल्क या अन्वेषण शुल्क, रॉयल्टी, सतह किराया या मृत किराया भुगतान करने की आवश्यकता होती है जैसे मामला हो। धारा 17ए केंद्रीय सरकार को किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार देती है जो किसी भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं हो ताकि किसी भी खनिजों का संरक्षण किया जा सके। हालाँकि उस शक्ति का प्रयोग भी राज्य सरकार से परामर्श करके किया जाना चाहिए। इसी तरह, धारा 17ए की उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार भी किसी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है, हालांकि केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से। इस प्रकार ये धाराएँ और धारा 18 के तहत केंद्रीय सरकार पर डाला गया कर्तव्य राज्य सरकार के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता जो उसके क्षेत्र में स्थित खानों और खनिजों पर होता है, या उन्हें कानून द्वारा प्रदान किए गए अनुसार संभालने का अधिकार रखता है।

38. एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों में कुछ नियम शामिल हैं। हालांकि, यह कहना कि कुछ प्रावधान शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं, एक बात है, और यह कहना कि कोई शक्ति नहीं है, दूसरी बात है। अधिनियम के प्रावधान किसी भी तरह से राज्य सरकार के उस अधिकार को नहीं छीनते या सीमित नहीं करते हैं जो सार्वजनिक हित में खानों के क्षेत्र को आरक्षित करने का है, जो अधिकार खानों के राज्य सरकार में स्वामित्व से उत्पन्न होता है। यह उसके खानों के स्वामित्व में अंतर्निहित है।

वर्तमान मामले में हम राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.9.2005 और केंद्रीय सरकार के पत्र दिनांक 6.3.2006, और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 की चुनौती से संबंधित हैं। यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि केंद्रीय सरकार को पत्र दिनांक 6.3.2006 में निहित दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है। जहां तक अधिसूचना 27.10.2006 का संबंध है, यह भी स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 17ए (2) से संबंधित है। यह धारा 17ए (2) इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"(2) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से किसी भी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, ताकि वह एक सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से अन्वेषण या खनन संचालन प्रारंभ कर सके जो उसके द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित हो और जहां वह ऐसा करने का प्रस्ताव रखती है, उसे आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की सीमाएँ और उन खनिजों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।"

जैसा कि देखा जा सकता है, यह उपधारा किसी नए क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है जो पहले से किसी सरकारी कंपनी या निगम के तहत नहीं है, और जहां ऐसा प्रस्ताव किया गया हो। अधिसूचना 27.10.2006 पहले की सूचनाओं का उल्लेख करती है जो 1962 और 1969 में जारी की गई थीं जिनके तहत घाटकुरी वन में खनन क्षेत्र पहले से आरक्षित थे, और राज्य सरकार के निर्णय को दोहराती है कि घाटकुरी क्षेत्र में पहले से आरक्षित खनिजों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं द्वारा किया जाता रहेगा। इसलिए, इस अधिसूचना 27.10.2006 को केंद्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

39. जब पत्र दिनांक 13.9.2005 की चुनौती का मामला आता है, तो यह देखा जाता है कि राज्य सरकार इसमें कहती है कि दस प्रस्तावों में से नौ सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निर्धारित क्षेत्रों पर ओवरलैप करते हैं और दो अन्य कंपनियों के लिए, और इसलिए प्रस्ताव वापस बुला लिए गए थे। इस तरह का निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार के पास उसके खानों के स्वामित्व के कारण होती है, हालांकि शक्ति के स्रोत का कोई संदर्भ नहीं हो सकता। किसी विशेष धारा या नियम का संदर्भ न होना जो शक्ति का स्रोत बताता हो, राज्य सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही इस न्यायालय ने डॉ. राम मनोहर लोहिया (उपरोक्त) मामले में कहा था कि शक्ति का स्रोत बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

40. अपीलकर्ताओं ने नियम 58 और 59 का उल्लेख किया है ताकि यह तर्क किया जा सके कि ये नियम राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खानों को आरक्षित करने की शक्ति नहीं देते हैं। इसलिए हम समय-समय पर संशोधित एम.सी. नियमों के नियम 58 और 59 का उल्लेख कर सकते हैं।

एम.सी. नियमों का नियम 58 और 59 जो 1960 में बनाए गए थे इस प्रकार हैं:

"58. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्रों की उपलब्धता की अधिसूचना- (1) कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत था या जिसके संबंध में अनुदान देने का आदेश दिया गया था लेकिन आवेदक लाइसेंस या पट्टा निष्पादित होने से पहले मर गया था, जैसा मामला हो सकता है, या जिसके संबंध में लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश उप-नियम (1) धारा 15 या उप-नियम (1) धारा 31 के तहत रद्द किया गया था, वह अनुदान देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक-

(ए) इस संबंध में धारा 21 के उप-नियम (2) या धारा 40 के उप-नियम (2) में संदर्भित रजिस्टर में स्याही से प्रविष्टि न की गई हो; और

(बी) जिस तिथि से क्षेत्र अनुदान देने के लिए उपलब्ध होगा उसकी अधिसूचना आधिकारिक गजट में कम से कम 30 दिन पहले दी जाए।

(2) केंद्रीय सरकार किसी विशेष मामले में लिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए उप-नियम (1) की प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।"

"59. कुछ क्षेत्रों की अनुदान हेतु उपलब्धता की अधिसूचना- किसी भूमि के मामले में जो अन्यथा अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने हेतु उपलब्ध हो लेकिन जिसके संबंध में राज्य सरकार ने यह कहते हुए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार किया हो कि भूमि को अन्वेषण या खनिजों के खनन के लिए किसी अन्य उद्देश्य हेतु आरक्षित किया जाना चाहिए, राज्य सरकार जब भी वह भूमि पुनः अन्वेषण या खनन पट्टा देने हेतु उपलब्ध होती है, तो लाइसेंस या पट्टा देने का कार्य करेगी, नियम 58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए।"

41. (i) नियम 58 को 16.11.1980 को संशोधित किया गया और संशोधित नियम 58 इस प्रकार हैं:

"58. सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन के लिए क्षेत्र का आरक्षण आदि- राज्य सरकार किसी अधिसूचना द्वारा आधिकारिक गजट में, किसी क्षेत्र को सरकार, केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय

अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनियों अधिनियम, 1956 (1 of 1956) की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी द्वारा दोहन के लिए आरक्षित कर सकती है।"

(ii) नियम 59 को पहले 9.7.1963 को संशोधित किया गया और फिर 1980 में नियम 58 के साथ। संशोधित नियम 59 जो 9.7.1963 को संशोधित किया गया था, इस प्रकार है:

"नियम 59. अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए कुछ क्षेत्रों की उपलब्धता की अधिसूचना- किसी भी भूमि के मामले में जो अन्यथा अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध है लेकिन जिसके संबंध में राज्य सरकार ने यह कहते हुए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार किया है कि भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, राज्य सरकार जब भी वह भूमि पुनः अन्वेषण या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध होती है, तो लाइसेंस या पट्टा देने का कार्य करेगी, नियम 58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए।"

(iii) नियम 59 जब 1980 में संशोधित किया गया तो इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"59. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलब्धता की अधिसूचना- (1) कोई ऐसा क्षेत्र-

(ए) जो पहले अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत था; या

(बी) जिसके लिए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन आवेदक लाइसेंस देने से पहले मर गया था, जैसा मामला हो; या

(सी) जिसके संबंध में लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश उप-नियम (1) धारा 15 या उप-नियम (1) धारा 31 के तहत रद्द किया गया था; या

(डी) जिसके संबंध में धारा 17 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी; या

(इ) जिसे सरकार ने नियम 58 के तहत आरक्षित किया है, वह अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि-

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध है, उप-नियम (2) धारा 21 या उप-नियम (2) धारा 40 में संदर्भित रजिस्टर में स्याही से प्रविष्टि न की गई हो; और

- (ii) क्षेत्र की उपलब्धता की अधिसूचना आधिकारिक गजट में दी जाए और एक तिथि निर्दिष्ट की जाए (जो ऐसी अधिसूचना के आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पहले तीस दिन से अधिक न हो) जिस तिथि से ऐसा क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा:

प्रावधान है कि इस नियम में कुछ भी मूल पट्टेदार या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में पट्टे के नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा भले ही पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका हो:

अतिरिक्त प्रावधान है कि जहां नियम 58 के तहत आरक्षित क्षेत्र को एक सरकारी कंपनी को देने का प्रस्ताव किया गया है, वहां उप-धारा (i) के तहत कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) केंद्रीय सरकार किसी विशेष मामले में लिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए उप-नियम (1) की प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।"

42. नियम 58 बाद में हटा दिया गया है, जबकि नियम 59 को 13.4.1988 को संशोधित किया गया। अब यह इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"59. पुनः अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलब्धता की अधिसूचना- (1) कोई ऐसा क्षेत्र-

(ए) जो पहले अन्वेषण अनुमति पत्र या अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत था; या

(बी) जिसे सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण ने खनन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित किया है; या

(सी) जिसके संबंध में अनुमति पत्र, लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश उप-नियम (1) धारा 7ए या उप-नियम (1) धारा 15 या उप-नियम (1) धारा 31 के तहत रद्द किया गया था, जैसा मामला हो; या

(डी) जिसके संबंध में धारा 17 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी; या

(इ) जिसे राज्य सरकार ने या अधिनियम की धारा 17ए के तहत आरक्षित किया है,

वह अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि-

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध है, उप-नियम (2) धारा 7डी या उप-नियम (2) धारा 21 या उप-नियम (2) धारा 40 में संदर्भित रजिस्टर में स्याही से प्रविष्टि न की गई हो; और
- (ii) क्षेत्र की उपलब्धता की अधिसूचना आधिकारिक गजट में दी जाए और एक तिथि निर्दिष्ट की जाए (जो ऐसी अधिसूचना के आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पहले तीस दिन से अधिक न हो), जिस तिथि से ऐसा क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा:

प्रावधान है कि इस नियम में कुछ भी मूल पट्टेदार या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में पट्टे के नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा भले ही पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका हो।

अतिरिक्त प्रावधान है कि जहां नियम 58 या अधिनियम की धारा 17ए के तहत आरक्षित क्षेत्र को एक सरकारी कंपनी को देने का प्रस्ताव किया गया है, वहां उप-धारा (ii) के तहत कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी:

अतिरिक्त प्रावधान यह भी है कि जहां कोई ऐसा क्षेत्र जो अन्वेषण अनुमति पत्र या अन्वेषण लाइसेंस के तहत हो, उसे धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार दिया जाता है, तो वहां उप-धारा (ii) के तहत कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) केंद्रीय सरकार किसी विशेष मामले में लिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए उप-नियम (1) की प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।"

43. (i) 1969 का नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से 9.7.1963 को संशोधित नियम 59 के तहत सुरक्षित है, क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य सरकार खनन पट्टा देने से इनकार कर सकती है, यदि भूमि किसी उद्देश्य के लिए आरक्षित हो। 1962 के नोटिफिकेशन के संबंध में, अपीलकर्ताओं का कहना है कि नियम 58 और 59, जैसे कि वे पहले थे, किसी उद्देश्य के लिए भूमि को आरक्षित करने की विशेष शक्ति नहीं रखते थे, जैसा कि 9.7.1963 के संशोधन द्वारा नियम 59 में शामिल किया गया था। जैसा कि देखा जा सकता है, ये नियम बताते हैं कि आरक्षित क्षेत्र को पुनः पट्टे के लिए कब अधिसूचित किया जा सकता है। नियमों में इस संबंध में बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि करने और क्षेत्र की उपलब्धता के बारे में आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता निर्धारित की गई है। ये प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जनक लाल (उपर्युक्त) में निर्णय का संदर्भ अपीलकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उस निर्णय में कहा गया है कि नियम में

संशोधन का परिणाम केवल नियम का विस्तार करना है, न कि इसके संचालन के क्षेत्र को सीमित करना। निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि इन नियमों का उद्देश्य सामान्य जनता को प्रस्तावित पट्टे के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है।

(ii) मूल रूप से नियम 58 ने दो संभावनाओं का प्रावधान किया। एक संभावना वह है जहाँ आवेदक लाइसेंस या पट्टा निष्पादन से पहले मर जाता है, और दूसरी वह है जहाँ लाइसेंस या पट्टा देने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। मूल रूप से तैयार किए गए नियम 59 ने तीसरी संभावना का प्रावधान किया, अर्थात्, जहाँ राज्य सरकार ने पहले किसी अन्य उद्देश्य (जैसे पर्यावरण) के आधार पर कुछ भूमि पर अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार किया था, और ऐसी भूमि पुनः पट्टे के लिए उपलब्ध हो जाती है। इन तीनों संभावनाओं के लिए, नियम 58 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था, अर्थात् निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि करना और आधिकारिक गजट में यह सूचित करना कि क्षेत्र कब पट्टे के लिए उपलब्ध होगा।

44. अपीलकर्ताओं ने फिर संशोधित नियम 59 का संदर्भ देते हुए तर्क किया कि क्योंकि 'किसी उद्देश्य' के लिए भूमि आरक्षित करने की शक्ति विशेष रूप से 9.7.1963 से प्रदान की गई थी, ऐसी शक्ति पहले के नियम 58 और 59 में मौजूद नहीं थी। इस व्याख्या को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर बताए गए कारणों से नियम 58 और 59 जैसे कि वे मूल रूप से थे, केवल तीन संभावनाओं से संबंधित थे जहाँ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जब यह सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खनन क्षेत्रों के आरक्षण की बात आती है, तो ऐसी शक्ति राज्य सरकार के पास 1963 के संशोधन से पहले नहीं थी। अधिनियम के विभिन्न धाराओं का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि खनन पट्टे देने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार के पास सुरक्षित रखी गई है, भले ही प्रमुख खनिजों के संबंध में केंद्रीय सरकार की मंजूरी हो। सार्वजनिक उपक्रमों या किसी उद्देश्य के लिए ऐसे आरक्षण करने की शक्ति उन खानों और खनिजों की स्वामित्व से आती है जो राज्य सरकार के पास होती हैं। 1963 में नियम 59 का संशोधन स्पष्ट करता है कि राज्य 'किसी उद्देश्य' के लिए भूमि आरक्षित कर सकता है, और 1980 में नियम 58 और 59 का संशोधन स्पष्ट करता है कि राज्य इसे सार्वजनिक निगम या सरकारी कंपनी के लिए आरक्षित कर सकता है। ये संशोधन केवल यह स्पष्ट करने के लिए किए गए हैं कि जो निहित था उसे स्पष्ट किया जाए। इन संशोधनों को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि वे उन शक्तियों को शून्य कर दें जो राज्य सरकार को अन्यथा अधिनियम के तहत थीं। वर्तमान मामले में हम राज्य सरकार द्वारा 13.9.2005 को जारी पत्र की वापसी की शक्ति को चुनौती देने से संबंधित हैं जो 1962 और 1969 के दो नोटिफिकेशनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था। इसलिए उक्त पत्र की वैधता को चुनौती को अस्वीकार करना होगा।

45. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहता ने भारतीय धातु और फेरो अलॉयज लिमिटेड (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए तर्क किया कि एक क्षेत्र जिसे आरक्षित किया गया है उसे निजी क्षेत्र को पुनः पट्टे पर दिया जा सकता है। हालाँकि, यह स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब क्षेत्र को पुनः आरक्षित किया जाता है, और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसी निर्णय के पैराग्राफ 45 में निम्नलिखित कथन को इस संबंध में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता:

"..... नियम 59(1) के अंतर्गत, एक बार जब नियम 58 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है, तो ऐसा आरक्षित क्षेत्र तब तक पट्टे पर उपलब्ध नहीं होगा जब तक उप-नियम (e) की दो आवश्यकताएँ पूरी न हों: अर्थात् रजिस्टर में प्रविष्टि और गजट अधिसूचना कि क्षेत्र पट्टे पर उपलब्ध है ....."

इस प्रकार, जब पुनः पट्टे के लिए क्षेत्र को पुनः आरक्षित करने का निर्णय लिया जाता है, तो उपरोक्त दो आवश्यकताओं का पालन किए जाने की अपेक्षा होती है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एक बार जब राज्य सरकार ने महसूस किया कि संबंधित क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग हेतु आरक्षित किया गया था, तो उसने अपीलकर्ताओं द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्तावों को वापस ले लिया, और इसे करने का पूरा अधिकार था।

46. श्री मेहता ने तब यह तर्क किया कि राज्य सरकार की शक्ति केवल अधिनियम की धारा 15 के तहत गौण खनिजों को विनियमित करने की है, क्योंकि वह धारा राज्य सरकार को गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है, और चूंकि धारा 14 कहती है कि धाराएँ 5 से 13 गौण खनिजों पर लागू नहीं होती हैं। दूसरी ओर, उपरोक्त धाराओं 4 से 17 के प्रावधानों का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य सरकार के पास खनन पट्टे, अन्वेषण लाइसेंस और अन्वेषण परमिट देने या न देने की शक्ति है और यह प्रमुख खनिजों के संबंध में भी उनके संचालन को विनियमित कर सकती है, जैसा कि अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, हालांकि केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खनन क्षेत्रों का आरक्षण करने की शक्ति भी शामिल होगी। भारत कोकिंग कोल (उपर्युक्त) पर भरोसा करना भी अस्वीकार्य है, क्योंकि निर्णय में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। इस मामले के तथ्यों में इस प्रस्तावना के साथ कोई संघर्ष नहीं है। राज्य की शक्ति उसके खानों के स्वामित्व से आती है, और इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून, अर्थात् एमएमडीआर अधिनियम या एमसी नियमों द्वारा किसी भी तरह से नहीं लिया गया है। इसलिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि श्री रंजीत कुमार का कहना है कि चूंकि अधिनियम के तहत एक विनियामक व्यवस्था बनाई गई है जो केंद्रीय सरकार को एक निश्चित भूमिका देती है,

इसलिए आरक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार से ले ली गई है। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय डी. के. त्रिवेदी एंड संस (उपर्युक्त) का संदर्भ भी गलत था। उस मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15(1) को संवैधानिक और वैध माना। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, इसके तहत, कार्यपालिका को विधायी शक्ति का अत्यधिक प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता। उस मामले में ऐसा कोई तर्क नहीं था कि राज्य सरकार की शक्तियाँ केवल धारा 15 तक सीमित थीं।

47. इसी तरह, हुकुम चंद (उपर्युक्त) पर भरोसा करना भी गलत था क्योंकि वर्तमान मामले में नियम बनाने की शक्ति का पूर्वव्यापी रूप से प्रयोग करने का कोई मुद्दा नहीं है। न ही एयर इंडिया (उपर्युक्त) में प्रस्तावना वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता रखती है क्योंकि यह किसी अधिनियम के निरसन के बाद किसी प्रावधान को बचाने का मामला नहीं है। राज्य का कार्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा असंगत होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि राज्य ने जो कुछ किया है वह केवल अधिनियम के पत्र और उसके वास्तविक अर्थ का पालन करना है।

48. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने तर्क किया कि एक बार जब राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को खनिज रियायत देने के लिए प्रस्ताव भेजा, तो यह एम.सी. नियमों, 1960 की धारा 63 ए के प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्य का हिस्सा हो जाता है, और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। जहां तक इस तर्क का सवाल है, सबसे पहले यह देखा गया कि अपीलित निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में 'सिफारिश' का अर्थ होगा एक पूर्ण और वैध सिफारिश जो नियम 22 के तहत खनन पट्टे के लिए आवेदन करने के बाद सभी पूर्ण विवरणों के साथ कानून के अनुसार होती है। वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने पाया कि उसका अपना प्रस्ताव दोषपूर्ण था, क्योंकि यह एक आरक्षित क्षेत्र पर ओवरलैप कर रहा था। ऐसी स्थिति में, राज्य द्वारा इसका वापस लेना नियम 63ए द्वारा प्रभावित नहीं कहा जा सकता। किसी भी स्थिति में, केंद्रीय सरकार ने बाद में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और इसलिए राज्य सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं के प्रस्ताव को प्रारंभिक रूप से भेजने से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता।

49. यह भी कहा गया है कि मोनेट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। राज्य सरकार द्वारा नियम 26 के तहत सुनवाई से इनकार का तर्क याचिका में नहीं उठाया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि उनकी याचिका के पैराग्राफ 2 (XVI) में एक और याचिका उठाई गई है, अर्थात्, केंद्रीय सरकार को अस्वीकृति आदेश जारी करने से पहले सुनवाई देनी चाहिए थी, हालांकि इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नियमों से नहीं बताया गया। अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि वे राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.9.2005 के खिलाफ नियम 54 के तहत अपनी पुनरीक्षण के निवारण का सहारा नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं किया जा

सकता क्योंकि अपीलकर्ता सीधे उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करने का विकल्प चुनते हैं (केंद्रीय सरकार के पत्र दिनांक 6.3.2006 के साथ) बिना उस निवारण का उपयोग किए। केंद्रीय सरकार को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संयोगवश, याचिका में कहीं यह नहीं कहा गया है कि मोनेट को राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच इन आंतरिक संचारों के बारे में कैसे जानकारी मिली। अन्य याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इसके बारे में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के माध्यम से सीखा, और आधुनिक ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन के माध्यम से इसकी प्रतियां प्राप्त करने का दावा किया।

50. अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय की संविधान पीठों के तीन निर्णयों पर भरोसा किया: *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी, एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी और बैजनाथ कडियो* (उपर्युक्त)। *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी* (उपर्युक्त) में, संविधान पीठ ने उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम, 1952 के तहत उपकर की वैधता के प्रश्न पर विचार किया। एक तर्क यह था कि उक्त कानून पूर्व खनिज और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के साथ संघर्ष में होने के कारण कानून में खराब था, जो कि एक केंद्रीय अधिनियम भी था। यह तर्क किया गया कि केंद्रीय कानून संघ सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 54 से संबंधित था। इसने क्षेत्र को कवर किया और इसलिए राज्य कानून जो प्रविष्टि संख्या 53 से संबंधित था, वह राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे था। न्यायालय ने पाया कि दोनों अधिनियमों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र मूलतः समान थे। हालाँकि, 1948 का अधिनियम एक पूर्व-संविधान अधिनियम था और संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों को भविष्यवाणी माना गया। इसलिए न्यायालय ने कहा कि जब तक 1948 अधिनियम की धारा 2 के तहत घोषणा संविधान लागू होने के बाद की गई थी, तब तक यह प्रविष्टि संख्या 54 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। इसलिए उपकर और उड़ीसा अधिनियम को कानून में खराब नहीं माना गया। इस न्यायालय ने इस संबंध में पैराग्राफ 23 में जो अवलोकन किया है वह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है .....

"23. अगला प्रश्न जो उठता है वह यह है कि यदि उपकर एक शुल्क है और इस प्रकार इसे सूची II में प्रविष्टियों 23 और 66 से संबंधित किया जा सकता है तो इसकी वैधता अभी भी चुनौती दी जा सकती है क्योंकि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता प्रविष्टि 23 के तहत संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची I की प्रावधानों के अधीन है; और यह हमें सूची I में प्रविष्टि 54 तक ले जाता है। यह प्रविष्टि इस प्रकार पढ़ती है: "खनिजों का विनियमन और विकास उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा विनियमन और विकास संघ के नियंत्रण में सार्वजनिक हित में संसद द्वारा कानून द्वारा आवश्यक घोषित किया जाता है"। इन दोनों प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ने का प्रभाव स्पष्ट है। प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानमंडल की

अधिकारिता उस प्रविष्टि के अंतिम भाग द्वारा लगाए गए सीमाओं के अधीन है। यदि संसद ने अपने कानून द्वारा घोषित किया है कि खानों का विनियमन और विकास सार्वजनिक हित में संघ के नियंत्रण में होना चाहिए तो उस घोषणा की सीमा तक राज्य विधानमंडल की अधिकारिता बहिष्कृत होती है। दूसरे शब्दों में, यदि एक केंद्रीय अधिनियम पारित किया गया है जिसमें संसद द्वारा आवश्यक रूप से प्रविष्टि 54 द्वारा आवश्यक घोषणा शामिल हो, और यदि वह घोषणा विवादित अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को कवर करती है तो विवादित अधिनियम अल्ट्रा वायर्स होगा, न कि किसी भी दो अधिनियमों के बीच किसी भी विरोधाभास के कारण बल्कि इसलिए क्योंकि राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। प्रविष्टि 23 के अंतिम भाग द्वारा लगाए गए सीमाएँ राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर खुद ही एक सीमा हैं। स्थिति विवादित नहीं है।"

(महत्वपूर्णता दी गई)

51. *एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी* (उपर्युक्त) में संविधान पीठ उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम, 1952 के तहत कुछ शुल्कों की मांग की वैधता पर विचार कर रही थी, और वही प्रश्न उठता है कि क्या उड़ीसा अधिनियम की प्रावधानों संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के संदर्भ में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 द्वारा प्रभावित थीं। राज्य अधिनियम की वैधता प्रविष्टि संख्या 23 के तहत उठाई गई थी और इसे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं माना गया था। न्यायालय ने उड़ीसा अधिनियम और शुल्क मांग को वैध माना। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में जो अवलोकन किया है वह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है ..... .

"5 ..... यह समझने के लिए अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है कि जिस सीमा तक संघ सरकार ने "अपने नियंत्रण" में "खनिजों का विनियमन और विकास" लिया था, उतनी ही मात्रा राज्य विधानमंडल की शक्ति से बाहर थी जो प्रविष्टि 23 के तहत थी और उस प्रविष्टि के तहत शक्ति होने पर आधारित राज्य का कानून उस "नियंत्रण" की सीमा तक निरस्त या अप्रभावी हो जाएगा; क्योंकि यहाँ हमारे पास दो अधिनियमों की प्रावधानों के बीच केवल विरोधाभास नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाई गई घोषणा द्वारा राज्य विधायी शक्ति का हरण या वंचना का मामला है जिसे बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है और उसने बनाया है।"

52. *बैजनाथ कडियो* (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1964 की धारा 10 के दूसरे उपबंध की वैधता पर विचार किया, जो खनिजों के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम, 1957

के प्रावधानों के साथ संघर्ष में था। न्यायालय ने *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी* और *एम.ए. टुल्लोक कंपनी* के सिद्धांतों का पालन किया और पाया कि यह क्षेत्र राज्य विधानमंडल के लिए खुला नहीं था, क्योंकि यह केंद्रीय अधिनियम के तहत कवर किया गया था।

53.इन तीन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि यदि संसद द्वारा कोई घोषणा की जाती है, तो उस घोषणा की सीमा तक खानों और खनिज विकास का विनियमन राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर होगा जैसा कि केंद्रीय सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के तहत प्रदान किया गया है। वर्तमान में, हम एमएमडीआर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संघर्ष से संबंधित नहीं हैं, न ही किसी राज्य विधानमंडल के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किसी कार्यकारी आदेश से। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि झारखंड सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए 1962 और 1969 के नोटिफिकेशन जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। राज्य सरकार का उत्तर है कि वह स्वयं इसी एमएमडीआर अधिनियम के तहत कार्य कर रही है, और नोटिफिकेशन उसके अधिकारों की सीमाओं के भीतर हैं जैसा कि केंद्रीय कानून द्वारा अनुमति दी गई है।

54.अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का पहले ही इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अमृतलाल नाथुभाई शाह बनाम भारत संघ मामले में निर्णय लिया था जो 1976 (4) एससीसी 108 में रिपोर्ट किया गया था। उस मामले में भी गुजरात सरकार ने बौक्साइट के सार्वजनिक क्षेत्र में दो निश्चित तालुकों में भूमि आरक्षित करने के लिए 31.12.1963 और 26.2.1964 की तिथि वाले समान नोटिफिकेशन जारी किए थे। अपीलकर्ता द्वारा बौक्साइट के लिए खनन पट्टे की प्राप्ति हेतु दायर आवेदन राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। अपीलकर्ता द्वारा केंद्रीय सरकार को दायर पुनरीक्षण आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में खनिजों की मालिक थी और खनिज उसमें निहित थे, और यह भी कि राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र को आरक्षित करने का अंतर्निहित अधिकार था। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया था।

55.इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने अमृतलाल नाथुभाई (उपर्युक्त) में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की शक्ति उसके खनिजों के स्वामित्व से उत्पन्न होती है, और उसके पास उनसे निपटने का अंतर्निहित अधिकार है। अपने निर्णय के पैराग्राफ 3 में न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"3. यह उल्लेखनीय है कि सूची I की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 54 से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की अपनी विशेष शक्ति का पालन करते हुए, संसद ने अधिनियम की धारा 2 में

विशेष रूप से घोषित किया कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि संघ खानों का विनियमन और खनिजों का विकास अपने नियंत्रण में ले। इसलिए राज्य विधानमंडल की प्रविष्टि 23 के तहत शक्ति समाप्त कर दी गई थी, और हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि खानों और खनिज विकास का विनियमन इसलिए अधिनियम और नियमों के अनुसार होना चाहिए। प्रश्नगत खनिज (बौक्साइट) हालांकि गुजरात राज्य की सीमा में थे और जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं के पुनरीक्षण आवेदनों पर पारित आदेशों में कहा गया था, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में "खनिजों की मालिक" है, और खनिज "उसमें निहित" हैं। अधिनियम या नियमों में इस मूल तथ्य को नकारने वाली कोई बात नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय सरकार ने अपने पुनरीक्षण आदेशों में आगे कहा कि राज्य सरकार को "सार्वजनिक क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र को आरक्षित करने का अंतर्निहित अधिकार" था। इसलिए यह स्पष्ट है कि, इसके विपरीत कोई कानून या अनुबंध आदि नहीं होने पर, बौक्साइट, एक खनिज के रूप में, और उसके खनन राज्य गुजरात में निहित हैं और किसी व्यक्ति को इसे अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निष्कर्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 10 और नियमों के अध्याय II, III और IV उन भूमि पर अन्वेषण लाइसेंस और खनन पट्टे देने से संबंधित हैं जिनमें खनिज राज्य सरकार के पास निहित हैं। यही कारण है कि अपीलकर्ताओं ने अपने आवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए।"

56. न्यायालय ने राज्य सरकार को पट्टा देने से इनकार करने की शक्ति को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 से जोड़ा। इसने कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से उस शक्ति को शामिल करती है जो पट्टा देने या न देने का निर्णय लेने की होती है यह आधार बनाते हुए कि प्रश्नगत भूमि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इसे किसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किया गया था। अपने निर्णय के पैराग्राफ 5 में इस न्यायालय ने कहा:

"5. अधिनियम की धारा 10 वास्तव में यह प्रावधान करती है कि जो खनिज राज्य में निहित हैं, उनके संबंध में अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे देने हेतु आवेदन स्वीकार करना केवल राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और उसे देना या अस्वीकार करना भी उसी का कार्य है। इसलिए यह धारा इस बात का संकेत देती है कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होती है, और यह कहने हेतु बहुत अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है कि उस शक्ति में इस आधार पर लाइसेंस या पट्टा देने से इनकार करने की शक्ति भी शामिल होती है कि प्रश्नगत भूमि ऐसी अनुमति देने हेतु उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इसे किसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किया गया था।"

57. निर्णय के पैराग्राफ 6 में, इस न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि अधिनियम की धारा 17 केंद्रीय सरकार को अन्वेषण या खनन कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है, इसलिए राज्य सरकार को आरक्षण करने की शक्ति नहीं हो सकती। इस पैराग्राफ का पहला भाग इस प्रकार है:

"6. हमने अधिनियम की धारा 17 के उप-धारा (2) और (4) का अध्ययन किया है, जिनका उल्लेख श्री सेन ने अपीलकर्ताओं की ओर से इस तर्क के लिए किया है कि ये आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को निर्दिष्ट करने के लिए केवल प्रावधान हैं, और चूंकि ये केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण या खनन कार्यों से संबंधित हैं, इसलिए ये यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि अधिनियम किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षण की कल्पना नहीं करता है या प्रदान नहीं करता है। हालांकि, यह तर्क अस्वीकार्य है क्योंकि धारा 17 की उप-धाराएँ किसी अन्य को अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से इनकार करने के अधिकार के पूरे क्षेत्र को कवर नहीं करती हैं, और राज्य सरकार के लिए किसी क्षेत्र को अपने लिए आरक्षित करने के अधिकार से संबंधित नहीं हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, आरक्षण का आदेश देने का अधिकार इस तथ्य से आता है कि राज्य अपने क्षेत्र में खानों और खनिजों का मालिक है, जो उसमें निहित हैं। ..... "

58. न्यायालय ने एम.सी. नियमों के नियम 59 का भी उल्लेख किया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के आदेश द्वारा ऐसे आरक्षण की कल्पना करता है। पैराग्राफ 7 में इस न्यायालय ने इस संबंध में कहा:

"7 ..... नियम 58, 59 और 60 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित क्षेत्र में लाइसेंस या पट्टा के लिए आवेदन करना तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि वह ऐसे अनुदान के लिए उपलब्ध न हो, और उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में अधिसूचित की जाती है। नियम 60 यह प्रावधान करता है कि किसी क्षेत्र के लिए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान हेतु आवेदन, जिसके लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, विशेष रूप से नियम 59 के तहत, लाइसेंस या पट्टे के अनुदान हेतु क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए, पूर्ववर्ती होगा, और "इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कोई शुल्क दिया गया हो तो उसे वापस कर दिया जाएगा।" इसलिए यह स्पष्ट होगा कि चूंकि वर्तमान अपीलों का विषय क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशनों में बताए गए उद्देश्य के लिए आरक्षित किया गया था, और चूंकि वे भूमि अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं

हुई, इसलिए राज्य सरकार ने नियम 60 के तहत अपीलकर्ताओं के आवेदन को पूर्ववर्ती रूप में अस्वीकार करने में अपने अधिकारों का सही प्रयोग किया ..... II

59. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, *अमृतलाल* (उपर्युक्त) में निर्णय को *हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी*, *एम.ए. टुल्लोक एंड कंपनी और बैजनाथ कडियो* (उपर्युक्त) में प्रस्तुत सिद्धांतों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह एक बाध्यकारी उदाहरण है। वर्तमान अपीलों के समूह में अपीलकर्ताओं द्वारा विवादित नोटिफिकेशन एमएमडीआर अधिनियम की प्रावधानों के तहत पूरी तरह से सुरक्षित थे, और जैसा कि *अमृतलाल* (उपर्युक्त) में बताया गया है।

### डेस्यूटेड

60. डेस्यूटेड के कारण प्रभावित दो नोटिफिकेशनों के संबंध में प्रस्तुतियाँ भी योग्यता रहित हैं, क्योंकि कानून की आवश्यकता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण अवधि की उपेक्षा होनी चाहिए, और यह दिखाना आवश्यक है कि इसके विपरीत एक प्रथा लंबे समय से चल रही है। अपीलकर्ताओं ने इस संबंध में कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहे हैं। झारखंड राज्य के अधिकारियों ने जैसे ही नोटिफिकेशन उनके ध्यान में लाए गए, उसी क्षण कार्य किया, और उन्होंने इसके अनुसार कार्य किया। यह निश्चित रूप से डेस्यूटेड नहीं हो सकता।

### वचनात्मक रोकथाम और वैध अपेक्षाएँ

61. जैसा कि हमने पहले देखा है, वचनात्मक रोकथाम के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक वादा होना चाहिए, और उस आधार पर संबंधित पक्ष को अपने नुकसान के लिए कार्य करना चाहिए। वर्तमान मामले में यह केवल एक प्रस्ताव था, और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसे केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था, इससे पहले इसे वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा, न्याय का उपयोग किसी वैधानिक प्रावधान या अधिसूचना के खिलाफ नहीं किया जा सकता।

62. अपीलकर्ता जो मांग कर रहे हैं, वह किसी प्रकार का विशिष्ट प्रदर्शन है जब पक्षों के बीच कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं है। एक एमओयू अनुबंध नहीं है, और किसी भी मामले में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के अर्थ में नहीं आता। एक पक्ष (आधुनिक) को छोड़कर अन्य पक्षों ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। किसी भी स्थिति में, किसी वादे की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता सहित आधुनिक को वैधानिक अधिसूचनाओं के खिलाफ वचनात्मक रोकथाम का दावा नहीं कर सकते। वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के तहत मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिद्धांत का आधार तर्कसंगतता और निष्पक्षता है। हालांकि, इसे तब भी लागू नहीं किया जा सकता जब सार्वजनिक

प्राधिकरण का निर्णय कानून के प्रावधान पर आधारित हो और यह सार्वजनिक हित के अनुरूप हो। हाल ही में इस न्यायालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में पुनः पुष्टि की गई थी कि "यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई मामला कानून द्वारा शासित होता है तो न्याय का उपयोग बाहर रखा जाता है"। हम बिहार स्पंज और आयरन लिमिटेड के पक्ष में अन्यायपूर्ण भेदभाव की प्रस्तुति को भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसे उच्च न्यायालय के समक्ष दबाया नहीं गया था और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की गई थी कि इसके पक्ष में अनुदान अन्यायपूर्ण था।

### उपसंहार

63. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जो राज्य तमिलनाडु बनाम हिंद स्टोन के मामले में है, जो एआईआर 1981 एससी 711 में रिपोर्ट किया गया है, जहाँ इस अधिनियम के प्रति दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। उस मामले में, इस न्यायालय को तमिलनाडु द्वारा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए तमिलनाडु गौण खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 8-C से संबंधित था। यह नियम इस प्रकार प्रदान करता है:

"8-सी. काले ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टे सरकार के निगम आदि को -

(1) इन नियमों में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, 7 दिसंबर 1977 से काले ग्रेनाइट के लिए निजी व्यक्तियों को कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार स्वयं काले ग्रेनाइट का खनन कर सकती है या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व वाले किसी निगम के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए पट्टे दे सकती है।

यह शर्त है कि किसी निजी व्यक्ति की भूमि के संबंध में, ऐसे खनन या पट्टे के लिए उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।"

64. हालांकि हिंद स्टोन में न्यायालय इस नियम के प्रावधानों से संबंधित था जो एक गौण खनिज से संबंधित था, इसके वैधता की जांच करते समय इस न्यायालय (जज ओ. चिन्नप्पा रेड्डी) ने एमएमडीआर अधिनियम के प्रति दृष्टिकोण और दायरे पर कुछ टिप्पणियाँ की हैं जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। इस प्रकार, पैराग्राफ 6 में यह अवलोकन किया गया:

"6 ..... वह सार्वजनिक हित जो संसद को खानों और खनिजों (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 2 में निहित घोषणा करने के लिए प्रेरित करता है, स्वाभाविक रूप से खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च विचार होना चाहिए। संसद की नीति अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है। यह खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण तथा विवेकशील निष्कर्षण है, जिसका उद्देश्य समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है ..... "

65. फिर पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने कहा:

"9 ..... जब भी 'निजी क्षेत्र' से 'सार्वजनिक क्षेत्र' में परिवर्तन होता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि नीति में बदलाव की आवश्यकता हो जो स्पष्ट विधायी स्वीकृति की मांग करे। यह विषय और अधिनियम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि सभी गौण खनिजों की निजी खनन पर सामान्य और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा प्रतिबंध एक प्रमुख नीति का उलटाव कर सकता है और इसलिए इसे विधायी स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यदि एकल गौण खनिज के निजी खनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाता है ताकि उसे संरक्षित किया जा सके, तो ऐसा प्रतिबंध, यदि यह अधिनियम द्वारा सरकार को दी गई शक्तियों की सीमाओं के भीतर हो, तो इसे नीति में बदलाव नहीं कहा जा सकता। अधिनियम की नीति वही रहती है और यह, जैसा कि हमने कहा, खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण तथा विवेकशील निष्कर्षण है, जिसका उद्देश्य समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है। निजी और/या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खनिजों का निष्कर्षण अपेक्षित है। यदि अधिनियम की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए यह समझा जाता है कि किसी विशेष खनिज के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निष्कर्षण सबसे अच्छा और बुद्धिमान है और इसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकरण उप-निर्णय बनाने वाला नियम बनाता है जो ऐसे खनिज का निजी निष्कर्षण प्रतिबंधित करता है, जिसे पहले अनुमति दी गई थी, तो हम केवल इसलिए नीति में किसी परिवर्तन को नहीं देख सकते क्योंकि जो पहले अनुमति दी गई थी वह अब अनुमति नहीं दी गई।"

अंततः पैराग्राफ 13 में इस न्यायालय ने कहा:

"13 ..... किसी को पट्टा देने या नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं होता और कोई भी विशेष तरीके से पट्टा देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं रखता ..... "

66. खान और खनिज एक राष्ट्र की संपत्ति का हिस्सा होते हैं। ये समुदाय के भौतिक संसाधनों का गठन करते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांतों का अनुच्छेद 39(बी) निर्धारित करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई को सर्वोत्तम रूप से सेवा दे सके। इसके बाद अनुच्छेद 39(सी) निर्धारित करता है कि राज्य सुनिश्चित करे कि आर्थिक प्रणाली का संचालन धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामान्य हानि का कारण न बने। सार्वजनिक हित एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और इसकी धारा 2 के तहत घोषित किए गए हित में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। झारखंड राज्य में खान का स्वामित्व बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धाराओं के अंतर्गत आता है जिसे संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई नौवीं अनुसूची में रखा गया है। वामन राव (उपर्युक्त) मामले में संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए चंद्रचूड़, सीजे ने अनुच्छेद 39(बी) और (सी) तथा पहले संशोधन के बीच संबंध पर निम्नलिखित कहा:

"26. संविधान का अनुच्छेद 39 उपधारा (बी) और (सी) के माध्यम से निर्देशित करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई को सर्वोत्तम रूप से सेवा दे सके; कि आर्थिक प्रणाली का संचालन धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामान्य हानि का कारण न बने। ये राज्य नीति के दोहरे सिद्धांत संविधान के मूल रूप से लागू किए गए भाग थे और इन निर्देशात्मक सिद्धांतों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले और चौथे संशोधन पारित किए गए ....."

67. अपीलकर्ताओं द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह यह है कि राज्य सरकार ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है, जिन कारणों का उल्लेख अपीलकर्ताओं ने किया है। हालांकि, हमें झारखंड राज्य द्वारा 13.9.2005 को जारी की गई वापसी के पत्र में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, और भारत संघ द्वारा 6.3.2006 को जारी अस्वीकृति के पत्र में भी इसमें बताए गए कारणों के लिए। हमारे विचार में, झारखंड राज्य ने निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों को पट्टे देने से इनकार करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने में पूरी तरह से उचित कार्य किया है, जो 1962, 1969 और 2006 के नोटिफिकेशनों के आधार पर है। राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है वह अधिनियम की नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया है और इसके लिए इसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

68. उपरोक्त कारणों के लिए हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है और सभी को अस्वीकार किया जाता है। इसमें पारित अंतरिम आदेश रद्द किए जाएंगे।

69. अवमानना याचिका (सी) संख्या 14/2009 अभिजीत द्वारा दायर की गई है, जो 15.12.2008 की एक पूर्व आदेश का कथित उल्लंघन करने के लिए है। 28.01.2009 की आदेश स्पष्ट करती है कि अवमानना याचिका पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। चूंकि अपील का निपटारा किया जा रहा है और इसे अस्वीकार किया जा रहा है, अवमानना याचिका भी अस्वीकार की जाती है।

70. लोहे का खनिज औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। इन अपीलों की लंबित स्थिति और अपीलकर्ताओं द्वारा इसमें मांगी गई स्थगन आदेशों को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लौह-अयस्क खानों का पट्टा छह वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जा सका। झारखंड राज्य और आम जनता ने इसके परिणामस्वरूप नुकसान उठाया है। इस संबंध में हम अपीलकर्ताओं पर लागत लगाने में उचित होते। हालांकि, चूंकि इन अपीलों में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए गए थे, हम ऐसा करने से बचते हैं। इसलिए पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे।

आर.पी.

अपीलें अस्वीकार की गईं।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।